राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 08] चौदहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का तेईसवां दिवस [संख्या: 13

शुक्रवार,
17 मार्च 2017

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल। श्री हीरालाल।

निवाई के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का क्रमोन्नयन

327. श्री हीरालाल (निवाई): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में किस-किस स्तर के कितने स्वास्थ्य केन्द्र, कहां-कहां संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नये स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो, कहां-कहां व कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झिलाय, राहोली एवं दतवास को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री कालीचरण सराफ): (1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में स्वीकृत 78 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 18 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र निवाई के अन्तर्गत पंचायत समिति निवाई का पूर्ण एवं पंचायत समिति टोंक का आंशिक क्षेत्र आता है।

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मापदण्ड के

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)
अनुसार सामान्य क्षेत्र में 05 हजार एवं जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्रों में 03 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर 01 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

पंचायत समिति निवाई की वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या 1.92 लाख है। ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पंचायत समिति निवाई में 38 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के विरुद्ध 46 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं।

पंचायत समिति टोंक की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या 2.39 लाख है। पंचायत समिति टोंक में 48 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के विरुद्ध 93 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं।

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सामान्य क्षेत्र में 30 हजार एवं जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्रों में 20 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर 01 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

पंचायत समिति निवाई में 06 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा पंचायत समिति टोंक में 08 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 20 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं।

इस प्रकार विधान सभा क्षेत्र, निवाई में उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मापदण्ड से अधिक स्वीकृत होने के कारण उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(3) आगामी वित्तीय वर्षों में गुणावगुण के आधार पर पंचायत समिति, निवाई के 01 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने पर विचार किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया, अब उन्होंने संसाधन की बात कर दी, अब हर जगह ही संसाधन की बात हो तो फिर आगे क्या बात करें।

श्री अध्यक्ष: फिर भी आगे कुछ प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सारी डिटेल बता दी।

श्री हीरालाल (निवाई): मैं तो माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि मेरे यहां झिलाय, माननीय पूर्व चिकित्सा मंत्री आदरणीय राठौड़जी भी यहां विराजमान हैं, पिछली बार 2014 में मैंने झिलाय सी.एच.सी. का प्रश्न उठाया था तो आपने सिद्धांतत: यह मूक स्वीकृति भी एक तरह से दे दी थी, फिर शायद इनके दिमाग से वह निकल गई हो, तो 1967 में मेरे झिलाय पी.एच.सी. स्वीकृत हुई है। अब 50 साल हो गये। आज तक कोई, इतनी पी.एच.सी. हुई हैं तो कोई क्राइटेरिया तो, 50 साल हो गये। ...(व्यवधान)... एक मिनट मंत्रीजी। दूसरा, मेरा यह है कि मेरे यहां राहोली बहुत इंटीरियर में है। 1990 में राहोली पी.एच.सी. स्वीकृत हुई है और एक दतवास है जो 1990 में हुई है, तो ये 27 साल से आज तक एक-एक स्वीकृति, जो इंटीरियर में है। दतवास तो पूरी एस.टी., ओ.बी.सी. और माधोपुर जिले की सीमा पर है। राहोली है, वह जयपुर के फागी सीमा पर पड़ती है तो निवाई आने में दोनों को 30-40 किलोमीटर आना पड़ता है। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि इस झिलाय की तो आप अभी घोषणा करें, यह 1967 की है। अब इसमें क्या बाकी रह गया। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय भंवरजी, हस्तक्षेप न करें।

श्री हीरालाल (निवाई): झिलाय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि 1967 में खुली है। मेरे यहां 1945 में सी.डी. डिस्पेंसरी खुली थी। 1945 से आज तक वहां दो ही ए.एन.एम. हैं। 1945 में भी दो थीं, आज भी दो ए.एन.एम. हैं, तो ए.एन.एम. बढ़ायी जाएं और झिलाय को सी.एच.सी. किया जाए। मैं आपके जवाब से संतुष्ट हो जाता हूं, कम से कम झिलाय को तो करो आप। मेरी दो पी.एच.सी. को क्रमोन्नत करने की मांग है, जो 27-28 साल से है और 50 साल से झिलाय पी.एच.सी. है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा, राठौड़ साहब भी विराजमान हैं, ये भी विराजमान हैं, वे भी मुस्करा कर कह रहे हैं तो आप एक तो करो, झिलाय। अब संसाधन की बात है तो 50 साल हो गये, 50 साल।

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, विराजिये। मैं आपके प्रश्न का जवाब दिलवाता हूं।

श्री हीरालाल (निवाई): मैं निवेदन करूंगा, करम्बद्ध प्रार्थना करूंगा कि झिलाय पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करें और आज ही करें। जवाब दे दें, आज ही। आज ही घोषणा कर दें।

श्री अध्यक्ष: मैं आपको जवाब दिलवाता हूं। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जैसे कहा कि वहां 50 साल से पी.एच.सी. है, सी.एच.सी. नहीं खुली। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): तो मैं बताना चाहूंगा कि आपके निवाई पंचायत समिति में छह पी.एच.सी. होनी चाहिए, उसकी जगह दस हैं, यानी चार ज्यादा हैं। जहां उप स्वास्थ्य केन्द्र आपके, यानी छह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता है, उसके विरुद्ध तो दस हैं और पंचायत समिति टोंक में आठ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की जगह बीस हैं। आपके जिले में भी ज्यादा हैं। जहां तक झिलाय में सी.एच.सी. का सवाल है, तो जैसा मैंने कहा कि गुण-दोष के आधार पर और वित्तीय प्रावधानों की उपलब्धता के आधार पर विचार करके निश्चित रूप से, और यदि पूर्व मंत्रीजी ने घोषणा की है तो इनसे बातचीत करके जो भी उचित होगा, वह करेंगे।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न टोंक का है। ...(व्यवधान)...

श्री हीरालाल (निवाई): यह तो मैंने पहले ही कह दिया। आप संसाधन की बात करो। ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: घोषणा करो आप।

श्री अध्यक्ष: संतोषजनक जवाब आ गया।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं। अब झिलाय, निवाई में इतनी दुर्घटनाएं होती हैं आये दिन, ट्रोमा की भी मांग की है, वह भी नहीं है तो सी.एच.सी. कन्वर्ट कर देंगे तो निवाई की सी.एच.सी. का काफी लोड कम हो जायेगा। आसपास की बहुत जनसंख्या है। आज निवाई की जनसंख्या, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो खुद वहां

(श्री हीरालाल)
से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। आप एम.एल.ए. भी रह चुके हैं, वहां से सांसद भी रह चुके हैं। मैं तो आपसे कहूंगा, पुरज़ोर शब्दों में आप इनको निर्देश प्रदान करें, ताकि ये करें। आप भी कहो, आप भी रहे हैं, झिलाय को 50 साल हो गये। अब आप भी मुस्करा रहे हैं। इनको मुस्करा कर कहें, झिलाय पी.एच.सी. को सी.एच.सी. आज ही करें। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री हीरालाल (निवाई): वे घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष: विराजो, आप। विराजो, जवाब दिलवा रहा हूं आपको। ...(व्यवधान)...

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, निवाई से आने वाले माननीय सदस्य की मांग पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाएगा और जो उचित होगा, वह करेंगे।

श्री हीरालाल (निवाई): गम्भीरतापूर्वक नहीं, आप तो घोषणा कर दो न। अगले बजट में कर दो, गम्भीरतापूर्वक क्या। जब 2014 में हो गया, माननीय राठौड़ साहब भी मुस्करा कर कह रहे हैं आपको, दोनों बैठे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: हीरालालजी, विराजिये। पूरक प्रश्न, श्री रामलाल शर्मा।

श्री हीरालाल (निवाई): आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, 50 साल हो गये। ...(व्यवधान)... मान लो, अगर ऐसा है कि ये ज्यादा है और कम है तो यह तो एक खाली टोंक जिले का दे रहे हैं। टोंक से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरे निवाई विधान सभा क्षेत्र से मतलब है। अगर ऐसा है तो सर्वे पूरे राजस्थान का कर दो, कहां ज्यादा, कहां कम है। बंद करो।

श्री अध्यक्ष: जवाब दे दिया, विराजिये। श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: यह निवाई है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): निवाई विधान सभा क्षेत्र में कई गांव, कई राजस्व गांव अब अस्तित्व में आये हैं।

श्री अध्यक्ष: कहां का बोले?

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): उन नये राजस्व गांवों के अन्दर अभी भी उप केन्द्र खुले हुए नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: निवाई के बारे में?

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, निवाई से पूछ रहा हूं, निवाई।

अध्यक्ष महोदय, निवाई विधान सभा क्षेत्र में कई उप केन्द्र ऐसे हैं जिनको खुले हुए दस साल हो चुके और अब तक भी उनके भवन के लिये पैसा स्वीकृत नहीं हुआ। आप कब तक, जो उप केन्द्र दस साल पुराने हैं और जो भवन रहित हैं तो कब तक आप भवन बनाने का काम करेंगे और नये राजस्व गांवों में सेण्टर खोलेंगे? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। माननीय मंत्री महोदय, आप जवाब दीजिये।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि निवाई में उप स्वास्थ्य केन्द्र कम हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि ....(व्यवधान)....

श्री हीरालाल (निवाई): 60 हजार की जनसंख्या है निवाई की।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सुनिए, आप बैठिए न, क्या है यह बीच-बीच में? 38 स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकता है, उसके विरुद्ध 46 उप स्वास्थ्य केन्द्र खुले हुए हैं यानी, आठ अभी ज्यादा हैं तो कम का तो सवाल ही नहीं है इसलिए वहां पर आवश्यकता नहीं है। इसलिए वहां पर अभी कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

श्री हीरालाल (निवाई): मंत्री महोदय, आप तो बहुत वरिष्ठ मंत्री है और आप अधिकारियों की भाषा में मत बोलो, आप तो खुद पावर-फुल है। यह क्या भाषा बोल रहे हैं आप? ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: श्री रामहेत सिंह, पूरक प्रश्न कर रहे हैं न आप या नहीं कर रहे?

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): जवाब आ गया। ....(व्यवधान)....

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको एक झिलाय के

(श्री हीरालाल)

लिए तो कह दीजिए और आप खुद प्रतिनिधित्व कर चुके, मेरी तो आपसे भी प्रार्थना है, इनको कह दो। ....(व्यवधान)....

प्रश्न संख्या 328

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल। डा. मंजू बाघमार।

अगला सवाल, श्री भंवरसिंह।

प्रदेश के नवगठित ग्राम पंचायत मुख्यालयों के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

329. श्री भंवरसिंह (कोलायत): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्थित विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाना सरकार के प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नवगठित ग्राम पंचायत मुख्यालय तथा क्रमोन्नत होने से वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालयों के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए, आप बैठिए। अंकित नहीं हो।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। यह अंकित नहीं हो। आप बैठिये, अंकित नहीं हो रहा है। यह आपका अधिकार नहीं है, आप बैठिए। हां, माननीय मंत्रीजी। ....(व्यवधान).... आपस में चर्चा नहीं।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री वासुदेव देवनानी): (1) जी नहीं। अपितु, बजट घोषणा वर्ष 2014-15 में प्रत्येक ग्राम पंचायतों पर जहां गैर राजकीय/राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित नहीं है, उन ग्राम पंचायतों पर माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का

(राज्य मंत्री, शिक्षा)
लक्ष्य निर्धारित था। लक्ष्य की क्रियान्विति की पालना में 5000 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मय विज्ञान/वाणिज्य संकाय सहित क्रमोन्नत किये गये। बजट घोषणा 2015-16 में ग्राम पंचायत परिक्षेत्र में गैर राजकीय/राजकीय उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षण सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत करने का लक्ष्य निर्धारित था। लक्ष्य की पालना में 114, 126 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किए जा चुके हैं। आगामी वर्षों में चरणबद्ध रूप से विद्यालयों को क्रमोन्नत वर्ष 2020 तक किया जा सकेगा।

(2) जी नहीं। 692 नवगठित ग्राम पंचायत में से राजकीय प्राथमिक से राजकीय उच्च प्राथमिक 461 तथा राजकीय उच्च प्राथमिक से राजकीय माध्यमिक में 240 क्रमोन्नत किये जा चुके हैं। वर्ष 2015-16 से बजट सत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत परिक्षेत्र में गैर राजकीय/ राजकीय उच्च माध्यमिक स्तर का विद्यालय नहीं होने पर माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का लक्ष्य निर्धारित था जिसकी पालना में 114, 126, कुल-240 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जा चुके हैं। चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2020 तक विद्यालय क्रमोन्नत किये जा सकेंगे, जिसमें मुख्यालय अथवा मुख्यालय के राजस्व ग्राम के विद्यालय भी हो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। पूरक प्रश्न नम्बर-एक।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जैसा कि अपने जवाब में बताया है कि 2014-15 और 2015-16 की बजट घोषणा के अनुसार राज्य में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि आपने 2020 तक विद्यालय क्रमोन्नत करने का जो जवाब दिया है, मेरा आपसे आग्रह यह रहेगा और मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की जो ग्राम पंचायतें हैं रणजीतपुरा और चारणवाला, ये दो ग्राम पंचायतें परिसीमन से पूर्व की ग्राम पंचायतें हैं, उसके बावजूद भी यहां पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय है और इनको उच्च माध्यमिक विद्यालय

(श्री भंवरसिंह)

में क्रमोन्नत नहीं किया गया है। तो क्या इन विद्यालयों को, वर्ष 2020 की बात तो अगले 15वीं विधान सभा की आपने बात कह दी है, मैं इस बात का विरोध भी करना चाहूंगा, मैं तो इस हाउस की बात करना चाहूंगा कि रणजीतपुरा और चारणवाला जो सैकण्डरी विद्यालय हैं, इनको क्रमोन्नत 2017-18 में क्या करने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): दूसरा मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां राज्य में सभी ग्राम पंचायतों पर लगभग 10वीं और 12वीं के विद्यालय हो गये हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र की 6 ग्राम पंचायतें नवीन ऐसी हैं जहां पर अभी भी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है, जिनमें ग्राम पंचायत खारिया पातावतान, ग्राम पंचायत देवड़ों की ढाणी, ग्राम पंचायत गज्जेवाला, ग्राम पंचायत मुख्यालय भूरासर, ग्राम पंचायत मुख्यालय जग्गासर और ग्राम पंचायत मुख्यालय 6/8 ए.एम. संतोषनगर, इन छह ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आज भी आठवीं तक के विद्यालय हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, अभी जवाब दिलवाता हूं।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): यह आस-पास के बीस किलोमीटर के दायरे में यहां कोई दसवीं का विद्यालय भी नहीं है। मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि क्या इन जो आठवीं तक के विद्यालय हैं, इनको दसवीं तक जो नवीन ग्राम पंचायतें हैं, सरकार की 2014-15 और 2015-16 की बजट घोषणा में भी है तो क्या इन नवीन ग्राम पंचायतों को और पुरानी जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें वंचित रही स्कूलों को क्रमोन्नत करने का आप विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिए, माननीय मंत्री महोदय।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के 12वीं की पढ़ने की व्यवस्था सभी ग्राम पंचायत में हो, यह एक ऐतिहासिक फैसला माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने लिया जिसके लिए मैं कह सकता हूं कि आपके पांच साल के अंदर कुल राजस्थान में केवल 1323 विद्यालय क्रमोन्नत हुए 12वीं के और हमने आते ही एक साथ पांच हजार क्रमोन्नत किये।

(श्री वासुदेव देवनानी)

जहां तक आपके विधान सभा क्षेत्र का प्रश्न है, वहां पर पांच साल के अंदर आपकी ही सरकार ने ही आपके क्षेत्र में केवल 4 ही विद्यालय क्रमोन्नत किये। हमने 28 विद्यालयों को क्रमोन्नत करके एक कीर्तिमान स्थापित किया। उसके बाद आपका जो प्रश्न है, उसमें कुल 9894 ग्राम पंचायतें हैं, जिसके अंदर 1464 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित नहीं है। उसमें 692 तो नई हैं, जिसका आपने अभी जिक्र किया और 772 ग्राम पंचायतें ऐसी थीं जहां पर निजी माध्यमिक विद्यालय संचालित है। वहां पर अभी बजट घोषणा में माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने घोषणा की कि जहां पर भी दसवीं के अंदर 40 विद्यार्थी होंगे, वहां पर हम उसको क्रमोन्नत कर देंगे चाहे भले ही प्राइवेट चल रही हो, तो भी हम क्रमोन्नत कर देंगे।

अब आपको उसमें स्थिति बता रहा हूं। हम सब लोग, मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप सबने 12वीं के लिए और शिक्षा के प्रति रुचि प्रकट की और क्षेत्र में भी एक वातावरण सरकारी स्कूलों का बना है। उसके आधार पर नामांकन बढ़ाने की आवश्यकता है। कुल इस समय 752 ऐसे हैं जहां पर निजी चल रहे हैं, उसमें से 177 तो इस बार क्रमोन्नत हो जाएंगे क्योंकि वहां पर 40 से अधिक हैं लेकिन वहां पर 166 ऐसे हैं जहां 30 से 39 है, 190 ऐसे हैं जहां 29 से भी कम हैं और 40 तो ऐसे हैं जहां पर 10 से भी कम विद्यार्थी हैं तो ऐसी स्थिति में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो और साथ में विद्यार्थी हो और जो सरकारी संसाधन है, अध्यापकों की जो एनर्जी है, वह सही ढंग से आगे उसका यूटिलाइजेशन हो सके और वैसे आपके समय में 2001 का ही एक नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन में यह साफ लिखा है कि उसी स्कूल को क्रमोन्नत करेंगे जहां दसवीं में पचास विद्यार्थी होंगे। यह तो माननीय मुख्य मंत्री महोदया की सहृदयता है कि उन्होंने इसको पचास से घटाकर के चालीस किया है, जिसके आधार पर किया।

हमारा प्रयत्न है और यह हमारी इच्छा है कि सब जगह हमारी स्कूल हो, अच्छी चले और जहां तक जो नव-गठित है, नव-गठित में भी 457 माध्यमिक विद्यालय हैं, उसमें से 105 ऐसे हैं जहां पर 40 से ज्यादा बच्चे हैं, उनको इस बार हम क्रमोन्नत कर रहे हैं। इस तरह 282 स्कूलों को इस

(श्री वासुदेव देवनानी)

बार हम क्रमोन्नत करने जा रहे हैं और इस नव गठित 457 में से 113 तो ऐसे हैं दसवीं के जहां पर दस से भी कम बच्चे हैं। हम बच्चों को यदि लाएंगे तो निश्चित रूप से आगे जो हमने एक व्यवस्था की है कि चालीस से ज्यादा होने पर हम करते जाएंगे, यह केवल इस साल के लिए नहीं है, यह नीतिगत प्रश्न है इसीलिए उस पर चलेंगे।

दूसरा प्रश्न जो आपने मुख्यालय का किया, यह मुख्यालय का कई बार चलता है कि मुख्यालय पर नहीं है। पांच हजार स्कूलों में से केवल 183 ऐसे हैं जहां पर मुख्यालयों पर स्कूल कमोन्नत नहीं किये हैं, बाकी सब जगह मुख्यालयों पर है। यदि वे एलिजिबल हैं, 46 ऐसे हैं जहां अभी तक प्राइमरी, अपर प्राइमरी है और इन 183 में भी व्यवस्था ऐसी है कि वहां पर नामांकन कम होने के कारण मुख्यालय पर नहीं खोल पाए और इसीलिए बाकी उसके राजस्व ग्राम, उसी ग्राम पंचायत में हमने खोल दिये हैं।

आज राजस्थान की एक भी ऐसी ग्राम पंचायत नहीं छोड़ेंगे जहां पर 12वीं की पढ़ने की व्यवस्था नहीं की गयी हो।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के जो भी मंत्री जवाब देते हैं सबसे पहले पिछली सरकार के कार्यकाल की बात करते हैं, अपनी बात करते हैं कि हमने यह किया।

मैं मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि आपने 20 हजार स्कूलों को बंद किया और कुछ ग्राम पंचायतों में आपने स्कूलें खोल दीं तो यह इस प्रश्न का जवाब नहीं था। अध्यक्ष महोदय, मुझे कहना पड़ रहा है 20 हजार स्कूलें राजस्थान में बंद कीं। मैं उस ओर नहीं जाना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन जिलों में एक-एक ग्राम पंचायत मुख्यालय से दूसरे ग्राम पंचायत मुख्यालय की दूरी 20-30-40 किलोमीटर तक है या पहाड़ी क्षेत्र है तो पंचायतों के पुनर्गठन में भी उस समय विशेष छूट दी गयी थी इन क्षेत्रों के लिये, तो मैं मंत्री महोदय से यही कहना चाहूंगा कि 2017-18 का सत्र जुलाई में चालू होने वाला है और आपके इस बजट घोषणा में जो मैंने आठवीं तक के मेरे विधान सभा क्षेत्र के छह विद्यालय बताये और छह विद्यालय ऐसे हैं जहां

(श्री भंवरसिंह)

आस-पास में दसवीं तक स्कूल है लेकिन बारहवीं का विद्यालय नहीं है। काकूसर, नानड़ा, सेवड़ा, राववाला, फूलासर बड़ा और स्वरूपदेसर, इन छह ग्राम पंचायत मुख्यालय के आस-पास के 20 किलोमीटर के एरिये में कोई भी बारहवीं का विद्यालय नहीं है तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यही निवेदन करना चाहूंगा कि रेगिस्तानी और मरुस्थलीय क्षेत्र में आपने छात्रों की सीमा बतायी है, मैं समझता हूं कि हमारा क्षेत्र आबादी के और जो क्षेत्रफल का घनत्व है, उसके अनुपात में राजस्थान के अन्य जिलों से भिन्न है और 40 की जो छात्र सीमा बतायी है, मैं समझता हूं कि वह संभव नहीं है। इन तीन-चार जिलों में जो रेगिस्तानी जिले हैं इनमें विशेष छूट देकर मेरे विधान सभा क्षेत्र के इन 12 विद्यालयों में और जो राजस्थान के अन्य जिले हैं, उन जिलों में जो क्रमोन्नत नहीं हुए हैं, उन विद्यालयों को क्रमोन्नत करवाने की इस सत्र में मंशा रखते हैं या नहीं?

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, जवाब आ रहा है। मंत्री महोदय।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो प्रश्नकर्ता ने जो कहा कि 20 हजार स्कूल बंद किये, हमने एक भी स्कूल राजस्थान में बंद नहीं किया है। ...(व्यवधान)...

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय असत्य बोल रहे हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, हमने बंद नहीं करके उसको पास की स्कूल में मर्ज किया है। यह कहीं भी नहीं चल सकता कि दो बच्चों से स्कूल चलाएं, पांच बच्चों का स्कूल चलाएं ...(व्यवधान)...

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, डेढ़ सौ विद्यालय मेरे कोलायत विधान सभा क्षेत्र में बंद किये गये हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): यदि हमने बंद किये होते तो नामांकन 13 लाख कैसे बढ़ता? बंद करने के बाद तो नामांकन कम होना चाहिये था। हमने मर्ज किया है। कई बार यह सरकार, आपके जमाने में दो बच्चों पर स्कूल, पांच बच्चों पर स्कूल, दस बच्चों पर स्कूल, यह विभाग शिक्षा का विभाग है, केवल वेतन देने वाला विभाग नहीं है, इसलिये हमने इसकी गुणवत्ता में सुधार किया है। ..(व्यवधान)...

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, ढाणियों में जो विद्यालय खोले गये, वहां नामांकन कम ही होंगे। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय पूरे सदन को गुमराह कर रहे हैं। ढाणियों में जो विद्यालय खुल रहे हैं, वहां छात्रों की संख्या कम होगी। उसके लिये मैंने पहले भी निवेदन किया है।..(व्यवधान).....

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): बोर्ड की परीक्षाओं के परिणाम में परिवर्तन आया है और इसके साथ नामांकन बढ़ा है। निश्चित रूप से मर्ज किये हैं, मर्ज करने पर इसको गुणवत्तापूर्ण एवं व्यवहारिक बनाया है। जहां तक आपके क्षेत्र की बात है, निश्चित रूप से गुणावगुण के आधार पर जो भी हमारे नार्म्स में आयेंगे, हमने बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के पांच हजार स्कूल खोले। आपके समय में तो जो आपकी पार्टी का एम एल ए आता था, वहां पर खोलते थे। हमने बिना यह देखें कि वहां का विधायक कौन है, वह कौनसी पार्टी का है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 5 हजार स्कूल बिना किसी भेदभाव के खोलकर एक इतिहास कायम किया है। इसके नार्म्स के अंदर भी हमने 282 क्रमोन्नत कर रहे हैं, उसमें कहीं नहीं देखा कि कांग्रेस के एम एल ए का क्षेत्र है, या बी.जे.पी के एम.एल.ए का क्षेत्र है, हमने तो एक ऑब्जेक्टिवली सारे राजस्थान के बच्चे हमारे हैं, सारे अपने हैं, इन सबकी शिक्षा की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। इसमें जहां भी गुणावगुण के आधार पर आपके क्षेत्र का भी कोई विद्यालय नार्म्स में आयेगा तो उसको भी सम्मिलित करेंगे।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): एक-एक करोड़ रुपये की एक एक बिल्डिंग है, वह सारी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो रही है अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेश धाकड़, पूरक प्रश्न।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सर्वप्रथम मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 50 विद्यालय क्रमोन्नत हो गये, लेकिन दो विद्यालय झालरबावड़ी और बस्सी, वह क्रमोन्नत नहीं हो पाये, तो मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि उनमें से एक झालरबावड़ी में बच्चों की संख्या 40 से भी ज्यादा है तो इस बार क्रमोन्नत करने की इच्छा है क्या? साथ ही एक और निवेदन है आपने टीचर्स का समानीकरण करके अच्छा काम किया, लेकिन व्याख्याताओं की

(श्री सुरेश धाकड़)

अभी कुछ विद्यालयों में कमी है। व्याख्याताओं के पद भरने में अभी आपने नौकरी के लिये वेकेंसी भी निकाली है, लेकिन आरक्षण को लेकर थोड़ा बहुत इश्यू है तो उसमें बैकलॉग रखकर उनको नौकरी देने का काम करेंगे क्या?

श्री अध्यक्ष: शिक्षा मंत्री महोदय, जवाब दें।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आपके जो विद्यालय नार्म्स में आएंगे, उनको क्रमोन्नत कर देंगे। एक भी विद्यालय जो नार्म्स में आ रहा होगा, हम सभी को क्रमोन्नत कर देंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे और अच्छी शिक्षा देंगे। उसके लिये जो कुछ भी सरकार को करना होगा, सरकार सभी उपाय करके श्रेष्ठ शिक्षा देगी।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न, श्री फूलसिंह मीणा।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मंत्री महोदय को बधाई देता हूं क्योंकि इन्होंने पंचायत मुख्यालय पर दसवीं से बारहवीं स्कूल की तो मेरे एक स्कूल में 35 बच्चों में से बालिकाओं को बढ़ावा दिया, उसमें 30 बालिकाओं ने एडमिशन लिया। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत बलीचा के पास में नया खेड़ा गांव है, उसमें लगभग 550 से 600 के बीच में छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं और लगभग 8-10 किलोमीटर की दूरी तक वहां बारहवीं की स्कूल नहीं है। क्या मंत्री महोदय, वहां पर ऐसी स्थिति में बच्चों को शिक्षा में बढ़ावा देने के लिये वहां पर बारहवीं की स्कूल खुलवाने का मन रखते हैं? यदि हां, तो इस बजट में लेने का इरादा है?

श्री अध्यक्ष: विराजिये, माननीय मंत्री महोदय।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि नोर्म्स के अन्तर्गत आने वाले सभी विद्यालय लिये जाएंगे और बाकी आप विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाओ, इसको क्रमोन्नत का क्रम आज खतम नहीं हो रहा है, यह लगातार नार्म्स के आधार पर जारी रहेगा। आप तो विद्यार्थी लाओ और स्कूल क्रमोन्नत कराते जाओ।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न श्री नारायण सिंह देवल।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जालौर जिला महिला

(श्री नारायण सिंह देवल)
साक्षरता के अंतिम पायदान पर है और वहां की भौगोलिक स्थिति भी दस-दस किलोमीटर की परिधि में आती है तो ऐसी स्थिति में विद्यालय क्रमोन्नत का काम तो बहुत अच्छा हुआ है, पर जालौर जिला शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा है तो उस नार्म्स में कुछ शिथिलता प्रदान करावें।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैं सभी विधायकों का आभारी हूं कि शिक्षा में क्रमोन्नत की उनकी जितनी रुचि है, बस इतनी रुचि स्कूलों में नामांकन बढ़ाने में लगाएंगे तो निश्चित रूप से हम क्रमोन्नत करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी छह विद्यालय क्रमोन्नत नहीं हुए हैं। ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में छह विद्यालय रह गये, जो निजी क्षेत्र में हैं, उनको भी क्रमोन्नत करने का कष्ट करें। .....(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न श्री मानसिंहजी।

गंगापुर के वजीरपुर उपखण्ड में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

330. श्री मान सिंह (गंगापुर): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गंगापुर विधान सभा क्षेत्र के वजीरपुर उपखण्ड में कोई कॉलेज संचालित नहीं है? क्या सरकार उपखण्ड स्तर पर कॉलेज खोलने की नीति के तहत वजीरपुर में कॉलेज खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त उपखण्ड में प्राईवेट कॉलेज में फीस अधिक होने के कारण एसटी/एससी के विद्यार्थियों द्वारा फीस देना संभव नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार वजीरपुर उपखण्ड में राजकीय कॉलेज खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्रीमती किरण माहेश्वरी): (1) वर्तमान में गंगापुर विधान सभा क्षेत्र के वजीरपुर में निजी क्षेत्र में एक महाविद्यालय संचालित है।

निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और संसाधनों की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर गंगापुर विधान सभा क्षेत्र वजीरपुर उपखण्ड में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और संसाधनों की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर गंगापुर विधान सभा क्षेत्र वजीरपुर उपखण्ड में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर एक।

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जो सरकार की नीति के तहत कॉलेज खोलने की नीति है कि उपखण्ड स्तर पर हम कॉलेज खोलेंगे, तो वजीरपुर उपखण्ड वहां पर एस.सी., एस.टी. का घनत्व है, सरकार एस.सी., एस.टी. के बच्चों को पूर्ण शिक्षा मिल सके, इसके लिये मैं यह चाहूंगा मंत्री महोदय, कि आपने जिन संसाधनों की बात कही है, क्या आप इसको प्रायोरिटी पर लेने का काम करेंगे कि अगली आपकी प्रायोरिटी में वजीरपुर में कॉलेज खुले। दूसरा, हमारे एस.सी., एस.टी. के बच्चों को जो छात्रवृत्ति और प्राइवेट कॉलेज की फीस है, वह रिएम्बर्स समय पर हो सके, क्या इसकी आप व्यवस्था करेंगे, जिससे कि उनकी शिक्षा के अंदर इस प्रकार परेशानी नहीं हो।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्षजी आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य के ध्यान में लाना चाहती हूं कि इन्होंने विषय उठाया वजीरपुर के अंदर राजकीय महाविद्यालय खोलने का, वजीरपुर में अभी वर्तमान में एक प्राइवेट कॉलेज है। सरकारी महाविद्यालय खोलने के संदर्भ में भी निश्चित रूप से विचार किया जाएगा, क्योंकि हम हर उपखण्ड मुख्यालय पर कालेज खोलना चाहते हैं। इसी क्रम में अभी वर्तमान में जो हमारा बजट पेश हुआ माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा, उसमें चार कॉलेजेज, जो उपखण्ड क्षेत्र के अंदर थे, उनको खोलने की उन्होंने घोषणा भी की है और वजीरपुर भी उनमें से एक हमारी प्रायोरिटी पर रहेगा। मैं यह कह

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

सकती हूं कि जहां-जहां पर भी बच्चों के नामांकन बढ़े हैं, उसमें एक अच्छा मैसेज सवाई माधोपुर का आया जहां पर हमारी जो गर्ल्स हैं उनके नामांकन 7617 हैं और बॉयज की 7340 है। यानी बॉयज से भी ज्यादा गर्ल्स का इंटरेस्ट कालेज एजुकेशन के अंदर सवाई माधोपुर में बढ़ा है। यह एक अच्छा संदेश है और इवन करौली को भी अगर देखें तो वहां पर भी जो इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें भी बॉयज की तुलना में गर्ल्स का नामांकन ज्यादा हुआ है। गर्ल्स का 6270 है और बॉयज का 5,959 है।

तो इस दिशा में हम जरूर विचार करेंगे कि गर्ल्स एजुकेशन को ज्यादा बढ़ावा मिल सके और जहां रुचि भी रख रही हैं लड़कियां पढ़ने में कालेज के अन्दर तो वहां निश्चित रूप से राजकीय महाविद्यालय को प्रायोरिटी पर लिया जाना, यह हम लोग अपनी तरफ से प्राथमिकता पर रखने की कोशिश करेंगे।

साथ-साथ, माननीय अध्यक्ष जी, जो विषय इन्होंने कहा कि एस.टी., एस.सी. के बच्चों की पढ़ाई के लिए, इनकी छात्रवृत्ति के संदर्भ में हमारी सरकार की क्या-क्या योजना है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत सारी योजनाएं, हमारे बच्चों की उच्च शिक्षा के अन्दर रुचि बढ़े और एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और एस.बी.सी. के बच्चों को छात्रवृत्ति देने की जो घोषणा की है उसमें एक योजना है जो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना है। माननीय अध्यक्ष जी, इस योजना के माध्यम से जो ट्वेल्थ पास होते हैं, 60 परसेंट मार्क्स से ज्यादा जिनके मार्क्स आते हैं, ऐसे फर्स्ट एक लाख बच्चों का चयन उसमें हो जाता है और वो छात्रवृत्ति उन्हें दी जाती है 500 रुपये प्रति माह और वार्षिक पांच हजार रुपये। ऐसी फेमेलीज जिनकी ढ़ाई लाख रुपये वार्षिक आय से कम आय है, ऐसे बच्चों को, सभी वर्ग के बच्चे उसमें आ जाते हैं और उनकी 60 परसेंट से एबूव परसेंटेज होनी चाहिए, ढाई लाख से कम उनकी वार्षिक आय होनी चाहिए और 500 रुपये प्रति माह उन्हें मिल रहे हैं। तो यह एक हमारी योजना है, जिसके अन्दर हमने गत वर्ष में लगभग 44 करोड़ 87 लाख रुपये वितरित किये और जो छात्र लाभान्वित हुए वो 75 हजार 305 छात्र उससे लाभान्वित हुए।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

इसी तरीके से मेधावी छात्र स्कूटी वितरण योजना भी हमारी है, जो सिर्फ गर्ल्स के लिए है। 75 परसेंट से एबूव जिनके मार्क्स आते हैं, उन बच्चियों को एस.बी.सी. और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में रहने वाली उन बच्चियों को दिया जाता है, उसमें भी वार्षिक आय ढाई लाख से कम होनी चाहिए। हर जिले के अन्दर ऐसी 50 स्कूटी वितरित की गयी हैं और लगभग 3 करोड़ 76 लाख रुपये हम लोगों ने इस पर गत वर्ष व्यय किये।

देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण छात्र प्रोत्साहन राशि योजना भी इसी में है जहां पर 50 परसेंट मार्क्स के बच्चों को भी हम लोग यह छात्रवृत्ति देते हैं। मैं समझती हूं कि बहुत अच्छी योजना माननीय मुख्य मंत्री जी ने बनायी। हमारे बच्चे-बच्चियां हायर एजुकेशन में आगे से आगे बढ़ें और यह छात्रवृत्ति उन्हें मिले ताकि वो और ज्यादा प्रोत्साहित हो, और ज्यादा उनका नामांकन हो, इस दृष्टि से अच्छी योजना है।

बहुत सारी योजना है। इसमें महिला योग्यता छात्रवृत्ति है, आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृत्ति। इसके अलावा जो सामाजिक न्याय विभाग है, उनके द्वारा भी बहुत सारी छात्रवृत्ति हमारे कॉलेज के बच्चों को दी जाती है। मैं इसका सम्पूर्ण विवरण माननीय सदस्य को दे दूंगी।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा क्या उपखण्ड स्तर पर कॉलेज खोलने की स्थिति में जमीन मिल सके, इस हेतु सरकार कोई ऐसा प्रयास करेगी कि वहां जमीनें चिह्नित हो जाएं? क्योंकि जब आप कॉलेज खोलते हैं तो जमीन नहीं होती है, कई बार कई दिक्कतें होती हैं तो किस प्रकार की कोई ऐसी मंशा है कि वहां पर कम से कम जमीन का चिन्हिकरण हो जाए जिससे कॉलेज खोलें तो दिक्कत नहीं हो। ऐसे कोई सरकार ने दिशा-निर्देश दिये हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने जो उपखण्ड स्तर पर महाविद्यालय खोलने के संदर्भ में

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

कहा, जैसा कहा कि संसाधनों की उपलब्धता पर ये कॉलेजेज खोले जाएंगे लेकिन उसके अलावा जमीन का चयन कर के और उसको कॉलेज परपज के लिए आरक्षित कर दिया जाए, उसके लिए जरूर हम जिला कलेक्टर को पत्र लिख रहे हैं। जहां पर हम यह लैंड असाइड करने के संदर्भ में कि वो जमीन उन कालेज के परपज के लिए सुरक्षित रख दी जाए, ऐसा उपखण्ड मुख्यालय पर हम अपने सभी कलेक्टर्स को पत्र लिख देंगे ताकि वो उपखण्ड स्तर पर जमीन को असाइड कर सकें कॉलेज परपज के लिए।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। श्रीमती शकुन्तला रावत। ...(व्यवधान)... बैठिये।

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): डूंगरगढ़ मुख्यालय पर कॉलेज की काफी दिनों से मांग है, अध्यक्ष महोदय। मंत्री महोदय को पूरा पता भी है इस बात का। ...(व्यवधान)...

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्यावर के लिए भी माननीय मंत्री महोदया से निवेदन है कि महिला कॉलेज के लिए आपने यस कर रखी है।

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): हजारों बच्चे पढ़ने के लिए बीकानेर जाते हैं और वहां से 70 किलोमीटर पड़ता है। ...(व्यवधान)...

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय मंत्री महोदया, ब्यावर के लिए तो यस कर रखी है ...(व्यवधान)...

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, यह किस तरह बोल रहे हैं बिना आपकी परमिशन के, इनका अंकित नहीं होना चाहिए। आप इनको तो नहीं बोल रहे।

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): डूंगरगढ़ मुख्यालय पर बहुत जरूरी है कॉलेज खोलना। हजारों बच्चे बीकानेर जाते हैं ...(व्यवधान)...

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ब्यावर की कॉलेज के लिए माननीय मंत्री महोदया से निवेदन किया था।

श्री अध्यक्ष: मैंने श्रीमती शकुन्तला रावत का नाम पुकारा है, बाकी माननीय विधायक विराज जाएं। श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से जानना चाहूंगी कि सरकार की तरफ से उपखण्ड स्तर पर कॉलेज खोलने का प्रावधान है, रख रहे हैं, नियमों में कर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो क्या बानसूर में भी सरकारी महाविद्यालय खोलने का विचार रखते हैं या नहीं? वहां आबादी में जमीन भी है, हम जमीन देने को तैयार हैं। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय, यह बीच में टोकते हैं। कालेज का मामला है, शिक्षा का मैटर है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बानसूर नहीं है इसमें। मैं बारबार कहता हूं कि इस विषय से ...

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): तहसील उपखण्ड, तहसील उपखण्ड पर खोलने का विचार है?

श्री अध्यक्ष: नहीं, आई विल नोट अलाउ। चन्द्रभान सिंह 'आक्या'।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, ऐसा तो नहीं होता।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): शिक्षा का मैटर है, मंत्री महोदय से पूछें।

श्री अध्यक्ष: शिक्षा का मैटर सीमित है। ...(व्यवधान)... सीमित है। श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या'।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): देवनारायण, टाड़ा, माड़ा कोई योजना में देवें, साहब।

श्री अध्यक्ष: श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या', दूसरा प्रश्न। श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या'। ...(व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, मूल प्रश्न वजीरपुर के संदर्भ में है।

श्री अध्यक्ष: वो मूल प्रश्न नहीं है, मैंने खुद ही रोक दिया, आप जवाब मत दीजिए। श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या'।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मंत्री जवाब दे रहे हैं, इनको पावर तो है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पावर तो है क्या इनके पास? कोई पावर नहीं है, केवल भाषण भाषण देने के लिए

(श्री श्रवण कुमार)

छोड़ रखा है इनको। एक भी कालेज खोल कर दिखा कर दो न ये, एक स्कूल खोल कर दिखा दो। इनको केवल भाषण देने के लिए बैठा रखा है बस।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, भदेसर उपखण्ड एस.डी.एम. ऑफिस है, सब कुछ है, बड़ा हैडक्वार्टर है, वहां भैरूंजी का स्थान भी है, सावरिया जी का स्थान भी है पर वहां कॉलेज नहीं है। तो, माननीय मंत्री महोदया वहां कॉलेज खोलने की घोषणा करें और इसका इसी सत्र में लें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदया।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने भी मंत्री हैं इनको एक को भी पावर नहीं है। इनके पास कॉलेज खोलने के लिए बजट ही नहीं है। यह सारे मामले तो विचाराधीन हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार की पूरी मंशा है कि सभी उपखण्ड मुख्यालय पर कॉलज खुलें और इसमें वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर समय-समय पर यह कॉलेजेज खोल दिये जायेंगे। सभी के लिए जो जमीन असाइन करनी है, वो भी हमने तय कर लिया और यह निर्देश दे रहे हैं इसीलिए कि मंशा है तभी तो। जितने भी माननीय सदस्य हैं वो यही चाह रहे हैं कि हमारे उपखण्ड पर महाविद्यालय खोला जाए। तो हमारे पास में ऐसे 30 उपखण्ड हैं जहां पर एक भी सरकारी या प्राइवेट कॉलेजेज नहीं हैं, उनको हम प्राथमिकता पर लेंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। तीसरा पूरक प्रश्न। श्री निर्मल कुमावत।

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, डूंगरगढ़ में कॉलेज खोलना बहुत आवश्यक है। भवन भी तैयार हुआ हुआ है। डूंगरगढ़ में कॉलेज का भवन भी तैयार हुआ हुआ है और हजारों बच्चे शिक्षा के लिए बीकानेर जाते हैं ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): दो उपखण्ड तो मेरे हैं ...(व्यवधान)... बजट नहीं दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, दो उपखण्ड तो मेरे हैं ...(व्यवधान)... सूरजगढ़ और चिड़ावा।

श्री अध्यक्ष: जवाब देने की जरूरत नहीं है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सूरजगढ़, चिड़ावा, भूवाणा सारे उपखण्ड पड़े हैं ...(व्यवधान)...

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): कम से कम डूंगरगढ़ की घोषणा तो कर दो। मंत्री महोदय, पी.एच.ई.डी. में आप थे, डूंगरगढ़ का काफी काम करा ...(व्यवधान)... इस कॉलेज की भी घोषणा कम से कम डूंगरगढ़ में तो कर दो। ...(व्यवधान)...

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, वैसे मंत्री जी का जवाब आ गया है। मैं केवल स्पेसिफिक एक ही बात पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार नियमों में शिथिलता देकर के वर्तमान में जितने भी महाविद्यालय संचालित हैं, विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में शिथिलता देकर, क्या ऐसी शिथिलता देकर जो बचे हुए उपखण्ड हैं, आपने अभी श्रीमुख से बता दिया कि होने वाले हैं और जो माननीय सदस्य की मांग है, शिथिलता देकर सब का आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते?

श्री अध्यक्ष: ठीक है, आप बैठिये। मंत्री महोदया, जवाब दीजिए फिर मैं अगला प्रश्न लेता हूं।

अगला प्रश्न। श्री शैतान सिंह।

भणियाणा उपखण्ड मुख्यालय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

331. श्री शैतानसिंह (पोकरण):- क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विधानसभा क्षेत्र पोकरण के उपखण्ड मुख्यालय भणियाणा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्रम एवं नियोजन मंत्री (डा. जसवन्त सिंह यादव): (1) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने हेतु मानदण्ड महानिदेशक (प्रशिक्षण) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित हैं। मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(श्रम एवं नियोजन मंत्री)

(2) माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2014-15 (संशोधित) के बिन्दु संख्या 136 के अनुसार अगले दो वर्ष में ऐसी कोई पंचायत समिति नहीं बचेगी जिसमें आई.टी.आई. उपलब्ध नहीं हो, उसकी पालना में राज्य की सभी पंचायत समितियों में राजकीय एवं निजी आई.टी.आई. स्वीकृत हो चुकी है।

विधानसभा क्षेत्र पोकरण के उपखण्ड मुख्यालय भणियाणा के अन्तर्गत पंचायत समिति साखडा के अन्तर्गत 01 राजकीय आई.टी.आई. संचालित है जो परिशिष्ट-2 पर है।

फिर भी यदि गुणवगुणों के आधार पर व जनप्रतिनिधियों की मांग अनुरूप व वित्तीय संसाधनों के अनुसार सरकार द्वारा निर्देश दिये जाते हैं तो विधानसभा क्षेत्र पोकरण के उपखण्ड मुख्यालय भणियाणा में नवीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाना संभव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री जी से निवेदन करना चाह रहा हूं, हालांकि आपका जवाब तो आ गया। क्योंकि मेरा विधान सभा क्षेत्र सीमांत क्षेत्र से है, पोकरण जिसका नाम है, राष्ट्र का शक्ति केन्द्र है। हमारी इस धरती पर, हमारी इस धरती ने अपने गर्भ में इतने शक्तिशाली जो विस्फोट हुए, उनको सहन किया है। तो हम बहुत दूर-दराज क्षेत्र में और विस्तृत क्षेत्र है। मेरा विधान सभा क्षेत्र 350 किलोमीटर लम्बा है जिसमें कई जिले निपट जाते हैं।

तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे उस उपखण्ड भणियाणा में एक आई.टी.आई. खोली जाए ताकि वहां के लोगों को लाभ मिले। वो एरिया सोलर हब है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। विराजिए।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): इस बात को ध्यान में रखते हुए आपसे विशेष निवेदन है कि वहां आईटीआई खुलाने की कृपा करावें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय। एक और मांगा है उन्होंने आपसे।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बातों को सहानुभूतिपूर्वक लिया जाएगा। संसाधन उपलब्ध होने पर निश्चित रूप से आईटीआई खोलने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न करेंगे? नहीं। श्री रामहेत सिंह यादव।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि बहरोड़, नीमराणा और तिजारा में सभी जगह आईटीआई हैं। मुण्डावर विधान सभा में भी है। बहरोड़ विधान सभा में है। तिजारा विधान सभा में है। क्या उपखण्ड कार्यालय कोटकासिम में जो कि मेरा क्षेत्र है, वहां पर नई सरकारी आईटीआई की घोषणा करते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कोटकासिम उपखण्ड के अंदर प्राइवेट आईटीआई है। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि अगले वित्तीय वर्ष में हो सके। देखते हैं कि वित्तीय संसाधन कितना उपलब्ध होता है।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): आप तो खोलने की घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष: श्री हबीबुर्रहमान। दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): है, जवाब मेरे पास।

श्री अध्यक्ष: नहीं करेंगे। श्री छोटूसिंह।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि पंचायत समिति तो जैसलमेर के भाग्य में नहीं थी, लेकिन उपखंड कार्यालय है। वह जैसलमेर के मुख्यालय से 70-80 किलोमीटर है। उपखंड कार्यालय बहुत पुराना है। मैं पूछना चाहता हूं कि फतेहगढ़ में आप औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलना चाहते हैं या नहीं?

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है, हम अपने वित्तीय संसाधन देखेंगे और वहां की आवश्यकता देखेंगे। इन सबके ऊपर विचार करेंगे। सरकार की मंशा है कि हर क्षेत्र में आईटीआई हो। मैं इसमें एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, क्योंकि हर सदस्य पूछ रहा है। गत सरकार के कार्यकाल में, अब

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

आप बात सुन लीजिए। वाजिब बात तो सुननी पड़ेगी। गत सरकार के कार्यकाल में आईटीआई तो स्वीकृत हुई, लेकिन उसकी स्थापना हेतु आज तक जमीन आवंटित नहीं हुई थी। सच्चाई सुनने में आपको एतराज है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): अब तो आप जाने वाले हो।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): अब तो 4 साल हो गए हैं। आप जाने वाले हो।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): एक बार माननीय सदस्यों की संतुष्टि के लिए तो बताएं।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): गत सरकार ने जो किए वह तो उन्होंने भुगत लिए। आप तो अपनी बात करो। गत सरकार के किस्से को छोड़ दो। जो कुकर्म किए वह तो भुगत लिए इन्होंने। अपनी बात करो, आप क्या करोगे?

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): अब तो आप खतम होने वाले हो। आपके पूरे होने में 1 साल बचा है।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न। श्री खेमाराम।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): कोटकासिम में आईटीआई की घोषणा करें आप तो।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे उपखंड कार्यालय बीदासर में आईटीआई कॉलेज की घोषणा हो चुकी है। लेकिन वहां अभी तक जमीन का कोई प्रावधान नहीं करने के कारण से वह चालू नहीं हो पाई है। कृपया उसको शीघ्र ही चालू कराने की व्यवस्था करावें।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसी माननीय सदस्य ने जानकारी दी है, पहले ही हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह घोषणा हो चुकी है। पिछली सरकार के टाइम पर 138 खुली थी और हमारी सरकार ने 3 साल में 103 खोल दी। टोटल 241 आईटीआई हैं और पंचायत समितियां 295 हैं। अब जो घोषणाएं हुई हैं, उसके अनुसार अगले वित्तीय वर्ष में एक भी पंचायत समिति ऐसी नहीं रहेगी जिसमें आईटीआई नहीं हो। वैसे टोटल 1894 आईटीआई संचालित हैं। जिन

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

आईटीआई की जमीनें अभी तक नहीं मिली हैं। हम इसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। सभी कलक्टर महोदय को हमारे विभाग ने पत्र लिख दिया है। हम हमारी हर आईटीआई को जुलाई तक चालू करने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री दर्शन सिंह।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप कह रहे हैं जमीन नहीं है, 5 हजार बीघा जमीन पड़ी है बुहाना में। आप बनाओ न बुहाना पंचायत समिति में।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इनकी संतुष्टि के लिए कि पता लग जाए कि इनकी सरकार ने क्या किया और हमारी सरकार ने क्या किया।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): क्या राजेन्द्र जी, बोलने नहीं देते हो क्या? आप खड़े होकर के यहां बोलते थे। किसी को बोलने नहीं देते थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अगला प्रश्न पुकार लिया।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप उधर जाते ही भूल जाते हो क्या? इधर तो बोलने नहीं देते हो हम लोगों को। खड़े होकर ऐसे पर्चे दिखाते थे। यह पर्चा देखो। अब भूल गए हम लोगों को? हम भी सामने आए हैं और आप भी सामने आओगे। आप बताओ, बुहाना में कब खोल रहे हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति है?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): बुहाना का बताओ ना। वहां आईटीआई नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप विराजें। मैंने अगला प्रश्न ले लिया।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): +++ वहां कोई कॉलेज नहीं है।

श्री अध्यक्ष: श्री दर्शन सिंह।

प्रदेश में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की योजना

332. श्री दर्शन सिंह (करौली): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में हैरिटेज, वन, वन्यजीव, झील,

(श्री दर्शन सिंह)

ईको और डेजर्ट पर्यटन जैसी विविधता आस-पास के पड़ौसी राज्यों में उपलब्ध नहीं होने के उपरान्त भी प्रदेश पर्यटन व्यवसाय और विदेशी पर्यटकों को राजस्थान में आकर्षित कर उनकी संख्या बढ़ाने, विदेशी मुद्रा अर्जन करने में पड़ौसी राज्यों से बहुत पिछड़ा हुआ है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश की पुरानी विरासतों व जैव विविधता तक विदेशी पर्यटकों को पहुंचाने के लिए प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर हवाई, रेल, सड़क सुविधाएं और होटल सेवाओं की कमी के कारण अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ गये हैं? यदि हां, तो प्रदेश के कौन-कौनसे पर्यटन हैरिटेज, वन, वन्यजीव, ईको, डेजर्ट पर्यटन गुणवत्तापूर्ण उक्त सुविधाओं से वंचित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़) (राज्य मंत्री, पर्यटन के स्थान पर): (1). जी नहीं। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की रिपोर्ट भारतीय पर्यटन आंकड़े एक झलक, 2015 के अनुसार विदेशी पर्यटकों के आगमन में राजस्थान का देश में छठा स्थान है तथा उत्तर प्रदेश को छोड़कर अन्य पड़ोसी राज्यों यथा गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा एवं पंजाब से अधिक विदेशी पर्यटक राजस्थान में भ्रमण हेतु आते हैं।

(2) जी नहीं। प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थल हवाई, रेल, सड़क सुविधाओं से भली भांति जुड़े हुए हैं एवं पर्यटकों की पहुंच में हैं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, नम्बर एक।

श्री दर्शन सिंह (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या प्रदेश को छठे स्थान से प्रथम स्थान पर लाने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं? इस बारे में आप कोई विचार रखते हैं या नहीं?

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2015 से 2016, इन 2 वर्षों में प्रदेश के अंदर देशी पर्यटकों में 17.93 की बढ़ोतरी हुई। विदेशी पर्यटकों में 2.60 की बढ़ोतरी हुई। यानी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

2015 के अंदर राजस्थान में कुल 3 करोड़ 66 लाख 2 हजार पर्यटक आए और 2016 में 4 करोड़ 30 हजार पर्यटक आए।

अध्यक्ष महोदय, अभी जो सर्वे हुआ है कि सारे देश में कहां-कहां, कितने-कितने पर्यटक आए, उसमें राजस्थान छठे स्थान पर है। इस बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस विभाग के बजट में जो बढ़ोतरी की है, वह भी 22.37 प्रतिशत की है। 2016-17 में राजस्थान सरकार का बजट इस विभाग के लिए जहां 133 करोड़ रुपये था, वह 2017-18 में 163 करोड़ है।

इसके अलावा इस बार हवाई परिवहन में भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट के पैरा 29 और 30 में राजस्थान के अंदर पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए वीजीएफ के आधार पर इंट्रा स्टेट हवाई सेवाएं प्रारंभ करने की बात की है। इसके तहत जोधपुर, उदयपुर व बीकानेर को जयपुर से जोड़ा जाएगा। कोटा, अजमेर एवं रणथम्भौर को जोड़ने का कार्यक्रम जल्दी प्रारंभ किया जाएगा। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंदर भी जयपुर को सीधे जैसलमेर, आगरा, बीकानेर से जोड़ने के प्रावधानों की घोषणा की है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से राजस्थान के आगोश में इतिहास है। उस दृष्टि से माननीय मुख्य मंत्रीजी और सरकार पूरी चिंतनशील है। हमारा प्रयास रहेगा कि हमारी योजनाओं के आधार पर आज हम देश में छठे स्थान पर हैं, हम अगले वित्तीय वर्ष में अपनी स्थिति को और सुधारें और पहले तीन, चार स्थानों पर आने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री दर्शन सिंह (करौली): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या पर्यटन क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करने वाले स्थल रणथम्भौर व सरिस्का को निजी हाथों में देकर के इनका नियम विरुद्ध निजीकरण करने का विचार चल रहा है? जो कि गलत है। यह किसके दबाव में हो रहा है? यह बताने की कृपा करें मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का संबंध निजीकरण से नहीं है।

श्री दर्शन सिंह (करौली): पर्यटन को नुकसान हो रहा है। निजीकरण हो रहा है। मेरा निवेदन है कि आप इस विषय में बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: कोई बात नहीं, दे दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह लिमिटेड प्रश्न था। मैंने सवाल के जवाब में दे दिया। मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि राजस्थान के अंदर पर्यटन स्थलों के बहबूदीकरण के लिए विभाग ने अनेक योजनाएं चलाई हैं। बड़े ही आक्रामक रूप से इन्होंने इस बार अपने एडवर्टाइजमेंट के कार्यक्रम को भी हाथ में लिया है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आप निजीकरण कर रहे हो।

श्री दर्शन सिंह (करौली): आप तो निजीकरण नहीं करें। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि विदेशी पर्यटक आ रहे हैं, इसलिए आप इनका निजीकरण नहीं करें। खासा कोठी का भी नहीं करें तो बहुत बड़ी बात होगी।

श्री अध्यक्ष: श्री नन्दकिशोर महरिया।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अध्यक्ष महोदय, हमारा नंबर नहीं है क्या? आपके राज में हमारा नंबर नहीं है?

श्री दर्शन सिंह (करौली): अध्यक्ष महोदय, मेरा तो पूरा जवाब नहीं आया। निजीकरण के बारे में जवाब नहीं आया। यह तो बता दें। निजीकरण करेंगे कि नहीं करेंगे यह तो बता दें। खासा कोठी का भी बता दो आप।

श्री अध्यक्ष: श्री नन्दकिशोर महरिया।

श्री दर्शन सिंह (करौली): मेरा उत्तर पूरा नहीं हुआ है, निजीकरण करेंगे कि नहीं करेंगे? खासा कोठी का भी बता दो आप। ...(व्यवधान)... पहले कैलादेवी का तो बता दें। ...(व्यवधान)...

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि शेखावाटी क्षेत्र में बहुत सी हैरिटेज महत्व की हवेलियां हैं जो पिछले कुछ समय से लगातार तोड़ी जा रही हैं। वहां मार्केट बन रहे हैं, उन हवेलियों के संरक्षण के लिए, वह बची रहे, जिनको विदेशी पर्यटक देखने आते हैं, उसके लिए सरकार की कोई योजना है और साथ ही शेखावाटी क्षेत्र व कालीबंगा क्षेत्र को हैरिटेज सर्किट या पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने की सरकार की कोई योजना है? ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, फतेहपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने शेखावाटी क्षेत्र में पुरानी हवेलियों को तोड़ने की बात कही है। राज्य सरकार जिला कलेक्टरों को पूर्व में निर्देश दे चुकी है कि इस प्रकार के जहां भिति चित्र हो, जहां पुरातत्व महत्व की हवेलियां हों, उनको तोड़ा नहीं जाए और राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि बिना जिला कलेक्टर की अनुमति के इस प्रकार की हवेलियों को नहीं तोड़ा जाए और उसको दुबारा सुनिश्चित कर लेंगे। निश्चित तौर पर शेखावाटी में जो एक सर्किट विकसित करने की बात है, उस सर्किट को विकसित करने की सरकार की योजना है और इस हेतु आवश्यक कदम सरकार उठा चुकी है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न। श्री रणधीर सिंह भीण्डर।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि सरकार ने काफी हवाई सेवाओं से ट्यूरिस्ट स्पॉट्स को जोड़ा है लेकिन फिर भी जितना ट्यूरिस्ट आ रहा है उसमें राजस्थान में 6.9 परसेंट ट्यूरिस्ट ही आ रहा है, इसका मतलब हमारे यहां से पब्लिसिटी अच्छी तरह से नहीं हो रही है, हमारे पर्यटन स्थलों को बार-बार टीवी और पत्रकारिता के माध्यम से जोर नहीं दिया जा रहा है। दूसरा, हम लोग फोरेन ट्यूरिस्ट पर तो डिपेंड होते हैं लेकिन डोमेस्टिक टयूरिस्ट भी आजकल बहुत आने लगे हैं लेकिन राजस्थान में उसमें से 2.7 परसेंट ही डोमेस्टिक ट्यूरिस्ट आ रहे हैं। इस बात पर भी हमको विशेष ध्यान देना चाहिए, मेरा सरकार से ऐसा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान और विशेष तौर पर हमारे पर्यटन स्थल, चाहे जयपुर हो या जोधपुर हो, बीकानेर हो, उदयपुर हो, सब हवाई मार्ग से भी जुड़े हुए हैं और सभी रेल मार्ग से भी जुड़े हुए हैं। जयपुर से माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष 38 हवाई उड़ानें प्रतिदिन उड़ा करती थीं जो इस वर्ष बढ़कर 50 हो गई हैं। निश्चित तौर पर इस पर चिंता भी है और कोशिश भी है और प्रयास भी है और मुख्य मंत्रीजी की घोषणा भी है कि राजस्थान के अंदर जो पर्यटन विभाग है वह पर्यटन को उद्योग के रूप में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

विकसित करे, राजस्थान में देश और विदेश के पर्यटक आएं इसके लिए जो भी आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने के लिए आवश्यक बजट का प्रावधान भी किया है और बजट में बढ़ोत्तरी भी 20 परसेंट ज्यादा की है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, आपसे भी चर्चा करके आपके और भी रचनात्मक सुझाव होंगे तो उनको सम्मिलित करके इस प्रयास को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न श्रीमती अलका सिंह।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगी कि आभानेरी एक प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट है यूनेस्को का और वहां पुरा महत्व की बावड़ियां हैं, हर्षद माता का भी बहुत पुराना मंदिर वहां पर है। प्रतिदिन वहां आठ सौ से हजार पर्यटक आते हैं जिनमें जापानी पर्यटक बहुत ज्यादा आते हैं तो क्या राज्य सरकार को स्पेशल इस तरह की बसेज या कोई आवागमन के साधन जो उस मोन्यूमेंट को और पर्यटन को बढ़ावा दे और रेवेन्यू बढ़े, उसका कोई प्लान रखती है और उस क्षेत्र के विस्तार के लिए, सौन्दर्यीकरण के लिए, राज्य सरकार की कोई योजना है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आभानेरी निश्चित तौर पर एक ऐसा स्थान है जहां बड़ी संख्या में जापान और दूसरे विदेशी पर्यटक भी आते हैं। पिछली बार भी आभानेरी के लिए वित्तीय प्रबंधन किया गया था, इस बार भी अगर किसी प्रकार का टयूरिस्ट के आवागमन के लिए कोई बस सेवा या दूसरी चीज संचालित करनी होगी तो निश्चित तौर पर विभागीय प्रक्रिया पूरी करके इसको पूरा करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्रीमती अनिता।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ...(व्यवधान)... पर्यटन में शेखावाटी की हवेलियां और शेखावाटी नम्बर वन पर है, वहां हवाई सेवा चालू करने का विचार रखते हैं क्या? वहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, हवाई सेवा से जोड़ने की इच्छा रखते हो झुन्झुनूं जिले को? ...(व्यवधान)... सीकर और झुन्झुनूं, दोनों में से कोई एक तो हो, बालाजी का, हनुमानजी का मंदिर है,

(श्री श्रवण कुमार)

वहां सालासर हनुमानजी का मंदिर है, श्याम बाबा का मंदिर है, हमारी तरफ भी देखो आप।

श्री अध्यक्ष: आप सुझाव दे देना मंत्रीजी को लिखित में। ...(व्यवधान)... श्रीमती अनीता। ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): दे रखा है, मैं तो हवाई सेवा की बात कर रहा हूं, हवाई सेवा की। ...(व्यवधान)...

नगर में पालनहार योजना के लाभार्थी

333. श्रीमती अनीता (नगर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र नगर में विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत वर्तमान में किन-किन योजनाओं का लाभ आम जनता को दिया जा रहा है? योजनाओं का नाम एवं लाभार्थियों की पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पालनहार योजना के अन्तर्गत माता के देहांत के बाद उन बच्चों को जिनके पिता नौकरी या अन्य कारणों से उनकी देखभाल नहीं कर पाते हैं, उन्हें लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व नहीं,तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अरुण चतुर्वेदी): (1) विधानसभा क्षेत्र नगर में निम्नांकित विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत आम जनता को लाभान्वित किया जा रहा है:-

1. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं
2. सहयोग एवं उपहार योजना
3. मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना
4. अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण सहायता योजना
5. पालनहार योजना
6. छात्रावास संचालन योजना
7. उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
8. पन्नाधाय योजना

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

उक्त योजनाओं में लाभान्वितों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में पालनहार योजनान्तर्गत माता के देहान्त के बाद उन बच्चों को जिनके पिता नौकरी या अन्य कारणों से उनकी देखभाल नहीं कर पाते हैं, उन्हें लाभान्वित किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्रीमती अनीता (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत गरीब लोग रहते हैं और जो मजदूर वर्ग है उसमें जब पति-पत्नी में अगर पत्नी का देहांत हो जाता है तो मजदूरी करने के लिए उसको बहुत परेशानी होती है। जैसा एक प्रकरण जालूकी में आया है, दो महीने की बच्ची थी और उसकी मदर की डेथ हो गई, उसका पिता मजदूरी नहीं कर पा रहा था और उसको भूखों मरने की नौबत थी, गांव वालों ने मदद की। मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें गंभीरतापूर्वक विचार हो और इसके लिए कोई नियम हो तो निश्चित रूप से जो बीपीएल में आते हैं या जो भी आपके तरीके हैं नियम के उसमें आप करें।

दूसरा पूरक प्रश्न मैं पूछ लेती हूं, मेरा निवेदन है कि जब पालनहार योजना है, उस पालनहार योजना के अंदर यह है कि जिसके माता-पिता नहीं होते हैं, उसके दादा-दादी या चाचा-चाची को पालनहार योजना में लाभांवित किया जाता है। मेरे क्षेत्र सीकरी के अंदर दो बच्चे हैं, एक की उम्र है दो वर्ष और दूसरे की उम्र है चार वर्ष, उनके न तो दादा-दादी जीवित हैं न कोई चाचा-चाची जीवित हैं, उनकी केवल एक बुआजी जीवित हैं, उनकी भी हरियाणा में शादी हो गई, बीस साल, दस साल पहले तो उनका यहां पर आधार या कोई आइडेंटीफिकेशन राजस्थान का नहीं है तो मैं चाहती हूं कि दोनों बच्चे पालनहार योजना के अंतर्गत आते हैं क्योंकि उनके ट्रस्टी में कोई नहीं है तो क्या मंत्री महोदय उनके किसी बुआजी या एडमिनिस्ट्रेशन में एसडीएम को, कलेक्टर को, किसी को ट्रस्टी मानकर उनको पालनहार योजना का लाभ देना चाहेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे 2005 में इस पालनहार योजना को शुरू किया था, चलते-चलते अलग-अलग चरणों में कई संशोधन करते हुए लगभग यह ऐसे बच्चे जो अनाथ होंगे, नाता गई, विधवा के बच्चे हैं तो उनको अलग-अलग चरणों में लेते हुए समावेश करने का प्रयास किया है। इसका परिणाम यह है कि आज देश में यह बिलकुल अभिनव योजना राजस्थान सरकार की है केवल और केवल राजस्थान ने शुरू की, अपने यहां से लेकर कई राज्यों ने इस योजना को शुरू किया। जम्मू-कश्मीर और दो अन्य प्रांतों के लोग पिछले दिनों इस योजना की स्टडी करने आए और उन्होंने भी इस योजना की बड़ाई करते हुए अपने यहां इसकी शुरूआत करने की बात की है। जहां तक नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने विषय को रखा है, निश्चित तौर पर आपके विषय को आप मुझे दें, हम नियमों के परव्यू में जहां भी शिथिलता प्रदान कर सकते हैं, सरकार इस बारे में संवेदनशील है और पूरी तरह ध्यान रखती है और पालनहार योजना का उद्देश्य भी यह है कि इस प्रकार के बच्चों को हम किस प्रकार से इसमें समावेश कर सकते हैं उसका कोई तरीका और नियम की परिधि में लाने का हम प्रयास करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी चीज, ऐसे बच्चे जो होते हैं जिनके माता-पिता नहीं है, कोई रिश्तेदार भी नहीं हैं, उनके लिए हमारे विभाग के कुछ छात्रावास भी चलते हैं, जिनमें बच्चों को रखने की योजना है, उनके पढ़ाने की योजना भी है, 18 वर्ष तक वहां रह सकते हैं। पालनहार में भी इसी प्रकार 18 वर्ष तक योजना का लाभ मिलने की बात है। उसके बाद मुख्य मंत्री हुनर योजना है जो 18 साल के बाद इसका लाभ मिल सकता है। आप कोई विशेष विषय बताएंगी तो उसका परीक्षण करके नियमों की परिधि में आता है तो कहीं न कहीं उसको लाभ देने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: दोनों प्रश्न हो गए आपके?

श्रीमती अनीता (नगर): नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया है और निश्चित रूप से मानती हूं कि उन बच्चों को पालनहार योजना से लाभ दिलाएंगे। मेरा एक निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में नवजीवन योजना में भी बहुत सारे लोग चयनित हैं। नवजीवन

(श्रीमती अनीता)

योजना जिसमें हमारे यहां पर रायसिख परिवार के लोग हैं, शराब बनाने का काम करते हैं, उनको नए जीवन से जोड़ने की योजना में चयनित बहुत हैं, तो क्या मंत्री महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो नवजीवन योजना में चयनितों की लिस्ट जो आपके यहां हैं, उन लोगों को लाभ देने के लिए कोई कार्य करेंगे? आपने अपना जो उत्तर दिया है उसमें यह योजना है नहीं, इसलिए मैं चाहती हूं कि इस योजना से भी मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों को लाभ मिले।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नवजीवन योजना में शराब और नशे के पेशे से जुड़े लोगों के बच्चों को रिहेबिलिटेट करने की योजना है। आपके क्षेत्र में भी जिला प्रशासन को कहूंगा कि नवजीवन योजना के नाते से जो भी बच्चे आइडेंटीफाई होंगे हमारी योजना के हिसाब से यदि वह नियम की परिधि में आते हैं तो सबको लाभ दिलाने का हम प्रयास करेंगे। नियम की परिधि में आएंगे तो ही।

श्रीमती अनीता (नगर): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: 18 सैकिंड में श्री धीरज गुर्जर, क्या कहेंगे, आपने अपने नाम का बटन दबाया है, 18 सैकिंड रह गए थे, अब 9 सैकंड रह गए हैं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): खतम करो। ...(व्यवधान)...

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

मुझे माननीय सदस्यों को निवेदन करना है कि आज दो वक्तव्य होंगे, एक चार बजे माननीय प्रतिपक्ष के नेता का, पांच बजे मुख्यमंत्री जी का। सहमति सब तरफ से ले ली गयी है। इसलिए यथासंभव आप चार बजे तक अपनी बहस पूरी करें, यह मेरा निवेदन है।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने फरमाया कि नेता प्रतिपक्ष भी बोलेंगे, माननीय मुख्य मंत्रीजी जवाब देंगे, उसमें भी काफी टाइम लगेगा और बोलने वालों की संख्या भी ज्यादा है। इसलिए आज 295 पढ़े हुए मान लिये जाएं।

श्री अध्यक्ष: मैं रखूं, तब बोल देना। मैं कर दूंगा। जब रखें, तब करेंगे।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से बानसूर ग्राम पंचायत को नगरपालिका बनाये जाने के संबंध में।
2. श्री पूरणमल सैनी, सदस्य की ओर से भीलवाड़ा के अरिहंत नगर, हलेड़ में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को खंडित किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

3. श्रीमती कामिनी जिन्दल, सदस्य की ओर से दिनांक 2 जून, 2012 को आयोजित तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में पंजाबी विषय में शामिल श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ के परीक्षार्थियों को पुन: शामिल करने के संबंध में।
4. श्री धीरज गुर्जर, सदस्य की ओर से भीलवाड़ा जिले में निर्माणाधीन राजमार्ग 148 डी के निर्माण में की जा रही अनियमितताओं के संबंध में।
5. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा चारागाहों की जमीन बिल्डर तथा खनन मालिकों को देने संबंधी आदेश निरस्त करने के संबंध में।
6. श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से राजगढ़ के सेउवा गांव में दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या से व्याप्त आक्रोश से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती कामिनी जिन्दल, श्री धीरज गुर्जर, श्री हनुमान बेनीवाल एवं श्री मनोज कुमार को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नागौर में विद्युत विभाग द्वारा बढ़ी हुई दरों से निकाली गई बकाया राशि को समाप्त करने के संबंध में।
2. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के सैटेलाइट अस्पताल में नार्म्स के अनुरूप संसाधनों का विकास किए जाने के संबंध में।
3. श्रीमती अनीता, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नगर में सरकारी महाविद्यालय खोलने के संबंध में।
4. श्री प्रताप लाल भील, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में शिविर लगाकर जनजाति आदिवासी परिवारों को वन अधिकार पत्र दिए जाने के संबंध में।
5. श्री मानसिंह किनसरिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र परबतसर में गौरव पथ निर्माण में यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य संबंधित विभागों द्वारा नहीं किए जाने से आ रही समस्या के संबंध में।
6. श्री हीरालाल नागर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांगोद की तहसील कनवास के गांवों में वर्षा जल से होने वाली तबाही से बचाने हेतु डायवर्जन चैनल का निर्माण किए जाने के संबंध में।
7. श्री पब्बाराम, सदस्य की ओर से फलोदी को नवीन जिला घोषित किए जाने के संबंध में।
8. श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से सीकर से लुहारू बॉर्डर तक फोर लेन सड़क बनाये जाने के संबंध में।
9. श्री रामहेत सिंह यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास की नगरपालिका खैरथल व किशनगढ़बास में सीवरेज व गंदे पानी के निकास की व्यवस्था किए जाने के संबंध में।
10. सुश्री कीर्तिकुमारी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ की तहसील बिजौलिया में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

11. श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के पाँच प्रमुख मंदिरों, मस्जिदों एवं पर्यटन क्षेत्रों तक सड़क निर्माण हेतु बजट प्रावधान किए जाने के संबंध में।
12. डॉ. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से जिला सवाई माधोपुर की तहसील चौथ का बरवाड़ा में लीजधारकों द्वारा अवैध खनन किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

माननीय सदस्यों द्वारा दी गयी सूचना आज पढ़ी हुई मानी जाएगी ऐसा निवेदन आया है, जिसको मैं हाउस की सहमति से स्वीकार करता हूं।

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

पर्ची

आज दिनांक 17 मार्च, 2017 को शून्यकाल में बोलने हेतु 47 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नांकित हैं:-

1. श्री रामचन्द्र, सदस्य की ओर से भवानीमण्डी, वार्ड नं. 16 स्थित मगनभाई मार्केट के भू-रूपान्तरण तथा हाउसिंग बोर्ड चौमेला (अपना घर) में निर्मित मकानों के आवंटन के संबंध में।
2. श्री घनश्याम, सदस्य की ओर से टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या के संबंध में।
3. श्री गोपाल कृष्ण, सदस्य की ओर से बीकानेर से सीकर टू-लेन की सड़क की जगह चार-लेन की सड़क डिवाइडर के साथ बनाये जाने के संबंध में।
4. श्री कंवर लाल, सदस्य की ओर से भामाशाह योजना में पात्र परिवारों को जोड़ने के संबंध में।

श्रीमती कामिनी जिन्दल।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2012 (पंजाबी विषय) की पुन: आयोजित परीक्षा में पूर्ववर्ती परीक्षार्थियों को ही अनुमति दी जाए

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियम 50 के अंतर्गत निम्न गंभीर एवं लोक महत्व के विषय पर चर्चा हेतु सदन को स्थगित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा राजस्थान में थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया जिसको बाहर जाना है, जल्दी जाएं। खड़े होकर यहां अव्यवस्था नहीं फैलाएं। आपस में बातचीत भी नहीं करें। सदन में आपस में बातचीत न करें। आप सब बैठिए। यह ठीक नहीं, यह उचित नहीं। बैठ जाइये।

श्रीमती कामिनी जिन्दल।

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा राजस्थान में थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2012, सैकिण्ड लेवल पंजाबी विषय की जिलेवार परीक्षा 2 जून, 2012 को आयोजित की गयी। इसमें ..

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अव्यवस्था हो रही है, डांटो इनको।

श्री अध्यक्ष: मैं बैठा हूं यहां व्यवस्था करने के लिए। आपकी आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): इसमें गंगानगर के कुल 136 पद एवं हनुमानगढ़ जिले के कुल 85 पद हेतु जिला परिषद, गंगानगर, हनुमानगढ़ द्वारा यह परीक्षा आयोजित की गयी, परन्तु एक ही कंपीटिटिव एग्जाम बुक से क्वेश्चन आने के कारण यह परीक्षा विवादों में हो गई और यह मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन हुआ। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 4 मई, 2016 को न्यायाधीश गोविन्द माथुर एवं नवनीत कोठारी द्वारा निर्णय सुनाया गया कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए एवं नये सिरे से यह परीक्षा करायी जाए।

विडम्बना यह है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के स्थान पर शिक्षा विभाग द्वारा पुन: परीक्षा करवाने के स्थान पर न्यायालय के

आदेशों का हवाला देते हुए नये सिरे से विज्ञप्ति जारी कर उक्त परीक्षा की अधिसूचना जारी की जा रही है। इस विज्ञप्ति से सैकड़ों नये आवेदनकर्ता भी इसमें आवेदन करेंगे जिसके कारण 5 वर्ष से पुन: परीक्षा का इंतजार कर रहे सैकड़ों परीक्षार्थियों के साथ अन्याय होगा। जून, 2012 में आयोजित परीक्षा के परीक्षार्थियों द्वारा विभिन्न मंचों पर यह मांग उठायी गयी है कि न्यायालय के आदेशों की पालना तभी संभव है जब पुन: आयोजित परीक्षा में केवल पूर्व में ही शामिल परीक्षार्थियों को मौका दिया जाए।

अत: मैं माननीय उच्च न्यायालय की मंशा के अनुरूप तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा, 2012, पंजाबी विषय की 2 जून, 2012 को आयोजित परीक्षा में शामिल गंगानगर, हनुमानगढ़ के परीक्षार्थियों की परीक्षा पुन: आयोजित करने हेतु नियम के अंतर्गत प्रस्तुत करती हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। आ गया आपका पाइंट।

श्री धीरज गुर्जर। (व्यवधान)

आप रेस्पोंड करेंगे। माननीय मंत्री महोदय।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने अपने संचालित विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत संबंधित जिला परिषदों के द्वारा किये जाने का जो प्रावधान है उसे 2012 में हमने 41 हजार थर्ड ग्रेड अध्यापकों की नियुक्ति की विज्ञप्ति जारी की। उसमें हनुमानगढ़ के 676 और श्रीगंगानगर के 741 पद विज्ञापित किये। इनमें से हनुमानगढ़ में 85 और श्रीगंगानगर में 136, कुल 221 तृतीय भाषा पंजाबी के लिए विज्ञापित किये गये। इसमें वाद संख्या 6235/2015 सुखदीप सिंह बनाम राज्य सरकार तथा 6236/2012 लखवीर सिंह बनाम राज्य सरकार के संबंध में पारित निर्णय 21.05.2015 द्वारा अध्यापक भर्ती 2012 में एक ही गाइड बुक से प्रश्न आने के कारण तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-2 पंजाबी विषय की भर्ती को अमान्य करते हुए एक विशेषज्ञ समिति बनाये जाने के निर्देश दिये गये। इस निर्णय के संबंध में दायर डी.बी. सिविल अपील संख्या 656/2015 एवं 636/2015 में पारित निर्णय दिनांक 4.5.2016 में पंचायत राज विभाग के पत्र दिनांक 2.5.2016 का उल्लेख करते हुए अपील को निस्तारित किया गया

(श्री वासुदेव देवनानी)

तथा पंचायती राज विभाग द्वारा पंजाबी विषय की उक्त भर्ती परीक्षा 2012 को निरस्त कर दिया।

अब उसके बाद नियमों में परिवर्तन हुआ और नियमों में परिवर्तन के आधार पर जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं दिनांक 15.10.2016 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 में संशोधन कर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक पद के चयन के प्रयोजन हेतु निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान को प्राधिकृत अधिकरण बना दिया गया है एवं भर्ती सम्बन्धी पूर्व प्रावधान/प्रक्रिया के स्थान पर नये नियम 277 (क) का अन्त:स्थापन किया गया है जिसमें प्रारम्भिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के पद के लिए सीधी भर्ती की प्रक्रिया एवं पद्धति प्रावधानित है जिसके अनुसार ही भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। इसके लिए हमने लॉ से भी कंसीडर किया है और लॉ ने यह ओपिनियन दी है कि अब नये नियम लागू हो गये हैं इसलिए नये नियम के तहत नई विज्ञप्ति जारी की जाए।

फिर भी आपने जिस मुद्दे को उठाया, मैं पुन: एक बार लॉ से इसका परीक्षण करवाऊंगा और उसके अनुसार जो नियमों के अन्तर्गत होगा उसके अनुसार हम कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री धीरज गुर्जर।

भीलवाड़ा में राजमार्ग 148-डी के निर्माण में अनियमितताएं

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आभार। मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले में शाहपुरा और जहाजपुर के अन्दर जो 148-डी नेशनल हाईवे बन रहा है उसमें अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत के कारण न केवल सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है बल्कि पर्यावरण का भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है।

संवेदक ने 148-डी पर जो प्लांट लगाये हैं उसके लिए न तो कंसेंट टू एस्टेब्लिश लिया है और न कंसेंट टू ऑपरेट लिया है और उसके बावजूद भी ठेकेदार के द्वारा प्लांट लगाकर वहां पर लगातार काम किया जा रहा है।

(श्री धीरज गुर्जर)

यही नहीं, जिस स्थान पर इन्होंने गिट्टी, मिट्टी और पत्थर के लिए टी.पी. ली थी उस टी.पी. के स्थान के अलावा दूसरी जगह से ये लोग मिट्टी उठा रहे हैं जहां चरागाह भी है और व्यक्तिगत लोगों के खेतों से भी उनको पैसा देकर खेती की जमीन से भी ये लोग मिट्टी उठाकर इस रोड के काम में ले रहे हैं।

इसके साथ-साथ जहाजपुर और शाहपुरा के अन्दर जो नरेगा के हरे पेड़ लगे हुए थे उन हरे पेड़ों को भी इनके द्वारा तहस-नहस कर दिया गया, उनको उखाड़ कर फेंक दिया गया और उन पेड़ों के जो ईंटों के ट्री गार्ड बनाये गये थे उन ईंटों को भी इस संवेदक द्वारा लेकर वहां से खुर्द-बुर्द कर दिया गया और सरकार को लाखों रुपये का राजस्व का नुकसान दिया है।

इसके साथ-साथ ही जो ये पत्थर काम में ले रहे हैं, गिट्टी काम में ले रहे हैं वो कच्ची है।

और तो और, सरसिया के आस-पास जो थ्री-डी की कार्यवाही हुई थी उस थ्री-डी की कार्यवाही की जगह से स्थान बदलकर दूसरे स्थान पर इन्होंने रोड का काम चालू किया है।

उससे भी ज्यादा गम्भीर अपराध तो इन्होंने यह किया है कि न तो कंसेंट टू एस्टेब्लिश लिया है और न कंसेंट टू ऑपरेट लिया है और उसके बाद भी जब हम जिलाधिकारियों को शिकायत करते हैं तो एस.डी.एम. और तहसीलदार का कमीशन बढ़ जाता है। एस.डी.एम. और तहसीलदार की गाड़ी में तेल ही ये डलवा रहे हैं, उनके घर पर राशन भी ये ही डलवा रहे हैं और अधिकारी आंखों पर पट्टी बांधकर, मिलीभगत कर सरकार को नुकसान दे रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आपने ध्यान खींच लिया।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): इसके साथ-साथ जो जहाजपुर की गंगा नदी नागदी है उस नागदी के अन्दर भी पूरी तरीके से इन्होंने पुलिया बनाने के लिए चौड़े-चौड़े बीम बनाकर पूरी नदी में मिट्टी भर दी है।

मैं चाहता हूं कि सरकार इसमें कार्यवाही करे और जनता को राहत मिले।

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): सर, रेस्पोंड कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: रेस्पोंड कर रहे हैं क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस भीम-बरसोली-गुलाबपुरा राष्ट्रीय राजमार्ग 148-डी की बात उठाई है। इसमें एजेंसी एनएचएआई है और राजस्थान सरकार सीधी एजेंसी नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें जो अपने अनियमितता की बात कही, आपने कहा कि प्लांट में कंसेंट टू एस्टेब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट नहीं लिया गया तो इसकी पूरी जानकारी करेंगे और मेरी जानकारी के अन्दर यह प्लांट लगाने से पहले कंसेंट टू एस्टेब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट दोनों लिये गये हैं।

आपने यह कहा कि पेड़ों को हटाया गया है तो अध्यक्ष महोदय, पेड़ जो रास्ते में आ रहे थे उनको निश्चित तौर पर परमिशन से ही उन पेड़ों को हटाया गया है और उनकी एवज में एक निश्चित मात्रा में पेड़ दुबारा लगाने का अनुबंध भी इसमें किया है।

राज्य सरकार को इसके सम्बन्ध में अब तक कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अगर राज्य सरकार के पास कोई शिकायत प्राप्त होगी तो निश्चित तौर पर उस पर कार्यवाही करेंगे। माननीय सदस्य अगर आपने कोई शिकायत दी है तो उसकी एक कापी आप दे दें, उस पर निश्चित तौर पर कार्यवाही करेंगे।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): एस.डी.एम. के घर में राशन भिजवा रहे हैं। राशन भिजवा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): जिला कलेक्टर को, एस.डी.एम. को, तहसीलदार को और सम्पर्क पोर्टल पर है। सब जगह हमने डाल रखी है शिकायत।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): एस.डी.एम. के घर में राशन भिजवा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब बैठो, हो गया, ध्यान खींच लिया। हनुमान बेनीवाल। श्रवण कुमार जी, माननीय विधायक, विराजिये। श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): एस.डी.एम. के घर में राशन भिजवा रहे हैं वो तो बताओ।

चरागाहों की भूमि बिल्डर व खान मालिकों को देने सम्बन्धी आदेश को निरस्त किया जाए

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के पर्यावरण संरक्षण और पशुधन हित के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 20 फरवरी को एक बैठक हुई और प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्र में भी यह प्रकाशित हुआ कि जो भी चरागाह नगरीय क्षेत्र में आते हैं उन चरागाहों की जमीन खान मालिकों और बिल्डरों को देने के लिए स्वायत्त शासन विभाग ने जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर पहले से ये नियम बने हुए हैं कि बड़ा पशु गाय-भैंस जहां भी होता है तो एक पशु के हिसाब से आधा बीघा चरागाह भूमि अलॉट हो रखी है। अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद लगातार पशुओं की संख्या बढ़ रही है और पशुओं की संख्या के अनुपात में भूमि घट रही है। अध्यक्ष महोदय, कई गांव तो ऐसे हैं जहां चरागाह की भूमि भी नहीं है और जहां भी गांवों के अन्दर गौशालाएं चला रहे हैं वहां लोग गौशालाओं के अन्दर सरकारी जमीन अलॉटमेंट के लिए प्रयास करते हैं लेकिन कई जगह आता है कि चरागाह की भूमि है इसलिए गौशालाओं को भी आप अलॉट नहीं करते हैं।

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन था कि प्रदेश में पहले ही मुख्य तौर पर शहरों में हजारों गायों की मृत्यु हुई है और कई पशुओं की आये दिन चारे के अभाव में मौत हो जाने के समाचार सामने आते हैं मगर यह दुर्भाग्य है कि सरकार इन चीजों पर गौर नहीं करते हुए इस तरह का तुगलकी फरमान निकालकर नगरीय निकायों की सीमा में स्थित चरागाहों की जमीन पर आबादी की योजना लाने की बात कर रही है जो पूर्ण रूप से गलत है।

(12.16 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(श्री हनुमान बेनीवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, हिंगोनिया की गौशाला में जो गायों की मौत हुई वो गूंज पूरे देश में रही और उसकी जांच भी आज ठण्डे बस्ते में चली गई। हम लोग भी वहां गये थे, सरकार के मंत्री भी वहां गये थे और हिंगोनिया गौशाला का मुद्‌दा एक राष्ट्रीय मुद्‌दा बना लेकिन उस मुद्‌दे में भी जो जांच होनी चाहिए वो जांच नहीं हुई।

उपाध्यक्ष महोदय, एक ओर तो प्रदेश पशुधन के हालात को मद्‌देनजर रखते हुए ..... (व्यवधान) आप रुको तो सही, बीच में क्यों बोल रहे हो? मुझे मेरी बात कहने दो न और बैठे-बैठे क्यों, खड़े होकर बोलो न। ऐसे आप कोई घर पर थोड़े ही बैठे हो। (व्यवधान) ....

सरकार को विकसित करने की आवश्यकता थी मगर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान की यह सरकार पशुधन हित और पर्यावरण संरक्षण को दरकिनार करके चरागाह की जमीन में आवासीय कॉलोनियां और दूसरे प्रकार के कार्य करने जैसे निर्णय ले रही है। आज चाहे गांव हो या शहर हो, बढ़ते पशुधन के लिए चरागाह क्षेत्र को बढ़ाने की आवश्यकता है और कई गांव तो ऐसे हैं जहां चरागाह की जमीन तक नहीं है। 2012 की जो पशु गणना है उसके अनुसार राजस्थान में 5 करोड़ 77 लाख पशु थे इसलिए इस प्रकार के निर्णय पशुओं और पर्यावरण के हित में नहीं होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, खान विभाग के कारोबारियों के दबाव में सरकार राजस्व विभाग के पुराने सर्कुलर को बदल रही है। केन्द्र सरकार के एमएमडीआर एक्ट के तहत 11 जनवरी, 2017 से पहले 8 खदानों को माइनिंग लीज पर दिया था लेकिन प्लान में चरागाह की भूमि खनन क्षेत्र में आने के कारण विधि विभाग ने चरागाह की जमीन को खदानों में आबंटन नहीं करने की राय दी थी। उपाध्यक्ष महोदय, आज कई जिलों के कलेक्टरों ने भी इस बात को कहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह कलेक्टर का बयान है कि चरागाह की जमीन की किस्म.....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं आपको अख़बार नहीं पढ़ने दूंगा यहां। आप वैसे बोल लें, अगर आपको कुछ स्मरण है तो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ठीक है, नहीं पढ़ूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, कई जिलों के कलेक्टरों ने यह कहा कि चरागाह की भूमि को आप दूसरी

(श्री हनुमान बेनीवाल)

जगह कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसकी किस्म नहीं बदल सकते। पर्यावरणविदों ने यह कहा है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने पहले एक आदेश किया था जिसके अन्दर चरागाह की भूमि में कोई कॉलोनी काटी थी और उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार चरागाह की जमीन को दूसरे उपयोग में नहीं लिया जा सकता। कुछ वर्ष पहले जयपुर के अन्दर आगरा रोड पर जे.डी.ए. ने चरागाह की जमीन पर अम्बेडकर आवासीय योजना के नाम से कॉलोनी काटी थी जिसको लॉटरी खुलने के बाद भी माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त किया था। अगर बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो चरागाह की जमीन को दूसरे उपयोग में लेने से पहले आपको दूसरी जमीन पर चरागाह डवलप करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए यदि हमें खासतौर से शहरी क्षेत्र के पशुधन हित और पर्यावरण संतुलन को बचाना है तो सरकार इस प्रकार के निर्णय को तत्काल निरस्त करे।......

सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स असमंजस की स्थिति में आ गये और इस प्रकार खान घोटाले की बहुत बड़ी चोट प्रदेश में हुई। उसके बावजूद सरकार उद्योगपतियों के दबाव में शहरी क्षेत्रों के चारागाहों को उन्हें सौंपने की तैयारी कर रही है, जो गलत है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वैसे भी राजस्थान के अंदर चाहे 90बी का घोटाला हो, चाहे हिंगोनिया गौशाला का चारा का घोटाला हो, चाहे खान घोटाला हो, घोटालों में राजस्थान एक नम्बर पर है। तो अब और इन घोटालों की ओर...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटे से पाइंट पर आपने माननीय सदस्य को अनुमति दी है...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ...मैं सरकार से मांग करता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि जो आपने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाकर ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप देखिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव है, उसके दायरे से कितनी दूर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

ये चले गये? माननीय सदस्य कितनी दूर चले गये? कहां है इसमें, हिंगोनिया गौशाला इसके अंदर आ गया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ...राजस्थान के जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही चाहता हूं...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल मात्र इनको दो मिनट का टाइम दिया गया था। दो की जगह पाँच-सात मिनट तो हो गये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट, साहब। आप भी जीतकर आये हो और मैं भी जीतकर आया हूं। मैं कोई यहां नोमिनेट थोड़े ही हुआ हूं। +++

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें इतना ही निवेदन था। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि आप इस तरह के निर्णय नहीं लें। एक साल बाद आपको चुनाव के अंदर जाना है और यूपी के चुनावों के नतीजों से आपको ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। यहां तो राजस्थान के अंदर आप काम करोगे तो, ही...

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, आपका जो विषय है, वह विषय आपने बहुत अच्छी तरीके से रख दिया। जो नहीं रखना चाहिए था, वह भी आपने रख दिया। तो अब तो आप विराज जाओ। इससे ज्यादा और आप कितना...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। जो तुगलकी आदेश इन्होंने निकाला मुख्य सचिव की अध्यक्षता की कमेटी बनाकर, उसको निरस्त करें, उसको जनहित के अंदर वापस लें। ये किसान विरोधी हैं और गाय माता के विरोधी हैं।

श्री उपाध्यक्ष: Do you want to react? जो इनका स्थगन प्रस्ताव था, उसी तक सीमित रहकर आप जवाब दीजिये। otherwise it is not necessary.

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत शासन मंत्री): मैं उसी पर बोल रहा हूं। मैं जवाब दूंगा भी नहीं और इनका जवाब देने लायक भी नहीं है।

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है, उसके संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है। राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक प.6(9)रेवेन्यु/6/39 दिनांक 8.12.2010 को जारी की गई थी, जिसमें मुख्यत: निम्नांकित निर्देश किये गये थे। जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण व नगर विकास न्यास व नगरपालिका क्षेत्रों में स्थित सभी राजकीय भूमियां संबंधित प्राधिकरण, न्यास, नगरपालिकाओं को हस्तान्तरित की जायेंगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शायद हनुमानजी को ध्यान भी होगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 68 में यह प्रावधान है कि निकाय क्षेत्र में स्थित समस्त सार्वजनिक एवं सरकारी भूमि संबंधित निकाय में निहित होंगी। वैसे भी निकाय क्षेत्र में स्थित चारागाह भूमियों का चारागाह के रूप में कोई उपयोग नहीं हो पाता है क्योंकि निकाय क्षेत्रों में नगरपालिका अधिनियम लागू होता है। शायद हनुमानजी आपको ध्यान होगा, नगरपालिका अधिनियम की जानकारी आपको होगी, जिसके अनुसार निकाय क्षेत्र में पशुओं को सार्वजनिक स्थानों और भूमि को चराई के लिए नहीं छोड़ा जा सकता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त निकाय क्षेत्र में स्थित चारागाह एवं सरकारी भूमि यदि संबंधित निकाय के नाम दर्ज नहीं हो तो उस पर होने वाले अतिक्रमणों, कब्जों के विरुद्ध निकाय प्रभावी कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ऐसी समस्त भूमि निकाय के नाम दर्ज होना आवश्यक है। निकाय क्षेत्रों में शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण आवासीय आवश्यकताएं निरन्तर बढ़ती जा रही हैं एवं इस कारण निकाय क्षेत्रों में स्थित सरकारी भूमियों पर आवासीय योजनाओं विशेष रूप से मुख्य मंत्री जन आवास योजना, प्रधान मंत्री जन आवास योजना सहित ऐसे कई सार्वजनिक कार्य हैं जिनको विकसित किये जाने के लिए निरन्तर आवश्यकता महसूस की जा रही थी और इसीलिए स्वायत शासन विभाग द्वारा दिनांक 26.12.2016 को समस्त जिला कलक्टर्स को निर्देश दिया गया, को लिखा गया पत्र उचित है। इसमें राजस्व विभाग की प्रासंगिक अधिसूचना दिनांक 8.12.2010 की प्रति संलग्न की जाकर जिला कलक्टर्स से अपेक्षा की गई कि वह निकाय क्षेत्र में स्थित समस्त राजकीय एवं चारागाह भूमि नगरीय निकाय को अविलम्ब हस्तान्तरित करने की कार्यवाही करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक सैकिण्ड, माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: इसमें मैं आपसे एक निवेदन करता हूं I can't allow, I'll not allow a debate on this issue. More or less अगर कुछ बाकी रह गया है तो you can go and get in touch with the Minister concerned.

श्री मनोज कुमार जी।

सेउवा ग्राम (राजगढ़) में दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की कार्य प्रक्रिया एवं संचालन नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा। एक लोक महत्वपूर्ण विषय।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के पुलिस थाना राजगढ़ में दिनांक 12.3.2017 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 117/2017, 302, 34, 120बी आईपीसी में दर्ज हुई।

उस विषय से गम्भीर विषय इस विभाग का है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि एफआईआर नम्बर 330/2015 दिनांक 27.8.2015/28.8.2015 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई जिसमें चार मुलजिमों का 376/2जी/366ए, 120बी में मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें चार अपराधी पुलिस ने माने, जिसमें से तीन अपराधी गिरफ्तार हो गये। एक अपराधी अपने पैसों के बल पर, सर्वप्रथम इन्वेस्टिगेशन अधिकारी को पैसे देकर अपना नाम निकालने में सफल हो गया। उसके बाद पीड़ित पक्ष ने उस मुकदमे की तफ्तीश चेंज कराकर उस मुकदमे में एडिशनल एसपी चूरू ने और सीआईडी सीबी के एडिशनल एसपी ने उस मुलजिम को दोषी माना। उसके बाद मुलजिम ने हमारे क्षेत्रीय सांसद के राजनैतिक संरक्षण के कारण उस पुलिस इन्वेस्टीगेशन को दुबारा चेंज कराकर, आज उस 376, नाबालिग बच्ची के साथ रेप करने वाला अपराधी, जिसे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी और उसी अपराधी ने छह महीने के अंदर-अंदर उस पिता को तीस लाख रुपये में राजीनामा करने के लिए दबाव बनाया और उस बच्ची के पिता ने मना कर दिया तो होली के दिन उस बच्ची के पिता की हत्या करवा दी गई, जिसमें आज तक छह दिन का समय बीत गया है, पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर पाई है।

(श्री मनोज कुमार)

गम्भीर विषय यह है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नाबालिग बच्ची के साथ रेप होने के बाद छह महीने तक पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई और गिरफ्तारी के साथ-साथ बार-बार हाईकोर्ट का निर्णय है कि किसी भी मुकदमे में तीन बार से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन, बहुत ही अति गम्भीर बात ना हो, तो इन्वेस्टिगेशन को चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन राज्य सरकार उस अपराधी को बचाने के लिए बार-बार इन्वेस्टिगेशन चेंज कर रही है और आखिर उसका परिणाम यह हुआ कि उस अपराधी ने उस बच्ची के पिता की हत्या करवा दी।

ऐसे गम्भीर विषय में आज उस परिवार के और समाज के लोग वहां राजगढ़ तहसील में आन्दोलन और धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे समाज में आक्रोश है और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्वेस्टिगेशन के नाम से पुलिस जिस तरीके से कार्यवाही कर रही है, सिर्फ पैसों के बल पर अनुसंधान हो रहा है।

माननीय गृह मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि जिन इन्वेस्टिगेशन में चार-चार, पांच-पांच बार तफ्तीश चेंज हो रही है, उसमें अपराधी आखिर सफल होता है क्योंकि कहीं न कहीं उसका एडजस्टमेंट होता है और अपराधी उसमें बचने में सफल रहता है।

ऐसा ही एक किस्सा मेरे राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र का, जिसमें एफआईआर नम्बर 75/2014, एफआईआर नम्बर 76/2014, एफआईआर नम्बर 79/2014, पुलिस स्टेशन सिद्धमुख की जिसको उस परिवार के बच्चे पर फायरिंग हुई, गोली लगी और अंतिम इन्वेस्टिगेशन एसओजी में आकर उस अपराध को तो प्रमाणित माना है लेकिन पुलिस ने लिखा है कि अदमपता मुलजिम, गांव की घटना, गांव के अपराधी, तीन-चार अधिकारियों ने, एडिशनल एसपी ने अपराधी माना और आपकी एसओजी ने अंतिम क्षणों में जाकर उसको अपराधी नहीं माना।

इस तरह का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है गृह मंत्री महोदय, ध्यान करिये आप, जिस तरीके से जनता के साथ पुलिस कर रही है, उस पर नियंत्रण करने की जरूरत है और आज इस विषय पर मैं कहना चाहता हूं, गृह मंत्री महोदय, जल्द से जल्द इन मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाये। इस परिवार

(श्री मनोज कुमार)

ने बार-बार गृह मंत्री महोदय को, मुख्य मंत्री महोदय को, महानिदेशक महोदय को लिखा है कि मेरी जान को खतरा है, मुझे मार सकते हैं और उस पर राजीनामे के दबाव के कारण, लेकिन प्रशासन सुरक्षा नहीं दे पाया। आखिर उसकी हत्या हुई।

गृह मंत्री महोदय, इसके लिए, अनुसंधान के लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि राजगढ़ पुलिस से नहीं कराकर चूरू जिले के मुख्यालय पर कराएं।

हमारे पंचायती राज मंत्री विराजमान हैं। मैं कहना चाहता हूं पंचायती राज मंत्री महोदय, आपके जिले में ऐसा हो रहा है और आपके पास भी पीड़ित लोग आये होंगे लेकिन आप उनकी, या तो आपकी सरकार में चलना बंद हो गया या फिर आप उन पर गौर नहीं कर रहे। आपके जिले में बैठे पुलिस अधीक्षक को आप भी अवगत करा चुके होंगे लेकिन आपकी बात की अनसुनी की जा रही है।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं, दोनों काबिल मंत्री सामने विराजमान हैं। आप इस विषय पर गम्भीरता से विचार करते हुए इसको चूरू जिला हैडक्वार्टर पर या किसी सीआईडी सीबी के आफिस में इसकी जांच कराई जाए और दोषी अपराधियों को जिन्होंने अपराध किया है और कराने वाले हैं, सभी अपराधियों को इसमें गिरफ्तार किया जाए। इसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि उस गरीब के साथ न्याय करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है, उसमें अधिकांश विषय सत्य है। यह घटना 2015 से प्रारम्भ हुई जब उसके साथ रेप हुआ और उसने एक मुकदमा 330/2015 दर्ज कराया, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई। जो एफआईआर दर्ज थी, उसमें विकास जाट का भी नाम लिखा हुआ था और उसके साथ मनोज और दो अन्य लोग थे। जांच करने वालों ने तीन लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया...और विकास जाट गिरफ्तार नहीं हुआ पुलिस उसको मान नहीं रही थी और उसका 173/8 में चालान पेश कर दिया जिसमें नरपत सिंह की गिरफ्तारी हुई, विनोद कुमार ब्राहमण की हुई और बाल अपचारी मनोज कुमार की भी गिरफ्तारी हो गई, लेकिन ये विकास बचा हुआ था।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

यह बात सच है कि 11 तारीख के दिन एक महेश नाम का लड़का आया था और ये अपने घर पर रेखा कंवर, उसके पिता और उसका पति महेश तीनों थे। उसको कहीं बुला कर ले गया और लगभग 8 बजे ले गया था। 10 बजे उम्मेद सिंह नाम के व्यक्ति ने आकर घर पर इनको सूचना दी कि आपके मानसिंह को कहीं दूरदराज ले जाते हुए दो लोगों को हमने देखा है। इसलिए इनके साथ कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। इसके आधार पर परिवार के लोग गये। वहां वास्तव में उसके साथ मारपीट चल रही थी जब तक परिवार के लोग पहुंचे वो भाग गये थे। महेश तो आईडेंटीफाई इसलिए था क्योंकि महेश ही मोटरसाइकिल लेकर आया और महेश ही बैठा कर के उसे ले गया लेकिन महेश पकड़ में नहीं आया अभी तक पुलिस के। लेकिन निश्चित रूप से महेश पकड़ में आने के बाद दूसरा व्यक्ति कौन था इस मर्डर केस में निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्यवाही होगी।

लेकिन यह भी बात सच है कि यह जो विकास जाट नाम का व्यक्ति उस पहले केस में 376 का जो मुल्जिम था उसकी किसी न किसी तरह से तफ़तीशें चेंज हो रही थी और एक तफ़तीश से दूसरी तफ़तीश में जब अन्तर आता है तो स्वाभाविक रूप से हम अगली तफ्तीश कराने की कोशिश करते हैं। एक में बिलकुल एफआर लगा रहा है, एक में उसको मुल्जिम मान रहा है। तो दो में अन्तर आने के कारण से जब कोई इस विषय को रखता है तो निश्चित रूप से उसकी तीसरी जांच कराते हैं।

लेकिन मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि दो महीने के अन्दर ये 330/15 का भी और अभी जो दर्ज हुआ 117/17 भी, इसमें जो भी मुल्जिम हैं, वो हण्ड्रेड परसेंट पकड़े जाएंगे। सदन में मैं यह आश्वस्त करता हूं। अभी तो सीआईडी सीबी कर रही है आपको अगर लगता है कि वहां विश्वास नहीं है, तो जिससे चाहे उसे मैं यह जांच देकर के दोषी को हण्ड्रेड परसेंट सज़ा दूंगा। इसमें बचाने का कोई पक्ष नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से श्री रामचन्द्र।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

भवानीमण्डी स्थित मगनभाई मार्केट का भू-रूपान्तरण व चौमेला में आवासन मण्डल द्वारा निर्मित मकानों का आवंटन

श्री रामचन्द्र (डग): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से आपने बोलने के लिए मुझे इजाजत दी उसके लिए धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भवानी मण्डी के अन्दर एक मगन भाई मार्केट है वार्ड नम्बर-16 । महाराजा झालावाड़ ने वो जमीन व्यापार एवं उद्योग मण्डल को दी थी और 1985 से वहां आवासीय कॉलोनी बनी हुई है। वो जमीन का खसरा नम्बर-521,522,524,525 है तथा 15 बीघा 13 बिस्वा है। अब उस पर नगरपालिका द्वारा रोड भी बना दी, लाइट भी बना दी। लाइट भी लग रही है नालियां भी बन रही हैं सारे विकास के काम हो गये, लेकिन राजस्व विभाग और स्वायत्त शासन विभाग की अनदेखी की वजह से उनको पट्टा नहीं मिल रहा है। वो जमीन मगन भाई के नाम दर्ज हुई थी। उसके बाद वो व्यापार एवं उद्योग मण्डल को दी गई और अभी तक वह अमूर्त है।

तो मेरा सरकार से आपके माध्यम से निवेदन है कि इनका भू-रूपान्तरण करके जिनके मकान बन गये उनको मालिकाना हक मिल जाए और नगरपालिका, क्योंकि राजस्व विभाग इसमें बार-बार अड़चन लगा रहा है, तो राजस्व विभाग और स्वायत्त शासन विभाग नगरपालिका दोनों मिल कर अगर ये सामंजस्य करें, तो करीब-करीब 1984 से जो मकान बने हुए हैं उन लोगों को अपना पट्टा मिल जाए और उनको जो भी राशि वहां जमा करानी है वह उनकी हो जाए।

दूसरा मेरा निवेदन है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में मलारगंज चोमेला में हाउसिंग बोर्ड के मकान बने। अब राजस्थान में आवासन मण्डल के गठन का एक उद्देश्य रहा होगा कि अल्प वेतन भोगी, मध्यम वर्गीय, उच्च आय वर्ग वालों को मकान बना कर दिये जाएं, लेकिन जब हाउसिंग बोर्ड इन मकानों को बनाता है तो मकान बनाते वक्त गुणवत्ता में घटिया किस्म का निर्माण होता है। अब उसमें धीरे-धीरे उन मकानों को स्केलटन ढांचा बना देते हैं। अब स्थिति यह है कि वो सैंकड़ों मकान जो बने

(श्री रामचन्द्र)

हैं वो सिर्फ मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही नहीं अन्य विधान सभा क्षेत्रों में भी बने होंगे। वहां आज उन पर जो भी खिड़की दरवाजे और जो भी उन पर मूल्यवान चीजें लगी हैं वो सब निकाल ले गये और वो बिलकुल ढांचे की तरह खड़े हैं।

तो हाउसिंग बोर्ड में ये जो परम्परा है कि जिस प्रकार से शहर से दूर बसाना और उसके बाद में फिर वो शहर के करीब आना और उसके बाद में इनके सारे कर्मचारी-अधिकारियों की मिलीभगत से दलाल उनके पास जाना, उनके सारे कागज इकट्ठे कर लेना, उनके पॉवर ऑफ अटार्नी ऑफ सेलिंग ले लेना। इस प्रकार से जो हाउसिंग बोर्ड का चलता है इसके माध्यम से वो मकान जिन आबंटियों को मिलना चाहिए उनको मिलता नहीं है जब तक उनको सुपुर्द नहीं करे तब तक तो हाउसिंग बोर्ड की जिम्मेदारी बनती ही बनती है और ऐसे कई जगह से भवानी मण्डी हाउसिंग बोर्ड में जो जगह छूटी हुई है हाउसिंग बोर्ड की उस पर अवैध निर्माण हो गये, कब्जा कर लिया, मकान बना लिया।

चूंकि माननीय मंत्री महोदय बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही सकारात्मक सोच के धनी हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जो मकान जिस प्रकार से चाहे भवानी मण्डी हो, चाहे मलारगंज हो, चाहे राजस्थान के किसी भी प्रदेश में हो, जिस प्रकार से गुणवत्ताविहीन और घटिया निर्माण करके, यह कोई इस सरकार का मामला नहीं है, सालों से हाउसिंग बोर्ड ऐसा करता आ रहा है और एक ऐसा विभाग है जहां दलालों की भरमार रहती है। कर्मचारी-अधिकारी सब मिले हुए हैं। वो स्केलटन टूटने के बाद में पुन: आबंटियों को जब आप मकान दोगे तो फिर उसके मेंटीनेंस के लिए अलग से और खर्चा देना पड़ेगा। तो मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की ये जो कारगुजारी इस आवासन मण्डल में होती है इसको रोकें और इसके संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करें।

जो वाकई, एक मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे भवानी मण्डी के अन्दर एक सुभाष चन्द्र सैन है वो स्वयं हार्ट पेशेंट है, उसने न जाने मजदूरी करके 48 हजार रुपये जमा कराये। उनके दोनों बच्चों के वॉल खराब है। उसकी पत्नी घर-घर जाकर काम करती है। बड़ी मुश्किल से पैसे जमा कराये। वो

(श्री रामचन्द्र)

दलाल के माध्यम से उसका मकान ही न जाने किसको आबंटित कर दिया। आबंटित जिसको होना चाहिए उसको नहीं हुआ और किसी को दलाल के माध्यम से बेच दिया।

इस प्रकार के न सिर्फ यह एक कारनामा है, यह पूरे राजस्थान में कई जगह ऐसी बीमारी है। तो माननीय मंत्री महोदय जो कि अभी-अभी इस विभाग को संभाले हैं निश्चित रूप से इसकी ओर कार्यवाही करेंगे।

तीसरा माननीय मुख्यमंत्री महोदया की 2003 से 2008 तक जब सरकार थी, उस समय अपना घर बनाने की योजना राजस्थान में लागू की थी। प्रत्येक व्यक्ति को दस रुपये महीना या दस रुपये रोज में। अब वो जगह-जगह आपने मकान बना दिये, बने हैं, उन मकानों में 92 मकान भवानी मण्डी नगरपालिका में बने हुए हैं। उन मकानों में दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया और जिनको आबंटन होना चाहिए गरीबों को उनको हुआ ही नहीं। तो मेरा निवेदन है कि उनको भी आप खाली कराएं और जो पात्र व्यक्ति हैं उनको मिले। धन्यवाद।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भवानी मण्डी वार्ड नम्बर-16 स्थित मगन भाई मार्केट के भू-रूपान्तरण के संबंध में आपने विषय रखा है। प्रकरण से संबंधित भूमि वर्तमान में व्यापार एवं उद्योग मण्डल भवानी मण्डी के नाम दर्ज है। यह भूमि मूलत: 48 खातेदारों की थी जिनमें से लगभग आधे खातेदार अब नहीं रहे, स्वर्गवासी हो चुके हैं। इस भूमि पर दो धर्मशाला, दो पाठशाला, दो मंदिर, एक सिनेमा हाल एवं लगभग दो सौ रिहायशी मकान उसमें बने हुए हैं जिनमें जलदाय विभाग एवं विद्युत विभाग द्वारा कनेक्शन दिये हुए हैं।

नगरपालिका भवानी मण्डी को इस कॉलोनी को नियमित करने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु अभी तक इस भूमि को रूपांतरण करने की कार्यवाही माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहीं हो पायी है, क्योंकि इसके मूल जितने भी खातेदार हैं उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो चुकी है एवं उनके द्वारा भू-रूपान्तरण नहीं करवाया जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनहित में नगरपालिका भवानी मण्डी द्वारा सुओमोटो भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90(क) के तहत रूपान्तरण

(श्री श्रीचन्द्र कृपलानी)

की कार्यवाही प्रारंभ की गयी थी, परंतु संबंधित तहसीलदार द्वारा फार्म-6 की सूचना यह कह कर उपलब्ध नहीं करायी गयी कि प्रश्नगत भूमि का खाता अमृत खाता है इसलिए अभी तक इस भूमि का रूपान्तरण नहीं हो पाया है।

आने वाले मई में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा जनकल्याण शिविर प्रारंभ किये जाने की योजना है। इस दौरान पुन: नगरपालिकाओं को सुओमोटो भू-रूपान्तरण के अधिकार दिए जा रहे हैं और तब इस भूमि के भू-रूपान्तरण की कार्यवाही करने का प्रयास किया जाएगा।

दूसरा इन्होंने जो मुद्दा रखा हाउसिंग बोर्ड चोमेला में अपना घर निर्मित मकानों के आबंटन के संबंध में इन्होंने जो अपनी बात रखी है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान आवासन मण्डल की चोमेला योजना वर्ष 2006 में प्रारंभ की गयी थी। इस योजना में ईडब्ल्यूएस वर्ग के 132 तथा अल्प आय वर्ग के 100 कुल 232 आवासों हेतु पंजीकरण योजना खोली गयी थी। इस पंजीकरण योजना में ईडब्ल्यूएस के 132 व अल्प आय वर्ग के 100 आवासों हेतु पंजीकरण प्राप्त हो गये थे। ये आवेदन घरौंदा योजनान्तर्गत थे। आवासों का निर्माण वर्ष 2009 में प्रारंभ कर 2010 में पूर्ण कर दिया गया एवं योजना के समस्त विकास कार्य भी पूर्ण कर दिऐ गऐ थे। आवासों के आबंटन उपरांत आबंटन पत्र जारी कर दिये गये थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 232 जारी आवंटन पत्रों में से सिर्फ 15 आवेदकों ने आवासों पर कब्जा प्राप्त किया तथा शेष 217 आवंटी द्वारा कब्जा राशि जमा नहीं कराई गई तथा कब्जा प्राप्त नहीं किया गया। इन 217 आवेदकों के आवंटन को निरस्त कर दिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात रखी है मैं उसमें एक निवेदन करूंगा कि 217 अधिशेष आवासों का निस्तारण खुली बिक्री योजना से दिनांक 1.8.2013 को, 30.8.2013 को, 20.8.2014 से 30.9.2014 को, 13.2.2015 से 27.2.2015 तक किया गया है। इस खुली बिक्री योजना में मात्र एक आवास का निस्तारण हुआ, 216 आवास शेष रह गये। 216 आवासों की कीमत पर 20 प्रतिशत छूट प्रदान की गई, छूट के साथ 20.4.2016 से 13.5.2016 की बिक्री खुली योजना से निस्तारण के प्रयास किये गये, परंतु एक भी आवास का निस्तारण नहीं हुआ। इस प्रकार

(श्री श्रीचन्द्र कृपलानी)

216 आवास अधिशेष रह गये। इन आवासों की छूट के साथ पुन: निस्तारण के प्रयास किये जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री घनश्याम।

टोडाभीम में पेयजल समस्या

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने पर्ची के विषय पर बोलने का मौका दिया इसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की बहुत घोर समस्या है। उस पेयजल समस्या के लिये सरकार की एक बहुत पुरानी लंबित परियोजना नादौती सवाई माधोपुर है। उस योजना पर सरकार के हजारों करोड़ों रुपये खर्च हो चुके हैं। आज उस योजना के हालात देखें तो 12 साल से उस पर कोई काम नहीं हुआ है। कंपनी और सरकार के आदमियों ने मिलकर उसमें बहुत भारी घोटाला हुआ है। इसकी जांच का पहले भी कई बार मामला सदन में उठ चुका है। आज जो हालात है वहां पर सिर्फ पाइपों की खरीद हुई है, इसके अलावा और कोई काम नहीं हुआ। चंबल के पास जो इंटेक वैल बनना था, उसका भी सिर्फ 25 परसेंट काम हुआ है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने पहले बजट भाषण में यह उल्लेख किया था कि इस योजना से हम दिसम्बर, 2016 में जनता को पानी पिलाने का काम करेंगे। आज 2017 आ गया है, आज भी उसमें किसी तरह की क्रियान्विति नहीं हो रही है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो उपखण्ड हैं नादौती और टोडाभीम। नादौती एक ऐसा उपखण्ड है जिसमें जमीनी स्तर पर कोई पानी नहीं है। चाहे आपकी सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो, वहां टैंकरों से पानी पिलाने की व्यवस्था करती है। पानी के टैंकरों के जो टेंडर होते हैं उसमें ज्यादातर एडजस्टमेंट होता है, जनता को उसका कोई फायदा नहीं मिलता। जो दूर दराज में पानी के पहले से स्रोत हैं सरकार उनकी जानकारी करती है तो बीच में बरसात हो जाती है तो गंदे एवं खारे पानी को पीने के लिये जनता को मजबूर होना पड़ता है।

इसी तरह से हमारे वहां जो सिंगल फेस लगे हुए हैं, 300-400 सिंगल

(श्री घनश्याम)

फेस करौली जिले में बंद पडे हैं। पहले सरकार ने कहा कि इन पर बिजली का बिल बकाया है तो पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम पंचायतों के द्वारा सारे पैसे जमा करा लिये गये। उसके बावजूद मेरे विधान सभा क्षेत्र के 29 सिंगल फेस ऐसे हैं जिनका पूरा पैसा जमा हो गया है और आज तक उनको चालू नहीं किया गया। मेरी चीफ इंजीनियर से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम एक्सप्लेनेशन कॉल करेंगे कि ऐसे कैसे कर दिया, यह ऐसे कैसे प्रस्ताव भिजवा दिये।

मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि जो जनता से जुडी हुई व्यवस्थाएं हैं, पानी हो, चिकित्सा हो, इस तरह की व्यवस्थाओं पर अगर अपन ध्यान नहीं देंगे तो यह बहुत अहित होगा, जनता के साथ कुठाराघात होगा।

दूसरी बात यह है कि हमारे क्षेत्र में डार्क जोन घोषित कर रखा है और डार्क जाने घोषित होने की वजह से लोग खुद भी ट्यूबवैल नहीं खुदा सकते। सरकार ने भी वहां पिछले तीन चार साल से एक भी हैंडपम्प नहीं खुदवाया है, न सिंगल फेस खुदवाये हैं। वहां पीने के पानी की इतनी घोर समस्या पैदा हो चुकी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर विषय है। हर बार सदन में मैं इस बात को रखता हूं। अब गर्मी का मौसम आने वाला है और इस मौसम में अगर हम पानी के लिये समय रहते नहीं चेते, आसपास के जो दूसरे जल स्रोत हैं उन पर सरकार ध्यान दे, हम से पूछे, जन प्रतिनिधियों से, अधिकारियों से पूछे। इसमें सिवाय एडजस्टमेंट होने के अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। वाटर वर्क्स में जितने घोटाले हो रहे हैं, इन घोटालों का ध्यान रखा जाये, इन पर अंकुश लगाया जाये और जो पाइपों का घोटाला हुआ है, उसमें ढाई सौ करोड़ रुपये का खरीद में ही पहले घोटाला हो गया, वह लाकर डाल दिये, न कोई काम आ रहे हैं, खेतों में पड़े हैं, कभी कहीं पड़े हैं, उनका कोई ध्यान देने वाला नहीं है।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो चंबल योजना है बहुत महत्वाकांक्षी योजना इसको सरकार बताती है, जनता को इससे फायदा निश्चित रूप से मिलेगा, पर जब वह पूरी ही नहीं होगी, काम नहीं होगा तो

(श्री घनश्याम)

उसका जनता को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि नादौती सवाई माधोपुर जो चंबल योजना है इसको कब तक पूरा करेंगे और इस बार इसमें कितने बजट का प्रावधान आपने रखा है, यह बताने की कृपा करें।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने चंबल सवाई माधोपुर नादौती वृहत् परियोजना के बारे में जिक्र किया, इसमें घड़ियाल अभयारण्य की एनओसी नहीं मिलने के कारण डिले हुआ है। जैसा कि सदन में यह प्रश्न भी आया था, उसमें मैंने रिप्लाई भी दिया था कुछ उस ठेकेदार की नेग्लीजेंसी समझो या काम धीमी गति से करने के कारण ज्यादा समय लगा है।

यह बात सही है कि नादौती के 59 गांव इसके प्रथम चरण सम्मिलित हैं और 126 गांव और टोडाभीम शहर इस वृहत् परियोजना में सम्मिलित हैं। जब तक वह पानी आए हम सख्ती से लगे हुए हैं, उनके साथ हमने मीटिंग भी की है और जल्दी से जल्दी इस वृहत् परियोजना को कार्य रूप में परिणत करके जल्दी से मीठा पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टोडाभीम शहर क्षेत्र में इन पांच वर्षों में करीब 5 करोड़ 44 लाख के कार्य पूर्ण करवाये गये और करीब 77.34 लाख के कार्य अभी प्रगति पर हैं।

टोडाभीम और उसके आस पास के जो चार गांव हैं, इसमें 21 लाख लीटर प्रतिदिन 70 लीटर प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन के हिसाब से उनको पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है।

इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में भी 13 योजनाएं हैं जो 34 करोड़ 37 लाख की तीन वर्षों में पूर्ण कर दी गई और अभी 23 योजनाएं जो 14 करोड़ 33 लाख की स्वीकृत की है, वह प्रगति पर हैं।

मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि आपके पानी के मामले में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने देंगे और आप लोग अगर मुझे परेशानी के बारे में और बतायेंगे, तो उसके ऊपर निर्देश देकर उनको कार्य रूप में परिणत करवा कर पानी मुहैया कराने का काम करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोपाल कृष्ण।

बीकानेर-सीकर टू-लेन सड़क का डिवाइडर सहित फोरलेन में परिवर्तन

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से आज पर्ची पर बोलने का अवसर मिला है। उसमें मैं बीकानरे से सीकर तक जो सड़क जाती है वह दो लेन की है। दो लेन की होने के कारण से इसमें आवागमन में बड़ी दिक्कत होती है और भीड़भाड़ भी बहुत रहती है। डूंगरगढ़ से सरदारशहर, राजगढ़, दिल्ली का रास्ता भी है। बीकानेर से सीकर 220 किलोमीटर करीब बना है और उसके बाद जयपुर जाने में 115 किलोमीटर और होता है। दिनोंदिन यातायात बढ़ रहा है। नेशनल हाई वे 11 टूरिज्म की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इस पर आजकल इतना ज्यादा जाम लगने लग गया कि बीकानेर सीकर होते हुए राजधानी जयपुर तथा बीकानेर से डूंगरगढ़, सरदारशहर होते हुए राजधानी दिल्ली तक जाता है। दिल्ली व जयपुर दोनों राजधानियों से जुड़े होने के कारण से यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस पर ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल भी खूब चलते हैं।

दिनोंदिन वाहनों का भार भी इस नेशनल हाई वे पर खूब बढ़ रहा है और टूरिज्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण से और भी ज्यादा भार है। मेले मगरियों के समय, जैसे सालासर का मेला लगता है तो इधर रतनगढ होकर जाते हैं। उसके बाद पूनरासर का बीच में मंदिर आता है, वहां जाते हैं तो इतनी भीड़ होती है कि गाड़ियों का घंटे दो घंटे तक जाम लगा रहता है। जाम लगने से लोग चल फिर नहीं सकते हैं।

यह बहुत ही कठिन जगह है। दो लेने से काम नहीं चलता है, वहां वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

लूणकरणसर क्षेत्र में दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं और मैं खास तौर से उन दुर्घटनाओं का जिक्र भी करूंगा, जिसके अंदर हमारे पूर्व विधायक श्री भीमसैन चौधरी का नेशनल हाइवे-11 पर फतेहपुर के पास एक्सीडेंट हुआ और उनका स्वर्गवास हो गया और कोलायत क्षेत्र के सात बार विधायक रहे श्री देवी सिंह जी की धर्मपत्नी कमलेश कंवर जी और सुपुत्र कुंवर रविन्द्र सिंह जी का भी दुर्घटना में निधन नेशनल हाइवे स्थित गुसाईसर के पास हुआ है। यह इसलिए हुआ कि यहां आवारा पशु बहुत बैठ जाते हैं। आवारा पशुओं को

(श्री गोपाल कृष्ण)

रोकने का कोई प्रबंध नहीं है। दो लेन होने के कारण, मैले- मगरियों के कारण से इस पर जाम भी बहुत लगता है। वाहन के आगे आवारा पशु आ गया था, इसलिए इनका एक्सीडेंट हुआ और डेथ हो गई।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी इसी ढंग से एक एक्सीडेंट हुआ है। मैं जब जा रहा था, तब वहां दूसरी तरफ से एक बुढ़िया एक गाय को लेकर आ रही थी। मैंने देखा आ रही है और यह मेरे से टक्कर खाएगी तो मैंने अपनी गाड़ी को बहुत धीरे किया, रोका, लेकिन रोकते-रोकते भी उस गाय का मुंह मेरी विंड स्क्रीन पर लग गया और टूट गया और मेरी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई। बुढ़िया ने कहा कि आपको चलाना नहीं आता और गाड़ी लेकर चला रहे हो। मैंने कहा भई ऐसा क्या हुआ? उसने कहा कि जिस स्पीड से आप चला रहे थे, उसी स्पीड से निकल जाते, तो आप निकल जाते है। वर्ना आपने धीमा किया, हम तो आ ही रहे थे। मैंने कहा तुमने क्यों नहीं रोका? तुम तो रोक लेते। उसने कहा कि हमने देखा कि आप तेज गति से चलते हैं, तो तेज गति से निकल जाएंगे। इस ढंग से गांव वाले कभी रुकते नहीं है और एक्सीडेंट हो जाते हैं।

नील गायों का भी वहां पर बड़ा जोर है। नील गायें आपस में चलती हैं तो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। इस ढंग से दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

अत: डिवाइडर सहित फोरलेन के साथ-साथ सड़क के दोनों ओर आवारा पशुओं को रोकने के लिए भी प्रबंध होना चाहिए।

केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गड़करी जब सूरतगढ़ आए थे तो मैंने उनसे पर्सनली बातचीत की थी और उनसे निवेदन किया था कि बीकानेर से सीकर तक, क्योंकि सीकर से आगे तो जयपुर तक फोरलेन है। तो यहां फोरलेन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। यहां फोरलेन नहीं होने के कारण से एक्सीडेंट भी होते हैं, जाम भी लगते हैं। तो यह नितिन गड़करी जी ने उस समय मेरे से दो बातें कहीं। एक तो यह कहा कि आप राज्य सरकार की ओर से इसका सुझाव भिजवा दें। आप भी लिख दीजिए। मैंने कहा कि मेरे लिखने का तो क्या महत्व है, जब तक राज्य सरकार इसके लिए सुझाव नहीं भेजे तो यह नहीं बन सकता। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप राज्य सरकार से निवेदन कीजिए और हमें भेज दीजिए।

(श्री गोपाल कृष्ण)

तो मेरा आपसे निवेदन है कि NH-11 यातायात, ट्यूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन और सुरक्षा की दृष्टि से भी, क्योंकि बीकानेर भी आपका सीमांत जिला है। यहां से पाकिस्तान की सीमा लगती है। इस दृष्टि से भी यह सुगम बन सके, इसलिए टू-लेन की जगह फोरलेन विद् डिवाइडर और ऐसा प्रबंध करें कि पशुओं का आना-जाना नहीं हो सके। मैं आपका बहुत आभार मानूंगा।

बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस राष्ट्रीय राजमार्ग-11 का जिक्र किया है। यह सीकर से बीकानेर का यह राष्ट्रीय राजमार्ग 237 किलोमीटर का है और 650 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इसका काम 31 मार्च, 2012 को इसका काम अवार्ड हुआ था और जब यह काम अवार्ड हुआ है, उससे पहले इंडियन रोड्स कांग्रेस ने प्रावधान बना रखे हैं कि कौनसी सड़क टू-लेन होगी और कौनसी सड़क फोरलेन होगी। उसमें जो पेसेंजर कार यूनिट है, जिसको हम पीसीयू कहते हैं, उसके आधार पर उन्होंने प्रावधान बना रखे हैं। उस समय जब पीसीयू की स्टडी हुई। माननीय सदस्य बीकानेर की जिस बात को कह रहे हैं, वहां पर 8 हजार 825 था, जबकि इस पर मिनिमम 10 हजार पीसीयू होना चाहिए था। इसलिए इसमें उसको नहीं लिया गया।

चूंकि पहले से ही यह काम अवार्ड हो चुका है और 31 मार्च, 2012 से यह काम चल रहा है। इसलिए अब इस काम में उसको सम्मिलित करना यह संभव नहीं होगा।

फिर भी ये कह रहे हैं, आपने केंद्रीय मंत्री महोदय से बात की है, तो इनकी भावना के अनुसार हम एक पत्र जरूर लिख देंगे, पर चूंकि कंसेशनर इसको बना रहा है और जिस समय स्टडी हुई थी, उस समय पीसीयू पूरे नहीं थे, इसलिए इसको टू-लेन विद् प्राइवेट शोल्डर्स के हिसाब से बनाया गया था।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कंवर लाल।

भामाशाह योजना में पात्र परिवारों को सम्मिलित किया जाना

श्री कंवर लाल (मनोहरथाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने पर्ची के माध्यम से मेरे को बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री कंवर लाल)

मेरा विषय है भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना (बी.एस.बी.वाई.) में पात्र परिवारों को जोड़ने को लेकर है। यह विषय मात्र विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना, झालावाड़ और कोटा डिवीजन का न होकर, पूरे राजस्थान का है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना मुख्य मंत्रीजी ने शुरू की और इसमें पात्र परिवार, राजस्थान सरकार की गाइड लाइन के अनुसार खाद्य सुरक्षा सूची में जो परिवार हैं, उसमें इसको जोड़ा गया है। जो स्मार्ट कार्ड धारक थे, उनको इसमें जोड़ा गया और जो श्रमिक कार्ड धारक हैं, उनको भी इसमें पात्र माना गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से तीनों मंत्री महोदयों को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि खाद्य सुरक्षा में जिनका नाम जोड़ा गया था और सीडिंग के माध्यम से उस साफ्टवेयर में अपलोड किया और कैम्पों के माध्यम से सरकार ने सीडिंग की कार्यवाही की। उस दौरान जो चतुर चालाक व्यक्ति था, उसने अपनी खाद्य सुरक्षा में yes करवा लिया, हां करवा लिया और वह पात्र बन गया। जबकि जो गरीब व्यक्ति है, जो वास्तविक पात्र है। जो मजदूरी करने शहर की तरफ चला गया और वह वहां पर उस समय नहीं मिला तो उसकी सीडिंग नहीं हो पाई और वह जहां शहर में मजदूरी करता है, वहां भी उसका नाम नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब वह बीमार होता है, अस्पताल में भर्ती होता है तो गरीब होने के बाद भी वह वंचित नजर आता है। उसका इलाज स्वास्थ्य बीमा योजना में प्राइवेट और सरकारी अस्पताल फ्री में नहीं करता है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो वास्तविक गरीब परिवार हैं, उनका सर्वे हो और वह जिस जगह काम कर रहा है। उसको वहां पर जोड़ा जाए। जो बड़े-बड़े मकान वाले, ट्रेक्टर वाले, फोरव्हीकल वाले और सरकारी...। कभी-कभी अस्पताल जाने में मौका मिलता है। एक जगह तो हमको देखने में यह तक मिला है कि जो सरकारी नौकरी में है, वह भी आपरेशन कराकर पलंग पर लेटे मिले। उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा हमारा yes है, हम पात्र हैं और अस्पताल वालों को भी उनका इलाज फ्री में करना पड़ा क्योंकि वे पात्र थे। साफ्टवेयर में yes हो रहा था, इसलिए उनका इलाज फ्री करना पड़ा।

(श्री कंवर लाल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह वास्तव में पूरे राजस्थान का मामला है और यह जन-कल्याणकारी योजना है, गरीबों को इलाज में बहुत फायदा होता है। इसका सर्वे कराकर जो पात्र व्यक्ति हैं, उनको जोड़ा जाए।

दूसरा, मेरा आपके माध्यम से श्रम मंत्री जी से निवेदन है कि हमने श्रम कार्ड बनाए और श्रम कार्ड बनाने के बाद वो भी इसमें पात्र माना गया है जो श्रम कार्ड धारक है, वे ऑनलाइन हो चुके हैं। वे चिकित्सा विभाग की डी.एस.पी.वाई. की जो लिस्ट है, उसमें वे जुड़े नहीं हैं और उनका अभी फायदा नहीं मिल रहा है। अस्पताल वालों द्वारा उसकी फाइल अलग से बनाकर डायरेक्ट बीमा कंपनी भेजी जा रही है, जबकि सरकारी सूची में जो नाम हैं, उनका ऑनलाइन भेजा जाता है। उसका सारा हिसाब-किताब ऑनलाइन रखा जाता है।

जो श्रम कार्ड धारी हैं, उनको भी इस लिस्ट में जोड़ा जाए और जो मजदूरी के लिए शहर की ओर पलायन किए हैं और उन लोगों को भी उनके स्थान पर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में जोड़ा जाए, खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जाए।

आपने बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने भामाशाह योजना में पात्र परिवारों को जोड़ने की बात कही है। उपाध्यक्ष महोदय, भामाशाह योजना के अंतर्गत परिवार की परिभाषा में वे सारे लोग शामिल होते हैं जो सम्मिलित परिवार के रूप में रहते हैं। यह सही है कि जब शादी के पश्चात् कोई लड़का वयस्क हो जाता है या परिवार से अलग होता है तो उसकी अलग यूनिट हो जाती है। इसलिए इसमें प्रावधान किया गया है कि ई-मित्र पर जाकर वह आवेदन करके अपना अलग से कार्ड बना सकता है।

यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, जो आपने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए.) में भी पात्रता सुनिश्चित होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में पात्रता के लिए शहरी क्षेत्र में एसडीएम के पास और ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओ के पास प्रावधान

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है। अलग होने वाले परिवारों को इसमें शामिल करने का, अलग यूनिट बनाने का प्रावधान है। इसके और निर्देश दे देंगे अगर कहीं इसमें किसी प्रकार की कमी खामी रही, निर्देश देकर जो अलग होने वाले परिवार हैं उनको एक यूनिट के रूप में इसमें पंजीकृत करेंगे।

(13.00 बजे)

समिति प्रतिवेदन

राजकीय उपक्रम समिति (क्रम संख्या 74 से 92)

श्री उपाध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन, श्री मोहन लालजी गुप्ता।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गये उल्लेख के अनुसार राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

1- राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड़ (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2011-2012) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 का 74वां प्रतिवेदन;

2- राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड़ (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2012-2013) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 का 75वां प्रतिवेदन;

3- राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन एवं प्रसारण निगम लिमिटेड़ तथा जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2012-2013) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 का 76वां प्रतिवेदन;

4- राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन एवं प्रसारण निगम लिमिटेड़ तथा जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2013-2014) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 का 77वां प्रतिवेदन;

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

5- राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड़ (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2013-2014) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 का 78वां प्रतिवेदन;

6- राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड़ (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2013-2014) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 का 79वां प्रतिवेदन;

7- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड़ (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2013-2014) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 का 80वां प्रतिवेदन;

8- राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड़ (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2013-2014) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 का 81वां प्रतिवेदन;

9- राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड़ (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2002-2003) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2012-2013 के 96वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 का 82वां प्रतिवेदन;

10- राजस्थान वित्त निगम(अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2006-2007) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2012-2013 के 100वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 का 83वां प्रतिवेदन;

11- राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड़ (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1994-1995) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2013-2014 के 110वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 का 84वां प्रतिवेदन;

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

12- राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड़ (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2010-2011) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 के 30वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 का 85वां प्रतिवेदन;

13- राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड़ (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2010-2011) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 के 32वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 का 86वां प्रतिवेदन;

14- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड़ (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2009-2010) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 के 37वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 का 87वां प्रतिवेदन;

15- बाड़मेर लिग्नाईट खनन कम्पनी लिमिटेड़ (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2010-2011) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 के 38वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 का 88वां प्रतिवेदन;

16- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड़ (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2011-2012) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 के 41वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 का 89वां प्रतिवेदन;

17- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2011-2012) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 के 42वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति,

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

2016-2017 का 90वां प्रतिवेदन;

18- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2012-2013) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 के 45वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 का 91वां प्रतिवेदन; एवं

19- राजस्थान वित्त निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2010-2011) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 के 59वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 का 92वां प्रतिवेदन।

श्री उपाध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री घनश्याम।

याचिका

नादौती में राजकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए उल्लेख के अनुसार दो याचिकाओं, विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के उपखण्ड मुख्यालय नादौती में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने बाबत एवं

गढ़मोरा में गौशाला निर्माण

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के उपखण्ड मुख्यालय नादौती की ग्राम पंचायत करवाये जाने बाबत याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुरेन्द्र पारीक।

जयपुर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में उर्दू साहित्य

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र हवामहल (जयपुर) वन विहार स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

उर्दू साहित्य ऐच्छिक विषय स्वीकृत करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मनोज कुमार।

राजगढ़ में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर (जिला-चूरू) के उपखण्ड मुख्यालय राजगढ़ में राजकीय महिला महाविद्यालय खोले जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शुभकरण चौधरी। एक मिनट विराज जाएं। मैं समस्त सदस्यों को यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी आज इस बजट के वाद विवाद पर बोल रहे हैं, आपको 15 मिनट से ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। तो लिमिटेशन इज 15, जैसे ही 15 मिनट होंगे, आटोमेटिकली दूसरे का नाम हम कॉल कर लेंगे।

सूचना

श्रम विभाग की बंद वैबसाइट

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इनफोरमेशन। श्रम विभाग की तरफ से जो कार्ड पहले आफ लाइन बन रहे थे फिर ऑन लाइन करे जाते थे, अभी 17 में उनका आर्डर निकाल दिया, सरकार की तरफ से, इसे ऑन लाइन बनाए जाएंगे। अब वह वेबसाइट पिछले दस दिन से बंद है, छात्र-छात्राएं बहुत परेशान हैं। श्रम विभाग की वेबसाइट खुल नहीं रही है। कृपया करके सरकार की तरफ से, 31 तारीख पाबंद कर दी गई कि 31 मार्च तक ही बनेंगे तो इस तारीख को बढ़ाएँ और वेबसाइट को खोला जाए जिससे बच्चों को छात्रवृति का लाभ मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शुभकरण चौधरी।

आय-व्ययक

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 8 मार्च, 2017 को इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा आने वाले साल में राजस्थान के विकास का ढांचा कैसा होगा, क्या हम लोगों ने पिछले साल

(श्री शुभकरण चौधरी)

किया, जनता की अपेक्षाओं के अनुसार सारा लेखा-जोखा सदन में रखने के बाद बहुत से मित्रों ने इसकी सराहना भी की। कुछ लोगों ने अपने हिसाब से इसे कुछ अपने शब्दों में भी परिभाषित किया। मैं आपसे मात्र इतना कहना चाहता हूं कि पहली बार राजस्थान का किसान माननीय मुख्य मंत्री द्वारा रखे गए इस बजट से इतना खुश है, संतुष्ट है। पहली बार किसान को लगता है कि वाकई सरकार ने किसानों की चिंता की है। किसानों को समर्पित यह बजट है। लोग चाहे अपने किसी भी शब्दों में इन चर्चाओं को करें, पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि किसान कलेवा जैसी योजना, राजीव गांधी कृषि योजना, पहले किसान को 50 हजार रुपये मिला करते थे, उसके बाद एक लाख रुपया, पहली बार राजस्थान की सरकार ने राजीव गांधी कृषि योजना में दो लाख रुपये किसान को देने का काम करने के बाद दो हजार किसानों को 26 करोड़ 22 लाख रुपये बांटे गए हैं।

राजस्थान सरकार ने 2016-17 मण्डी यार्ड और सड़क निर्माण के कार्यों में 310 करोड़ 13 लाख रुपये खर्च किए हैं। राजस्थान की सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले मण्डी श्रमिक कल्याण योजना 2015 के द्वारा प्रसूति सहायता, पुत्री विवाह के लिए 20 हजार रुपये का अनुदान देना, छात्रवृत्ति और चिकित्सा जैसी सहायता प्रदान करने का काम किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना, राजस्थान के कई भू भाग जो डार्क ज़ोन होते जा रहे हैं वहां का जल स्तर ऊँचा लाने के लिए एक अनूठी पहल की शुरूआत राजस्थान की सरकार ने की है। 13 हजार 946.42 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि इससे सिंचित होने का काम होगा। 44 हजार 380 जल संग्रहण ढांचों का निर्माण कर 53 हजार 182 किसानों को इससे लाभ मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मानव के स्वास्थ्य की चिंता करना। कई सरकारों ने इस बात का काम भी किया है, पर पहली बार कोई सरकार है जो प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना के साथ-साथ पशुओं का बीमा करती है, जमीनों के रख रखाव की चिंता करती है। पशु पालन में 70 प्रतिशत अनुदान उस बीमा प्रीमियम में एससी, एसटी, ओबीसी, बीपीएल परिवारों को, 25 प्रतिशत अनुदान सामान्य पशुपालकों को देकर राजस्थान की सरकार ने एक इतिहास रचा है।

(श्री शुभकरण चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय, पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत 313 प्रगतिशील किसानों को कुल 42 लाख 30 हजार रुपये की राशि पारितोषिक रूप में दी गई है। ग्लोबल राजस्थान एग्रो मीट, एक ऐतिहासिक पहल करके किसानों को यह बात समझाने की कोशिश की है कि हमारे मेलों में आकर आप क्या-क्या फायदा उठा सकते हैं। अपनी कृषि को कैसे उन्नत कर सकते हैं, किस प्रकार उन्नत नस्ल के पशु आप पाल सकते हैं, यह काम भी हमारी सरकार ने किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, 2016-17 के दौरान खाद्यान्न का उत्पादन कुल 213 लाख 12 मीट्रिक टन होने की संभावना है। 2015-16 में 182 लाख 98 हजार मीट्रिक टन की तुलना में 16.47 प्रतिशत हमारी पैदावार बढ़ी है। सरसों के मामले में तो हम आत्मनिर्भर ही नहीं हिन्दुस्तान में दूसरे नम्बर पर आने लगे हैं। कल एक चर्चा भी थी कि सरसों के तेल के उत्पादन के लिए हम विदेशों में निर्यात करने की स्थिति में आने वाले हैं। मैं भी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की फैक्ट्रियों को लगाया जाए ताकि सरसों का उत्पादन करके हम लोग सरसों के तेल का निर्यात भी कर सकें।

सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण सूचंकाकों में, वर्ष 2016-17 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार स्थिर कीमतों और 5 लाख 17 हजार 815 करोड़ रुपये के अनुमानित किए गए, वर्ष के 15-16 में 4 लाख 85 हजार 646 करोड़ रुपये का उत्पाद करके 6.42, 62 प्रतिशत अधिक की उपलब्धि हमने अर्जित की है।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले पांच साल लगातार कांग्रेस की सरकार में, प्रधानमंत्री सड़क योजना जो मृत प्राय: हो गई थी, बंद हो गई थी उन सड़कों को बनाकर हमारी सरकार ने 1480 बसावटों को जोड़ा है। 825 करोड़ रुपये की लागत से 5 हजार किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई हैं जो एक इतिहास है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ग्रामीण गौरव पथ जिसकी बहुत बढ़-चढ़कर चर्चा भी हुई है। एक ऐतिहासिक पहल हमारी सरकार ने ग्रामीण गौरव पथ के रूप में शुरू की है और शहरों में भी गौरव पथ बनाकर एक ऐतिहासिक काम की शुरुआत की गई है। मैं सरकार से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि शहरी गौरव पथ बनाए जा रहे हैं उनमें यूटिलिटी शिफ्टिंग करने का काम सरकार अपने स्तर पर करे या विभागों से करे क्योंकि ढाई

(श्री शुभकरण चौधरी)

करोड़ रुपये में जो सड़क बनने वाली है, कई शहरों में ऐसा होता है कि बहुत से पैसे उनकी यूटिलिटी शिफ्टिंग में ही लग जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से मित्रों ने इस बजट को अपने हिसाब से, यह भी बताया कि सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार लोगों को मात्र प्रलोभन देती आई है, सरकार ने सिर्फ वादे किए हैं, काम कुछ नहीं किया, मैं इतना कहना चाहता हूं कि असत्य कहूं तो लफ्जों का दम घुटता है, सच कहूं तो लोग खफा हो जाते हैं।

पर मैं लोगों को खुश रखने के लिए उनके अनुसार बोलूं। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि पहली बार सरकार ने ऐसी ऐतिहासिक शुरुआत की है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देते- देते, 50 साल से हम लोग सुनते आ रहे हैं। पहली बार कोई सरकार है जो वाकई बेटी को बचाना चाहती है। मेरे झुन्झुनूं जिले में 852 के लिंगानुपात से शुरू करके सरकार के सुनहरे प्रयासों के माध्यम से आज 997 का लिंगानुपात है। हमने तय कर रखा है, केन्द्र की सरकार ने झुन्झुनूं जिले को सम्मानित भी किया है। वहां हमने तय कर रखा है कि सरकार की जो मदद मिल रही है बेटी पैदा होने के दिन से, सरकार मदद कर रही है ढाई हजार रुपये, प्रसव होने के बाद, मां के गर्भ के पैदा होते ही, बेटी के जन्मदिन पर ढाई हजार रुपया और बेटी कॉलेज पढ़ने जाती है तब तक 50 हजार रुपया सरकार बेटी के मां के खाते में जमा कराती है, ऐतिहासिक पहल की वजह से राजस्थान में बेटियां पैदा होने लगी हैं। बेटियां विकसित होने लगी हैं, बेटियां पढ़ने लगी हैं, बेटियां सुरक्षित हैं। यही कारण है कि आज लिंगानुपात बढ़ता जा रहा है। पहली बार बेटियों को 90 प्रतिशत अंक लाने पर स्कूटी देने जैसी योजना, गार्गी योजना में 75 प्रतिशत अंक लाने पर उनको 3 हजार, 5 हजार रुपये देकर, एक-एक लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है उससे बेटियों की पढ़ाई हो रही है।

मैं एक बात बताना चाहता हूं कि शिक्षा के ढांचे को सुधारे बिना किसी देश का विकास नहीं हो सकता। 70 साल में पहली बार, मैं राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हम राजस्थान में गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारा एक भी उच्च माध्यमिक विद्यालय ऐसा नहीं है जिसमें प्रिंसिपल नहीं हो।

(श्री शुभकरण चौधरी)

एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें प्रधानाध्यापक नहीं हो। इस प्रयास की वजह से आज स्कूलों का अनुशासनिक ढांचा और शैक्षणिक ढांचा इतना सुधरा है कि आज बच्चों का नामांकन बढ़ा है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की चर्चा करूं, झुंझुनूं जिले में पढ़ने वाले 13 हजार नामांकनों में से 07 हजार नामांकन अकेले उदयपुरवाटी में बढ़ा है। उस पहाड़ी क्षेत्र का इतना विकास होता जा रहा है, लोग सरकारी स्कूलों में भरोसा पैदा करने लगे हैं। बच्चे पढ़ना चाहते हैं। इस काम के लिये सरकार की सराहना, मैं उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं कि सरकार ने ऐसी योजना शुरू करके बच्चों को पढ़ाने का काम किया है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से पहली बार सरकार दावे के साथ कहती है कि हम घर-घर में बल्ब जलाएंगे, घर-घर में कनेक्शन देंगे। दो लाख कृषि कनेक्शंस की घोषणा करके सरकार ने तय किया है कि 2010 में डार्क जोन घोषित होने से पहले-पहले जिन विधान सभा क्षेत्रों में डार्क जोन घोषित हुआ है, उनके समस्त किसानों के कनेक्शन कृषि के कर दिये जायेगे और उनके घरों में भी बिजली का काम करके लाइट्स लगा दी जाएंगी। शहरों के अन्दर एल.ई.डी. लाइट लगा कर हम लोगों ने बिजली को बचाने का काम किया है, वह भी बहुत सराहनीय काम है।

डोडा-पोस्त की लत छुड़ाकर पहली बार सरकार ने समर्पण के भाव से लोगों को नशे से मुक्त कराने की जो योजना बनाई है, जो शिविर लगाये हैं उन शिविरों के माध्यम से भी बहुत से लोगों को इसका फायदा हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री राजश्री योजना में 03 लाख 16 हजार 66 बालिकाओं को लाभान्वित तो किया गया है, पर एक निवेदन है कि पूर्व में एक योजना थी जो शादी के बाद पात्र लोगों के बेटे-बेटियों को पैसा मिलता था, उसमें शायद कहीं न कहीं कोई दिक्कत आई है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार जब तक बेटियां 18 साल की हमारी योजना के बाद हों नहीं, तब तक होने वाली पात्र परिवारों की बेटियों को शादी के बाद जो पैसा मिलता था, वह उसी प्रकार मिलता रहे, इस बात के लिये मैं सरकार से सिर्फ निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री शुभकरण चौधरी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जगह-जगह पानी की योजनाओं के बारे में बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और माननीय मुख्य मंत्री महोदया से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि झुंझुनूं-तारानगर क्षेत्रीय कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना में पिछली बार पिछले बजट में डी.पी.आर. बनाने के लिये उदयपुरवाटी और सूरजगढ़ का नाम प्रस्तावित किया गया था। उसकी डी.पी.आर. बन चुकी है, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से सरकार की मुखिया से निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुरवाटी, सूरजगढ़ और बुहाना में, जहां भूमि का बिलकुल सतही पानी सूख गया है, वहां उस योजना की वित्तीय स्वीकृति भी जारी करवाने का काम करेंगी।

सोलर वाटर पम्प सैट, पीने के पानी में सिंगल पाइण्ट जहां-जहां भी लगाये हैं, वहां इतनी परेशानी आई है कि सिंगल पाइण्ट का लोग बिल जमा नहीं कराते, सरकार के यहां प्रावधान नहीं है, पर सोलर वाटर पम्प जो हमने लगाये हैं, मैं हमारी पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि एक अनूठी योजना है, आप इसको अनवरत चलाएं। जो पहले नौ-नौ, दस-दस सिंगल पाइण्ट के ट्यूबवैल आपने एक-एक विधान सभा क्षेत्र में खोदने का वादा किया था उसमें कुछ कमी की है। उस बजट को बढ़ा कर, आप भले थ्री-फेस न लगाएं, पर उन सिंगल पाइण्ट्स को सोलर पम्प के माध्यम से लगा कर, एक-एक पंचायत मुख्यालय पर भी अगर एक-एक राजस्व ग्राम में इसकी व्यवस्था कर दी जाए तो लोगों के पीने के पानी का समाधान होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो प्रधान मंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिससे बहुत से लोगों को अच्छा फायदा मिल रहा है, उसमें लोगों से इस बात को भी बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार प्रधान मंत्री बीमा सुरक्षा योजना में कम प्रीमियम भर कर बीमा किया जाता है, उसी प्रकार जो पशुओं का बीमा किया जाता है, उसमें 50 प्रतिशत सामान्य किसानों के लिये रखा गया है, उसको भी 70 प्रतिशत किया जाए ताकि लोगों के पशुओं का बीमा हो सके और कम प्रीमियम पर पशुओं का बीमा किया जा सके।

(श्री शुभकरण चौधरी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में करीब 25 हजार उचित मूल्य की दुकानों में से प्रथम चरण में 5800 दुकानों को अन्नपूर्णा भण्डार में खोलकर राजस्थान की सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल की है। बिना भेदभाव के पहली बार पांच हजार स्कूलों को एक साथ क्रमोन्नत करना एक ऐतिहासिक पहल है, राजस्थान की सरकार इस बात के लिये धन्यवाद की पात्र है। झुंझुनूं जिले की वालीबॉल अकादमी में दो करोड़ रुपये का प्रावधान करके और वित्तीय स्वीकृति जारी करके सरकार ने जो हमें मदद की है, उसके लिये मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 2016 तक 308 करोड़ 84 लाख रुपये बी.पी.एल. परिवारों के लिये खर्च किया गया था, जिसमें जीवन रक्षा कोष में दिसम्बर, 2016 तक 49 लाख 18 हजार रोगियों को लाभान्वित किया गया है। जननी सुरक्षा योजना, शुभ लक्ष्मी योजना के तहत 242 करोड़ 33 लाख की राशि ऑन लाइन ट्रांसफर करके भ्रष्टाचार को खतम करने की कोशिश की है। पहले बहुत से मित्र पूछते थे कि यह डी.बी.टी. क्या होती है। बहुत लोगों ने इस बात की चर्चा की। आज पहली बार राजस्थान का आदमी, पूरे देश का आदमी यह कह सकता है कि डाइरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से केन्द्र की सरकार एक रुपया भेजती है तो पूरा का पूरा रुपया पात्र व्यक्ति के खाते में पहुंचता है। सालों तक लगातार यह चर्चाएं होती आईं। कांग्रेस के प्रधान मंत्री तक ने यह बात कही कि एक रुपया हम दिल्ली से भेजते हैं तो 15 पैसे पात्र व्यक्ति के पास पहुंच पाते हैं और 85 पैसे रास्ते में रह जाते हैं। इस काम का निवारण हमने किया। हमारी सरकार ने डाइरेक्ट पात्र लोगों के बैंक खातों में पैसा भेजने का काम किया। पूरे राजस्थान का एक-एक व्यक्ति इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता है। मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं कि व्यक्ति जब काम करता है तो अपने आप जनता उसको धन्यवाद देती है। 11 तारीख की चर्चाएं जो लोग कर रहे थे, 11 तारीख को हम आपको यह बताएंगे, वह बताएंगे, नोटबंदी, नोटबंदी, नोटबंदी की वजह से पता नहीं क्या हो जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, वे लोग जो नोटबंदी की चर्चाएं कर रहे थे, जो 11 मार्च के

(श्री शुभकरण चौधरी)
सपने देख रहे थे, एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय जनता ने हमें दिया है और लोगों ने कहा है, जनता ने हमें कहा है कि हमने, 'हमको जमाने ने बसा रखा है दिलों में अपने, हम किसी हाल में बेघर नहीं होने वाले', ये जो सूरज लिये कंधों पर फिरा करते थे कल तक, ये मर भी जाएं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जैसे नहीं होने वाले। यूं ही थोड़ा सा वक्त बचा है डेढ-एक साल का, गुजर जाने दो यारों, यकीन करो बीते हुए जमाने तुम्हारे कभी नहीं आने वाले''।

मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान ही नहीं, हिन्दुस्तान की जनता नोटबंदी से खुश है। हिन्दुस्तान की जनता भारतीय जनता पार्टी के द्‌वारा किये गये निर्णयों से खुश है। इस बात की मुहर इस देश की जनता ने लगाई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड का जनादेश इस बात को कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करना चाहती है। किसान को समर्पित है और किसान के लिये काम कर रही है। इस बात का जनादेश आने के बाद एक-एक, इस बात में कोई दो राय नहीं कि हम लोगों का जिम्मा बढ़ा है, हमें काम करना है। पांच साल लगातार पिछली बार घोटालों की सरकार, कभी पनडुब्बी घोटाला, कभी बोफोर्स घोटाला, कभी चारा घोटाला, कभी कोयला घोटाला, कभी भूमि घोटाला, कभी खनिज घोटाला, तो कभी सीमावर्ती जमीनों को बेचने का घोटाला। घोटलों की इतनी लम्बी फ़ेहरिस्त पांच साल में की कि हालात आपके ऐसे हो गये। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, लगातार सरकार ऐतिहासिक विकास के काम कर रही है, जनता उसको इस बात के लिये धन्यवाद भी दे रही है। जनता अपना सहयोग भी दे रही है, अपना समर्थन भी दे रही है।

मैं सरकार से इतना सा निवेदन करना चाहता हूं, एक ऐतिहासिक योजना, स्किल डवलपमेंट, एक ऐसी अनूठी पहल सरकार की, छोटे-छोटे बच्चे आठवीं क्लास से ग्यारहवीं क्लास तक स्कूल में पढ़ने जाते हैं, ग्यारहवीं क्लास पढ़ने के बाद बेटियों की मां कहती है, आगे पढ़ाएँ कैसे, पैसा नहीं है। पहली बार सरकार ने इस बात का चिंतन किया है कि अलग से आई.टी.आई. करा कर बेटियों को पढ़ा नहीं सकते। आठवीं से ग्यारहवीं क्लास, तीन साल

(श्री शुभकरण चौधरी)

के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार अध्ययन के साथ-साथ बेटियों को ब्यूटी पार्लर का काम, ब्यूटीशियन का काम और अनेकों प्रकार से, बेटों को इलेक्ट्रिशियन का काम, इलेक्ट्रोनिक्स का काम, बाइंडिंग का काम, इस प्रकार के कौशल आजीविका मिशन के माध्यम से स्किल डवलपमेंट के ऐसे काम सिखाये जाते हैं। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में, धन्यवाद देना चाहता हूं सरकार को कि 12 स्कूल नये खोले थे उनमें से छह स्कूलों के अन्दर आज कौशल आजीविका मिशन का सब्जैक्ट पढ़ाया जा रहा है। बेटे आठवीं, नवीं क्लास से पढ़-पढ़ कर ग्यारहवीं क्लास में जब वे अपना सर्टिफिकेट लेकर बोर्ड की परीक्षा पास करके निकलेंगे तो उनके हाथ में हुनर होगा। लोग कहते हैं आपने 15 लाख नौकरियों का वादा किया था। हमने वादा किया था लोगों को नौकरियां देने का नहीं, लोगों के हाथ में हुनर देने का। हम लोगों को नौकर नहीं बनाना चाहते। हम लोगों को इस प्रकार का हुनर देना चाहते हैं कि वह 15 लाख लोग लोगों को नौकर रखें। वे दुकानें खोलेंगे, वे फैक्ट्रियां खोलेंगे, वे मोटर बाइंडिंग की शॉप खोलेंगे। कोई बेटी ब्यूटी पार्लर का काम करेगी और उन दुकानों पर नौकर रखेगी। 15 लाख नहीं, 50 लाख लोगों के हाथ में हुनर देंगे और वे कौशल आजीविका मिशन से कमा कर खाएंगे। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

हम लोगों को आत्म निर्भर बनाना चाहते हैं। हम उन लोगों को इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि 'ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए बीच में वह संकल्प नहीं होता। असफलता को भविष्य में भी, मैं मेरे मित्रों से कहना चाहता हूं कि असफलता को भविष्य में भी लक्ष्य से दूर ही रखना दोस्तों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता', जो कि हमारे पास है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोशिश करूंगा कि आपके निर्धारित समयावधि में मैं अपनी बात कह सकूं लेकिन लगता असंभव-सा है, फिर भी कोशिश करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जब बजट पर चर्चा हो रही है, उस समय हमने दोनों तरफ से, मैं यह लगातार कोशिश करता हूं कि सदन में

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
बैठूं या सदन के बाहर बैठूं, मैंने बहुत अच्छी तरह से यह चर्चा सुनी और मैं आज यह कहने के लिए कि राजस्थान का पहला बजट जब 1952 में 23 फरवरी को स्वर्गीय श्री नाथूरामजी मिर्धा ने पेश किया था वह 16 करोड़ और 32 लाख का बजट था और आज जब यह बजट पेश किया है तो 1.66 लाख करोड़ का बजट है। इन 67 साल में इस सदन ने इतना बड़ा जो काम किया है उसमें यह कहना कि सत्ता-पक्ष तीन साल पूर्ण निष्क्रिय था या यह कहना कि प्रतिपक्ष ने पांच साल में कुछ भी नहीं किया, मैं इन दोनों बातों से सहमत नहीं हूं। किस ने कम किया, किस ने अधिक किया लेकिन एक बात से मैं सहमत हूं कि इस सदन में सबसे कम निष्क्रिय और निष्प्रभावी प्रतिपक्ष है और पूर्ण निश्चिंत सत्ता-पक्ष है, एक तो बजट के अभिभाषण का यह सार है।

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब अपन बजट में चर्चा करें तो आज हम किस स्थान पर खड़े हैं राजस्थान, उसकी चर्चा हो और उसको देखने में कितनी प्रकार की कैसी मदद हमारी सरकार ने की है, वह हमारे लिए बहुत आवश्यक है। राजस्थान का परिदृश्य अगर हम सम्पूर्ण देश की परिधि में देखें कि इन 67 साल में जो 1952 के बाद राजस्थान का क्रम शुरू हुआ, हम कहां खड़े हैं तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें जो पुस्तक मिली है, बजट का सारा विश्लेषण आर्थिक राजस्थान की, उसी के आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं।

दशकीय वृद्धि जो जनसंख्या की हुई है वह भारत की 17.7 है और राजस्थान की 21.3 है। इसी प्रकार लिंगानुपात जो है वह भारत का 943, एक हजार व्यक्तियों में 943 है और राजस्थान का 928 है। बाल लिंगानुपात जो बच्चे-बच्चियां हमारी इस समय हैं छह साल की आयु के उनमें देश का अनुपात है 919 का और राजस्थान का 888 का है। अभी झुन्झुनूं से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, मैं समझता हूं कि इन आंकड़ों में और उनमें फर्क है। यह भी सरकार के दिये हुए आंकड़े हैं और आप जो बता रहे थे, वह भी सरकार के दिये हुए आंकड़े हैं। साक्षरता दर देश की 73 परसेंट है और हम 66 परसेंट पर है। साक्षरता महिलाओं की दर 64.6 परसेंट देश की है और राजस्थान की 52.1 परसेंट है। जन्म दर जो बच्चे मरते हैं जन्मते

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
ही, देश में 20.8 है मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर देश में 37 परसेंट है और हमारे यहां पर 43 परसेंट है। मातृ मृत्यु दर हमारे यहां 37 परसेंट, देश में 37 परसेंट है और हमारे यहां 43 प्रतिशत है। मातृ मृत्यु अनुपात में मातृ मृत्यु अनुपात 167 भारत में है और 244 हमारे यहां पर है। इन बातों को इस बजट में जितना डील किया गया है, उसके ऊपर बजट की सारी बात निर्भर करती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अब जब चर्चा हो रही थी, हमारे माननीय सदस्य भी कर रहे थे कि यह रिजल्ट कैसे आ गये? मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा वैसे तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, साहित्य में एक शब्द है पृष्ठ-प्रेषण, उसका अपने यहां पर अर्थ होता है कि पीसे हुए को ज्यादा नहीं पीसना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी वैसे पिसी हुई है इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं पीसना चाहता, पृष्ठ-प्रेषण नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले हम किसको एड्रेस करें और जब यह 70 साल की बात होती है देश की स्थिति की तो उस स्थिति का चिंतन करना इस सदन को आवश्यक है। जब हम बारबार कहते हैं कि 70 साल में क्या हुआ तो उसका एक परिणाम यह है कि सर्वप्रथम गरीबी हटाओ का नारा स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था और नारा देकर उन्होंने बहुत बड़ा जबरदस्त जन-समर्थन हासिल किया, राजाओं का प्रीवीपर्स समाप्त किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और गरीब के हित की बात करने लगे लेकिन बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद क्या गरीबों का कल्याण हुआ इस देश में? तो अभी-अभी जो आंकड़े प्रकाशित हुए हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनको देखकर लगेगा कि गरीबों का विकास नहीं, इसके बाद अमीरों का विकास हुआ है।

भारत दुनिया का पहला देश है, दूसरा, जिसमें गरीब और अमीर का फर्क सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा रूस का है और दूसरे नम्बर पर भारत का है। भारत की कुल सम्पदा जो है विश्व बैंक के अनुसार, 54.8 परसेंट सम्पदा एक परसेंट व्यक्ति के हाथों में केंद्रित हो गयी। भारत के 68.8 परसेंट जो किसान हैं, उनके पास केवल 8 परसेंट सम्पत्ति है और 50 परसेंट जो भारतीय हैं, वह 2.5 परसेंट भारत की सम्पदा में गुजारा करते हैं और

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

यह एक परसेंट जो कॉरपोरेट लोग हैं, यह कॉरपोरेट जागीरदारी जो पैदा हुई है, वह बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद सारी बैंकों का कर्जा उनके पास जाना और इसके कारण से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इस देश में जबरदस्त माहौल पैदा हुआ। उसमें प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी निकले। अभी यह उत्तर-प्रदेश की चर्चा कर रहे थे। मैं बताना चाहता हूं कि लोगों पर असर कैसे पड़ता है। कई बार बैठे-बैठे हम सोच लेते हैं, काम होता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री मुद्रा योजना जो 2015-16 में प्रधान मंत्रीजी ने शुरू की। उत्तर-प्रदेश में 33.5 लाख लोगों ने 12275 करोड़ रुपये का लोन उससे लिया, उत्तर-प्रदेश में। दूसरा, 2016-17 में 28.6 लाख लोगों ने 10755 करोड़ का लोन कोलैटरल फ्री लोन उन्होंने लिया।

उत्तर-प्रदेश में चार करोड़ जन-धन खाते खोले गये, उत्तर प्रदेश में जिसमें 2.5 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में थे। जन-धन खातों में सीधे लाभ सब्सीडी भेजी गयी और दस लाख से अधिक लोगों को 12 रुपये में सुरक्षा बीमा योजना से उत्तर-प्रदेश को जोड़ा गया और उत्तर-प्रदेश में 52 लाख घरों में नए एल.पी.जी. कनेक्शन पहुंचाये गये। यह जब जन-धन खाते खोले गये ....(व्यवधान)....

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह यू.पी. में ही हुआ क्या? पंजाब में नहीं हुआ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, यह यू.पी. में हुआ। पंजाब में भी हुआ। ....(व्यवधान).... आप सुनो भैया, मैं इनको निपटा दूंगा आप तो निपटा ही रहे हो।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह जो योजनाएं हैं, उस योजना में प्रधान मंत्रीजी को गरीबों के प्रतीक के रूप में मान लिया राष्ट्र की जनता ने और आप लोगों ने उसका विरोध किया और इसका परिणाम था कि जन-धन खाते में शून्य पर खाता खुलवा दिया, शून्य पर खाता खुलवा दिया तो आपने गरीब की मजाक उड़ाई और लोगों ने कहा कि हम आज तक बैंक के दरवाजे पर नहीं जा सकते थे, हमारे पास रुपये नहीं है तो क्या हम बैंक में खाता नहीं खुलवा सकते? जब यह नोटबंदी हुई और फिर आया कि 47 हजार करोड़ रुपये जन-धन खातों में जमा है तो फिर गरीबों की मजाक उड़ाई गयी।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

फिर बाद में आया कि 24 करोड़ खाते हैं, 1500 रुपये से ज्यादा किसी खाते में नहीं है, वह भी भारत सरकार के भेजे हुए खाते हैं, उसमें कौनसा काला और गोरा धन हो गया? तो यह बातें जब जहां तक जाती हैं उन बातों तक हम नहीं जाते तब तक हम आम जनता को एड्रेस नहीं करते, इसको मैं कहना चाहता हूं और हमारे यहां पर जो अब सारे काम की स्थिति है, उसके बारे में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा।

यहां पर यह बजट की पहली स्टेज है। पहली स्टेज में जब हम चर्चा करते हैं तो यह पहला काम है जिस पर बहस नहीं होती, वोट नहीं पड़ता, बजट के अभिभाषण पर और आज पहला दिन है जब माननीय राजेन्द्रजी राठौड़ यहां पर उपस्थित नहीं हैं क्योंकि उनको पता है कि आज मैं इस पर, वोट नहीं है और घनश्याम बोलने वाला है तो मेरे रहने की आवश्यकता भी नहीं है। आज उनके नम्बर कम हो जाएंगे। आज है नहीं वह।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी, वित्तीय स्थिति की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो कि बहुत जरूरी है। 2014-15 में हमने पूंजीगत प्राप्तियां 22251 करोड़ रुपये सोची थी और पूंजीगत खाते का व्यय 26039 करोड़ रुपये का सोचा था लेकिन उसमें 3888 करोड़ रुपये का घाटा रहा और संशोधन स्थिति जो रही वह 29546 करोड़ रुपये बचे और पूंजी खाते में 25223 करोड़ रुपये खर्च हुए। अधिक 4322 करोड़ रुपये यानी, हमको जो डवलपमेंट का काम करना था पूरा वह 4322 करोड़ रुपया हमारी ब्यूरोक्रेसी पैसा होने के बाद भी खर्च नहीं कर सकी। दूसरा, फिर हम आये 2015-16 में 26526 करोड़ रुपये हमने कहा, प्राप्तियां देखी, व्यय 26978 करोड़ रुपये सोचा और घाटा 382 करोड़ रुपये का, संशोधित स्थिति रही 30684 करोड़ रुपये प्राप्त हुए और 25433 करोड़ रुपये व्यय हुए और 5251 करोड़ रुपये हमारे पास फिर बच गये।

इसी प्रकार तीसरे वर्ष में, 2016-17 में प्राप्तियां हमने तय की 27 हजार 986 करोड़ रुपये और व्यय हुए 28 हजार 75 करोड़ रुपये और घाटा 118 करोड़ रुपये का। संशोधित स्थिति रही कि हमारे पास 32 हजार 90 करोड़ प्राप्त हुए और 23 हजार 240 करोड़ रुपये खर्च हुए और पूंजी खाते में 8 हजार 849 करोड़ रुपये हमारे पास बचे। इस प्रकार 2014-15 में 3 हजार

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
888 करोड़ का घाटा और 4 हजार 332 करोड़ का आधिक्य रहा। वर्ष 2015-16 में 332 करोड़ का घाटा, जबकि 5 हजार 251 करोड़ का आधिक्य रहा। कुल मिलाकर पूंजी खाते में तीन वर्ष में प्राप्तियां अधिक रहीं और खर्च कम हुआ। यह गंभीर स्थिति की ओर इंगित करता है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी किस ढंग से काम करती है। उपाध्यक्ष महोदय, इसको हर स्थिति में देखा जाना चाहिए।

इसी प्रकार राजस्व की स्थिति रही। राजस्व में जो भी हमने मांगा, जो स्थिति हमने की, राजस्व का भी हमारा काम ऐसा रहा तो कुल-मिलाकर मैं यह कह सकता हूं कि राजस्व खाता पूंजी खाता जिनको अभी राजस्व व्यय को और इसको मुख्य मंत्रीजी ने एक साथ करने की बात कही है। इसका अगर हम विश्लेषण करें तो हमारा राजकोषीय घाटा 3.37 इस साल रहेगा, जो एफ.आर.बी.एम एक्ट की सीमा के बाहर जा रहा है, उसको नियन्त्रित करना हमारे लिये बहुत आवश्यक है। उसके बिना आप विकास के कार्यों पर खर्च नहीं कर सकते हैं।

इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो हमारा बजट है, इस बजट में हमने इतना खर्चा किया, लेकिन कुछ समस्याएं हैं जिनकी ओर हमको ध्यान देने की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। राजस्थान राज्य में कुछ काम ऐसे हैं जिनको हमको हर हालत में करने पड़ेंगे। जब हमारी नई सरकार आयी तो राजस्व खाते में हमने एक लाख छह हजार करोड़ रुपये सोचे थे, राजस्व व्यय एक लाख पांच हजार करोड़ रुपये और राजस्व आधिक्य 737 करोड़, लेकिन खर्चा हमारा ज्यादा हुआ और राजस्व प्राप्तियां 91 हजार 445 करोड़ और खर्च 90 हजार 272 करोड़। राजस्व प्राप्ति कुल मिलाकर तीन साल में अगर अपन देखें तो हमारा राजस्व खाता था उसमें प्रथम वर्ष में चार हजार करोड़ का, द्वितीय वर्ष में पांच हजार करोड़ और तृतीय वर्ष में सात हजार करोड़ रुपये का रेवेन्यू कलेक्शन कम हुआ हमारा, जो हमने सोचा था। रेवेन्यू कलेक्ट मंत्री नहीं करता, मुख्य मंत्री नहीं करते। रेवेन्यू कलेक्ट और उसका आंकड़ा ब्यूरोक्रेसी हमको देती है और ब्यूरोक्रेसी ही कलेक्ट करती है। यह कर संग्रहण में जो कमी हुई है, इस कमी के लिये कौन जिम्मेदार है? प्रथम वर्ष में चार हजार करोड़, द्वितीय

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
वर्ष में पांच हजार करोड़ और तृतीय वर्ष में सात हजार करोड़, यह जो कम कलेक्शन हमारा हुआ है, उसी के कारण से राजकोषीय घाटे का असंतुलन हमारे सामने हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, हम 200-500 करोड़ के नये टैक्स लगाते हैं, कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि 30-35 परसेंट गुना टैक्स हम वसूल नहीं कर पाते। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ एक है कि हम सब सोचें कि पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय, राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय और वित्तीय घाटा, इन तीनों चीजों को हम नियन्त्रण नहीं कर पाएंगे तो हम जो काम सोचते हैं, वह काम हम नहीं कर पाएंगे। इसलिये हमको यह काम करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कई चर्चाएं हुईं, उन चर्चाओं में ज्यादा नहीं जाकर, क्योंकि समय की पाबन्दी है, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। आज सुबह भी चर्चा हुई मेरे पास एक जवाब भी आया हुआ है। मेरा प्रश्न पी.डब्ल्यू.डी. के डाक बंगलों के बारे में पूछा था। सरकार ने पी.डब्ल्यू.डी. के डाक बंगलों के बारे में मुझे यह जवाब दिया है कि 12 डाक बंगलों को सरकार ने पी.पी.पी. मोड पर देने का तय कर लिया है। मेरे पास यह जवाब है। 12 डाक बंगलों का तय किया है। दूसरा मैंने एक और प्रश्न पूछा था उसका भी जवाब आया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम ट्रस्टी हैं, जन-प्रतिनिधि ट्रस्टी है, मालिक नहीं है। भगवान राम जब वनवास में गये तो भरत को राज देकर गये थे। भरत ने भगवान राम की खड़ाऊ रखकर 14 वर्ष तक राज किया था और राम आये तो राम को वापस सौंप दिया। यह सारी सम्पदा राजस्थान की जनता की है और भरत की जैसे खड़ाऊ है, उस खड़ाऊ की तरह से राज को हमको संरक्षण करना है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह समझाओ इनको।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पहले आपको समझाना जरूरी है, क्योंकि काम तो आपका ही बंटाधार किया हुआ है न।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हम तो हमारे घर बैठे हुए हैं, इनको समझाओ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इनको समझाऊं ताकि बैठे नहीं। ये यही बैठे रहें, ठीक है न। मेरे लिये तो कोई दूसरी बात सोचो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था ऐसे ही प्रश्न का जवाब माननीय गजेन्द्र सिंह जी ने दिया। यह जो माहौल बनाया जा रहा है, सरकार को इस माहौल को क्लियर करना चाहिये। चाहे हमारे अभयारण्य के बारे में हो, चाहे डाक बंगलों के बारे में हो, चाहे पी.एच.सी., सी.एच.सी. के बारे में हो, चाहे राजस्थान स्टेट रोडवेज के बारे में हो, जिसको अभी क्लियर किया है कि हमने एक हजार नई बसें खरीदी हैं। यह सरकार का मन्तव्य साफ आ जाना चाहिए कि हम ट्रस्टी हैं और ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त के अनुसार हम चलते हैं।

'भू से ले अम्बर तक यह जल, कभी न मिटने वाला,

यह प्रकाश, यह पवन, कभी भी नहीं सिमटने वाला।।'

यह जो चीजें हैं जो प्रकृति ने हमको दी हैं, वह हमारे पूर्वजों की हैं और आगे आने वाली पीढ़ी की हैं। हम उसके मालिक नहीं हैं। यह डेमोक्रेसी का, ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त है और इस डेमोक्रेसी के, ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त को हमको मानकर चलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने जो काम किये, हम यहां तक आ गये। राजस्थान में मैं नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के राज में यह प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना नहीं बनती तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के राज में तो आज हम वहां तक नहीं पहुंचते। अगर सर्व शिक्षा अभियान नहीं चलता तो हम वहां तक नहीं पहुंचते और मनरेगा की भी मैं प्रशंसा करता हूं कि मनरेगा नहीं पहुंचता तो हम लोगों को वहां तक काम नहीं दे पाते। यह हम सब लोगों ने मिलकर काम किया है, लेकिन आज स्थिति बदल गयी है और आज बदली हुई परिस्थितियों में काम करना है देश में भी और राज्य में भी, वह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

आज विश्व में आर्थिक न्याय की लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। आज हम ऋणी हैं। इस कर्ज से केवल किसान को ही मुक्त नहीं होना है। किसान को इस कर्ज से जो मुक्त करने की बात प्रधान मंत्रीजी ने कही कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमण्डल की पहली मीटिंग में हम किसान का कर्जा माफ करेंगे। यह

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
उन्होंने कहा, उसका कारण है। किसान को इस स्थिति में पहुंचाने के लिये हमारी आर्थिक नीतियां जिम्मेदार रही हैं, इसलिये किसान का कर्ज माफ करना उस पर दया करना नहीं है। किसान का कर्ज माफ उसका राइट है। मैं बार-बार कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार बड़ी इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव दिया जाता है 60 हजार करोड़ रुपये का, उसी प्रकार से किसान को प्रतिवर्ष कर्ज नहीं, खेती करने के लिये इंसेंटिव दिया जाना चाहिए, यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यह हमारे प्रधान मंत्री ने कहा है कि 60 हजार का इंसेंटिव हम बड़ी इंडस्ट्रीज को देते हैं, लेकिन किसान के बारे में चिंतन नहीं करते।

उपाध्यक्ष महोदय, देश की कुल सम्पदा का 58.4 प्रतिशत एक प्रतिशत लोगों के पास है, थाइलैंड में 58 प्रतिशत है, ब्राजील में 47.9 प्रतिशत है, चीन में 43.8 प्रतिशत है और भारत में 58.4 प्रतिशत सम्पदा एक प्रतिशत लोगों के पास है। यह इतने साल की गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करो, यह सारा काम गरीब के नाम पर करके अमीरों के घर में पैसा भरने का काम कांग्रेस सरकार ने किया, इसका परिणाम यह हुआ और इसके बाद में जो काम किये, वह मैं बताना चाहता हूं। दुनिया में, और राजस्थान का जहां तक सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, हम तीन बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। सबसे पहली समस्या रोजगार की है। रोजगार उपलब्ध कराना हमारी आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। दूसरा काम बिजली का है और तीसरा काम कर्ज माफी का है। इन तीनों कामों के लिये तीन साल में जो काम किये, वह सरकार ने आपके सामने रखे हैं। लेकिन, मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हमने ढांचागत भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया तो हमारा काम ठीक नहीं होगा।

आज गुड गवर्नेन्स है लेकिन क्या रजिस्ट्री के दफ्तर में जाने वाला आदमी, सरकार ने रजिस्ट्री का शुल्क कम कर दिया लेकिन रजिस्ट्रार के यहां जाने वाला आदमी क्या बिना पैसे के आज भी रजिस्ट्री करा नहीं पा रहा। क्या आर.टी.ओ. के दफ्तर में जाने वाला आदमी सुशासन समझ पा रहा है? क्या अन्य किसी स्थान पर जाने वाला आदमी यह जो ढांचागत भ्रष्टाचार है, इस ढांचागत भ्रष्टाचार पर सरकार को कठोरता से प्रहार करना पड़ेगा।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

यह स्थिति वैसी ही है, एक आदमी ने मुझे यह बताया, कल मैं तैयारी कर रहा था, उसने कहा, तिवाड़ी जी, आप मन्दिर में जाते हो कि नहीं? मैंने कहा, गया हूं, जाता ही हूं, मेरा काम ही यही है। तो उन्होंने कहा, एक बड़े मन्दिर का नाम बताया मेरे को, मैं नाम नहीं बता रहा हूं, कि आप वहां जाओ। क्या होगा? बोले, पहले तो आप जाकर देवता की पूजा करो और उसको भेंट चढ़ाओ। चढ़ा देंगे। उसके बाद बाहर आओ तो यह टीका काढ़ने वाला आदमी बाहर बैठा रहता है, वो कहे टीका कढ़ाओ, तो टीका कढ़ाया, तो उसको भी भेंट देनी पड़ती है। उसके बाहर आए तो एक पांख लिये हुए आदमी रहता है, कि सर पर पांख रखाओ, तो पांख के लिए भी पैसा देना पड़ता है, उसके आगे जाओ तो चरणामृत देने वाला रहता है, तो चरणामृत लो उसको पैसे चढ़ाओ और उसके आगे आओ तो नगाड़ा बजाने वाला रहता है, उसको दो और नगाड़ा बजाओ। सरकारी कई दफ्तरों की वैसी हालत हो रही है। ...(व्यवधान)...

सुनो भाई। यह एक दिन का, हमारी सरकार का काम नहीं है, इस व्यवस्था में से पैदा हुआ है। इसलिए इस ढांचागत भ्रष्टाचार की व्यवस्था पर अगर हम प्रहार नहीं करेंगे, उसके बारे में कोई काम नहीं करेंगे तब तक हमारा सारा किया हुआ काम वो उस हद तक उस आम आदमी के पास नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार ढांचागत भ्रष्टाचार पर प्रहार करने की कोशिश करे। उसके लिए नियमों में परिवर्तन करे, व्यवस्था में परिवर्तन करे। जब परिवर्तन करेंगे तो यह पैसा ठेठ तक पहुंच जाएगा।

दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि रोजगार का जहां तक सवाल है, सरकार की नौकरियों में 15 लाख रोजगार देना, यह किसी सरकार के बस की बात नहीं है। आज चार लाख या पांच लाख सरकारी कर्मचारी काम कर रहे होंगे तो 15 लाख नये सरकारी कर्मचारी ...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): घोषणा तो नहीं करें न फिर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बता रहा हूं न घोषणा क्यों करी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): धोखा दिया न?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, की न।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, करी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मानों इस बात को तो, आप तो मानो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, मान रहा हूं न तो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): धोखा दिया न? ...(व्यवधान)... वो नहीं बोलोगे। घनश्याम जी, आज बोलो, खुल कर बोलो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, बोल रहा हूं न, बैठो तो बोलूं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): धोखा दिया न?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नियम है, बैठ जाओगे तो बोलूंगा। धोखा खाया क्यूं?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): धोखा खा लिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, 15 लाख रोजगार की बात कही गयी थी और रोजगार अगर देश में देना है तो नौकरियों के माध्यम से नहीं होगा। नौकरियों में भी देना आवश्यक है। हमने नौकरियों में भी रिकार्ड किया था जब पिछली बार सरकार में थे तो 1 लाख 18 हजार को तो केवल शिक्षा में हमने नियुक्त किया था, आज जितने भी टीचर बचे वो हमारे सब के सब हैं। पुलिस में भर्ती की थी। अभी भी सारी भर्तियां हैं लेकिन अभी जो सारी भर्तियां हैं, मैं यह कहना चाहता हूं वो इस आरक्षण के विवाद के कारण से वो आज सारी कोर्टों में, उपाध्यक्ष महोदय, रुक गयी है।

मैं विनम्र शब्दों में आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार तुरन्त इस आरक्षण की समस्या का समाधान निकाले। इसमें हम को हाथ फेर कर काम नहीं करना पड़ेगा, इसमें मैं साफ-साफ सुझाव देना चाहता हूं कि 50 परसेंट की सीमा के बाहर जाने के लिए हम को राजस्थान की विधान सभा में अधिकतम आरक्षण की अधिकतम सीमा अधिरोपण कानून बनाने के बारे में यहां विचार कर के कानून पेश करना चाहिए कि 68 परसेंट हम करेंगे और 32 परसेंट हमारा खुला रहेगा और इसको हम को सर्वसम्मति से लागू करना चाहिए।

आज जिन-जिन लोगों ने आन्दोलन किया वो सारे के सारे लोग किसी न किसी प्रकार के आन्दोलन में हैं और उन आन्दोलनों का गलत असर पड़ता है, सारी बातें उनसे दब जाती हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि रोजगार के सारे जो न्यायालय में रुके हुए रोजगार हैं वो भी एक समस्या है। हमने

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

प्रस्तुत किया था कि राजस्थान लोक सेवा आयोग से परीक्षा करा कर 600 से अधिक रिट याचिकाओं को समाप्त करा कर नियुक्ति की थी लेकिन धीरे-धीरे पिछली सरकार ने इसको बढ़ाने का काम शुरू किया, उससे लेकर आज तक यह बढ़ती जा रही है। इसलिए दूसरा काम रोजगार का है।

तीसरा, कर्ज माफी की जो बात है उसके बारे में जिस प्रकार की उत्तर प्रदेश में योजना बनती है उस प्रकार की योजना बनाने का काम हमारी सरकार भी करे।

सोलर एनर्जी पर हम ध्यान देने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि 40 हजार मेगावाट का जो दो लोगों से समझौता किया था वो समझौता परिपूर्ण नहीं हुआ है। हम को किसानों के माध्यम से, किसान को पार्टनर बना कर, प्रवाह का काम तो सरकार कर ही रही है, प्राइवेट पार्टी भी कर रही है तो प्रवाह का काम कर रही है इसलिए हमको प्रवाह का काम कर के किसान को पार्टनर बना कर सोलर एनर्जी अधिक से अधिक पैदा करने का काम हम करें।

एक, उपाध्यक्ष महोदय, अंत में कहूंगा। आप ऊपर से यूं देख रहे हैं, मैं समझ रहा हूं। आपका तो मैं बॉडी लेंग्वेज से समझ जाता हूं कि मुझे कब खतम करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि सोलर एनर्जी के बारे में तुरन्त हमको कोई न कोई निर्णय करना चाहिए और उसको अधिक से अधिक बढ़ावा देकर हम बिजली फ्री करने की बात करें। हमारे 13 लाख कनेक्शन हैं, 80 हजार करोड़ रुपये जो हम इनका कर्जा अपने सिर पर ले रहे हैं, इतनी सब्सिडी हम दे रहे हैं तो एक लाख करोड़ में तो आधे से ज्यादा सोलर पम्प हम लगा सकते हैं। अगर यह लगा देंगे तो हर साल का खर्चा भी नहीं आएगा और इससे मुक्त भी हो सकेंगे।

पानी की बहुत बड़ी बात है लेकिन मैं नहीं कहूंगा। एक अंतिम बात मेरे विधान सभा क्षेत्र की कह कर समाप्त करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां सांगानेर में दो बड़े काम अभी रुके हुए हैं, मेरे पास सरकार का जवाब आया है, एक सीवरेज का और एक पेयजल का। यह पृथ्वीराज नगर से लेकर सारे काम जो मन्जूर किये हैं उनमें पेयजल का हमारा काम बाकी है। सरकार ने मन्जूर भी किया, 60 हजार करोड़ रुपये

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जमा भी कराया लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि सांगानेर की जितनी भी बची हुई कॉलोनियां हैं और जयपुर शहर की 1400 कॉलोनियां जो बची हुई हैं, जिनमें पेयजल नहीं हैं उनको हम तुरन्त पी.एच.ई.डी. के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराएं। और दूसरा, 1440 करोड़ की पृथ्वी राज नगर की और सारा जो हमारा इलाका है, उसकी स्कीम पास होकर आ गयी थी और भारत सरकार से मन्जूरी आ गयी थी। मन्जूरी आने के बाद में जयपुर विकास प्राधिकरण ने राज्य सरकार को लिखा कि अगर इसकी गारंटी दे देंगे तो हम निश्चित रूप से यह सीवरेज लाइन डाल देंगे, राज्य सरकार ने वापस जे.डी.ए. को लिख दिया कि राज्य सरकार गारंटी नहीं देगी, इसका कोई दूसरा विकल्प तलाश किया जाए। वो विकल्प मिला नहीं, मिला नहीं तो फिर दोबारा जे.डी.ए. ने प्रस्ताव बना कर भेजा। अब पुन: राज्य सरकार ने भारत सरकार को 1440 करोड़ की जयपुर के बचे हुए हिस्सों में जो सीवरेज लाइन है उसका प्लान भेजा है, मैं आग्रह करूंगा सरकार से कि जयपुर का सीवरेज का जो बची हुई कॉलोनियां हैं, 1440 करोड़ की जो योजना है वो भारत सरकार से जल्दी मन्जूर कराएं, उसको लागू कराएं।

इसी प्रकार पृथ्वीराज नगर सहित बाकी बचे हुए सांगानेर विधान सभा क्षेत्र के प्रताप नगर, पृथ्वी राज नगर, गोवर्धन नगर, सारी कॉलोनियां जो पेयजल से वंचित हैं, वहां की जो स्कीम सरकार ने मन्जूर की है उसको लागू कराएं ताकि जयपुर शहर में पूरे में सीवरेज और पानी की व्यवस्था हो सके। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल जी जीनगर।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बजट भाषण पर बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका आभार।

राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी के द्वारा 8 मार्च, 2017 को राजस्थान की विधान सभा में राजस्थान की खुशहाली का चौथा बजट रखा गया है, निश्चित रूप से इस बजट से राजस्थान का चहुंमुखी विकास होगा, इसमें कोई संशय नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने लगातार बजट पेश कर के शिक्षा, सड़क, रोजगार, स्वास्थ्य, स्वच्छता, बिजली, पानी, औद्योगिक विकास,

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)
कौशल विकास, जल स्वावलंबन के अन्दर इस बजट को समर्पित किया है और इस बजट के माध्यम से यह प्रदेश आगे बढ़ेगा। सरकार की मुखिया ने हमेशा यह प्रयास किया है कि राजस्थान एक खुशहाल प्रदेश बने। इसके तहत हम सब मिल कर के प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।

पिछली सरकारों ने राजस्थान को बीमारू प्रदेश बना दिया और विकास के काम ठप्प कर दिये, राजस्थान एक अंधकार और निराशामय भाव में चला गया। वसुन्धराजी पिछली बार आज के तीन साल पहले सुराज संकल्प यात्रा का संकल्प लेकर के मैदान में उतरीं। तब से लगा कर के आज तक राजस्थान नई ऊंचाइयां छू रहा है और राजस्थान की जनता ने वसुन्धरा जी को अपने हाथों में बागडोर सौंपी है और इसी के तहत यह राजस्थान प्रदेश आगे बढ़ रहा है।

मुख्य मंत्री महोदया की पहली प्राथमिकता है आर्थिक आधारभूत संरचना को ठीक करना और बिजली, पानी और सड़क को सुदृढ़ करना। वहीं सामाजिक, आर्थिक संरचना जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, रोजगार के नए अवसर प्रदान करना एवं राजस्थान को आकर्षक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करना भी है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार कृषि और पशुपालन है। कृषि और पशुपालन को मजबूत करके इस प्रदेश को आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके साथ-साथ आपदा प्रबंधन भी सुनिश्चित किया जाए। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने पिछली बार जो किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ था, इसके तहत करोड़ों रुपयों का किसानों को फसलों का मुआवजा देकर के, आर्थिक सहायता देकर के उनको मजबूत करने का काम किया। राजस्थान खुशहाल बने, इस अवधारणा को लेकर के प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। प्रदेश विकास के पथ पर आगे चल रहा है। हमारी सरकार ने आर्थिक आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए सड़कों का काम हाथ में लिया है। इस प्रदेश को अच्छा सड़क तंत्र देने का काम किया है। प्रत्येक गांव में अच्छी सड़क हो, उसके लिए ग्रामीण गौरव पथ के निर्माण करने का काम किया। समस्त ग्रामवासी आज इस बात को ध्यान में रखते हैं कि हमारे गांवों में भी शहरों के मुकाबले की सड़कें बनी हैं।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी लगभग 50 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर गौरव पथ बने हैं। इससे लोगों में खुशी की लहर है। सरकार ने नॉन पेचेबल सड़कों को भी ठीक करने का काम किया है। मिसिंग लिंक सड़कों का काम किया है। राज्य की प्रमुख सड़कों को चौड़ा करने का काम किया है। सीआरएफ के माध्यम से, नाबार्ड के माध्यम से सरकार सड़कों का जाल बिछाने का काम कर रही है। जब सड़क तंत्र सुदृढ़ होगा तो आवागमन के साधन अच्छे होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ ही हमारी मुख्य मंत्री महोदया को और सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे क्षेत्र में पिछले बजट में 77 करोड़ की 55 किलो मीटर लंबी सड़क देकर के बहुत अच्छा काम किया है। वह सड़क भोपाल सागर से नारेला, धार्मिक तीर्थ स्थल मातृकुंडिया को जोड़ रही है। यह बहुत ही अच्छी सड़क बन रही है। इसके साथ ही सीआरएफ के माध्यम से और सरकार के मद से कपासन के आरोई, कीरकी चौकी से फतेहगढ़ वाया आकोला बन रही है। जिसके टेंडर लग चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ धार्मिक क्षेत्र की सड़कें भी मेरे इलाके में हैं। इन सड़कों को बनाने की महती आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि आरोई से लगाकर के सांवरिया जी तक सड़क बने। उससे मातृकुंडिया धार्मिक स्थल जुड़ेगा, दिवानाशाह दरगाह कपासन जुड़ेगी, शनि महाराज आली जुड़ेंगे और सांवरिया जी तक यह सड़क पहुंचेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण गौरव पथ के साथ-साथ जो सड़कें मिसिंग लिंक में बननी हैं, उनका काम भी चल रहा है। मैं इस अवसर पर हमारे यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री अटलजी को याद करना चाहूंगा कि उन्होंने गांव और ढाणी को सड़कें दिलाने का काम किया। पहले गांवों में सड़कें नहीं होती थी। उन्होंने प्रधानमंत्री स्वर्ण चतुर्भुज योजना के द्वारा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के द्वारा गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक सड़कें पहुंचाने का काम किया है। फोर लेन सड़कें बनी हैं। ईस्ट-वैस्ट कॉरीडोर सड़कें बनी हैं। मैं चाहूंगा कि जो सड़कें पहले की बनी हुई हैं, उनको चौड़ा करने का काम भी हम करेंगे तो अच्छा रहेगा।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में बनास नदी बहती है। वहां बजरी का दोहन होता है। पत्थरों का दोहन होता है। वहां पहले बनी हुई सड़कें कमजोर थी। वह टूट चुकी हैं। बनास नदी के किनारे बजरी और पत्थरों का दोहन होने वाली सड़कों को पुन: बनाकर के उनका जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता है। यह हमारी वह सड़कें हैं जहां पर खनिज के ट्रक अधिक चलते हैं, हमीरगढ़ से गंगापुर वाया राश्मी, चंदेरिया-बोरदिया-रुंद-भीमगढ़-लांगचसिंहपुर-सुरपुर-बासोड़ा यह बड़ी सड़क है। कपासन-गुमानपुरा-शनि महाराज-बासोड़ा की सड़क है। रोलिया-बबराणा-भूपालसागर-आकोला, यह जो बड़ी-बड़ी सड़कें हैं, जहां पर माइनिंग की ट्रकें चलती हैं। इनको भी अच्छी कराने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने पेयजल के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। मुख्य मंत्रीजी को हमारे इस प्रदेश में भूमिगत जल स्तर गिरने के कारण चिंता हुई और उन्होंने मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन अभियान प्रारंभ करके हमारे क्षेत्र में जगह-जगह छोटे नाड़ी, नालों को रोककर के और चैक डैम बनाकर के धरती को रिचार्ज करने का काम किया है। इसी योजना के तहत आज हमारे क्षेत्र के अंदर अच्छी बरसात हो रही है और भूमिगत जल स्तर भी बढ़ा है।

हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में पेयजल व्यवस्था के लिए हैंड पंप, सिंगल फेस बोर मोटर, सोलर पंप, जेजेवाई स्कीम और कई योजनाएं प्रारंभ कर रखी हैं। सरकार 55,650 गांव, ढाणियों को पेयजल उपलब्ध करा चुकी है। सरकार इन 3 वर्षों में 13,473 करोड़ रुपए पेयजल पर व्यय कर चुकी है। जो पिछली सरकार से दुगुना है। हम पेयजल के लिए बहुत चिंतित हैं। शुद्ध पेयजल मिलेगा तो बहुत ठीक रहेगा।

मेरे क्षेत्र में फ्लोराइड ज्यादा है। उसके कारण से लोगों के दाँत काले पड़ रहे हैं। लोग कूबड़े हो रहे हैं। मैं चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र के बीच में घोसुंडा डैम बना हुआ है। उस डैम के माध्यम से अतिरिक्त पानी को राश्मी, कपासन, भूपाल सागर, भदेसर, चित्तौड़, गंगरार इन तहसीलों के समस्त गांवों को इस बाँध के द्वारा पानी उपलब्ध कराकर के संयुक्त पेयजल योजना बनाने की आवश्यकता है। हमारी पूर्व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री किरण जी

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

माहेश्वरी ने मेरे क्षेत्र कपासन की योजना का नवीनीकरण करने की घोषणा की थी, लेकिन वह अभी फाइलों में अटकी हुई है। सिंचाई और जलदाय मंत्री के बीच में पानी के रिजर्वेशन को लेकर के काम पूरा नहीं हो रहा है। मैं चाहूंगा कि यह काम जल्दी से जल्दी पूरा हो। इसी तरह से तत्कालीन मंत्री जी ने बामनिया, ताणा, पारी, आकोला, बासोड़ा, सिंगपुर की पेयजल योजनाओं की भी घोषणा की है। मैं चाहता हूं कि इन योजनाओं को भी अतिशीघ्र पूरा किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने जो काम ऊर्जा के क्षेत्र में किया है, वह 'भूतो न भविष्यति' है। हमारे इस बिजली निगम को मजबूती प्रदान करने के लिए, घाटे को पूरा करने के लिए 62,421 करोड़ और 96 लाख रुपये का ऋण राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण करके इनको जीवनदान दिया है। इसी प्रकार से प्रसारण एवं वितरण तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए कई बिजली के सब स्टेशन बनाकर के इसको ठीक करने का काम किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि अगर बिजली तंत्र सुदृढ़ होगा तो किसानों के लिए बहुत अच्छा होगा। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने आगामी 2 वर्षों में 1 लाख कृषि कनेक्शन देने की जो घोषणा की है, उससे किसानों में खुशी की लहर है। इससे हर खेत को पानी मिलेगा और हर हाथ को काम मिलेगा। इसी प्रकार से किसानों को कृषि कनेक्शनों में जो सहायता दी जा रही है, 7500 करोड़ रुपए का जो कृषि अनुदान दिया जाता है, वह आगामी वर्ष में बढ़कर के 8500 करोड़ का हो जाएगा। इसी तरह से इस वर्ष 400 केवी के 2, 220 केवी के 6, 132 केवी के 15 और 33 केवी के 200 नये सब स्टेशन बनाने की घोषणा की है।

(14.00 बजे)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश और प्रदेश कृषि प्रधान है, इसके अंदर कृषि और पशुपालन के आधार पर किसान काम करता है। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने आधुनिक तकनीक के माध्यम से खेती हो सके इसके लिए राजस्थान की राजधानी जयपुर में ग्लोबल राजस्थान एग्रो मीट का आयोजन

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

करके, पूरे राजस्थान से 56 हजार किसानों को बुलाकर उस मीट में भाग लेने का अवसर दिया। इस मीट में कई देशों और प्रदेशों के प्रतिनिधि भी आए और इसमें किसानों को नई चीज सीखने को मिली। 53 लाख किसानों की खरीफ की फसल का बीमा किया, पहले बीमा होता था लेकिन कोई जानकारी नहीं थी लेकिन इस बार प्रधान मंत्रीजी ने फसल बीमा योजना लागू करके किसानों की फसलों को, किसानों को नया जीवन देने का काम किया है। इसी प्रकार खरीफ की फसल में 53 लाख किसानों की खरीफ की फसल का बीमा किया गया और रबी की फसल के लिए 30 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जल स्वावलम्बन योजना के द्वारा और बीज में भी किसानों को आत्म निर्भर बनाने के लिए मुख्य मंत्री बीज स्वावलम्बन अभियान प्रारम्भ किया है इससे निश्चित रूप से हमारे राजस्थान में अधिक मात्रा में अच्छे बीजों की उपलब्धता हो सकेगी। इस वर्ष किसानों के लिए 3156 करोड़ 61 लाख रुपए का प्रावधान किया है जो एक कीर्तिमान है। मैं यह चाहूंगा कि जब किसान के बारे में चर्चा होती है तो इस सदन के अंदर लोग नहीं होते हैं, जबकि किसान ही एक ऐसा व्यक्ति है जो देश और प्रदेश के आर्थिक ढांचे को मजबूत करने का काम करता है और जब किसान की बात होती है तो सदन के अंदर बहुत कम माननीय सदस्य रहते हैं। मैं बार-बार क्षेत्र में भी यही बात कहता हूं कि आप जब भी जनप्रतिनिधि को भेजो तो कम से कम किसान की बात कर सके तब तो जाकर आपका उस व्यक्ति को भेजना सार्थक होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि किसान ही एक ऐसी कौम है, इस राजस्थान को मजबूती प्रदान करनी है और इस देश को मजबूत बनाना है तो किसान की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्रीजी, वसुन्धराजी ने बहुत बड़ा काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शेखावत साहब को, जिन्होंने 1993 में एक घोषणा की थी, तब गुलाबचन्दजी कटारिया शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने एक आदेश में कहा, ग्राम पंचायत मुख्यालय की

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)
समस्त स्कूलों को हम आठवीं तक करने की घोषणा करते हैं, और वह आठवीं तक हो गई। मुझे आज भी याद है कि एक स्कूल खोलनी होती थी तो लोगों के जूते घिस जाते थे नेताओं के घरों पर घूम-घूम कर, लेकिन एक आदेश से ऐसा होने लगा है। पिछली बार वसुन्धराजी आईं, ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर एक आदेश से दसवीं के स्कूल हो गए। इस बार वसुन्धरा जी ने घोषणा की कि बारहवीं तक के स्कूल प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर खोले जाएंगे। इस प्रकार से शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से बालिका शिक्षा को भी बढ़ावा मिला है। मैं यह तुलना करना चाहूंगा कि यही देश, मेरे इसी देश में केरल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में हमसे बहुत आगे है और राजस्थान 60 साल केरल के मुकाबले में पीछे है। हमारी शिक्षा को पीछे करने का काम किया है वह कांग्रेस पार्टी ने किया है। मैं चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी कोई कसर छोड़ने वाली नहीं है, 37 हजार शिक्षकों की भर्ती की और 86 हजार शिक्षकों को पदोन्नति देने का काम किया है, यह भूतो न भविष्यति। इतना बढ़िया काम उन्होंने किया है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा कार्ड बनाकर गरीब व्यक्ति को इलाज के लिए दर-दर की ठोकरें खानी नहीं पड़े इसके लिए सबसे बड़ा कदम उठाया गया है। मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। एक और बड़ा काम किया है, जो भूतो न भविष्यति, श्रमिक कल्याण योजना। श्रमिक कल्याण योजना इतनी महत्ती आवश्यकता थी, हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने इसको लागू करके प्रदेश में बता दिया कि मजदूरों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मजदूर के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हमेशा रहेगी। इसके तहत उन्होंने डिलीवरी पर पैसा देना, पढ़ाई पर पैसा देना, श्रमिक के बच्चे का ट्रेनिंग में नम्बर आए तो पैसा देना, बीमारी पर पैसा देना, आवास का पैसा देना, दुर्घटना पर पैसा देना, घायल पर पैसा देना, सामान्य मृत्यु पर पैसा देने का काम किया है। मैं यही निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने राज्य के विकास का बजट पेश किया है, हम उस बजट के साथ

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

क्षेत्र में जाकर इस काम को करने का काम करेंगे। निश्चित रूप से राजस्थान हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है और हर चुनौती का सामना करते हुए यह प्रदेश आगे बढ़ेगा, किसी ने कहा है, माना कि अँधेरा घना है लेकिन दीया जलाना कहां मना है, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नवीन पिलानिया।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आपने मुझे मौका दिया। साथ में एक निवेदन भी करना चाहता हूं क्योंकि आप उदारमना हैं, मेरा जो दल है, उसे बड़ी पीड़ा और अफसोस है कि उसे मौका नहीं मिला गवर्नर के अभिभाषण पर एक सैकिण्ड की भी बात रखने का। कांग्रेस विपक्षी दल के बाद में सबसे बड़ा दल मेरी पार्टी का है जिसमें एक दलित महिला है, एक अनुसूचित जन जाति की महिला है, पार्टी के नेता अनुसूचित जनजाति से है और मैं ओबीसी, पिछड़े वर्ग से आता हूं। दो तिहाई प्रदेश की जनता को रिप्रजेंट करते हैं, आप जैसे उदारमना रहे हैं, तीन सदस्यों पर ऐसे ही आपसे उपेक्षा चाहता हूं, बहुत मेहरबानी है आपकी ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 'उपेक्षा' नहीं, 'अपेक्षा'।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): हां, अपेक्षा, वही, वही।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपने 'उपेक्षा' मांगी है।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): 'उपेक्षा' नहीं है, आपने तो शुरू में ही टोकाटाकी शुरू कर दी, अभी तो मैं आया ही नहीं मुद्दे पर। माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी भी पधार गये हैं, मैं उनका बिलकुल स्वागत करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात इस चीज से चालू करना चाहूंगा कि अब का जो अभिभाषण था महामहिम राज्यपाल महोदय का, मुझे बड़ा थका हुआ, हारा हुआ सा प्रतीत हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का इकबाल और सरकार का जो रुतबा है, वह जो शेर का चिन्ह है इसी से प्रतीत हो जाता है, आप सब देख सकते हैं, यह पिछले साल का है, यह इस साल का है, यह नया लगता है, इसका चिन्ह अपने आप ही बोलता

(श्री नवीन पिलानिया)
है, इस बात पर आऊँगा कि क्या कारण रहा कि इस पिछले साल में सरकार के पास गिनाने के लिए कोई उपलब्धियां ही नहीं थी या कोई कार्य नहीं किए क्योंकि यह पिछले साल की तुलना में 75 पन्ने थे, 41 पन्ने में सिमट गया, 41 पन्ने में। अब मैं सीधा आता हूं क्योंकि मैं जानता हूं मुझे समय बड़ा सीमित मिलेगा। इस साल का बजट पेश हुआ, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लाखों करोड़ का बजट हुआ, उसकी परिकल्पना आने वाले साल में कैसी होगी, उसके लिए पिछले साल में क्या हुआ उसको देखना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से बताना चाहूंगा कि सबसे पहले राजस्थान का किसान ही नहीं, पूरे देश का किसान बदहाली पर है और विशेष तौर पर राजस्थान में। मैं सीधा कृषि पर आता हूं, कृषि विभाग वर्ष 2016-17 में जो प्रावधान थे विभिन्न योजनाओं में उनके अनुसार दिसम्बर माह तक क्या स्थिति है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, एलोकेशन था 323 करोड़ का, खर्च हुआ 39 करोड़, केवल 12 प्रतिशत, राष्ट्रीय कृषि विस्तार तकनीक मिशन, 75.58 करोड़, खर्च हुआ 16 करोड़, माननीय, 21 प्रतिशत।

राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन 39 करोड़ एलोकेशन है, 9 महीने में 1 करोड़ 90 लाख खर्च हुआ है। 5 प्रतिशत खर्च हुआ है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पीएमकेएसवाई, 484 करोड़ का प्रावधान है, खर्च हुआ है महज 95 करोड़ रुपया। कृषि मंत्री आज यहां नहीं है, हार्टिकल्चर कहां पीछे रह जाएगा, जब कृषि विभाग का यह हाल है। हार्टिकल्चर में, जो नेशनल हार्टिकल्चर मिशन है, 96 करोड़ का प्रावधान है, 33 करोड़ रुपया खर्च होता है। पूरे हार्टिकल्चर को जोड़ लें तो 445 करोड़ में केवल 119 करोड़ ही खर्च हुआ। यह हाल उस कृषि का है जिसको लाखों-करोड़ों के बजट से केवल 5 प्रतिशत मिलता है। उस 5 प्रतिशत में भी एनिमल हजबेंडरी भी जुड़ी हुई है। आप अचम्भा करेंगे उसमें डेयरी भी जुड़ी हुई है, उसमें सहकारिता भी जुड़ी हुई है और उसके अंदर फोरेस्ट व वाइल्ड लाइफ भी घुसी हुई है। उस 5 प्रतिशत का भी यह हाल है।

अब मैं जरा आपको यह बताना चाहता हूं कि जो ईयर वाइज रिवाइज प्लान आउटले कृषि का था, माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, जरा इस

(श्री नवीन पिलानिया)

पर गौर फरमाएं। आप भी अचम्भा करेंगे, 2014-15 में कृषि का रिवाइज आउटले 4127 करोड़ था, खर्च हुआ 3487 करोड़। 640 करोड़ कम खर्च हुआ। जब आप पहले साल में थे 2014-15 में। अब आ जाइये 2015-16 पर। वहां प्रावधान था 4144 करोड़, खर्च हुआ महज 3271 करोड़। 873 करोड़ कृषि में खर्च नहीं कर पाये। इस साल के आंकड़े की तो आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। रिवाइज्ड प्लान आउटले 2016-17, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 5044 करोड़, खर्च हुआ है 1756 करोड़। 3228 करोड़ खर्च नहीं हुआ इस साल। यह मजाक है? मुझे अचम्भा है, मैं ट्रेजरी बैंच के भाइयों से पूछना चाहता हूं, जब बजट पेश हुआ था तब आपने बहुत मेजें थपथपायी थी। ये मैं आपके एक साल के एक विभाग के आंकड़े बता रहा हूं। जरा उस पर भी तो मेज थपथपाइये। अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो मैं मेरे विपक्ष के भाइयों से पूछता हूं आपको शायद ये आंकड़े पसंद आएंगे।

इसी के साथ-साथ एक चीज जो इस दफे अभिभाषण से गायब हो गई, जिसे मैंने पिछली बार पुरजोर तरीके से उठाया था, उसका जिक्र तक नहीं है, आंकड़ा नहीं है, वह है फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना का इस दफे ये बताते हैं, केवल एक आंकड़ा आया है जितने मैंने टटोले हैं। वे यह बताते हैं खरीफ 2016 का आंकड़ा बताते हैं, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, खरीफ 2015 में 64 लाख किसानों का बीमा किया गया। इस साल खरीफ 2016 में 53 लाख किसानों का, 64 लाख से 53, 11 लाख किसान तो इसमें गायब हो गया। उस टाइम पर जो कुल बीमित राशि थी वह 4459 रुपये थी। इस दफे यह बढ़ गयी है भयंकर, तीन गुना, 12207 करोड़ पहुंच गई। मुझे अचम्भा आता है, पिछले साल खरीफ में प्रीमियम लिया गया 571 करोड़ और इस दफे 2381 करोड़ का प्रीमियम। जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रीमियम की दरें घटायी गयीं, 557 करोड़ के एवज में एक खरीफ सीजन में 2381 करोड़ का प्रीमियम। आगे इसका क्या हुआ, कहीं उल्लेख नहीं है। अब मैं थोड़ी देर आंकड़ों को रोकता हूं क्योंकि वे बहुत ज्यादा हो जाएंगे। एक दूसरे बिन्दु पर आता हूं, फिर आंकड़ों पर आऊंगा। इनमें हर साल जिक्र है। लोक अदालतों, राजस्व अदालतों में लाखों मामले निपटा दिये गये। हर साल मेरे यहां भी कैम्प लग रहे हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उन कैम्पों की असलियत क्या है?

(श्री नवीन पिलानिया)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां आमेर तहसील में 365 ऐसे प्रकरण हैं जो मंदिर माफी जागीर के रेफरेंस 2007 में गलत तरीके से सरकार के द्वारा दर्ज किये गये थे, हर कैम्प में जाकर मैं गुहार लगाता हूं, जनता जाकर गुहार लगाती है, तहसीलदार से बात कर ली, एसडीएम से बात कर ली, उनमें से एक का भी निपटारा नहीं हुआ जबकि एक स्पष्ट आदेश है। माननीय राजस्व मंत्री महोदय, दो मिनट ध्यान दीजिएगा, 6 जनवरी, 2010 को यह आदेश निकलता है राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर से, कहा जाता है "समस्त संभागीय आयुक्त/समस्त जिला कलक्टर/समस्त राजस्व अपील अधिकारी। मंदिर माफी की भूमि में खातेदारी अधिकारों के संबंध में परिपत्र दिनांक 24.5.07 द्वारा अंतिम तौर पर यह व्यवस्था सुनिश्चित की गयी थी कि जागीरों के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार के नाम से दर्ज थी उनमें उन खातेदारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तांतरित अधिकार प्राप्त होंगे, ऐसी भूमियों को पुन: मंदिर के नाम दर्ज कराया जाना विधिसम्मत नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज होगा।" आखिर में यह निर्देश आता है, "अत: निर्देशानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक इतने का गहनता से अवलोकन करें एवं विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों तथा विभिन्न स्तरों पर त्रुटिवश संदर्भ हेतु लम्बित प्रकरणों का निस्तारण तदनुसार ही कराया जाना सुनिश्चित कराएं।" मैं पूछना चाहता हूं क्या यह सरकार की असलियत है? जो लाखों का जिक्र है वह थोथा नामान्तरण और सादा नामान्तरण है। राजस्व मंत्री महोदय, इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता। यह जनवरी, 2010 का आदेश है और मार्च, 2017 चल रहा है। उन किसानों की जमीन है। वे न कर्ज ले सकते, न क्रेडिट कार्ड बन सकता, न कनेक्शन हो सकते। यह घोर जुल्म है। यह असलियत है सरकार की।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब दूसरी चीज पर आता हूं। एक और मजाक है। यहां बहुत दफे उल्लेख हो गया। माननीय प्रधानमंत्री बीकानेर में सोइल हैल्थ कार्ड की बात करते हैं। इनका आंकड़ा बताता है। सोइल हैल्थ कार्ड का जो इन्होंने लक्ष्य लिया, 59.85 लाख का टार्गेट है। बनाये हैं 14.85 लाख। ऐसा टार्गेट आया कहां से? किसने यह टार्गेट ले लिया? किसान को जरूरत नहीं है

(श्री नवीन पिलानिया)

सोइल हैल्थ कार्ड की। किसान को खूब पता है उसकी जमीन कैसी है उसकी पुश्तें निकल गयी उस जमीन में काश्त करते हुए। यह क्या मजाक है? टार्गेट लेते हैं 60 लाख, बनाते हैं 14 लाख, फिर भी ये मेज थपथपाते हैं, कमाल की बात है।

अब दूसरी चीज पर आता हूं। अभी सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी उल्लेख किया किसानों की दशा के बारे में कि प्रधानमंत्रीजी किसानों के कर्ज माफ करने जा रहे हैं। जरा सहकारिता की बात करिएगा। 2014-15 में मैं बात कर रहा हूं अल्पकालीन ऋण, जो ब्याज मुक्त होता है, शॉर्ट टर्म लोन जिसे बोलते हैं, 2014-15 में वह वितरित हुआ, डिस्बर्स हुआ 16017 करोड़। 2015-16 में यह घट गया, यह पहुंच गया 15441 करोड़। इस साल का तो आप अचम्भा करेंगे, कोई गैस नहीं कर सकता। कोई अंदाजा लगा सकते हो इस साल का आंकड़ा क्या है? यह पेश करता हूं 2016-17 में क्या हुआ? 2016-17 में 9656 करोड़ ही ऋण बंटा।

पिछले साल की तुलना में 4844 करोड़ कम। कैसे जी सकता है वो किसान? इसी कारण से यहां आज चाहे कितनी ही मेज थपथपा लें, जब गांव-ढाणी में जाकर असलियत देखेंगे तो यही तस्वीर नजर आती है। इनमें से एक भी आंकड़ा ऐसा नहीं है जो मैं कहीं और से लाया हूं, सारे आपकी किताबों से निकालकर ये आंकड़े पेश कर रहा हूं। मुझे शर्म आती है कि इस तरीके का व्यवहार अगर सरकार किसान के साथ में करती है और सोच रखती है तो बहुत अचम्भे और बड़े दु:ख की बात है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो कृषि था। मैंने सोचा कि पेयजल को लेकर के बहुत बात होती है तो पेयजल के जरा आंकड़े देखें। शहरी क्षेत्र में पूंजीगत एवं वृहत् परियोजनाओं का 2016-17 का हाल यह है कि बजट एलोकेशन 989 करोड़ है और 9 महीने में खर्च हुआ है 539 करोड़, 54 प्रतिशत ही खर्च हुआ है। अगर ग्रामीण पेयजल योजना की बात कर लें जिसमें तीन केन्द्रीय स्कीम्स आती हैं एनआरडीडब्ल्यूपी, आरडब्ल्यूएसएस और सीएसएस। यह तो अचम्भित करने वाला है ग्रामीण पेयजल। 2016-17 में बजट एलोकेशन है 4463 करोड़ और खर्च हुआ है 2015 करोड़। अचम्भा है न? हमारी गांव-ढाणियां जो भूजल से पेयजल पीती है, सरकार का रिकार्ड है,

(श्री नवीन पिलानिया)
इनमें 33489 तो गांव हैं और 57834 ढाणियां हैं और उसके लिए भी आप 2 हजार करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो क्या सोचते हैं आप? क्या यह सरकार का आइना नहीं है क्या? यह सरकार का पिछले साल का आइना है।

उपाध्यक्ष महोदय, नलकूपों की स्थिति यह है कि ये निरन्तर घटाते गये। 2012-13 में 4072 नलकूप थे जब कांग्रेस की सरकार थी। 2013-14 में 3004, 2014-15 आते ही 1989, 2015-16 में और भी कम 1913 हो गये। कितने गांव हैं और इस साल का आंकड़ा जो अभी तक पहुंचा है वो 1360 ही पहुंचा है। इतनी तो मेहरबानी करें और मेरा 15 मिनट का ही तो था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोचा कि सड़क पर बढ़ा होगा। हमेशा सड़कों को लेकर तो पता नहीं क्या स्थिति होगी तो सड़कों की स्थिति क्या है कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, जो गांवों की सड़कें हैं उनमें इस साल का बजट एलोकेशन है 800 करोड़, मंत्री हैं नहीं, खर्च हुआ है 226 करोड़। कमाल नहीं हो गया? पिछले साल 2015-16 में इसी के अन्दर एलोकेशन था 960 करोड़ रुपये का और पिछला पूरा साल निकल गया और 321 करोड़ ही खर्च कर पाये और फिर यहां मेज थपथपाते हैं जबकि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क की यह स्थिति है। ग्रामीण सड़कों का जो हैड है 1300 करोड़ रुपये का प्रावधान और खर्च हुए हैं 453 करोड़ रुपये। एक और बात, सड़क विकास निधि में पैसा पड़ा है इस साल 500 करोड़। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 31.7.... (व्यवधान) मैं सारे टेबल करूंगा, एक-एक कागज। मेरा समय जाया नहीं करें। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कहां से आंकड़े ला रहे हैं? ग्रामीण जलापूर्ति में भी प्रतिवर्ष बढ़ा है। आप आंकड़े गलत पेश कर रहे हैं और सदन को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): बिलकुल नहीं, मेरा समय जाया मत करो। यह मेरे राइट ऑफ प्रिविलेज में जा रहे हो आप। मैं एक-एक आंकड़ा यहां रखूंगा। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप पता नहीं कहां से लेकर आए हो ये आंकड़े।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): आप बैठिये, मेरा समय जाया मत करिये। एक-एक आंकड़ा जो पढ़ा है न वो एक-एक आंकड़ा यहां पेश करूंगा।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): बताऊं आंकड़े आपको?

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): आप मुझे बाद में बताइये, मेरा समय जाया मत करिये। जब मैं रखूं तब बताइएगा और एक भी आंकड़ा....

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट माननीय सदस्यगण। अगर आपको कुछ आंकड़े बोलने हैं न तो पहले वो उनके आंकड़े बोल लें, फिर आप भी अपने आंकड़े बोल लेना। आपको आसन इस बात की इजाजत देगा।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं पूरे सड़क महकमे का एक साथ ही टोटल खींच देता हूं जिससे झंझट खतम हो जाए। वह आखिरी में लिखा हुआ है, क्योंकि समय मिलेगा नहीं। आखिरी में लिखा हुआ है पूरे सड़क का टोटल है 6255 करोड़, दिसम्बर तक खर्च हुआ है 2306 करोड़। ये आंकड़े यहीं से निकाल कर दूंगा। माननीय, आप ज्यादा समय देंगे नहीं इसलिए एक मिनट थोड़ी सी इतनी और चर्चा कर लूं कि इसमें यह जो था न, सड़क विकास निधि की बात आ गई.....

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप विराज जाएं। अब आप फरमाएं।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, 2013-14 में शहरी जलापूर्ति....

श्री उपाध्यक्ष: आप अपनी रेफरेंस बुक को कोट कर दो जिससे वो भी उसको रेफर कर लें।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): यह बजट आय-व्ययक का दे रहा हूं, मैं 2013-14 का भी बता रहा हूं, 2014-15 का भी बता रहा हूं, 2015-16 और 2016-17 का।

श्री उपाध्यक्ष: यह वर्तमान में जो आपके बजट के साथ में आई वो ही किताब है? साल बताइए, किताब का साल बताइए फिर आप आंकड़ों का साल बता दीजिये।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): बजट स्टडी पेज नं. 24....

श्री उपाध्यक्ष: बजट स्टडी ऑफ 2016-17?

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): मैं तीनों का आकलन करके बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, नहीं, इसके प्रथम पृष्ठ पर साल क्या है? यहां लिखा हुआ है न।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 2017-18 है और उसमें पेज नम्बर 24 आप निकालकर देख लें। 2013-14 में 1 लाख 1 हजार 198 लाख, 2014-15 में 1 लाख 7 हजार 645.41 लाख, 2015-16 में 1 लाख 24 हजार 633.07 लाख। यह जलापूर्ति का बता रहा हूं, ये जलापूर्ति का बोल रहे हैं। शहरी जलापूर्ति योजनाओं के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। इसी प्रकार से 2016-17 में संशोधित अनुमान 1 लाख 40 हजार 529.76 लाख। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से ग्रामीण जलापूर्ति में भी मैं बताना चाहूंगा कि 2013-14 में 58232.20 लाख, 2014-15 में 75376.33 लाख, 2015-16 में 90099.08 लाख। अब आप कम बता रहे हैं पर यह लगातार बढ़ता जा रहा है आंकड़ा। इसी प्रकार से 2016-17 में 1 लाख 11 हजार 984.66 लाख।

श्री उपाध्यक्ष: उप सचेतक महोदय, अब हो गया।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ये कुओं की संख्या बता रहे हैं और आपको गलतफहमी हो रही है। ये कुओं की संख्या बता रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अब ये दोनों बुद्धिजीवियों के बीच का मामला है। सम्माननीय सदस्य, अब आप कन्क्लूड करें।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मैं इनका जवाब तो बाद में दूंगा, आप मेरे से लीजिए और मैं सारे आंकड़े टेबल करूंगा कि ये सारे आंकड़े किससे आये हैं। यह जो अभी मैंने ग्रामीण पेयजल का आंकड़ा दिया न यह ये रहा। इसमें यह टेबल दी हुई है और इसी में से पढ़ा है 4463 करोड़ और खर्च हुआ है 2015 करोड़। यह रहा आंकड़ा। आप कोई दूसरी किताब पकड़ते हो, माननीय, यहां आपकी और भी किताबें हैं। आप सारी किताबें नहीं पढ़ते हो। सब हैं न तो ये भी आप ही का आंकड़ा है, यह मेरा आंकड़ा नहीं है और जो-जो आंकड़े दिये हैं न वो यहां टेबल करके जाऊंगा। मैं सिर्फ एक इम्पोर्टेंट बात रह गई थी जो पूरे राजस्थान के लिए इम्पोर्टेंट है। सड़क विकास निधि में 500 करोड़ हैं और 31 करोड़ खर्च। पिछले साल 2015-16 में ये 600

(श्री नवीन पिलानिया)

करोड़ थे जिनमें से केवल 29 करोड़ खर्च हुए थे। एक चीज जो हो रही है कि पैट्रोल पर 1.50 रुपये और डीजल पर 1.75 रुपये प्रति लीटर सड़क निधि के लिए लिये जा रहे हैं। पर जब सड़कों में इतना पैसा पड़ा है कि खर्च ही नहीं हो रहा तो इस राजस्थान की जनता पर क्यों जुल्म कर रहे हो आप? यह बताइये। वो क्यों लग रहा है 1.50 रुपये पैट्रोल पर और 1.75 रुपये डीजल पर? क्यों आप उप कर लगा रहे हैं यह आप मुझे बताइए। सिर्फ एक सैकिण्ड में ही खतम कर रहा हूं।

नेशनल हैल्थ मिशन, बस इतना सा बोलूंगा। नेशनल हैल्थ मिशन, जो पहले मंत्री महोदय थे, जो इसमें बड़ा सुर्खियों में रहा, यह बताता हूं कि 2014-15 में 2190 करोड़ का प्रावधान था और खर्च हुआ 1784, 406 करोड़ खर्च नहीं कर पाये। 2015-16 में 2515, खर्च हुए 1826, 689 करोड़ खर्च नहीं कर पाये और इस साल का आंकड़ा है 2454 और उसमें से खर्च हुए हैं 1280, 1174 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पाये। अब क्या है। मैं अब बात समाप्त करता हूं लेकिन मेरे जो ट्रेजरी बेंचेज के भाई हैं, उनके लिए एक पंक्ति याद आ रही है। कह दूं? "जो तुमको हो पसंद, वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो, रात कहेंगे।" बहुत-बहुत धन्यवाद। राम-राम।

श्री उपाध्यक्ष: श्री धीरज गुर्जर।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के अंदर बजट पर चर्चा चल रही है, उसमें मुझे आपने बोलने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आसन का आभारी हूं।

मैं कहना चाहता हूं कि जनता बजट बनाने का अधिकार सरकार को देती है और बहुत विश्वास से देती है लेकिन इस बजट के अंदर जो हमको खर्च करने के लिए पैसा देता है, क्या उस आदमी को इस बात का अधिकार भी है कि वह इस बात का निर्णय कर पाये कि जो पैसा वह सरकार को दे रहा है कि वह पैसा खर्च कहां पर होगा? हम यह मान लेते हैं कि उद्योगपतियों ने इन्कम टैक्स दिया है तो हमारी पहली जिम्मेदारी उस पैसे को उद्योगपतियों के विकास के लिए खर्च करने की है, लेकिन हम यह क्यों भूल जाते हैं कि जो पैसा हमें खर्च करने के लिए मिलता है, वह सिर्फ उद्योगपति ही नहीं देते, बल्कि गरीब, किसान, मजदूर और आर्थिक रूप से

(श्री धीरज गुर्जर)

पिछड़ा हुआ आदमी भी छोटी-छोटी चीजें खरीदकर, उन चीजों के ऊपर लगने वाला टैक्स हमारे को देता है। उस टैक्स से सरकार के पास पैसा आता है और जो व्यक्ति देने वाला है, जो दानदाता है, जो हमको दे रहा है। उसी को इस बात का अधिकार नहीं है कि वह पैसा कहां पर खर्च होगा लेकिन हम यह मान लेते हैं कि लोकतंत्र में एक व्यवस्था की गई कि जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जो जनता के लोग हैं, उनको लोग चुनकर भेजते हैं और वह जनता की आवाज को उठायेंगे लेकिन यहां हां पक्ष और ना पक्ष के अंदर बंटा हुआ जो सदन है, यह कभी भी इस बात का निर्णय नहीं कर पाता है कि जिन लोगों ने पैसा हमारे को दिया है, वह पैसा उसके अनुपात में उनके ऊपर खर्च हो।

बजट की तो मैं कहता हूं, अवधारणा ही उल्टी है। जब बजट पेश हो जाता है, तो उसके बाद उस पर चर्चा करने से क्या फायदा? अगर चर्चा करनी हो तो पहले इस सदन के अंदर उस बजट को कैसे खर्च करना है, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए और उस सकारात्मक चर्चा के बाद में बजट बनना चाहिए ताकि जनता को यह एहसास हो पाए कि जो प्रतिनिधि उन्होंने चुनकर भेजे हैं, उन प्रतिनिधियों की अभी भी इतनी चलती है कि वह अपने-अपने क्षेत्र के अंदर पैसा लेकर आ जाते हैं। मुख्य मंत्रीजी चाहे किसी भी पार्टी की हों, जब मुख्य मंत्रीजी खड़ी होती हैं तब किसी विधायक को पता नहीं होता है कि बजट के अंदर क्या आने वाला है। या तो अधिकारियों को पता होता है, जो यह मानकर चलते हैं कि सत्ता का मतलब मुख्य मंत्री और कुछ मंत्री। सत्ता पक्ष के विधायकों को भी वह सत्ता नहीं मानते। वह मानते हैं कि सत्ता पक्ष का मतलब मुख्य मंत्री और मुख्य मंत्री जब बोलती हैं, तब विधायकों को भी पता नहीं होता है कि उनके क्षेत्र के अंदर किसकी घोषणा होने वाली है या उनके क्षेत्र के अंदर क्या विकास होने वाला है।

(14.33 बजे)

(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)

लेकिन जैसे ही अपने क्षेत्र का नाम आता है और विधायक ताली बजाता है, जैसे कि उसके कहने से वह घोषणा हो रही हो। हमें इस गलतफहमी के अंदर नहीं रहना चाहिए कि बजट के अंदर जो घोषणा हो रही है, वह घोषणा हमारे कहने से हो रही है। वह घोषणा मुख्य मंत्रीजी की मर्जी से हो रही है जबकि वह घोषणा जनता की मर्जी से होनी चाहिए और जनता की मर्जी से

(श्री धीरज गुर्जर)

घोषणा तब होगी, जब विधायक का उसमें हस्तक्षेप होगा कि मेरे क्षेत्र के अंदर सबसे पहले यह विकास कराया जाए। सिर्फ विधायक का मतलब यह नहीं कि जो हां पक्ष के अंदर बैठते हैं। विधायक का मतलब यह है कि जो ना पक्ष के अंदर भी बैठता है, उसको भी जनता ने चुनकर भेजा है, इसलिए आप लोगों को पैसा खर्च करना चाहिए क्योंकि आज अगर आप लोग हां पक्ष में बैठे हो तो कल आप लोग ना पक्ष के अंदर बैठोगे, इसलिए विधायक का मतलब होना चाहिए कि यह पैसा उसकी मर्जी से खर्च हो और हम लोगों ने एक नियम बना लिया...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय धीरज जी, यह परम्परा तो आपके शासनकाल से डाली होती तो बहुत अच्छा होता। तो आपको उस समय ही सलाह देनी चाहिए थी।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मैं कह रहा हूं कालू लालजी, शासन आपका है। देखो, हम तो 21 पर आ गये, अब आप नहीं सुधरोगे तो आप 11 पर आ जाओगे। (व्यवधान) नहीं, आप यूपी मत देखो, राजस्थान देखो। हम 21 आये थे। 21 से हम 24 हो गये उप चुनावों के अंदर और धौलपुर के बाद हम 25 हो जायेंगे, तो हम तो बढ़ रहे हैं, आप घट रहे हो।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अब अगली बार 21 के 11 रह जाओगे।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मैं यही कहना चाहता हूं कि हां पक्ष का काम तो रह गया, हां बोलना और ताली बजाना और ना पक्ष का काम रह गया, विरोध करना लेकिन जनता ने हमारे को मुनीम बनाकर भेजा है। हमारे से मतलब सिर्फ मैं नहीं या विपक्ष नहीं, सत्ता और विपक्ष दोनों पक्षों ने हमारे को मुनीम बनाकर भेजा है लेकिन हमारी कमजोरी यह हां पक्ष और ना पक्ष में बंटा हुआ सदन है। उसकी कमजोरी से इस खजाने की चाबी इन अधिकारियों के हाथ में सौंप दी है और यह हमारी कमजोरी है कि ये जो अधिकारी हैं, जो अफसरशाह कहलाना पसंद करते हैं। अगर कोई इनको बड़ा बाबू बोल दे या अगर कोई इनको नौकरशाह बोल दे तो इनके कान खड़े हो जाते हैं। ये जनता के नौकर हैं और इनको इस बात का एहसास कराने के

(श्री धीरज गुर्जर)
लिए इस सदन को एक होना पड़ेगा। तब जाकर हम लोग इस अफसरशाही के ऊपर लगाम लगा पाएंगे। अगर हम अफसरशाही के ऊपर लगाम नहीं लगाएंगे तो बजट के अंदर ऐसे-ऐसे झूठे आंकड़े ये मुख्य मंत्री और वित्त मंत्रियों के मुंह से कहलाते रहेंगे, जो इनकी पसंद के आंकड़े हों।

मैं आपको इसलिए भी कहना चाहता हूं कि सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे सरकार भाजपा की रही हो, जब-जब सरकारें बनी हैं और जब-जब सरकारों का बजट बना है, उस बजट का सबसे बड़ा हिस्सा अगर खर्च होता है तो विकास पर खर्च नहीं होता। उस बजट का सबसे बड़ा हिस्सा खर्च होता है इन नौकरशाहों की तनख्वाह के ऊपर और तनख्वाह लेते हैं जनता की सेवा करने के लिए और कुर्सी पर बैठते हैं राजा बनकर न्याय करने के लिए। हमारा सबसे पहला कर्त्तव्य यह होना चाहिए कि हम इन नौकरशाही पर लगाम लगाएं और लगाम लगाकर इस नौकरशाही से जनता की सेवा करवाएं, तब जाकर हमारी बात होगी। हम यह तो मानते हैं कि सरकार हमारी नहीं है, हम विपक्ष के लोग हैं। हमारे क्षेत्रों में विकास नहीं होगा लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके क्षेत्रों के अंदर जो विकास हो रहा है, उस विकास के अंदर आपकी भागीदारी सुनिश्चित करिएं। क्या आपसे पूछा है कि आपके क्षेत्र के अंदर क्या विकास कराएं? यह एक परम्परा सी बन गई है। इस परम्परा को बदलने के लिए हम लोगों को एक होना पड़ेगा और सही मायने में कांग्रेस या बीजेपी या कोई और दल जनता का भला तब तक नहीं कर पाएंगा, जब तक इस नौकरशाही के नाक में नकेल नहीं डालेगा। आज दिन पर दिन राजस्थान की हालत ऐसी होती जा रही है कि यह नौकरशाही और अफसरशाही हमारे ऊपर हावी होकर राजस्थान की जनता को लालफीताशाही में, भ्रष्टाचार में, टालमटोली के अंदर और लोगों के काम अटकाने के अंदर कर रही है।

इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि पिछले दिनों जिस तरह से, मैं इस सदन का ध्यान चाहूंगा, एक दलिता महिला विधायक जो इसी सदन के अंदर बैठती हैं, कोटा की धरती पर जो वीडियोग्राफी आप देखोगे तो आपके प्राण कांप जायेंगे। आप लोगों के सामने एक ही वीडियो सामने लाया गया। दूसरा

(श्री धीरज गुर्जर)

वीडियो भी सामने आता तब पता लगता कि किस तरह से हमारी साथिन महिला दलित विधायक पुलिसकर्मियों के पाँव के अंदर गिरी हुई थीं और इस सदन के अंदर एक भी आवाज नहीं उठी। कांग्रेस और बीजेपी और दूसरे दलों को भूलकर इस सदन को एक होकर, जब बिहार के एक आईएएस के खिलाफ अत्याचार के बाद राज्यपाल को ज्ञापन दे सकते हैं तो...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): बजट पर बोलो।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): बजट पर ही आऊंगा।

श्री रमेश (सपोटरा): आपके स्प्रिंग लगी हुई है क्या? आप बिना मतलब ही खड़े हो जाते हो। स्प्रिंग लगी हुई है क्या आपके? यह बजट में नहीं है क्या कानून व्यवस्था?

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मदन जी, सुनो। आपको भी पीट सकते हैं।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपके क्या हो गया?

श्री रमेश (सपोटरा): नहीं, आप बताओ। आप बीच-बीच में यूं ही खड़े हो जाते हो। आप उप मुख्य सचेतक हो। नियम-कानून की जानकारी होनी चाहिए आपको। जानकारी नहीं है आपको। जानकारी रखो, तब बोलो। ऐसे मत बोला करो। चाहे जभी खड़े हो गये।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप बजट पर बोलो न। बजट पर तैयारी करके आओ। बजट को पढ़ो आप तो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कनक्लूड करें आप।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): मैं खड़ा नहीं हूं। मैं सही कह रहा हूं, आप बजट पर बोलो। आपकी तैयारी है तो आप बोलो ना। यूं बैठे-बैठे ही।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): अबकी बार मदन जी का नम्बर है। कोटा वाली का नम्बर आ गया। अब आपका नम्बर आएगा। तब हम इकट्ठे होकर ज्ञापन देंगे। अब आपने जब बजट की बात कह ही दी है तो... कोटा वाली दलित महिला विधायक की पिटाई हुई है, अब इनको पीटेंगे तब ज्ञापन दे देंगे।

मैं यह कह रहा था, चलो बजट की बात करते हैं। नहीं नहीं, बजट की बात करते हैं अब। सत्ता पक्ष के विधायकों ने सोच रखा था कि इस बार तो

(श्री धीरज गुर्जर)
चौथा साल है, बहुत बढ़िया बजट आएगा। सबके चेहरों पर चमक थी तो विधायकों ने सोचा कि बजट अच्छा आएगा और उसके बाद, मैं तो बाहर गया हुआ था, वापस आया तब सदन में देखा, तब सब मजबूरी से खड़े हो रहे हैं। अब तारीफ तो करनी है, क्या करें, मजबूरी है लेकिन सबका मुंह ऐसा हो रहा था कि जैसे तुस खाई हुई गाय होती है। हमारे इधर मेवाड़ी में कहावत है कि गाय को आटा दिखाते हैं पहले कि गाय माता, तेरे को आटा देंगे और आटे की जगह उसको तुस खिला देते हैं तो गाय का मुंह बिगड़ जाता है तो सब विधायकों का मुंह ऐसा हो गया, जैसे तुस खाई हुई गाय हो और राजस्थान की जनता को जो बजट आपने दिया है न, यह बजट बकरी की गलकियों जैसा है। हमारे इधर मेवाड़ी में कहते हैं छाली के गलकियां। कितना ही खींचो, दूध नहीं निकलेगा। बकरी जो होती है तो उस बकरी के गले में जो गलके होते हैं तो उन गलकियों को कितना ही खींचो, उन गलकियों से दूध नहीं निकलता है तो राजस्थान की जनता को जो आपने बजट दिया है, यह वही बजट है जो छाली के गलके है। इनको कितना भी खींचोगे, लेकिन इस वजह से राजस्थान की जनता का और लोगों का विकास नहीं होने वाला है और इसलिए मैं कह रहा हूं मदन जी,... (व्यवधान) मदनजी के हिस्से का दूध मैं पी गया और मदनजी का वज़न कम हो गया।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय सभापति महोदय, इन्होंने उप सचेतक महोदय के बारे में कहा है कि अगली दफा आपका पिटने का नम्बर आयेगा, तो यह कार्यवाही से निकाला जाये, मैं इसको निवेदन करूंगा आपसे। उप मुख्य सचेतक के लिए यह कहना शोभा नहीं देता है। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज धीरज जी, कन्टीन्यू करें, आपका टाइम जा रहा है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): गुरूजी एक मिनट। माननीय सभापति महोदय, मदन जी, ये धीरज जी आपके ऊपर बैठ जाएंगे, मेरी बात सुनो, फिर दिक्कत हो जाएगी आपके ऊपर बैठ गये तो।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप विराजो।

श्री सभापति: आप बैठें। कन्टीन्यू करें आप।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): धीरज जी, आपके बकरियां तो हैं नहीं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मेरे बकरियां भी हैं गाय भी हैं (व्यवधान)...

श्री सभापति: कृपया सभी माननीय सदस्यों से रिक्वेस्ट है कि व्यवधान नहीं करें। आप अपना वक्तव्य जारी रखें।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): दुःखी हैं युवा, रो रहा किसान है, बदहाल हैं व्यापारी, सिर फोड़ रही है जनता सारी, फूटे थे कर्म हमारे जो भाजपा को हमने सत्ता दे डाली। राजस्थान में आपने ये ही हालात कर दिये हैं। हिंगोनिया गोशाला में गायें मार दी। चालीस लाख करोड़ का आपने घोटाला खानों के अन्दर कर दिया। हजारों किसानों का मुआवजा आप लोग खा गये उसके बाद भी आपका मन नहीं भर रहा है और तो और राशन की दुकानों के बाहर बेचारे गरीब आदमी को ईमानदारी से थोड़ा बहुत राशन मिल जाता था वो मशीनें उनको दे दी। इनको ये ही पता नहीं, न तो अफसरों को पता है न आपको पता कि गांव का आदमी जब खेत के अन्दर गैंती चलाता है, फावड़ा चलाता है तगारी उठाता है तो उसके अंगूठे के फिंगर प्रिंट मिट जाते हैं बेचारे के। वो सुबह से शाम खड़ा-खड़ा आपकी पोस मशीन के ऊपर अंगूठा घिसता रहता है लेकिन उस किसान को एक रुपये, दो रुपये किलो का गेहूं लेने के लिए सुबह की चालीस रुपये, साठ रुपये, सौ रुपये की मजदूरी छोड़ कर लाइन के अन्दर लगना पड़ता है। इसलिए राजस्थान की जनता आपको माफ नहीं करेगी। हां एक काम आपकी सरकार ने किया। मेरी पंचायत समिति कोटड़ी के अन्दर मैं बैठा हुआ था और हमारी वहां पर जन सुनवाई चल रही थी, तब एक बूढ़ी डोकरी मेरे पास आई और बोली कि धीरज तू तो विधायक बन गया लेकिन मुझे फायदा नहीं हुआ। मैंने कहा कि बोलो क्या हुआ तो वह बोली कि तुझको वोट देने से मेरी पेन्शन बंद हो गयी। मैंने कहा कि पेन्शन कैसे बंद हो गयी आपकी तो बोली कि मेरे पहले पेन्शन आती थी आजकल मेरे पेन्शन नहीं आ रही है तो मैंने कहा कि आपके कार्ड दिखाओ तो उसने एक थैली निकाली और पूछा कि कौन सा कार्ड। मैंने कहा कि सरकार ने आपको एक आधार कार्ड दिया होगा वो कार्ड दे दो मुझे तो उसी बूढ़ी महिला ने मेरे सामने एक थैला निकाला और उस थैले को उलटा करके मेरे सामने टेबल पर डाल दिया तो उन कार्डों में आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, रुपे कार्ड, मृदा कार्ड जाने कौन-कौन से कार्ड निकल गये, लेकिन उस बूढ़ी महिला को जो पेन्शन मिले ऐसा कार्ड उसके पास नहीं

(श्री धीरज गुर्जर)

निकला। आपकी सरकार ने इस चार साल में अगर कुछ किया है तो लोगों की जेबें काट-काट कर ई-मित्र वालों से लोगों के कार्ड बनवाये हैं। ये कार्ड बनने से लोगों का भला होने वाला नहीं है और मैं आप लोगों के कान खोलने के लिए एक कहानी और सुनाना चाहता हूं आपको।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): पेन्शन का कार्ड भी होता है क्या?

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): पेन्शन का कार्ड नहीं होता है राशन कार्ड होता है राशन कार्ड में नाम होता है तो पेन्शन मिलती है। अब मदन जी आप जब वोट मांगने जाओगे तब आपको लोग कहेंगे कि वोट नहीं देंगे आपने हमारी पेन्शन रुकवा दी।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): मदन जी, ये इतना ही समझते हैं कोई बात नहीं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): अब ये करेंगे वो ही क्योंकि दुःखी मन है इनका। आज नम्बर लेने हैं मुख्य मंत्री जी आएंगी कोई अच्छा परफोर्मेंस कर देगा तो छोटा-मोटा पद मिल जाएगा। चलनी तो है नहीं पद मिलने से क्योंकि आप लोग कितने ही हाथ जोड़ लो ये अधिकारी आपकी सुनने वाले नहीं हैं। ये आपके माथे पर बैठ कर तांडव करेंगे। ये तो हमारे ही कब्जे में आएंगे अगली बार। एक बार एक किसान के घर में अच्छा अनाज हो जाता है तो वो ताऊ अपने भतीजे को कहता है ...(व्यवधान)... हनुमान जी सुनो, आपके एरिया की कहानी है यह। वो ताऊ अपने भतीजे को कहता है कि चल बेटा पुष्कर कार्तिक नहा कर आ जाते हैं। कार्तिक का महीना आता है जानते हो न आप? कार्तिक के महीने में आदमी कार्तिक नहाता है और तालाब में नहाने के लिए जाता है तो वो ताऊ अपने भतीजे को कहता है कि चल भतीजे अपन कार्तिक नहा कर आ जाते हैं तो भतीजा अपने साथ में अपने ताऊ को लेकर रवाना होता है। जब वो पुष्कर उतरते हैं तो पुष्कर उतरते ही जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं एक आदमी सफेद कपड़ों में उसको आवाज देता है कि ताऊ कहां जा रहा है, ताऊ कहां जा रहा है तो भतीजा कहता है कि ये कौन है तो वो पूछता है कि तू कौन है तो वह बोलता है कि मुझे नहीं पहचाना मैं तेरे गांव में रहने वाली कमला बाई का छोरा तेरा भानजा हूं भानू

(श्री धीरज गुर्जर)

भानजा तो वह कहता है कि भानू भानजा। भतीजा कहता है कि हम तेरे को जानते ही नहीं तू कौन सा भानजा है ताऊ का ये तो मेरा ताऊ है। वो कहता है कि नहीं मैं इनका भानजा हूं तू जानता नहीं है और वो उस ताऊ को साथ लेकर कहता है कि ताऊ चल, तू मुझे अगर पहले बता कर आता तो मैं तेरी अच्छी व्यवस्था करता, तेरे को ठहराता तो वो ताऊ को लेकर जाता है एक दुकान...।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सदस्य, यह राजस्थान की विधान सभा है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह कोई कहानी सुनाने की जगह है क्या? कोई कहावत सुनाने की जगह है क्या?

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आपकी अभी इस कहानी से आंखें खुल जाएंगी, साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इसकी गरिमा को तो जरा देखो न। यह कोई सब्जी मंडी में कहीं बोल रहे हो क्या?

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): नहीं-नहीं। ये कहानी आंखें खोलने वाली है, उदाहरण है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ये क्या है? सभापति महोदय, ये क्या ज्ञान दे रहे हैं हमें। क्या सुना रहे हैं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): अभी दो मिनट में मिल जाएगा, साहब। यह कहानी...।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): हरियाणा के ताऊ की बात सुना रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): होली के अन्दर जिस तरह का मजाक होता है वो यहां करने लग गये। आप होली खेल कर आये हो उसका खुमार उतरा नहीं है अब होली नहीं है। आप इस बजट पर बात करें।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय मंत्री महोदय, अभी आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे मेरी बात सुन कर। तो उसके बाद वह ताऊ को लेकर भानजा...।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): इन्होंने केसरिया होली खेली है।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह पता लग गया न राहुल गांधी को कि यह केसरिया होली खेली है तो इनके साथ गड़बड़ हो जाएगी।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): देखो, मेरी बात सुनो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ये खाट रैली में उनके साथ थे। जब उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी खाट रैली निकाल रहे थे तब उनके साथ थे। 56 जगह उनके साथ गये और उसमें 36 जगह जमानत जब्त हो गयी।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आप पंजाब गये तो सीट एक ही आयी वहां पर।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): तभी तो इनके यूपी में ठाठ हो गये। तभी ठाठ हो गये खाट से।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मेरी बात सुनो, यूपी में तो हमें सात सीट मिली हैं पर पंजाब में आपको एक ही मिली है।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आप तो बीजेपी को जिताने ही गये थे वहां। ...(व्यवधान)...

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): उसके बाद वो भानजा उस मामा को कहता है कि चल तुझे रबड़ी खिलाता हूं, जलेबी खिलाता हूं। दुकान पर ले जाता है नये कपड़े दिलाता है। भतीजा कहता है कि मामा इसकी बातों में मत आ यह कोई ठग आदमी है अपने को ठग लेगा और इसके चक्कर में अपने को नहीं चलना है, लेकिन वह मानता नहीं ताऊ कहता है तू रुक जा भतीजे, आज मुझे माल मिल रहा है मुझे खा लेने दे और उसके बाद वो कपड़े की दुकान पर ले जाता है उसको कपड़े दिलवाता है फिर उसके बाद वो भानू भानजा मामा को कि चल मामा मैं तेरे को कपड़े दिलवा देता हूं। कपड़े दिलाता है फिर मंदिर में ले जाता है। फिर उसके बाद कहता है कि तू पुष्कर सरोवर में स्नान कर ले तो वो भतीजा कहता है कि ताऊ तू नहा ले मैं तेरे कपड़ों का ध्यान रखता हूं तो वह भानजा कहता है कि नहीं-नहीं, तुम दोनों साथ जाकर नहाओ, मैं तुम्हारे कपड़ों का ध्यान रखूंगा तो भतीजा मना करता

(श्री धीरज गुर्जर)
है कि ताऊ इस भानजे की बातों में मत आ तो ताऊ कहता है कि भाग यहां से इसने मेरी सेवा की है मैं इसकी बात मानूंगा और उस भतीजे को भगा देता है और उसके बाद वो अपने कपड़े अपने पैसे अपनी नकदी अपने गहने सब अपने भानजे के हाथ में दे देता है और ताऊ उस सरोवर में नहाने चला जाता है और जैसे ही सरोवर में डुबकी लगाता है वो कहता है चिन्ता मत कर मैं तेरा ध्यान रख रहा हूं मामा और जैसे ही वह ताऊ बाहर आता है दूसरी बार तो देखता है वो भानजा गायब हो जाता है वो ताऊ तो राजस्थान की जनता थी और वह भतीजा कांग्रेस पार्टी थी और वो भानजा आप लोग हो जो राजस्थान की जनता को आपने सपना दिखाया कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो तुम्हारे को पेन्शन देंगे, पन्द्रह लाख नौकरी देंगे, तुम्हारे को रोजगार देंगे तुम्हारा विकास करेंगे और जैसे ही ...(व्यवधान)...

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): वाह जी! भानजा शानदार-शानदार। वाह! भानजे ने शानदार सुनाई।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): राजस्थान की जनता ने उस वोटों की पेटी में डुबकी लगाई राज की चाबी आपके हाथ में सौंपी। जनता को कांग्रेस ने समझाया था कि इनकी बातों में मत आओ ये लूटने वाले लोग हैं तुमको लूट लेंगे, लेकिन उस जनता ने कहा कि नहीं-नहीं ये तो हमारा भानजा है हमारे को रबड़ी खिलाएगा, हमारे को पेन्शन देगा, नौकरी देगा और राजस्थान की जनता ने जैसे ही वोटों की पेटी में डुबकी लगाई, आप लोगों ने उनकी पेन्शन लूट ली। युवाओ का रोजगार लूट लिया। किसान का मुआवजा लूट लिया। क्षेत्रों का विकास लूट लिया। लोगों की जेब के अन्दर जो नोट थे वो नोट तक आपने लूट लिये और आपका मन नहीं भरा।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अब असली दुख आया आपका सामने। नोटों वाली बात आपकी सामने आयी।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): और आपका मन नहीं भरा, मदन जी तो राजस्थान के अन्दर आप सत्ता में आये थे मंदिर और गो के नाम पर। हिंगोनिया गोशाला में आपने गायें मारने का विश्व रिकार्ड बना दिया। राजस्थान के इतिहास में गायों का अनुदान किसी सरकार ने नहीं खाया उतना अनुदान आप खा गये और तो और...।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आप ऐसा लगता है कि नोटबंदी से पीड़ित हैं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मैं बिलकुल पीड़ित नहीं हूं, मेरे पास तो नोट ही नहीं हैं। कालीचरण जी, नोट सबसे ज्यादा आपके पास हैं इस सदन में। ...(व्यवधान)...

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): ये तीस दिन वहां रह कर आये हैं न तो सदमा लग गया थोड़ा।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): कालीचरण जी के तो नोट तो पैट्रोल पंप की आड़ में बदल गये।

श्री सभापति: आपका समय जा रहा है। टाइम हो गया।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): हां ठीक है, साहब, ये कर रहे हैं बदमाशी। तो राजस्थान के लोगों को आप लोगों ने जो सपना दिखाया था। आप कहते हो कि हमने पन्द्रह लाख नौकरियां दी हैं किसमें दी तो बताया कि नरेगा में। नरेगा में नौकरी नौकरी होती है क्या? राजस्थान के युवाओं को आपने यह रोजगार दिया है। राजस्थान की जनता को आपने यह तोहफा दिया है। आज गरीब आदमी पेन्शन के लिए मारा-मारा फिर रहा है। बीपीएल में मकान की किश्तों के लिए मारा-मारा फिर रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता आपको माफ नहीं करेगी। माननीय सभापति महोदय, मेरा बहुत समय खराब किया है और आपने एक नयी परम्परा बना ली। रोडवेज पीपीपी के ऊपर, होस्पिटल पीपीपी के ऊपर, शिक्षा पीपीपी के ऊपर तो सारे काम पी के ही करते हो बिना पीये कोई काम नहीं करते हो। यह नशा उतार लो अपना नहीं तो जनता नशा उतार देगी आप लोगों का। मैं यह कहना चाहता हूं आप लोगों से, सरिस्का और रणथम्भौर को निजी हाथों में दे रहे हो, खासा कोठी के सौदे कर रहे हो। मतलब राजस्थान में जब-जब सत्ता में आओगे तब राजस्थान को बेचने के लिए ही सत्ता में आओगे, जनता का भला करने के लिए सत्ता में नहीं आओगे आप लोग। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ अभी भी मौका है, बार-बार हम पर ऊँगली मत उठाओ। हम तो इस सदन में 21 आये थे, 21 के उप चुनाव में 24 हो गये और इस वाले उप चुनाव में 25 हो जाएंगे। संख्या आपकी घट रही है हमारी

(श्री धीरज गुर्जर)

नहीं घटेगी राजस्थान में। उत्तर प्रदेश तो दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। उत्तर प्रदेश को देख कर आपको राज़ी होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को सोचना पड़ेगा। राजस्थान की जनता ने आपको एक ऐतिहासिक बहुमत दिया है और उस बहुमत के बदले में आपने क्या दिया राजस्थान को। बलात्कार में पूरे देश में आप राजस्थान को तीसरे नम्बर पर ले आए। एवरेज 3644 बलात्कार आपके राज में हर साल हो रहे हैं।

राजस्थान में एसटी, एससी अत्याचार में आप लोग चौथे नंबर पर आ गये हो। राजस्थान में ओवर आल क्राइम में आप लोग नवें नंबर पर हो, यह आपने राजस्थान की जनता को सौगात दी है। सभापति महोदय, इससे भी इनका मन नहीं भरा, जयपुर के लॉ एण्ड आर्डर की हालत देखो, जयपुर कमिश्नरेट है, इस कमिश्नरेट में ली मिरिडियन होटल में पूरे हिन्दुस्तान के 400 सटोरिये जयपुर की धरती पर इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर सट्टे का हिसाब कर रहे हैं, यह जयपुर की और राजस्थान की आपने दशा कर दी है। इसलिए आपको राजस्थान की जनता माफ करने वाली नहीं है।

श्री सभापति: थैंक्यू।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मेरे क्षेत्र की बात कहने से रह गया था मैं, यह सरकार कहती है कि हम लोग भेदभाव नहीं बरत रहे हैं। जहाजपुर की जनता ने मुझे विधायक बनाया, पिछली सरकार ने हमारे यहां पर कॉलेज की घोषणा की थी। मंत्रीमंडलीय समीक्षा के नाम पर आप लोगों ने उस कॉलेज को चार साल से रोक रखा है। चार साल से आपसे समीक्षा नहीं हो पाई तो आप देश का विकास क्या करोगे, प्रदेश का विकास आप लोग क्या करोगे। मंत्री कृपलानी जी गरदन हिला रहे हैं, आपके विभाग की ही मैं कहता हूं, हमारे नगरपालिका का चेयरमैन जनता के वोटों से जीत कर आया, जिसको लोगों ने चुन कर भेजा और बीजेपी का चेयरमैन हार गया तो आप लोगों ने उस आदमी को एक ऐसे काम के लिये बर्खास्त कर दिया जो काम उस नगरपालिका के चेयरमैन ने किया ही नहीं था। अगर बर्खास्त करना है तो मेरे को बर्खास्त करो। ऐसे लोगों को जिनको लोग चुन कर भेजते हैं, आप बर्खास्त करने का काम मत करो। मैं तो आपसे यही निवेदन करता हूं, अपनी बात एक बार वापस दोहरा देता हूं कि दुःखी है युवा रो रहा किसान

(श्री धीरज गुर्जर)

है, बदहाल है व्यापारी, सिर फोड़ रहा है जनता सारी, फूटे कर्म हमारे जो भाजपा को हमने सत्ता दे डाली, ऐसी गलती हम आइंदा नहीं करेंगे, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: यह पहले बोल दिया आपने। माननीय सदस्य श्री अर्जुन लाल जी गर्ग।

सूचना

जोधपुर शहर में नकाबपोश युवकों द्वारा फायरिंग

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, पाइंट ऑफ इन्फोरमेशन। सभापति महोदय, आज जोधपुर शहर में दो जगह फायरिंग की घटना हुई है, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कर बताना चाहता हूं। एक तो निजी अस्पताल के मालिक के घर के बाहर और एक ट्रेवल एजेंसी के मालिक के घर के बाहर फायरिंग हुई है। गाड़ियों को जलाया गया, नकाबपोश युवक थे। 10 दिन पूर्व भी फायरिंग का प्रयास इस ट्रेवल एजेंसी के बाहर हुआ था। पुलिस को सूचित भी किया लेकिन अभी तक पुलिस गंभीर नहीं है। बहुत बड़ी घटना जोधपुर में हुई है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि शीघ्र इन आरोपियों की गिरफ्तारी करें और जोधपुर में जो कानून व्यवस्था बिगड़ गई, पूरे राजस्थान में जो कानून व्यवस्था बिगड़ गई, उसको ठीक करें।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय अर्जुन लाल जी गर्ग।

आय-व्ययक

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको और सदन के माध्यम् से इन सौगातों के बजट 2017-18 जो माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी ने 8 मार्च, 2017 को इसी सदन में रखा था, उनके इस बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और साथ ही साथ मुख्य मंत्री महोदय का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।

सभापति महोदय, मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं जहां की जनता बजट

(श्री अर्जुन लाल)

घाटा, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, अधिशेष आदि आंकड़ों के मायाजाल से भ्रमित न होकर मोटे मोटे तौर में वह बजट में अपने हित से, अपनेपन से जुड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं की गंभीरता व सारगर्भिता को महसूस करते हैं। मैं पश्चिमी राजस्थान से आता हूं जहां पानी की महत्वता बहुत अधिक रहती है। वहां की जनता पानी की भयंकर कमी से त्रस्त होकर सरकारों में अपना योगदान देती है। पूर्व में हमारे पूर्व मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत भी पश्चिमी राजस्थान से आते हैं लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल में माणकलाव दांतीवाडा योजना जो हमारी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी ने 2008 में उसकी 308 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी कर उसका शिलान्यास किया था। पांच साल बाद जैसे ही अशोक जी की सरकार आई उन्होंने उस योजना को एक पुलिंदे में बाँध कर रख दी और उस पर एक रुपया उन्होंने नहीं दिया। जब वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हमारे क्षेत्र की जनता में एक उम्मीद की किरण जगी कि हमारी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी वापस आ गई हैं, इस योजना को फलीभूत करेंगी। उन्होंने इन तीन सालों में 308 करोड़ की योजना जिसमें दो नगरपालिकाएं और 119 गांवों को उन्होंने इस पेयजल योजना से जोड़ा। उससे वहां के गरीब लोग, जो आमजन हैं, वहां की जनता है अपने अंतरमन से निशब्द आशीषें उनको दे रही हैं। उसी का कारण रहा है कि ऐसी ऐसी योजनाएं मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी ने रखी हैं। अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा था कि योजनाएं निष्फल रहीं। अभी 11 मार्च को पांच राज्यों के जो चुनाव परिणाम आये उससे इनको पता चल गया कि वास्तव में इस प्रकार की योजनाओं से सरकार और जनता पुन: इनको आगे बढाने का और उनसे मिलने वाली दुआओं का असर आगामी कई वर्षों तक रहेगा।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में कई वर्षों से ट्रोमा सेंटर के लिये मांग उठ रही थी। तुरंत चिकित्सा सहायता के अभाव में जब घायल दम तोड़ता है तो उसके परिजनों की क्या स्थिति होती है, वही जानते हैं। हमारे मुख्य मंत्री जी को जब ऐसा आभास हुआ तो उन्होंने इस बजट में बिलाड़ा शहर में ट्रोमा यूनिट की स्थापना की घोषणा की। मैं मुख्य मंत्री जी का बहुत बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। सड़क दुर्घटना में घायलों

(श्री अर्जुन लाल)
का उपचार, दुर्घटना में बेवा होने से जो विधवा माताएं या जिनकी गोद सूनी हो जाती है, उन माताओं की और अनाथ संतानों की दुआएं माननीय मुख्य मंत्री जी को निश्चित रूप से मिलेगी। इसके साथ मुख्य मंत्री जी ने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत एक करोड़ गरीब परिवारों को जो निजी चिकित्सालय के अनुरूप अपना इलाज करवा सकते हैं, जो निजी चिकित्सालयों की दहलीज तक नहीं छू सकते थे, उनका इलाज उन चिकित्सालयों में 30 हजार से लेकर 3 लाख तक उनका नि:शुल्क इलाज होगा।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदया को जर्जर और बदहाल स्थिति में यह राजस्थान मिला था। इस राजस्थान की सुध लेकर नींव से मजबूत करने का जिम्मा जनता ने उनको दिया था। उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी ने विशेष योग्य जनों की पेंशन बढ़ाकर, विधवाओं की पेंशन बढ़ा कर, बुजुर्गों की पेंशन बढ़ा कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा कर राजस्थान का जो निचले पायदान पर नंबर था, उसको उच्च पायदान पर लाने का इन्होंने पूरा पूरा प्रयास किया। यह जो गरीब लोग हैं, विशेष योग्यजन, विधवा, वृद्धावस्था या अन्त्योदय परिवार के जो लोग हैं उनमें नया आत्मविश्वास पैदा कर के उनका स्वाभिमान बढ़ाने का उन्होंने कार्य किया है।

सभापति महोदय, मैंने पूर्व में ही कहा था कि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं और गांवों की कल्पना ही यह थी कि उस गांव में उड़ती हुई धूल, कंटीले रास्ते, कीचड़ से भरे हुए मार्ग, गांव में कोई जाता तो वह अलग ही कल्पना करता, उनको सुदृढ़ करने के लिये, गांवों को सुदृढ़ करने के लिये, ग्रामीण जनता को सुदृढ़ करने के लिये माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने ग्रामीण गौरव पथ की एक सोच इस राजस्थान को दी और इससे पूरे गांवों का एक नया रूप संवारा। दुष्यंत के उस शेर की अवधारणा को इन्होंने फीका कर दिया और जिसमें कहा गया हर किसी के पैर घुटने तक कीचड़ से सने हैं।

(15.00 बजे)

और ऐसा कर माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा राजस्थान की आधी से अधिक आबादी को एक ग्रामीण गौरव पथ के रूप में अपनेपन का आभास करवाया और ऐसा एक संवेदनशील मुख्य मंत्री ही कर सकता है। हमारी मुख्य

(श्री अर्जुन लाल)

मंत्री जी ने आज पूरे राजस्थान को, चाहे शहरी गौरव पथ हों, चाहे ग्रामीण गौरव पथ हों, उनसे पूरे राजस्थान को गौरव के पथ पर चलाकर राजस्थान का पूरे देश में गौरव बढ़ाया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि आपकी यह जो कार्य योजना है, निश्चित रूप से आने वाले आगामी चुनावों में और इन जन कल्याणकारी नीतियों के कारण कई पीढ़ियों तक अपनी पार्टी को बल मिलेगा और आपका यशोगान होगा। मेरे बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी ने हाल ही में एडीजे कैम्प कोर्ट की स्थापना कर उसे प्रारंभ करने के लिए जो प्रयास किया और आज स्वीकृति जारी की है, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री द्वारा मेरे गांव के गरीबों का कितना इन्होंने खयाल रखा है, इस बात से पता चलता है कि जब गांव का गरीब मजदूर शहरों की तरफ अपनी मजदूरी करने के लिए शहर जाता है तो वहां पर उनके लिए कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि खाली पेट सोना पड़ जाता है। जैसा महात्मा गांधी जी ने भी कहा था 'दुनिया में ऐसे लोग हैं, जो इतने भूखे हैं कि भगवान उन्हें किसी और रूप में नहीं दिख सकता, सिवाय रोटी के' रूप में। लेकिन उन गरीबों के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने प्रदेश के सभी शहरों में अन्नपूर्णा रसोई योजना को लागू किया और उन मजूदरों को फाइव स्टार जैसा खाना बहुत ही सस्ती दर पर देने का निर्णय किया। महोदय, यहां सस्ती दर का जिक्र करें तो मुख्य मंत्री महोदया भोजन मुफ्त में भी दे सकती थीं, लेकिन उन्होंने हमारी पार्टी की विचारधारा के अनुरूप और उन लोगों का स्वाभिमान बढ़ाने के लिए उनको मुफ्त भोजन नहीं देकर न्यूनतम दर पर भोजन देने का प्रयास किया है। इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि यह जो योजना है, यह शहरी क्षेत्र के अंदर लागू हुई है, लेकिन ऐसे कई धार्मिक स्थल हैं, ऐसे कई पर्यटक स्थल हैं। जैसे नागौर के अंदर बुटाटी धाम है। वहां पर लकवा ग्रस्त पीड़ितों को आध्यात्मिक पद्धति से चिकित्सा लाभ हो रहा है। वहां पर पूरे देश और विदेश से भी लोग अपने पैरालाइसिस के इलाज के लिए आते हैं और उनका वहां पर निश्चित रूप से उपचार भी होता है। वहां पर प्रतिदिन करीब हजारों की संख्या में रोगियों और उनके परिजनों का

(श्री अर्जुन लाल)

जमावड़ा रहता है। मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि वहां के ट्रस्ट के द्वारा उनके लिए रहने की तो व्यवस्था है, लेकिन भोजन की व्यवस्था वहां पर नहीं हो पा रही है। तो अन्नपूर्णा रसोई योजना को ऐसे धार्मिक स्थल, चाहे बुटाटी धाम हो, जैसे रामदेवरा हो, पुष्कर है, मेंहदीपुर बालाजी है, जो छोटे स्थान हैं और वहां पर उनके भोजन की व्यवस्था नहीं हो सकती तो ऐसे स्थलों को भी इस अन्नपूर्णा रसोई योजना से जोड़ें तो निश्चित रूप से मुख्य मंत्री जी को ईश्वरीय आशीर्वाद मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार शास्त्रों में माना गया है - 'क्षिति-जल-पावक-गगन-समीरा, पंचतत्व से बना शरीरा'। जिस जल को मानव शरीर का एक अभिन्न घटक माना गया है। महोदय, जहां राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से पानी की कमी रहती है, उससे निजात दिलाने के लिए हमारी माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक महत्वाकांक्षी अभियान इस राजस्थान को दिया, जिसका नाम मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान रखा गया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में, पूरे ज़िले में और इसके अलावा पूरे प्रदेश में इसकी सराहना की गई और गत वर्ष पूरे राजस्थान के अंदर इस अभियान के तहत जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं, उससे निश्चित रूप से हमारे इस प्रदेश का जल स्तर ऊँचा हुआ है और मूक बधिर पशुधन को पानी पिलाने के लिए छोटे-मोटे तालाबों में, एनिकट्स में आज भी पानी भरा हुआ है। उससे आज निश्चित रूप से पूरे प्रदेश को लाभ मिला है। निःसंदेह इन दूरगामी परिणामों से प्रदेश को नहीं, अपितु पूरे देश को फायदा मिलेगा और आने वाले समय में यह अभियान जन मानस के लिए वरदान साबित होगा।

मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के अंदर बिलाड़ा और पिपाड़ शहर दो नगरपालिकाएं, जिनकी आबादी करीब पचास हजार है और स्वच्छता अभियान के तहत अभी दोनों नगरपालिकाओं को हमने ओ.डी.एफ. करवाया, लेकिन इन नगरपालिकाओं को सीवरेज सिस्टम से जोड़ने की घोषणा निश्चित रूप से इसी बजट में करें तो यह मेरे क्षेत्र के लिए और प्रदेश के लिए बहुत अच्छा होगा और अंत में, मैं इस बजट के बारे में अपनी यही राय दूंगा-

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री अर्जुन लाल)

'सपनों में नया सवेरा है, जिसमें इंकलाब लिखा है,

अपनी स्वर्णिम कलम से विकास का सच्चा ख्वाब लिखा है,

माना बहुत सवाल उठाओगे तुम इस पर,

लेकिन इसके हर शब्द में उनका जवाब लिखा है'

आपने समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री धर्मपाल जी।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय सभापति महोदय, आपने आज बजट 2017-18 पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री ने सदन में 2017-18 का जो बजट पेश किया है, उसके समर्थन में मैं अपने विचार रखते हुए राजस्थान के चहुंमुखी विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी जो 'सबका साथ, सबका विकास' की अवधारणा रखती है, उसको पूरा करने के लिए यह बजट पेश किया गया है। अभी जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य बहुत ऊंची-ऊंची आवाज में अपनी बात कहकर गए हैं कि राजस्थान की सरकार ने तीन साल में कोई विकास नहीं किया। इस बजट का कोई मतलब नहीं, कहावतों के माध्यम से अपनी बात कहकर। इस सदन में जो लोग अपनी बात को कहकर जाते हैं तो उनको दूसरे की बातों को भी सुनना चाहिए और कहने के बाद चले जाते हैं। ऐसे सभी माननीय सदस्यों के लिए, सभापति महोदय, विधान सभा में यह होना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करता है, उसको दूसरों के विचार भी सुनना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। अब जहां तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आज नोटबंदी पर कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता चार करोड़ की गाड़ी में चार हजार रुपए बैंक से निकलवाने जाते हैं और पूरी कांग्रेस सड़कों पर आकर यह कहती है कि आने वाले समय में जो नोट बंदी का मामला है, वह इस सरकार को बहुत भारी पड़ेगा।

इससे आमजन को, गरीब को बहुत बड़ी तकलीफ हुई है। लेकिन जो पांच राज्यों के चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य जहां पर 80 सांसद चुनकर आते हैं वहां पर यह पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ सकी।

एक माननीय सदस्य: 85 हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): 80 हैं, 5 तो उसमें से चली गईं उत्तराखण्ड में, 403 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने 325 सीट का इतिहास बनाया है उससे इनको सबक लेना चाहिए। उत्तराखण्ड को किसी ने याद ही नहीं किया। उत्तराखण्ड में 70 में से 57 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती और कांग्रेस 11 सीट जीती है। गोवा और मणिपुर में क्या हुआ...

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): घोटाला...

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): घोटाला तो जनता जानती है, किसका घोटाला, क्या घोटाला।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा रहे हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ऐसा है हाथी कहां गया, कहां नहीं गया ...(व्यवधान)...

श्री रमेश (सपोटरा): आपकी जगह बोलो, भूल जाओगे। राज्य सभा की तरह आपने वोट में, क्रम में बदल जाएगा। सही-सही बोलो। भूल जाओगे कहीं।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ऐसा है कौन किसका बदल जाएगा, कौन किसका नहीं बदलेगा, आपसे पूछकर तो कोई किया नहीं। आपने कुछ देखा नहीं। आपको वोट दे दो, आपने कोई पैसा दिया नहीं, कोई दिया तो बता दो कि आपने कोई माल पानी दिया हो। आपके बीच में किसी से बात की हो। तब तो कोई बात बनती है, कहने से, यह जो पर्सनल मामले हैं उन पर नहीं बोलें तो अच्छा रहेगा। ...(व्यवधान)... यह बोलते रहेंगे मेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला।

श्री सभापति: आप अपना वक्तव्य जारी रखें।

श्री मदन राठौड़, (सरकारी उप मुख्य सचेतक): यह कितने दल बदल चुके, यह तो बता दो।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): इस तरह से पूरे हिन्दुस्तान में, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का सपना है कांग्रेस मुक्त भारत। जिस तरह का माहौल चल रहा है, आप राजस्थान में भी सपने लेने छोड़ दीजिए। अगली बार भी यहां भारतीय जनता पार्टी का राज बनेगा। यहीं नहीं, 6 विधान सभाओं के चुनाव, 2017-18 और 2019 में है, उसमें भी सारी

(श्री धर्मपाल चौधरी)
सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का राज होगा। उमर अब्दुल्ला जी ने पहले कहा कि 2019 की छोड़िए 2024 के चुनाव की तैयारी कीजिए। इसलिए आपको उन बातों को ध्यान में रखकर आगे अपनी मेहनत करनी चाहिए। तब ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आप इस स्थिति में ही नहीं हो कि इन स्टेट में आप किसी के साथ खड़े हुए बिना चुनाव लड़ सकें।

माननीय मुख्य मंत्री महोदया के कुशल नेतृत्व में प्रदेश के जन साधारण के जरिए राजस्थान प्रदेश के सामाजिक विकास का कदम उठाया है। कौशल विकास के लिए, सर्वश्रेष्ठ कौशल राज्य के रूप में गोल्ड मैडल राजस्थान की सरकार ने प्राप्त किया है। ई-गवर्नेंस का स्वर्ण पदक भी राजस्थान सरकार की झोली में आया है। एलइडी लाइट के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सौर ऊर्जा पुरस्कार भी मिला है। कर्मण पुरस्कार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ में। वैसे काका कहते हैं, मेरा मामा, झुन्झुनूं जिले को पूरे भारत वर्ष में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान में पुरस्कार मिला है। इस बजट में जो विजन है वह 2020 है। उसके विकास की नई दिशाओं को ध्यान में रखते हुए इस बजट में जो पेश किया है उसमें खुशहाल राजस्थान, खुशहाल राजस्थानी, हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्री का सपना। सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए महिला सशक्तीकरण को बल देने के लिए इस बजट में अनेक प्राथमिकताएं हैं। कहते हैं कोई काम नहीं है, सड़क एक ऐसी चीज है जो 21 वीं सदी में महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह योजना चालू की थी कि एक हजार आबादी तक के गांवों को सड़क से जोड़ा जाए। मैं ज्यादा आंकड़ों में नहीं पड़ते हुए आपसे यही कहना चाहता हूं कि सड़क में गौरव पथ, लिंक रोड, नेशनल हाइवे, अभी 27 हजार करोड़ के नेशनल हाइवे का शिलान्यास देश के परिवहन मंत्री गडकरी जी ने किया वह सब आपके सामने है। सड़क मार्ग के लिए सबसे अच्छा काम किया।

शिक्षा के क्षेत्र में भी जितनी पदोन्नति इस सरकार ने दी वह पिछली सरकार के समय नगण्य थी। एक साथ पांच हजार हायर सैकण्डरी स्कूल प्रत्येक पंचायत में, 12वीं का स्कूल हो, प्रिंसिपल की पदोन्नति हो, शिक्षा के जगत में भी (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मैं दो मिनट अपनी बात कह लूं,

(श्री धर्मपाल चौधरी)

बाकी छोड़ देता हूं। अलवर जिले को 907 करोड़ रूपये एनसीआरपीबी में, पूरे जिले को दिया इसके बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे विधान सभा क्षेत्र में, नीमराना में जापानी जोन के अंदर कौशल, काम करने के लिए, स्थापना की उसके लिए धन्यवाद।

मेरे क्षेत्र की कुछ मांगे हैं। एडीजे कोर्ट की स्थापना, एडीजे कोर्ट सैकिण्ड जो किशनगढ़बास में चलता है उसके अंदर एक हजार केस मुण्डावर के हैं इसलिए इसको किशनगढ़ से मुण्डावर में शिफ्ट किया जाए।

मुण्डावर में बालिका डिग्री कॉलेज खोला जाए। उसके लिए पूरी बिल्डिंग और जितनी जमीन सरकार को चाहिए उतनी दानदाता देने के लिए तैयार हैं। नीमराना को जिला बनाने के लिए भी मैं, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): कोर्ट मांगो आप।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): एडीजे सैकिण्ड है उसमें आपके मुकदमे हैं ही नहीं।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): वह एडीजे किशनगढ़ है सैकिण्ड।

श्री सभापति: अपना वक्तव्य पूरा करें।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): मेरी सबसे बड़ी मांग है डीएमआईसी में दिल्ली मुम्बई इंडस्ट्रीयल कोरीडोर के अंदर जो जमीन किसान से 2012 में ली है, कांग्रेस के समय भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हुआ अब वह भूमि अधिग्रहण हो चुका है, उसकी पेमेंट सरकार जल्दी से जल्दी कराने की कृपा करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री गोरधन जी।

श्री गोरधन (धोद): धर्मपाल जी भाई साहब जैसा कह रहे हैं ना कि यूपी और उत्तराखण्ड में जिताने के लिए, तो वह जिताया तो राहुल गांधी जी ने है, क्योंकि वह जहां जहां जाते हैं वहां वहां ही बंटाधार है।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्री जी वसुन्धरा जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने प्रदेश के लिए इतना शानदार बजट पेश किया है।

(श्री गोरधन)

इस बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किसी भी वर्ग या किसी भी वस्तु को अछूता नहीं छोड़ा है, जिससे किसी वर्ग को फायदा नहीं हुआ हो, किसी समाज को फायदा नहीं हुआ हो, किसी बेरोजगार को फायदा नहीं हुआ हो। व्यापारी, किसान, मजदूर सबके हितों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को पेश किया गया है।

इस बजट की एक खास बात और भी है कि इस बजट के अंतर्गत एक भी न तो किसी कर को बढ़ाया गया है, न कोई अतिरिक्त कर लगाया गया है। मैं सोचता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस प्रकार से इन तीन सालों के समय में जितनी मेहनत इस राजस्थान के विकास के लिए की है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने जिस प्रकार से इस प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा किया था, आज यह प्रदेश विकसित प्रदेशों की श्रेणी में गिना जाता है। जिस प्रकार से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का राज, चाहे केन्द्र में आया हो या स्टेट में आया हो, जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो प्रत्येक व्यक्ति के हितों को ध्यान में रखते हुए, उस गरीब जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसी योजनाएं बनाई जाती हैं जिससे आमजन को फायदा हो। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की जनता का रुझान बढ़ा है। मैं सोचता हूं कि जिस प्रकार से, क्योंकि सभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि 2024 तक भारतीय जनता पार्टी लगातार आती रहेगी, मैं तो यह कहूंगा कि मोदीजी जब तक जिंदा हैं, तब तक भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): इसके बाद नहीं आएगी न।

श्री गोरधन (धोद): उसके बाद में आएगी, उसके बाद दूसरा आ जाएगा, राजकुमारजी। चिंता मत करो आप। लेकिन उसके बाद में तो आप भी नहीं रहेंगे ना इसकी क्या गारण्टी है।

एक माननीय सदस्य: उससे पहले तो भारत कांग्रेस मुक्त हो ही गया, बचेगा ही क्या।

श्री गोरधन (धोद): हां, उससे पहले तो हो गया।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद इसलिये भी देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से इस प्रदेश की जनता के लिये अनेक योजनाओं, चाहे

(श्री गोरधन)

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना हो, चाहे भामाशाह योजना हो, चाहे मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना हो, चाहे मुख्य मंत्री राजश्री योजना हो, चाहे ग्रामीण गौरव पथ हो, चाहे आदर्श विद्‌यालय हो, ऐसी अनेक योजनाएं चलाई गयी हैं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति का भला हो सके। मैं सोचता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला, 08 मार्च को भी अपने बजट में घोषणा की थी, किसानों के हित में लिया है। बिजली की जो दरें बढ़ाई गयी थीं, उन दरों को वापस कम करते हुए पूरा भार राज्य सरकार के ऊपर लिया गया है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को मेरी धोद की जनता की ओर से, पूरे प्रदेश की ओर से बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने किसानों के हित में एक बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया है। राजस्थान सरकार जिस प्रकार से माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में और हमारे मंत्रिमण्डल टीम के सहयोग से राजस्थान के विकास के लिये जिस प्रकार से प्रयत्नशील है, उसी का एक ताजा उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी पिछले दिनों सालासरजी में सड़कों का जो भव्य शिलान्यास हुआ था, उसमें हमारे केन्द्रीय मंत्री माननीय गडकरीजी पधारे थे। उसमें हमारे माननीय राठौड़ साहब और यूनुस खानजी भी वहां मौजूद थे। उन्होंने जो भी मांग वहां पर रखी, उन सब मांगों को पूरा किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि आपके पास में और भी कुछ सड़कों के सम्बन्ध में बचा है तो वह भी मैं कर सकता हूं। तो, मैं सोचता हूं कि राजस्थान में जिस प्रकार से हमें कहीं देखने को मिलता था कि जहां सिंगल रोड नहीं होती थी, वहां आज डबल रोड, फोर लेन रोड और सिक्स लेन रोड भी हमें चमचमाती हुई दिखाई देती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी ओर से इस बजट के लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सीकर के पास में मेरे विधान सभा क्षेत्र धोद में जो हर्ष पहाड़ पड़ता है, पर्यटन की दृष्टि से वहां पर हर्षनाथजी का काफी अच्छा मन्दिर भी बना हुआ है। माउण्ट आबू के बाद में दूसरी चोटी है, क्योंकि उसकी ऊँचाई भी काफी है, लेकिन छोटा सा एक पहाड़ है। हमारे माननीय मंत्री राजकुमारजी रिणवा भी दो-तीन बार, जब इस डिपार्टमेंट के मंत्री रहे हैं, गये हैं। वहां पर 15 किलोमीटर सड़क जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी स्वीकृत की है, मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूं कि

(श्री गोरधन)

वह सीकर के लिये ही नहीं, पूरे राजस्थान के पर्यटन के लिये एक बहुत अच्छी सौगात माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दी है। शेखावाटी यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, जो बजट के अभाव में यूं कह सकते हैं कि उसको गति नहीं मिली थी, लेकिन इस बजट में उसका भी 12 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उसके लिये भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, क्योंकि समय कम है, तो मैं मेरी एक-दो बात बताना चाहूंगा। वैसे तो धोद विधान सभा क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ इलाका है, क्योंकि वहां पर लगातार बीस सालों से कम्युनिस्ट जीतते रहे हैं।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): आपने क्या किया, वह बता दो।

श्री गोरधन (धोद): हमने वह किया, जो 50 सालों में नहीं हुआ। चाहे, आप जाकर देख लेना। चाहे वहां की जनता से भी पूछ लेना। मैं नहीं कह रहा, आप वहां से पूछना। क्योंकि राजकुमारजी उधर से आते हैं तो इनको पता है, लेकिन फिर भी क्या है कि मैं सोचता हूं कि ये कम्युनिस्टों से शायद भली-भांति परिचित नहीं हैं। ...(व्यवधान)... वे भोली-भाली जनता को बहला-फुसला कर, जिस प्रकार से अपने पक्ष में करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वहां की जनता अब समझ चुकी है। इसी के परिणामस्वरूप वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल जीता है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र धोद में नगरपालिका लोसल का एक क्षेत्र पड़ता है, जिसमें श्री बद्रीनारायण सोढानी हास्पिटल पूर्व में संचालित है, जिसमें काफी बड़ी बिल्डिंग भी बनी हुई है। वहां पर स्वास्थ्य-चिकित्सा से सम्बन्धित जो भी मशीनरी है, वह भी वहां पर उपलब्ध है और वहां डाक्टर भी बैठता है। लेकिन मेरा निवेदन है कि उस हास्पिटल को सिटी डिस्पेंसरी का दर्जा दिया जाए। वह नगरपालिका क्षेत्र के बीच में स्थित है, जिससे लोगों को काफी फायदा होगा। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) मेरा दूसरा निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र धोद, क्योंकि पूरे सीकर जिले में नहीं, पूरे राजस्थान में हर तहसील में रीको स्थापित है, तो मैं मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र में भी एक रीको की स्थापना हो, जिससे छोटा-मोटा उद्योग वहां भी लगाया जा सके। मेरी अंतिम एक छोटी सी मांग और है कि विधान सभा

(श्री गोरधन)

क्षेत्र धोद में, क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र काफी अच्छा है ओर वहां पर निजी शिक्षण संस्थाएं काफी हैं, लेकिन वहां पर सरकारी कॉलेज नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकारी कॉलेज की वहां पर स्थापना की जाए। आपने समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जयहिन्द। वंदे मातरम।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय श्री राजेन्द्र सिंहजी भादू।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। 8 तारीख को आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया, उस बजट का मैं पुर-जोर शब्दों में समर्थन करता हूं और याद करता हूं उस दिन को, उस 19 जनवरी के दिन को जब देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्रजी मोदी मेरे विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में पधारे और राजस्थान, पंजाब और हरियाणा सहित सभी क्षेत्र के किसानों ने वहां इकट्ठा होकर उनकी मौजूदगी के अंदर मिट्टी परीक्षण केन्द्र का, जो देश को समर्पण किया, वह एक मिसाल है और उस मिट्टी परीक्षण केन्द्र की वजह से, मिट्टी का परीक्षण करने की वजह से जो पूरे देश के किसानों को फायदा हो रहा है, निश्चित रूप से अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। राजस्थान के माध्यम से देश के प्रधान मंत्री ने जो यह सौगात दी है किसानों को, इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।

इसके साथ-साथ जब आदरणीय मोदीजी का सूरतगढ़ में दौरा हुआ तो कृषि विभाग के अंदर एक बहुत व्यापक स्तर पर एक वातावरण बना। कृषकों के प्रति समर्पित कृषि विभाग ने बड़े-बड़े मेलों का आयोजन शुरू किया। अच्छी खाद और बीज की व्यवस्था की और पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर की कभी कमी नहीं आए, इस बात को लेकर यह सुनिश्चितता तय की कि किसानों को अच्छी किस्म की दवाइयां मिले, बीज मिले और समय पर उनको खाद मिले। उसके साथ-साथ में यह व्यवस्था की गयी कि जिस तरह से अभी कृषि जिंसों की जो खरीद है, सहकारिता विभाग है या तिलम संघ हो, सबके साथ मिलकर, उनकी समय पर खरीद की जाए, उनकी व्यवस्था ठीक ढंग से की जाए और उसी का परिणाम है कि कृषि के क्षेत्र में हमारा प्रदेश बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है।

आदरणीया वसुन्धरा जी ने पिछले दिनों जयपुर में एक बहुत बड़े मेले का आयोजन किया और हमारे क्षेत्र से किसान जब यहां पर पहुंचे तो उन्होंने

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)
इस बात को महसूस किया कि कृषि के क्षेत्र में राजस्थान सरकार की क्या सोच है। क्या सोचती हैं आदरणीया वसुन्धरा जी कि इस तरह से व्यापक स्तर पर जब काम होंगे तो निश्चित रूप से किसानों को राहत मिलेगी। मुझे याद है 17 अगस्त का वह दिन भी जब आदरणीया वसुन्धरा जी ने नितिन जी गडकरी को, देश के परिवहन मंत्री को, आदरणीय युनुसजी को साथ लेकर जब सूरतगढ़ में प्रवास किया तो 292 करोड़ रुपये की पहली सी.सी. रोड जो सूरतगढ़ से अनूपगढ़ तक अब बनने जा रही है, उसका शिलान्यास किया और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि 15 किलोमीटर सड़क आज वह बनकर तैयार हो गयी है। एक साल के अंदर यह 78 किलोमीटर लंबी जो परियोजना है, वह पूरी की पूरी तैयार होने वाली है।

उसके साथ-साथ सूरतगढ़ से गंगानगर तक के लिए 75 किलोमीटर का नेशनल हाइवे का लोकार्पण भी उसी दिन हुआ। उस दिन सूरतगढ़ का बहुत अच्छा दिन था, उस दिन सूरतगढ़ के अंदर 107 करोड़ रुपये की सीवरेज योजना का भी शिलान्यास हुआ। उस दिन सूरतगढ़ शहर के अंदर आम जन को निकलने के लिए व्हीकल अंडर पास के लिए भी आदरणीया वसुन्धरा जी और नितिनजी गडकरी ने शिलान्यास किया और न जाने कितने इतने काम हैं, जिनके बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहूं। वह दिन ऐसा था जो सिंचाई के क्षेत्र में शायद पहली दफा ऐसा बड़ा काम हुआ, अनूपगढ़ ब्रांच के 132 करोड़ रुपये की री-लाइनिंग का काम भी उसी दिन शुरू हुआ। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि जल संसाधन मंत्रालय द्वारा जिस तरह से सूरतगढ़ ब्रांच का पुनर्निर्माण का काम अब शुरू किया है, जिस तरह से पक्के खालों का, भाखड़ा के अंदर और भाखड़ा की सब नहरों का काम शुरू किया है, वह अपने आप में एक उदाहरण है, उसको भुलाया नहीं जा सकता, झुठलाया नहीं जा सकता।

मैं ऐसे विधान सभा क्षेत्र से आता हूं जहां पांचों नहरों का पानी लगता है। पांच तरह से सिंचाई योजनाएं होती हैं। गंग कैनाल का कुछ क्षेत्र मेरे विधान सभा क्षेत्र में है। राजस्थान कैनाल प्रमुख रूप से मेरे सूरतगढ़ के पास से निकलती है। भाखड़ा नहर का पानी मेरे सूरतगढ़ क्षेत्र में लगता है। ट्यूबवैल से खेती वहां पर होती है और इसके साथ-साथ घग्घर बहाव क्षेत्र के

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

अंदर घग्घर नदी का पानी भी वहां आता है। इतनी सब बातें, सब व्यवस्थाएं होने के बाद में अब जब मनरेगा के अंदर हमारे क्षेत्र के लोगों को, क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 29 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति के रहते हैं। उन्हें काम देने के लिए राज्य सरकार ने बहुत बड़ी योजना बनाई। 'आपणा खेत, आपणा काम' योजना के तहत जब अनुसूचित जाति के किसान को 3 लाख रुपये घर बैठे मिलता है, उस अनुसूचित जाति के मेरे भाई को एक लाख रुपया कैटल-शेड का मिलता है, बनाने के लिए तो यह अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन है। जिन गांवों की गलियों में, जिस शहर के मौहल्लों से हम गुजरते थे और जहां पर थोड़ी बदबू आनी शुरू हो जाती थी तो हम बात करते थे कि यह कांग्रेस का मौहल्ला आ गया लेकिन आज हमें फख्र इस बात पर, हमारी आदरणीया मुख्य मंत्रीजी पर कि उन्होंने गौरव पथ का निर्माण करवा कर, वहां पर नालियां बनवाकर और आदरणीय नरेन्द्रजी मोदी की प्रेरणा से वहां पर जो सफाई का कार्यक्रम आया है, वह अपने आपमें एक बहुत अनूठी पहल है। अब हमारे वहां पर पता नहीं लगता कि कौन सी बस्ती किस तरह के लोगों के रहने वाली है तो यह हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है।

इसके अलावा पशु-पालन विभाग के द्वारा समय-समय पर हमारे बहुत बड़े काम किये गये हैं। पशु-पालन विभाग द्वारा टीकाकरण का काम, जगह-जगह पर उप-स्वास्थ्य केन्द्र पशुओं के लिए और हमारी जो बीकानेर की यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा समय-समय पर पशुओं की सार-संभाल और प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जो पशु-पालन विभाग द्वारा कार्य किये जा रहे हैं, निश्चित रूप से वह सराहनीय है। बहुत लंबी चौड़ी फेहरिस्त है हमारे पास में विकास के काम की लेकिन ज्यादा समय न लेते हुए एक-दो बात निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदया को, सरकार से निवेदन करना चाहूंगा।

मेरे सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में ठीक सूरतगढ़ से 25 किलोमीटर की दूरी पर थर्मल पावर स्टेशन है। 250 x 6 की यूनिट्स लगी हुई हैं, 1500 मेगावाट का वहां पर प्रोडक्शन होता है, 660-660 की दो यूनिट अभी और लग रही है। इतनी बड़ी चिमनियां लगने के बाद में वहां बड़े धुआं का जो

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)
प्रकोप बना रहता है, आस-पास के गांवों में। 15-20 गांव वहां पर ऐसे हैं जिनमें हर वक्त प्रदूषण बना रहता है। उस क्षेत्र के अंदर बिलकुल पास ही राजस्थान कैनाल, इंदिरा गांधी की जो मुख्य नहर है, वह निकलती है और वह जो क्षेत्र है वह सारा का सारा टीबा क्षेत्र है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करूंगा कि वहां लगातार चल रही 40 साल पुरानी एटा सिंगरासर माइनर नहर का वहां पर निर्माण किया जाए और वह नहर उस क्षेत्र के लिए जीवन-दायिनी होगी और पिछली बार सदन में आदरणीय जल संसाधन मंत्री महोदय ने एक कमेटी का गठन भी किया था कि पानी की उपलब्धता पर उस नहर का निर्माण किया जाएगा। आज मैं इस मंच के माध्यम से, इस विधान सभा के अंदर यह फिर निवेदन करना चाहूंगा कि 60, 70, 80 क्यूसेक्स पानी कोई ज्यादा नहीं होता तो मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उस नहर का निर्माण कराया जाए।

इसके साथ-साथ जिला परिषद द्वारा और पंचायत समितियों द्वारा जो पक्के खालों का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, उसमें बहुत शिथिलता है। उदासीन रवैये के अधिकारियों के चलते हुए जो काम हमें जितनी तेजी से और जल्दी से करवाने चाहिए वह काम ठीक ढंग से पूरी तरह से नहीं हो पाते हैं। ग्राम पंचायत स्तर हो या पंचायत समिति स्तर हो या जिला परिषद स्तर पर हो, उस कार्य को जल्दी स्वीकृतियां नहीं मिलने की वजह से वह काम अटके पड़े रहते हैं तो मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि उन कामों को जल्द से जल्द स्वीकृत कराया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री पूरणमल सैनी, कृपया पांच मिनट में वक्तव्य पूरा करें।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, बजट सत्र 2017-18 के आय-व्ययक पर दिनांक 9 मार्च से लगातार सदन में चर्चाएं हो रही हैं और इस पर मुझे भी मेरी बात रखने का अवसर दिया, मेरी बात रखने से पहले आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को यहां से स्टार्ट करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता हमारे प्रदेश के लिये तीसरे स्तम्भ के रूप में माना जाता है। माननीय सभापति महोदय,

(श्री पूरणमल सैनी)
जिसमें सामाजिक समरसता कायम रखने के साथ-साथ बेहतर चिकित्सा व्यवस्था प्रदान करना, लिंगानुपात को प्रोत्साहित करना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना होता है। लेकिन जहां एक ओर आर्थिक आधारभूत संरचना जैसे बिजली, पानी, सड़क को मजबूत करना सरकार की प्रमुखता होनी चाहिये तथा सामाजिक आधारभूत संरचना जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास एवं रोजगार के नये अवसर सृजित करने चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, यह बात सही है लेकिन मेरा यहां एक छोटा-सा सवाल है कि सरकार के आ जाने के तीन वर्ष बाद में आज तक किस विभाग में कितने रोजगार सरकार ने उपलब्ध करवा दिये? सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा जब बात रखी जाती है तो माननीय मुख्य मंत्रीजी के गुणगान में ही लगे रहते हैं और प्रतिपक्ष का माननीय सदस्य रखता है कि आपने रोजगार उपलब्ध करवाने की बात नहीं की तो उनको यह कहकर रोक दिया जाता है कि आपके वक्त में हालात प्रदेश में क्या हुए? आपके पहले यह कहते रहे कि राजस्थान में आपके समय में क्या हालात हुए?

माननीय सभापति महोदय, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आजादी से 70 वर्षों के बाद और 70 वर्षों में 70 प्रतिशत राज इस देश और प्रदेश पर कांग्रेस ने किया है। मैं पहले भी बार-बार निवेदन करता रहा हूं कि उस गरीब को, जिसको रोजगार देने की बात करनी चाहिये थी, उसको केवल कहने के लिये बी.पी.एल. का सर्वे करवाकर मासिक रूप से उसे दो रुपये किलो के हिसाब से 35 किलो अनाज उपलब्ध करवाते हुए और अपने वोट तक उनको जिन्दा रखने का काम किया। इसलिए वह गरीब तो जिन्दा है, लेकिन पार्टियां अपनी सरकारों के माध्यम से मरती जा रही हैं। माननीय सभापति महोदय, यह कोई अतिश्योक्ति नहीं है। चाहे वह उत्तराखण्ड में सरकार बने, चाहे उत्तर प्रदेश में बने, चाहे राजस्थान में बनी, लेकिन इसके लिये ज्यादा खुश होने की किसी को जरूरत नहीं है। माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान प्रदेश में इस बात की जरूरत है युवाओं को रोजगार देने की और उस रोजगार के लिये हम किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं कर रहे।

माननीय सभापति महोदय, कृषि से संबंधित अगर हम कोई बात कहें, तो कोई भी सरकार जब बनी तो अपना हर वर्ष का बजट लेकर आती रही है

(श्री पूरणमल सैनी)
और वहां की पब्लिक की, विभाग की जरूरत के अनुसार लेकर आती रही है और उस बजट में हर बार वृद्धि होती रही है, यह कोई विशेष बात नहीं है। आवश्यकता के अनुसार वृद्धि भी करनी पड़ती है, लेकिन उपलब्धता के आधार पर। माननीय सभापति महोदय, कृषि की हम बात करें तो 2017-18 में भी सरकार किसानों के लिये किये हुए वादों पर खरी नहीं उतरी और एग्रेटेक मीट का आयोजन संभाग स्तर पर कराने की घोषणा की, लेकिन इसमें किसान वर्ग का सदस्य उस मीटिंग में होता नहीं है। यह केवल और केवल कृषि व्यापारियों के हित में इस मीट का आयोजन किया जाता है। माननीय सभापति महोदय, किसान का नाम लेकर उनके वोट को लूटने का काम किया जाता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार वास्तव में अगर किसान के हित के लिये काम करना चाहती है तो फिर फसल बीमा योजना में, स्वैच्छिक बीमा योजना में सारी व्यवस्था देना चाहती है तो मेरा इतना सा आग्रह है कि जब जब भी कोई पीड़ा किसान के साथ होती है, चाहे वह ओलावृष्टि होती हे, या किसी दूसरे प्रकार की कोई विपत्ति किसान पर आती है तो उनकी मांग थी कि हमारे बिजली का बिल माफ किया जाए, हमारा कर्ज माफ किया जाए। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के किसानों की एक वाजिब मांग थी, उस पर गौर नहीं किया गया। यही नहीं, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान का किसान हर बार कहता है कि हमारी फसल ओलावृष्टि या दूसरे किसी आघातों से नष्ट होती है, उसकी समीक्षा जो करवायी जाती है रेवेन्यू विभाग के द्वारा, वह खेत और खसरा नम्बर के हिसाब से करवायी जाए और यूनिट आपने राजस्व ग्राम के हिसाब से आज तक की है। माननीय सभापति महोदय, किसान के हित में यहां भी कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकारें उपकार के रूप में हर बार कहती हैं कि हम आम आदमी को साथ लेकर चलना चाहते हैं लेकिन मैं बात करूं चाहे वह कांग्रेस की सरकार के समय 2013 की बात करें और एक-एक विभाग की हम बात करना चाहे तो हमारे पास ज्यादा समय है नहीं, मैं अकेले मेरे विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के लिये कहना चाहूंगा।

(श्री पूरणमल सैनी)

अभी मेरे पूर्व वक्ता के रूप में गोरधन जी भी कह रहे थे कि झुन्झुनूं जिले के लिये बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ में हमें केन्द्र सरकार की तरफ से एक तोहफा दिया गया। इसमें माननीय स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री का और राजस्थान की सरकार का क्या योगदान था? वहां के जो रहने वाले निवासी हैं, उनकी उपलब्धता थी। बजट के नाम पर अगर हम कहीं बात करें तो माननीय सभापति महोदय, झुन्झुनूं को ऊँट के मुंह में जीरे के समान बजट मिला है। कल माननीय सदस्य राजकुमार जी कह रहे थे कि उन्होंने वालीबॉल के लिये जो व्यवस्था की, उसमें भी पहले से व्यवस्था की हुई है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं और खेतड़ी की बात करूं तो इन्दिरा गांधी कैनाल आधारित चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना थी, वह 2013 में प्रावधान रखा गया था, उसके लिये बजट का भी प्रावधान था और आज यह जो बजट पेश किया गया है, इसमें यह लिखा गया है कि हम 2018 में पूरी कर लेंगे। माननीय सभापति महोदय, यह तो 2016 में ही पूरा होने वाला था और सब तरीके के प्रावधान इसमें रखे गये थे।

सभापति महोदय, यही नहीं, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो मैं बार-बार सदन में कह चुका हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में दो पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने के लिये फरमाया था, आज तक अगर सबके साथ न्याय एवं समानता का व्यवहार कर रहे हैं तो उन पी.एच.सी. के लिये किसी प्रकार का प्रोविजन न तो कांग्रेस सरकार करके गयी है, न ही आपने किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात को खतम करूं उसके पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सदन की माननीय नेता, मुख्य मंत्री महोदया पिछले दिनों दिसम्बर, 2016 को नागौर की धरती पर किसी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थीं और उन्होंने वहां ध्वजा उत्सव में शिरकत की और जनता की विशेष मांग पर उन्होंने आश्वासन दिया था ऑफ रिकार्ड, कि जब अगली बार होगा तो हम इसके लिये घोषणा करेंगे। इसलिये, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ही वहां कहा था उसके लिये मांग करना चाहूंगा 11 अप्रैल को महात्मा

(श्री पूरणमल सैनी)
ज्योतिबाफुले की जयन्ती के उपलक्ष्य में ऐच्छिक अवकाश की घोषणा करने के लिये सरकार के संज्ञान में डालना चाहता हूं कि वह नागौर की धरती पर गये और जो उन्होंने उस दिन ऐच्छिक अवकाश का आश्वासन दिया था। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि सारे विभागों का न कहकर अकेले खेतड़ी की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग का मैं कह चुका, बिजली की बात करें, क्योंकि दरें बढ़ा दीं। **(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि सब लोगों ने अपनी अपनी तरफ से बड़ाई की, लेकिन इस बजट के लिये मैं यह कहना चाहूंगा कि 'न हमें कुछ रब ने दिया, क्योंकि बरसात नहीं हुई, और न कुछ हमें सदन की नेता सिकन्दर ने दिया, जो भी कुछ हमें दिया, वह बाबा साहब डॉ. बी.आर.अम्बेड़कर ने दिया'। जय भीम। जय भारत।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अनिता कटारा।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा): माननीय सभापति महोदय एवं सदन में बैठे मेरे सभी साथियों को वन्देमातरम् और होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं माननीय सभापति महोदय का आभार एवं धन्यवाद देती हूं जिन्होंने मुझे आज बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया। बड़े हर्ष का विषय है कि सुशासन की मंशा को सार्थक रूप प्रदान करते हुए मुख्य मंत्री महोदया ने अपने चौथे बजट में हर वर्ग को अपनी पूरी संवेदनशीलता के साथ ध्यान रखते हुए अपेक्षित राहत दी है और जनता की अपार उम्मीदों को आधार प्रदान किया है। आमजन को सुगम आवागमन मुहैया कराने की दृष्टि से सड़कों का विस्तार हो, चाहे ग्रामीण गौरव पथ हो या सी.सी. सड़कों का निर्माण हो, बस अड्डों का विकास हो या हवाई सेवाओं की सुदृढ़ता, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हो, चाहे बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था हो, पेंशन में बढ़ोतरी हो, चाहे नवीन छात्रवृत्तियों को प्रारम्भ करने का विषय हो, हर एक के लिये पूरी संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेकर मुख्य मंत्री महोदया ने यह साबित कर दिखाया कि हमारी सरकार आम जनता को आधारभूत साधन-सुविधाओं की पूरी-पूरी उपलब्धता के माध्यम से राहत देने की मंशा रखती है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में विधवाओं की पेन्शन में दोगुनी बढ़ोतरी करते हुए समाज के उपेक्षित वर्ग को सम्बल प्रदान करने की अपनी

(श्रीमती अनिता कटारा)

मंशा उजागर की, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदया को मैं धन्यवाद देती हूं।

आम जनता को शुद्ध पेयजल दिलाने के लिए सरकार की मंशाओं को उजागर करते हुए मुख्य मंत्री जी ने आदिवासी क्षेत्र प्रतापगढ़, अरनोद की पेयजल योजना के लिए 912.55 करोड़ रुपये तथा कुशलगढ़ व सज्जनगढ़ पंचायत समिति के लिए 684 करोड़ रुपये की पेयजल योजना की स्वीकृति व बजट प्रावधान करते हुए क्षेत्रीय जनता की वर्षों पुरानी उम्मीदों को पूरा करने का अनूठा कार्य किया है।

काश्तकारों के लिए सरकार ने आगामी दो वर्षों में एक लाख नये कृषि कनेक्शन का प्रावधान करते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी के माध्यम से अपनी संवेदनशीलता उजागर की है।

शैक्षिक विकास की दृष्टि से छात्रावासों की क्षमताओं में बढ़ोतरी, नवीन भवनों का निर्माण और मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहयोग जैसी योजनाओं को प्रारम्भ करने जैसे निर्णय से माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने विकास और राहत की सोच को साकार किया है।

इसी प्रकार वागड़ क्षेत्र की बात करें तो डूंगरपुर से बिछीवाड़ा सड़क को विकसित करने की घोषणा की है, वो स्वागत योग्य है। इस सड़क की जिले वासियों की लम्बे समय से मांग थी। यह सड़क गुजरात राज्य से जोड़ती है। इसके निर्माण से 8 विधान सभा क्षेत्र की जनता को लाभ मिलेगा।

बांसवाड़ा जिले में मां त्रिपुरा सुंदरी उद्यान के लिए 47 लाख रुपये की घोषणा की। वहीं डूंगरपुर जिले में दो पंचायत समिति मुख्यालय पर प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय खोलने की घोषणा की जिससे पशु पालकों को सम्बल मिलेगा। साथ ही जिले में दो आई.टी.आई. स्थापित करने की घोषणा की। वहीं सब से स्वागत योग्य बात यह है कि एक महिला मुख्य मंत्री होते हुए आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं की भावनाओं को सम्मान देते हुए प्रति माह 250 रुपये से बढ़ा कर 500 रुपये तक प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। वहीं पूरे राजस्थान राज्य सहित जनजाति क्षेत्र के सभी वर्गों को ध्यान में

(श्रीमती अनिता कटारा)
रखते हुए कई योजनाओं का संचालन किया जाएगा जिससे राज्य सहित अन्य क्षेत्र का आम जन विकास, मुख्य धारा से जुड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सागवाड़ा विधान सभा क्षेत्र की जनता की भावनाओं को सदन में रखते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि बजट 2017-18 में सड़कों के नवीनीकरण कार्य के लिए 500 करोड़ रुपये सम्भावित है जिसमें धरियावद से पीठ स्टेट हाई-वे के तहत वाया सागवाड़ा-चीकली स्टेट हाई-वे निर्माण की जरूरत है, जिसकी अनुमानित लागत 70 करोड़ है। वर्तमान में इस सड़क की हालत काफी खराब है। इस सड़क को इस वर्ष में ही निर्माण की जरूरत है।

वहीं नीलकंठ महादेव वांदरवेड़ से सिलोही हाई लेवल ब्रिज का निर्माण, जिसकी अनुमानित लागत 37 करोड़ है। वहीं भीखा भाई नहर का कार्य जो अभी चल रहा है उसको जल्द से जल्दी पूरा करवाने की मैं मांग रखती हूं।

माननीय सभापति महोदय, आपने आज मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य, श्री विट्ठल शंकर अवस्थी जी।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): आदरणीय सभापति महोदय, बजट पर सामान्य वाद-विवाद में आपने मुझे बोलने का जो अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, बजट प्रति वर्ष पेश होते हैं। लोकतंत्र में जो सरकार चुनी जाती है उसका प्रमुख उद्देश्य होता है जन कल्याण, जनता की सेवा करना और जनता इसीलिए हम को चुनती है कि हम किस तरीके से जनता का सर्व प्रकार से भला कर सकें, उनके दुख और दर्द दूर हो सकें। हमारा राजस्थान प्रदेश जो विकास की गति में पिछड़ रहा था पिछली सरकार के कार्यकाल में, उसको हम किस प्रकार से आगे लाए, इसी को ध्यान में रखते हुए यह सारे बजट तैयार किये गये हैं।

घोषणाएं तो प्रति वर्ष होती हैं लेकिन प्रमुख बात यह है, सभापति महोदय, कि इन घोषणाओं पर अमल किस प्रकार से किया जा रहा है। मेरे

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)
भीलवाड़ा क्षेत्र में पिछले वर्ष बजट में मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने राजस्थान में सात-आठ मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी, उसमें भीलवाड़ा भी था। इस एक साल में वो मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग तैयार हो का जुलाई में उसका पहला सत्र प्रारम्भ होने जा रहा है। सच्चाई तो यह है कि इस तरह से घोषणाएं होकर अगर उनका क्रियान्वयन हो तब पब्लिक को उसका लाभ मिलता है।

घोषणाएं तो इन्होंने अपने कार्यकाल में की थीं। हमारे भीलवाड़ा जिले में जब सी.पी. जोशी साहब सांसद थे, उन्होंने पूरे जिले में चम्बल का पानी लाने की घोषणा की थी और उन्होंने यह घोषणा की थी कि अगर चम्बल का पानी नहीं ला पाया तो मैं भीलवाड़ा से चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने पांच साल के बजट में कुल छह करोड़ रुपये मेरे नगर में लगाये। पहले बजट में उन्होंने घोषणा की थी और माननीय मुख्य मंत्री जी के आशीर्वाद से जब हमारी सरकार बनी, इनकी योजना पर पूरा बजट हमने लगा कर और भीलवाड़ा में चम्बल का पानी हमने अभी, इसी वर्ष शुरू करवाया है। क्रियान्वयन इसको कहते हैं। मेडिकल कॉलेज ऐसी 179 करोड़ की योजना, एक वर्ष में उसका सम्पूर्ण कार्य प्रारम्भ होना, सेशन प्रारम्भ होना, चम्बल का पानी इनके पांच साल पहले की घोषणा, आठ साल पहले की घोषणा का अब हमने क्रियान्वयन करके, और इस वर्ष भी हमारे आदरणीय जलदाय मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने चम्बल के पानी के लिए प्रावधान रखा है, 32 करोड़ रुपये और हमारे इस जिले में लगेंगे।

तो इनकी घोषणाओं को भी हम पूरा कर रहे हैं। हमारी घोषणाएं भी हम पूरी कर रहे हैं। इसीलिए हमारे मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत होता जा रहा है। इनके जो वादे हैं, इनके जो सपने हैं वो कहीं पूरे नहीं होते। जनता कहीं धरातल पर देखती नहीं है और इनकी हालत यह हो जाती है कि 403 में 7 आते हैं और उसका भी बहाना बना कर के फिर मशीन पर आरोप डालते हैं, तो इनको सोचने की जरूरत है। मेरे को तो यह चिंता हो रही है कि आने वाले दो सालों के बाद इनकी जो यह 20-21 की संख्या है यह कहीं सात-आठ रह जाएगी तो इस विधान सभा में इतनी नीरसता होगी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैं आप लोगों से भी प्रार्थना करता हूं कि जो भी आप बातचीत करें, जो जनता से वादे करें उनके

लिए अपना पूरा जोर लगा कर और अपना कार्य करने की क्षमता विकसित करें जिससे जनता में थोड़ा बहुत विश्वास तो आपका भी जमे। ...(व्यवधान)...

ऐसा कुछ नहीं है। आप स्वयं को इसका आत्म चिंतन करने की आवश्यकता है अभी कांग्रेस को।

हमारे नगर में पिछले वर्ष सीवरेज की घोषणा हुई थी, इस साल टेण्डर हो चुके, 325 करोड़ रुपये का भीलवाड़ा शहर में सीवरेज प्लान लागू हो चुका है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): यू.पी. में 22 में से 7 ही रह गये हैं, यहां 21 में से 7 ही रहेंगे ...(व्यवधान)...

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आहूजा जी, आपको तो आजकल साइड लाइन कर रखा है।

श्री सभापति: आप अपना वक्तव्य जारी रखें, समय जा रहा है।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): मैं यह नहीं कह रहा हूं आप कितने रहेंगे लेकिन विधान सभा की एक मर्यादा होती है, विपक्ष की भी आवश्यकता होती है इसलिए हम को चिंता हो रही है कि आप किस स्थिति में पहुंचेंगे आने वाले चुनावों में।

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): वह तो समय बताएगा।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): समय तो बता रहा है, अब और क्या बताना बाकी रहा है?

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): आप यू.पी. से राजस्थान की तुलना मत करो।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): राजस्थान में तो और ज्यादा दुर्गति होने वाली है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): 24 के अब 25 हो जाएगे, आप ध्यान रखना और आगे चुनाव में पता लगेगा ...(व्यवधान)...

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): राजस्थान में और ज्यादा दुर्गति होने वाली है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बजट पर बोलें।

(16.00 बजे)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, यह जो बजट का प्रभाव होता है, मैं उस पर बात कर रहा हूं। यह बजट का ही प्रभाव है कि हमने जो घोषणाएं की, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणाएं की हैं, हमारे माननीय मोदी जी ने जो घोषणाएं की हैं, उनके क्रियान्वयन का ही यह असर आ रहा है कि इनकी दुर्गति बढ़ती जा रही है।

अभी तो हमारे 2 साल बाकी हैं। इन पौने 2 साल में जितनी स्पीड़ से काम करेंगे, क्योंकि परसों ही मोदी जी ने कहा है कि 'न तो बैठूंगा और न बैठने दूंगा, न रुकूंगा और न रुकने दूंगा और न खाऊंगा और न खाने दूंगा'। अगर इन तीनों चीजों पर अमल हमने शुरू किया तो आपकी क्या स्थिति होने वाली है, यह आप लोगों को सोचना है। लेकिन मैं तो भगवान से फिर भी प्रार्थना करूंगा कि 10,20, 25 की संख्या तो इनकी देना, जिससे इस विधान सभा का थोड़ा हालचाल ठीक रहे और कुछ बोलने वाले सामने भी बैठे रहें।

आज की स्थिति में जिस तरह से इस सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, जल स्वावलंबन के क्षेत्र में, पशु चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में काम हो रहा है उससे किसान, काश्तकार, आम मजदूर संतुष्ट है। आज नरेगा में मजदूर जो अपना 100 दिन पूरा कर लेता है, उसको इतना बड़ा पैकेज दिया जा रहा है। लाखों की संख्या में नरेगा मजदूर होते हैं, जिनके बच्चे के जन्म से लेकर के उसकी सारी पढ़ाई, चिकित्सा सुविधा, ब्याह, सारी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की जा रही हैं।

सभापति महोदय, आम जनता इस बजट से प्रसन्न है, हमारी सरकार के कार्यकाल से प्रसन्न है। आने वाले समय में इस बजट घोषणाओं की जो क्रियान्वित होगी तो उनके माध्यम से राजस्थान की जनता की सारी तकलीफें दूर होने वाली हैं। मैं निश्चित रूप से दावा करता हूं कि आने वाले समय में जो आपने सपना देखा है, वैसे तो 11 तारीख के बाद आपके वह सपने ध्वस्त हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर मन के किसी कोने में विचार बना हो तो उसको भी निकाल दें। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुन: आएगी।

मैं इस बजट के पक्ष में अपनी बात रखते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

(16.02 बजे)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। नेता, प्रतिपक्ष। नेता, प्रतिपक्ष। आप अपना वक्तव्य दें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आप आ गये क्या?

श्री अध्यक्ष: 4 बजे पहले ही आपको निवेदन कर दिया था।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): सर, आप आ गये, मैंने देखा नहीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज चौथा दिन है, इस बजट पर सत्ता पक्ष के, प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों ने चर्चा की। मैं अपनी बात आसन के पीछे लगे हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रेरक चित्र को नमन करते हुए शुरू करना चाह रहा हूं। गांधीजी के चित्र के समीप अंकित यह कथन हम सभी के लिए प्रेरणादायी है, 'सभा में या तो प्रवेश न किया जाए और यदि प्रवेश किया जाए तो वहां स्पष्ट और सच बात कही जाए। वहां न बोलने से या गलत बोलने से, दोनों ही स्थितियों में मनुष्य पाप का भागी बन जाता है'। यह कथन लिखा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, यह महान सदन प्रदेश में लोकतंत्र का शिखर सदन है। यह प्रदेश के साढ़े 7 करोड़ लोगों की आस्था और विश्वास से ऊर्जा प्राप्त करता है। यह सदन एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जिसकी रोशनी प्रदेश के कोटि-कोटि किसान, गरीब, मजदूर की झोंपड़ी में विकास का उजाला लाती है। राज्य का बजट विकास का उजाला लाने का एक सशक्त माध्यम होता है।

एक संपूर्ण बजट वह होता है जिसमें प्रदेश के बहुआयामी विकास के लिए बड़ी योजनाओं का समावेश हो। गांव, गरीब और किसान के कल्याण के लिए समर्पण हो। प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार सृजन हो। महिलाओं, आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए संकल्प हो। एक ऐसा बजट खुशहाल राजस्थान के सपनों का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन 8 मार्च को इस सदन में मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट प्रस्तुत किया, इसमें प्रदेश में विकास के संकल्पों का पूरा का पूरा अभाव है।

इस बजट के शुरूआती 3 पन्नों के अंदर विजन 2020 की बात कही गई है। प्रदेश के विकास के लिए हर प्रकार की चुनौतियों को स्वीकार करने का दावा किया गया है। प्रदेश में निवेश, आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, सुशासन के जरिए विजन 2020 के लक्ष्य को पा लेने का एलान किया गया

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

है। यह बिलकुल सही बात है, लेकिन पिछले 3 साल से इस राजस्थान प्रदेश में यह जो चारों बातें हैं, वह पटल से गायब हैं।

हमने वेलफेयर स्टेट बनाने का संकल्प लिया, जब हम पिछली बार सत्ता में थे, और हमने राजस्थान को वेलफेयर स्टेट बनाया। आपने इन साढ़े 3 सालों में उस राजस्थान स्टेट को कॉरपोरेट स्टेट बनाने का काम किया। इसके अलावा कोई काम नहीं किया। विकास की तस्वीर धुंधली पड़ने की सबसे बड़ी वजह प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार और सरकार के कमजोर इरादों के कारण प्रदेश के विकास पर सेंसरशिप लग गई है। सरकार का यह चौथा बजट भी विकास पर सेंसरशिप का पुलिंदा है।

श्री अध्यक्ष: शांत रहें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आज हम राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार की बात करें तो यह इस कदर फैल गया कि प्रदेश के अंदर बड़े-बड़े घोटाले हुए हैं। चाहे आप खनन घोटाला लो, चाहे चिकित्सा विभाग के अंदर एनआरएचएम घोटाला लो, चाहे जलदाय विभाग का घोटाला लो, यह आपके सामने हैं। भ्रष्टाचार इस कदर हुआ है कि इन्होंने प्रदेश को पीछे धकेलने का काम किया है। भ्रष्टाचार की वजह से इस प्रदेश का विकास रुक गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज चाहे हम प्रदेश के किसानों की बात करें कि आज उनके क्या हालात हैं? राजस्थान प्रदेश का किसान कितना दुःखी है। आप सारे बात कर रहे थे कि नोट बंदी से कोई असर नहीं हुआ है। मैं आप सभी माननीय सदस्यों को यह कहना चाहता हूं कि नोट बंदी से राजस्थान पर असर ...।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नोट बंदी से असर हुआ। नोट बंदी से असर हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आप राजस्थान प्रदेश की बात करो। उत्तर प्रदेश से आपका पेट नहीं भरेगा। आप राजस्थान प्रदेश के किसान, झोंपड़ी की बात करो।

आज राजस्थान प्रदेश का किसान इस नोट बंदी की वजह से कितना दुःखी है। किसान की फसल का उचित मूल्य नहीं मिला। आज भी उस

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

किसान की फसल उसके खेत में सड़ रही है। कोई उसको लेने वाला नहीं है। मंडियों के अंदर पैसे नहीं हैं। आप भी उसके भुगत भोगी हो। लेकिन आप विवश हो, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आपकी पार्टी के हैं। उन्होंने जो निर्णय लिया, उसके लिए आप विवश हो। उस पर आप बात नहीं करना चाहते। आप बार-बार उत्तर प्रदेश के चुनावों की बात कर रहे हैं। इस प्रदेश में जब 2018 में चुनाव आएंगे तब आपको जनता माफ नहीं करेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 2009-10 की बात कर रहे हैं, जब हम सत्ता में थे, उस 2009-10 में राजस्व घाटा 4,747 करोड़ रुपए का था।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): यह राजस्व घाटा क्या होता है?

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि हम तो किसान हैं।

श्री अध्यक्ष: आप आसन से कहिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, नहीं, यह जो बात कर रहे हैं, हम तो किसान हैं और झोंपड़ी से आते हैं और आप सत्ता में रहकर और भ्रष्टाचार में व्याप्त होकर बड़े-बड़े और मोटे-मोटे हो गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप खड़े होकर बता दो कि कितने मोटे हो गये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आपको घाटे और इन आंकड़ों का पता है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से यह जो कह रहे हैं कि आंकड़े किताबों के अंदर लिखे हुए हैं, हम भी कुछ पढ़े-लिखे हैं, कोई आप ही उस हिसाब से पढ़े-लिखे नहीं, क्योंकि आंकड़े आप ही के हैं, सरकार आंकड़े पेश करती है, मैं और बताऊंगा आपके पेश किए हुए आंकड़े। वह तो आापके ही किए हुए हैं, किस तरह की हालत आपने बजट की की है, यह मैं आंकड़ों से ही बताऊंगा। आप सुनते जाओ, फिर बताना मुझे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अपन बात कर रहे थे किसान और मजदूर की, आज किसान प्रदेश का इतना दु:खी है, मैं आंकड़ों से सिद्ध कर रहा हूं, आपकी बात मान रहा हूं। ...(व्यवधान)... उस पर मैं बाद में आउंगा।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो पूछ रहा था कि राजस्व घाटा है क्या चीज?

श्री अध्यक्ष: आप उधर सीधा संवाद मत कीजिए। आप चेयर के साथ संवाद कीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी, राजपालजी तो अपने को ऐसे समझते हैं जैसे मन घड़गी वा बाड़ मं ही बड़गी। ...(व्यवधान)...

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): ये शाही खून वाले किसान के खून को दबाना चाहते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नोटबंदी की बात कर रहा था। नोटबंदी के अंदर प्रदेश का किसान मरा है। प्रदेश का गरीब मरा है, प्रदेश के मजदूर के हाथ को काम नहीं। आज हालत यह हो गई कि किसान पूरा का पूरा कर्ज में डूबा हुआ है और आप बात कर रहे हो किसान की।

हमारे देश के प्रधान मंत्रीजी ने अभी यूपी में जन सभाओं में कहा कि यदि हम यूपी के अंदर जीतते हैं तो हम किसान का कर्जा माफ करेंगे। यह बात कही कि नहीं कही? कही न यूपी के अंदर? लोक लुभावने भाषण देकर सत्ता जरूर हथिया ली ...(व्यवधान)... आप भी 2013 में सत्ता में आए थे, इन्हीं बातों को लेकर राजस्थान की जनता ने आपको बहुमत दे दिया, एक प्रचंड बहुमत, 163 सीटें जीतकर आए थे और उन 163 सीटों के बाद इतना प्रचंड बहुमत देने के बाद इन साढ़े तीन साल में क्या हुआ, माननीय अध्यक्ष महोदय? इन साढ़े तीन साल में राजस्थान का आम जन आपकी सत्ता से दु:खी है। आप जिस तरीके से सत्ता चला रहे हो, जिस तरीके से आपका सोच है, जिस तरीके से आपकी कार्य शैली है उससे आम जनता परेशान है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि प्रधान मंत्रीजी ने जिस तरीके से, यूपी के अंदर जीत गई अब सरकार, आपकी सरकार बन रही है, वहां प्रचंड बहुमत आ गया और प्रधान मंत्रीजी ने कह दिया कि यूपी के किसानों का कर्जा माफ करेंगे। तो राजस्थान को अछूता क्यों छोड़ रहे हो? राजस्थान के किसान का भी कर्जा माफ करो। प्रधान मंत्रीजी जाते हैं बिहार के चुनाव में, उन बिहार के चुनावों के अंदर वहां सवा

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

लाख करोड़ का पैकेज देकर आते हैं कि सवा लाख करोड़ का पैकेज देंगे, राजस्थान को अछूता क्यों छोड़ दिया? उनको भी दो साल, आपको साढ़े तीन साल हो गए, ढ़ाई साल उस सरकार को हो गये, आप सवा लाख करोड़ का पैकेज यहां नहीं दे सकते? आपने मांगा? इन्होंने मांगा? ...(व्यवधान)...

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): आपने दौसा में सुना होगा, ...(व्यवधान)... दो हजार सात सौ पचास करोड़ रुपए नितिन गडकरीजी रोड्स के लिए देकर गये हैं। आपकी जानकारी के लिए। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: नो इंटरप्शन।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): प्रधान मंत्रीजी जाते हैं बिहार में, सवा लाख करोड़ का पैकेज दिया कि नहीं दिया? घोषणा करके आये। वहां घोषणा करके आये, सवा लाख करोड़ रुपए का पैकेज देकर आये।

तो मेरा कहना यह है कि यदि केन्द्र सरकार से राजस्थान प्रदेश के विकास का धन आप ला सकते हैं तो आपको लाना चाहिए, विपक्ष भी आपके साथ है इस मामले के अंदर। क्योंकि हमारा अधिकार है केन्द्र सरकार पर, आप पैकेज लाओ, विशेष दर्जा राजस्थान को दिलाओ, विकास का पैसा लाओ राजस्थान के लिए, उसमें आप बिलकुल नाकाम रहे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कर्ज की बात कर रहा था, किसान कर्ज में डूबा हुआ है, किसान को बिजली नहीं, किसान को खाद और बिजली नहीं और इस बजट के अंदर जिस तरीके से आपने बजट पेश किया उसमें किसान को चारों तरफ से काटा है। तीन लाख टन यूरिया पिछले साल थी, इस साल आपने डेढ़ लाख टन कर दी, बीस हजार टन आपके डीएपी का आपने रखा, उसमें सोलह हजार टन ही उठा सके। अबकी बार बीस हजार टन रख रखा है, पता नहीं आप कितना उठाएंगे? किसान को बीज और खाद असली नहीं मिलता, नकली बीज और खाद उस किसान के खेत में जाता है, वह चार महीने तक पानी देता है, उसको पालता, है पोसता है, बच्चे से ज्यादा और उसका बीज उगता नहीं, उसका पूरा का पूरा चौपट हो जाता है। आज प्रदेश में किसान किस तरीके से बेकदर और दु:खी है इसकी गणना आप कर ही नहीं सकते। इसमें सोचना चाहिए, यह आपका कर्तव्य है, उस किसान को मजदूर को संभालने का।

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा पिछली बार आपने किसान की बिजली की रेट बढ़ाई, उस किसान की बिजली की बढ़ी रेट को इन्होंने वापस लिया, रोलबैक हुए क्योंकि किसान सड़कों पर आ गया, लाखों किसान जब सड़कों पर आए..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह बात तो आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कह चुके, किसी को भेजकर दूसरा कागज मंगवा लो। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय राजेन्द्र सिंहजी, प्लीज। ...(व्यवधान)...

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय राठौड़ साहब, आप अब विराज जाओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हां, अब ले आएंगे।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): उसमें आप रोलबैक हुए, उसमें आपने रेट घटाई, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, लेकिन बूंद-बूंद सिंचाई योजना के तहत उस किसान ने क्या गलती की थी? उसकी रेट आपने क्यों नहीं घटाई? जबकि आपके माननीय मंत्रीजी ने, बीकानेर में वहां पचास हजार किसान थे आपके बिजली विभाग के और कम्पनियों के सारे अधिकारी वहां थे, उन किसानों के बीच में बैठकर इनका समझौता हुआ उन सारी मांगों पर और एक-एक मांग मानी। तीन साल आपने जो उसमें कर दिया बूंद-बूंद में जबकि ढ़ाई साल वहां मंत्रीजी बोल कर आये थे। बूंद-बूंद सिंचाई योजना की रेट घटाने की बात करके आए थे और बाकी जो मांगें थीं उनकी चर्चा नहीं करना चाहते। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भी किसान वहां धरने पर बैठे हैं, बूंद-बूंद वाला, वह रेट के लिए कर रहा है, उसकी रेट घटाई नहीं, आपको उसकी भी रेट घटानी चाहिए। मैं सदन की नेता से निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें आप सोचो और वापस यह घोषणा करो कि उस किसान की रेट भी, आपने साधारण, जनरल श्रेणी का जो कनेक्शन था उसकी घटा दी और उस बूंद-बूंद का पहले ही चालीस हजार का बिल आता था वह तो आज भी उतना ही आता है और तीन साल का आपने जो किया उसका ढ़ाई साल करो। यह तो आप ही वादा करके आए थे, आपके नुमाइंदे बातचीत करके आए थे। उसके बाद में आपने बिलकुल उस चीज को नकार दिया।

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, प्रधान मंत्रीजी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, आप पैकेज ला नहीं सकते, चालीस हजार करोड़ रुपए आपने बजट के अंदर घोषणा पिछली बार की थी कि हम ड्रिंकिंग वाटर, इर्रिगेशन का हम पूरे प्रदेश की जनता के लिए करेंगे। अभी प्री-बजट के अंदर प्रदेश के आपके प्रतिनिधि भी गये होंगे, उसमें आपने प्रपोजल रखे होंगे। एक बात आपकी मानी नहीं, उनको बिलकुल रद्दी की टोकरी में डाल दिया। जिस तरीके से चार दिन हो गये, आपके सत्ता पक्ष के सदस्य जब पहले बजट के बारे में बोलते हैं तो सब अच्छा बोलते हैं कि बजट बहुत अच्छा आया, बजट में यह कर दिया, बजट में वह कर दिया, लेकिन अंतिम क्षणों में सारे यह कहते हैं कि मेरे यह खाला नहीं बना, मेरी यह नाड़ी नहीं बनी, मेरे वह नहीं हुआ, मेरे वह टूटा हुआ है, मेरे वह कर दो, मेरे वह कर दो, मेरे यह कर दो। आपने भी बजट बनाने से पहले सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्यों को बुलाया था और उस पर बैठकर चर्चा की। हम कौनसे अछूते हैं, हमें भी आप बुलाते। प्रतिपक्ष के सदस्यों को भी बुलाओ, बजट के बारे में चर्चा करो, हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रदेश के विकास को करना चाहते हैं, उस विकास में भागीदार हैं, आप यदि इस तरीके का सोच तो रखो लेकिन आपका यह सोच नहीं। सत्ता पक्ष् के सभी माननीय सदस्य जाकर बजट के बारे में बता कर आए, लिखकर देकर आए, आपका एक भी काम हुआ, बजट में कोई घोषणा हुई क्या? मैं पूछना चाहता हूं। ...(व्यवधान)... यह सारे के सारे आपके रद्दी की टोकरी में हैं। ...(व्यवधान)... आप सब असत्य बोल रहे हो। ...(व्यवधान)... तो फिर बाहर पोर्च के अंदर, बाहर जो बात करते हो कि प्रदेश के विकास का बजट तो बिलकुल कुछ है नहीं, विकास की बात है ही नहीं। आप ही लोग बात करते हो कि विकास का कोई लेना-देना नहीं। ...(व्यवधान)... यहां आप विवश हो, इसकी प्रशंसा करने के लिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया 2020 के विजन के बारे में। आपने सुशासन की बात की। इन तीन-साढ़े तीन सालों में क्या प्रदेश के अंदर सुशासन है? मैं पूछना चाहता हूं सुशासन की इन्होंने बिलकुल धज्जियां उड़ा दीं। आज पूरे प्रदेश के अंदर पिछले एक साल के अंदर जिस तरीके से

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)
किसान आंदोलन कर रहा है। आपके आंदोलन की लिस्ट पुलिस के प्रशासनिक प्रतिवेदन में दी हुई है, 2016 में किसान संगठनों के 326 धरने-प्रदर्शन हुए, वामपंथी संगठनों ने 187 किये, श्रमिक संगठनों के 510, राज्य कर्मचारियों के 509, छात्र एवं युवा संगठनों ने 1318, राजनैतिक दलों एवं अन्य संगठनों ने 1035 धरना-प्रदर्शन, आंदोलन के कदम उठाये। कहां जरूरत पड़ गई?

यह चौथा बजट है। बजट में सारी अच्छी विकास की बातें कर रहे हो। जिस तरीके से पिछले दिनों से चर्चा कर रहे हो कि बजट बहुत बढ़िया है। बजट बढ़िया और विकास का आईना है। यदि बजट विकास का आईना है तो ये धरने और प्रदर्शन क्यों? काहे का सुशासन? सुशासन लेकर आप विजन 2020 का लक्ष्य पूरा करना चाह रहे हो। प्रदेश की आम जनता को कहीं सुशासन नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से आपका प्रदेश का किसान, श्रमिक, कर्मचारी, छात्र युवा सभी दुःखी हैं तो फिर कैसा सुशासन?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, अब आंकड़ों पर आ जाते हैं। घाटा आपने बता दिया, आपको हंसी आ रही है। (व्यवधान) वर्ष 2009-10 में हमारी सत्ता थी। उस वक्त राजस्व घाटा 4747 करोड़ रुपये का था जिसे 5 साल के दौरान 2013-14 में 1039 करोड़ रुपये तक हम ले आये। हमने राजस्व घाटे में लगभग 78 प्रतिशत की कमी की जबकि 2013-14 में यह घाटा 3215 करोड़ रुपये का आपने कर दिया। 2017-18 के बजट में यह घाटा बढ़कर 13528 करोड़ होना अनुमानित है। पिछले तीन साल में इस घाटे के अंदर तीन गुना तक वृद्धि हुई है।

आपकी विकास की जो योजनाएं हैं, आप विकास की योजनाएं देख लो। लोक-लुभावने सपने दिखा रहे हो। जब बजट ही घाटे का है, पैसा ही आपके पास में नहीं, बजट दिन-प्रतिदिन, हर साल घाटे में आ रहा है तो ये सारे के सारे सपने कागजों के अंदर हैं।

आज प्रदेश की यह स्थिति हो गयी, प्रदेश पूरा का पूरा कर्जे में डूबा हुआ है। किसी भी व्यक्ति को अपना धंधा, बिजनस, व्यापार या खेती करने के लिए किसान को भी लोन लेना पड़ता है। कर्ज लेकर विकास करना राज्य के हित में है। हम यह नहीं मानते कि यह राज्य के हित में नहीं है, लेकिन कर्ज लेकर घी पीना सबसे ज्यादा नुकसानदायी है। आप कर्ज लेकर घी पी

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

रहे हो। विकास का उसमें देख नहीं रहे। यह राज्य के हित में कभी नहीं हो सकता। (व्यवधान) दारू विच घी महंगो है। क्या दारू महंगी हो गयी?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कहा गया है "ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत" ऋण करके घी पीओ। यह लिखा है शास्त्रों में। दारू पीना मना है, घी पीना मना नहीं है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): प्रदेश कर्जा ले और सरकार घी पीये तो वह प्रदेश कभी तरक्की नहीं कर सकता। प्रदेश की सरकार यह काम तीन सालों से कर रही है। आज प्रदेश का हर बच्चा जो जन्मा है वह 50 हजार रुपये का कर्जदार है। जन्मते ही वह 50 हजार का कर्जदार हो गया। जो बच्चा नया आया है, बच्चा पैदा हुआ है, उसने क्या गलती की? वह आते ही 50 हजार का कर्जदार हो गया। आज पूरा प्रदेश कितना घाटे में है? कितना कर्जदार प्रदेश को बना दिया आपने? आज प्रदेश पर 2 लाख 78 हजार करोड़ रुपये का कर्जा है। इसका मतलब सरकार की जो रेवेन्यू है उस रेवेन्यू का 15 प्रतिशत सिर्फ ब्याज के अंदर जा रहा है। उस प्रदेश का कोई विकास हो सकता है? यदि सरकार बड़े कदम उठाती और ऐसे बड़े प्रोजेक्ट आप लेकर आते तब आप कर्जा लेते तो लगता और उससे प्रदेश का विकास भी होता। उसमें तो इन्होंने किया नहीं। आपके बजट में खाला, नाला, इतने छोटे काम किये। आज माननीय सदस्य बोल रहे हैं कि हमारे 20 लाख का बना दो, हमारे 50 लाख का बना दो, यह सड़क अधूरी है, वह नाला अधूरा है, वह पुलिया टूटा हुआ है। यह विजन है आपका? इस विजन से प्रदेश आगे बढ़ेगा? इस विजन से प्रदेश विकास की ओर अग्रसर हो सकता है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, अपन खनिज सैक्टर की बात करें। खनिज और पैट्रोलियम सैक्टर की बात करें। खनिज विभाग के अंदर जो राजस्व घाटा हुआ है, हर विभाग के अंदर राजस्व घाटा हुआ है। यह सरकार की बिलकुल नाकामी है। आज मैं खनिज विभाग की बात करूं, खनिज विभाग का आपने 5200 करोड़ रुपये के मुकाबले 3186 करोड़ रुपये वसूल किये। यह भी फिगर मैं बताऊंगा। ये फिगर भी दो-तीन तरह के हैं। आप एक लक्ष्य रखते हो 5200 करोड़ रुपये का। जिसके मुकाबले आप बता रहे हो 3186 करोड़ रुपये। एक जो आप बता रहे हो, जो आपका वार्षिक प्रतिवेदन है, उस

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)
वार्षिक प्रतिवेदन के अंदर लक्ष्य बता रहे हैं 4000 करोड़ रुपये। उस चार हजार करोड़ के अगेंस्ट में 2748.69 करोड़ रुपये वसूले हैं। दूसरी इनकी जो आर्थिक समीक्षा है, उसमें आपने लिखा है "राज्य में प्रधान खनिज के 156 खनन पट्टे तथा अप्रधान खनिजों के 15300 खनन पट्टे एवं 18103 खदान लाइसेंस हैं। वर्ष 2016-17 में 4 हजार करोड़ के राजस्व लक्ष्य की तुलना में दिसम्बर, 2016 तक 2748.70 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। इस आर्थिक समीक्षा में तो यही लिखा हुआ है।

यह आपका वार्षिक प्रतिवेदन है। इस वार्षिक प्रतिवेदन के अंदर 4 हजार का लक्ष्य रखा है। यह संशोधित है। जो आर्थिक समीक्षा है वह आपने टेबल कर दिया। यह किसी के पास आया ही नहीं होगा। यह आपके पास आया मंत्रीजी? इसमें आपने वापस उसको संशोधित करके 4 हजार के अगेंस्ट 2748.69, उसमें कर दिया 2748.70। यह क्या प्रतिवेदन है आपका? इसमें आपने 2016-17 के अंदर लिख दिया 5200 करोड़ रुपये। उसके अगेंस्ट हुआ 3186.50 करोड़ रुपया। अब इसको 2748 करोड़ रुपये मानें या 3186 करोड़ रुपये मानें। उसमें आपने कौनसा लिया? माननीय अध्यक्ष महोदय, इन तीनों में, आर्थिक समीक्षा, आपका आय-व्ययक और आपका वार्षिक प्रतिवेदन, इन तीनों में अलग-अलग है और यह सोचने की बात है। आपके पास में रेवेन्यू कितनी आई? रेवेन्यू आपके पास में 2748.70 करोड़ रुपये आई या 3186.50 करोड़ रुपये आई? मतलब 438 करोड़ का इसमें फर्क है माननीय अध्यक्ष महोदय।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अलग-अलग टाइम का है। टाइम अलग-अलग है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): किसका टाइम अलग? कौनसा?

श्री अध्यक्ष: भिण्डा साहब, विराजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन तीनों के अन्दर अलग-अलग है, 438 करोड़ का घपला है और अब इन सबको हंसी आ रही है और इसको मानते नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह जो आपके हाथ में है आर्थिक समीक्षा, इसमें दिसम्बर तक के आंकड़े हैं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अच्छा, यह आय-व्ययक का है ये?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): और वो जो आपके पास में वार्षिक प्रतिवेदन है वो उसके बाद छपा है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिए। जोगाराम जी, विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह तो कॉमन-सेंस की बात है, कोई लम्बी-चौड़ी बात ही नहीं है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): कौनसा? तो इसमें अलग-अलग क्यों है? यह बताओ न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): एक दिसम्बर का आंकड़ा है और एक फरवरी तक का आंकड़ा है। तो अलग-अलग होंगे ही और हमेशा होते आये हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अच्छा लक्ष्य फिर आपका? सुनो अध्यक्ष जी, इनके लक्ष्य भी एक महीने में चैंज होते हैं। जो खनन विभाग को लक्ष्य दिये थे, आप एक तरफ तो 5200 करोड़ रुपये दे रहे हो और एक तरफ आप 4000 करोड़ के अगेंस्ट में कर रहे हो। तो ये आप छिपा रहे हो। 5200 करोड़ के अगेंस्ट में 3186 करोड़ रुपये होंगे और एक 4000 में 3186 करोड़ रुपये होंगे। तो आप अपने आपको आंकड़ों में ही बढ़ाना चाह रहे हो। मतलब, 5200 करोड़ रुपये लक्ष्य रखा और दुबारा आप 4000 करोड़ का लक्ष्य रख रहे हो। तो क्यों, भाई? लक्ष्य फिक्स नहीं होता? जब आप विभाग का तय करते हो कि इस विभाग का इतना लक्ष्य है और फिर आप लक्ष्य भी चैंज कर रहे हो, टार्गेट चैंज कर रहे हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): प्रतिपक्ष के नेता, यह क्रूड ऑयल का है, क्रूड ऑयल की अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर कीमतें लगातार कम होती चली गईं। इसलिए लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। इसमें किसी का कसूर नहीं है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं क्रूड ऑयल का नहीं कह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप बजट स्टडी के अन्दर पढ़ लो न।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं क्रूड ऑयल का नहीं कह रहा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप उसी की बात कर रहे हो।

श्री अध्यक्ष: संसदीय कार्य मंत्री जी, डिस्टर्ब मत कीजिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं खनिज विभाग की बात कर रहा हूं। यह खनिज विभाग का है, क्रूड ऑयल का अलग है। अच्छा इस क्रूड ऑयल को मान रहे हो?

श्री अध्यक्ष: सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय राठौड़ साहब, यह खनिज विभाग का दिया हुआ है और इसी में ही क्रूड का आपका रेवेन्यू है। तो आपके पास में क्रूड की और खनिज दोनों की इतनी ही रेवेन्यू आई क्या? इतनी ही रेवेन्यू आई? आप इसको प्रोसीडिंग में नोट कर लो इनकी, ये कह रहे हैं कि इतनी ही आई है। आपकी क्रूड की रेवेन्यू अलग नहीं है? खाली खनिज की जो रेवेन्यू है.....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): देखिए आप बजट स्टडी का पेज नं. 12 निकाल लो, इसके अन्दर पूरी चीज लिखी हुई है।

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): राजेन्द्र जी राठौड़ को वित्त मंत्री बना दो या खनिज मंत्री बना दो।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): राठौड़ साहब, मैं यह कह रहा हूं कि यह रेवेन्यू जो है, यह रेवेन्यू 3186 करोड़ रुपये क्रूड सहित है क्या? आपके क्रूड की है क्या? क्रूड के साथ है क्या? मैं क्रूड की अलग बता देता हूं आपको।

श्री अध्यक्ष: आप अपना भाषण जारी रखिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): क्रूड की और पूरे खनन विभाग की, पैट्रोलियम सैक्टर ही अलग है माननीय अध्यक्ष महोदय। इसका खनन विभाग से कोई लेना-देना नहीं, उसकी रेवेन्यू अलग है और आप बता रहे हैं। फिर 3186 करोड़ रुपये रेवेन्यू, टोटल मिलाकर दोनों? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सब छिपाने का काम कर रहे हैं अगर आप देखोगे तो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहना चाह रहा हूं कि आपने जो

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)
बजट पेश किया है वो सिर्फ दिशाहीनता का एक पुलिंदा है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। आप इस पवित्र सदन में बैठे हैं और वो लिखा हुआ है कि पाप के भागी, यदि गलत बोले तो पाप के भागी आप हो, आप ही बोल रहे हो क्योंकि सत्ता आपके पास है। आप सत्ता के मद में चूर हो, आपको कहीं कोई दिख नहीं रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जोगाराम जी, प्लीज।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आप सत्ता के मद में चूर हो और आप सही तरीके से राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हो।

बजरी की चर्चा, यह बजरी इस खनन विभाग में ही आती है या पैट्रोलियम सैक्टर में आती है? लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने बार-बार बजरी का मुद्दा उठाया है कि आज पूरे प्रदेश के अन्दर एक तरफ अपना घाटे का बजट जा रहा है, रेवेन्यू अपन ला नहीं रहे हैं और बगैर रेवेन्यू के विकास कैसे होगा माननीय अध्यक्ष महोदय? आज अपन बजरी खनन की बात करें तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इस सैक्टर के अन्दर है। 10 हजार करोड़ रुपये का राजस्व घाटा, राजस्व की हानि इस एक बजरी सैक्टर के अन्दर है। हमारे माननीय मंत्रीजी, सरदार जी उस वक्त जवाब दे रहे थे.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): मैं आपको बता दूं कि 600 करोड़ का तो आपने एसएमएस का घोटाला किया और 250 करोड़ का वो जो आपके मोरदिया जी वाला आपने माफ किया। वो घोटाले किसके हैं? और बताऊं क्या दो-चार? एक हजार करोड़ रुपये तो उसी में निकल जाएगा। इतने-इतने हैं कि एक किताब लिख दें आपके घोटालों की। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आप प्रतिपक्ष के नेता को अपना हिसाब दे रहे हैं। तो हिसाब देना है तो प्रश्न के उत्तर में क्यों नहीं दिया इन्होंने हिसाब। (व्यवधान) प्रश्न के अन्दर उत्तर देते सफाई देने वाले। (व्यवधान) प्रश्न के उत्तर में तो नहीं दिया इन्होंने। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): 600 करोड़ का तो एसएमएस का घोटाला जो मैंने उस दिन कहा और 250 करोड़ रुपये मोरदिया का जो घोटाला है जो पत्थर को मार्बल और मार्बल को पत्थर बना दिया। वो घोटाले किसने किये? क्या बात करते हो आप? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, विराजिए।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): 40 लाख करोड़ का आपने खान घोटाला कर दिया।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय मंत्री जी का ही कहा हुआ है। माननीय मंत्री जी ने इस सदन में ही कहा था कि जो बजरी लीजेज हैं उनका आज तक लीज एग्रीमेंट नहीं हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय। लीज एग्रीमेंट नहीं है। माननीय मंत्री जी के द्वारा जवाब दिया गया कि हम लीज एग्रीमेंट कर नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट में उनको लिखकर दे दिया यथा स्थिति का। आपने ही यह कहा था। लीज एग्रीमेंट नहीं और रात और दिन कहीं कोई उस माइनिंग डिमार्केशन नहीं, जिससे मर्जी आये वहां खोद रहे हैं। अब उधर से आवाज आई ई.सी. की।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): ई.सी. के बगैर लीज एग्रीमेंट नहीं हो सकता यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं यही तो कह रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब था कि ई.सी., एनवायरनमेंट सर्टिफिकेट नहीं आया इसलिए लीज एग्रीमेंट नहीं हो सकता। वो एक पर्चा जो सुप्रीम कोर्ट से लिखाकर ले आये और आप सुप्रीम कोर्ट में कोई पैरवी नहीं कर रहे, जिससे 10 हजार करोड़ का घाटा आपने प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का कर दिया। इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। हमने बार-बार मांग की कि सरकार को संवेदनशील होकर इसकी जांच करवानी चाहिए, पर कहीं कोई जांच का मामला नहीं।

खनन घोटाले की और अपन बात करेंगे तो 45 हजार करोड़ रुपये का खनन घोटाला है और उसकी बात करेंगे तो इनको मिर्ची लगेगी, ये दु:खी होंगे।

45 हजार करोड़ रुपये का घोटाला, उसके साथ में 10 हजार करोड़ का घोटाला बजरी का और फिर आप प्रदेश को विकास की ओर ले जाना चाह रहे हो। बगैर धन, बगैर रेवेन्यू, बगैर राजस्व आप प्रदेश का विकास कैसे कर सकते हो?

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके बारे में बैठकर सोचना चाहिए। मंत्री जी, खनन विभाग सुप्रीम कोर्ट में जाए और यदि उसमें ई.सी. नहीं है तो फिर आप लीज एग्रीमेंट क्यों कर रहे हो? नये सिरे से उसका ऑक्शन करो। आपकी खनन पॉलिसी अभी तक आई नहीं, अभी तक कागजों में पड़ी है। उसके कोई नियम-कानून नहीं बने तो फिर कहां आप प्रदेश की जनता को, उस मजदूर को काम दे सकते हो। प्रदेश को आपने विकास के नाम पर बिल्कुल ठप कर दिया और यह स्थिति आपकी सरकार की है।

माननीय राठौड़ साहब अभी बात कर रहे थे पैट्रोलियम सैक्टर की।

श्री अध्यक्ष: चेयर को एड्रेस कीजिये। जसवंत सिंह जी।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अपन पैट्रोलियम सैक्टर की बात करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय राठौड़ साहब कह रहे थे कि खनन विभाग और क्रूड ऑयल की रॉयल्टी, जो भी उसकी रेवेन्यू है वो 3186 करोड़ रुपये है। पैट्रोलियम की रॉयल्टी में दिन-प्रतिदिन कमी आ रही है।

हम जब सत्ता में थे, उस वक्त क्रूड आयल और प्राकृतिक गैस में आशातीत वृद्धि हुई है। 2012-13 में क्रूड आयल का उत्पादन 86 लाख मैट्रिक टन था, जिसमें राज्य को 5,041 करोड़ रुपये की रायल्टी मिली थी, 2013-14 में यह उत्पादन बढ़कर लगभग 91 लाख मैट्रिक टन हुआ और इससे मिलने वाली रायल्टी बढ़कर 5,905 करोड़ रुपये हो गई और आपकी सरकार आते ही, वर्ष 2014-15 में क्रूड आयल का उत्पादन घटकर 87.60 लाख मैट्रिक टन हुआ और इसमें मिलने वाली रायल्टी घटकर 4,782 करोड़ रुपये रह गई और 2016-17 के अंदर आपका क्रूड आयल का उत्पादन घटकर 61.17 लाख मैट्रिक टन रह गया और रायल्टी घटकर मात्र 1,600 करोड़ रुपये रह गई। अब कहां इसमें आप 3,186 करोड़ रुपये की बात कर रहे हो। 5,000 करोड़ रुपये से ऊपर की रायल्टी मिलती थी।

फिर पेट्रोलियम की बात आएगी तो फिर रिफाइनरी की बात भी आएगी। रिफाइनरी से आपने पूरा मुंह मोड़ रखा है। आज प्रदेश का इतना बड़ा प्रोजेक्ट, यदि प्रदेश का... (व्यवधान) अब वह घाटे का बजट है। आपकी बनिये की दुकान है? बनिया घाटा और मुनाफा देखता है। यदि प्रदेश की जनता के हित में कोई काम होगा, कोई विकास होगा, कोई प्रोजेक्ट होगा,

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)
उसमें घाटा और नफा नहीं देखा जा सकता। आप बात कर रहे हो रोजगार की कि हम 15 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। यह रोजगार से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मुद्दा है। आज रिफाइनरी लगती माननीय अध्यक्ष महोदय, साढ़े तीन साल हो गये हैं। साढ़े तीन साल में करीब-करीब काम हो जाता और लाखों युवाओं को रोजगार मिलता। एक बहुत बड़ा पैट्रो-केमिकल हब बनता उस बाड़मेर और जैसलमेर एरिया की धोरां की धरती में, बहुत बड़ा विकास होता।

हमारे बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य मेवाराम जी ने कहा था कि बाड़मेर रिफाइनरी यदि बन जाती तो बाड़मेर और जैसलमेर दुबई बन जाता। बनता कि नहीं बनता दुबई? आज उसको रोकने का काम किया। उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं और सीधा कह दिया कि भई यह अनवायबल प्रोजेक्ट है। (व्यवधान) यह स्थिति आपकी सरकार की है। आज न तो कोई रोजगार है, न कोई किसान सुखी है।

मैं निवेदन करना चाह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, आप लाओ न। इस रिफाइनरी के मामले में मैं मांग करता हूं कि आप इस पर श्वेत-पत्र लेकर आओ कि बाड़मेर रिफाइनरी लगनी चाहिए कि नहीं चाहिए? इस पर श्वेत-पत्र लाओ राजस्थान की जनता को पता लग जाएगा कि बाड़मेर की रिफाइनरी का क्या, कैसे करना है, क्या करना है, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे? इसका जनता को तो बताओ। आप कूलड़ी के अंदर गुड़ फोड़ना चाहते हो। ऐसा है न, जनता माफ नहीं करेगी। ऐसा मत करो। उस जनता के हित में काम करो। आज हम श्वेत-पत्र की मांग करते हैं।

पिछले तीन बजट आपने पेश किये। उन तीन बजटों के अंदर आपने बहुत लम्बी-चौड़ी घोषणाएं कीं। मैं गवर्नर स्पीच पर भी बोल रहा था। मैंने यह निवेदन किया था कि आपने जो पीछे तीन बजट पेश किये थे, उन तीन बजटों के अंदर जो घोषणाएं की थीं, वे घोषणाएं भी 50 प्रतिशत से अधिक तो धरातल पर आईं नहीं। उन बड़ी-बड़ी योजनाओं के बारे में मैं निवेदन करना चाह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर रिफाइनरी, बांसवाड़ा-डूंगरपुर रेल प्रोजेक्ट। वह भी आपका बड़ा प्रोजेक्ट था, उसको भी रोक दिया। मतलब इतना बड़ा आदिवासियों का एक सपना था। आदिवासियों के उस

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

सपने को आपने चकनाचूर कर दिया। यह भी सब कुछ हो गया, पैसे मंजूर, सारा कुछ हो गया, काम चालू हो गया, उस काम को रोक दिया। उसमें काफी पैसे लग गये। लोगों की जमीनें एक्वायर हो गईं। यदि यह बांसवाड़ा-डूंगरपुर-रतलाम रेल लाइन बनती तो वहां कितना बड़ा विकास होता। एक तरफ आप पर्यटन की बात कर रहे हो। हमारी माननीया सदन की नेता और मुख्य मंत्रीजी त्रिपुरसुन्दरी बार-बार जाती रहती हैं। धर्म के प्रति आपकी पूरी आस्था है। बेणेश्वर धाम वहां है। त्रिपुरसुन्दरी वहां है। यदि रेल लाइन से जुड़ता तो पर्यटन में भी बहुत बड़ा चढ़ाव आता और उसका विकास होता। उसको उन्होंने बिलकुल रोक दिया। अपनी जयपुर मेट्रो...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय नेता प्रतिपक्ष का पूरा भाषण होने और माननीया मुख्य मंत्रीजी का जवाब पूरा होने तक के लिए बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की सहमति है?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

आय-व्ययक

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): जयपुर मैट्रो का द्वितीय चरण, उसका भी आपने कुछ किया नहीं। मैं इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करना चाह रहा। आप बनाओगे तो हो नहीं। आप तो यह कहोगे कि मैट्रो ट्रेन भी घाटे का सौदा है। जब तक आप सैकिण्ड फेज को पूरा नहीं करोगे, तब तक यह वायबल नहीं होने वाला। उसको आपको करना चाहिए।

मैं प्रदेश के बिजली तंत्र की बात करना चाह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। हम बार-बार निवेदन करते आये हैं कि बिजली कम्पनियां जिस तरीके से घाटे में जा रही हैं, हमारे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों के द्वारा बार-बार यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने यह कर दिया, कांग्रेस ने इसको

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

एक लाख करोड़ रुपये के घाटे में ला दिया। हमने जब 2013 के अंदर सत्ता छोड़ी थी, उस समय में बिजली की कम्पनियां 36,000 करोड़ रुपये के घाटे में थीं। हम मानते हैं इसको कि 36,000 करोड़ रुपये के घाटे में थीं लेकिन आज इन साढ़े तीन साल के अंदर आपने एक लाख करोड़ रुपये के घाटे में पहुंचा दिया और बिजली की रेट आप बढ़ा रहे हो। एक झोंपड़ी के अंदर एक बल्ब लगा हुआ है, उसका भी 1,000 रुपये महीना बिल आता है। इतनी रेट आपने बढ़ा दी। हमने पांच साल तक रेट नहीं बढ़ाई, और फिर भी इतना घाटा आपने कर दिया।

मैं निवेदन करना चाह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली कम्पनियों पर भी आपको श्वेत-पत्र लाना चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि आप रेट बढ़ा रहे हो, फिर आप घाटे में जा रहे हो।

छीजत आप रोक नहीं रहे। किस तरीके के हालात आपने पैदा कर दिये? बिजली कम्पनियां और थर्मल पावर कोटा, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर आप दे रहे हो। बीकानेर तो आपने दे ही दिया। प्राइवेट बिजली कम्पनियों को सौंप दिया। जो शहर फायदे में थे, उनकी रेवेन्यू आ रही थी, छीजत नहीं थी। मैं बीकानेर की बात करूं, तो वहां छीजत मात्र 15 प्रतिशत है। कम्पनी फायदे में है। वहां पूरे के पूरे बीकानेर को आपने उस प्राइवेट कम्पनी को दे दिया और अभी जो वहां का कंज़्यूमर है, वह 5.50 रुपये पर यूनिट से पैसा दे रहा है। आपकी बिल रेट उसके लिए 5.50 रुपये पर यूनिट है और प्राइवेट कम्पनी आते ही वह 7.75 रुपये पर यूनिट करेगी। उसके 7.75 रुपये होंगे। आप बता दो। आप बता दो फिर। आप बता दो ना इस पर, कितने पैसे करेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह आंकड़ा कहां से ले आए आप 7.75 रुपये वाला?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं कह रहा हूं न, आप बताओ न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): जिम्मेदार आदमी हो। मैं कह रहा हूं न।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, आंकड़े आप बताओ न। मैं कह रहा हूं राठौड़ साहब, आप बताओ, फिर क्या रेट लगेगी? फिर क्या रेट लगेगी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): जहां निजीकरण हुआ है, वहां बिजली के दाम में प्रति यूनिट में एक परसेंट भी बढ़ोतरी नहीं है। आप बिना मतलब ही चेप रहे हो यूं ही।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, अभी कितने पैसे ले रहे हो? अच्छा, कम्पनी आपकी सेवा करने के लिए आएगी? (व्यवधान) नहीं नहीं, कम्पनियां आपकी सेवा करने के लिए आएंगी? कम्पनी सिर्फ सेवा करने के लिए आएगी, उसको कोई माल नहीं चाहिए? वह कैसे चलायेगी? वह चलायेगी कैसे, माननीय अध्यक्ष महोदय? राठौड़ साहब ने कह दिया...

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान पर विराजें। शांत रहें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ...कम्पनी तो प्रदेश की सेवा करने के लिए आएगी। आप अभी कंजूमर से क्या रेट ले रहे हो? मैं पूछना चाह रहा हूं इसमें, आप बताए कि अभी आपकी कंजूमर रेट क्या है बिजली की और फिर कम्पनी के आने के बाद क्या रेट होगी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर बहस करा लो। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर आधा घंटे की चर्चा करा लो। हमारे मंत्रीजी जवाब दे देंगे। इनका ज्ञानवर्द्धन भी हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिये विराजिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अब इनके द्वारा तो सीधा जवाब दिया जाता है कि नहीं, कंपनी तो सेवा करने के लिए आती है कोई रेट नहीं बढ़ाएगी। तो कंपनी अपना खर्चा कहां से निकालेगी, माननीय अध्यक्ष महोदय? मैं बार-बार यह कह रहा हूं कि आप सदन में बैठ कर असत्य बोल रहे हो। आप जो वो लिखा हुआ है उसमें आप बोल रहे हो, आप पाप के बड़े भागीदार हो। ये पाप के भागी बनेंगे बोल रहे हैं इसमें।

इसलिए मैं मांग करता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि बिजली कंपनियों पर भी श्वेत-पत्र लाए और राजस्थान की प्रजा को आप बताए कि हमारी कंपनियों के ये हाल हैं।

दूसरी तरफ निजीकरण का मामला, आप प्रदेश की हर पब्लिक प्रोपर्टी को बेच रहे हो। चाहे थर्मल पॉवर हो, चाहे आपके आरटीडीसी के होटल्स हों

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)
उनको आपने निकाल दिया उनको बेच रहे हो। थर्मल पॉवर, मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था कि वह घाटा सिर्फ आपका किया हुआ घाटा है। उसमें भ्रष्टाचार की बू आती है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हालात बिजली कंपनियों के आपने कर दिये।

मैं निवेदन करना चाह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि प्रदेश में, अपने मारवाड़ी में कहते हैं कि 'जितनी रज़ाई हो उतने ही पैर पसारने चाहिए' यह है न? आप क्या करते हो? यह प्रदेश की फिजूलखर्ची की स्थिति है माननीय अध्यक्ष महोदय, तो आप रज़ाई नहीं है तो भी आप ओढ़ना चाह रहे हो। रज़ाई आपके पास में नहीं है और फिर भी ये ओढ़ना चाह रहे हैं तो प्रदेश चल सकता है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति सरकार की है। फिजूलखर्ची की मैं बात करूं अभी प्रदेश में 170 करोड़ का जेट विमान खरीदने की बात चल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जनता की गाढ़ी कमाई को पानी की तरह बहाने का काम कर रहे हैं। 170 करोड़ के जेट की कहां जरूरत पड़ी, जबकि सरकार के पास में दो विमान पहले ही खड़े हैं। वो विमान आपके किंग एयर बी-200 और दूसरा किंग एयर सी-90ए। उसमें रिपोर्ट आयी कि दोनों ये चालू हालत में हैं? ये उड़ान भर सकते हैं। ये जो 170 करोड़ का जेट विमान है इसका सीधा फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एविएशन डिपार्टमेंट को प्रस्ताव भेजा कि 170 करोड़ का जेट विमान खरीदना है आप फटाफट बजट प्रस्ताव बना कर भेजो। चीफ सैक्रेटरी की हाईपॉवर कमेटी के अन्दर तुरंत प्रस्ताव आ गया। उन्होंने उसको मंजूर कर दिया और ये विमान ऐसा है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि सी.एम. हाउस से उड़कर सीधा यूरोप जा सकता है। 41 हजार फीट तक ऊँचाई में उड़ सकता आप कहां ऊँचाई की बात कर रहे हो। मतलब ये सीधा यूरोप जा सकता है माननीय अध्यक्ष महोदय, मतलब वहां से सीधा यूरोप जा सकता है बीच में कहीं रुकने की जगह ही नहीं। इतनी उसकी फ्युल कैपेसिटी है तो इस विमान को खरीदने की जरूरत कहां है जब आपके पास में ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): पैसा नहीं और प्रदेश घाटे में

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

और प्रदेश की जनता दुःखी, प्रदेश का आम जन दुःखी और उसमें आप फिजूलखर्ची करने में लगे हुए हो।

मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि जितनी आपके पास में रज़ाई है उतने ही पैर पसारो। ज्यादा पसारोगे तो घाटे में रहोगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, फिजूलखर्ची का एक दूसरा उदाहरण और है। आपके तीन साल पूरे हुए 13 दिसम्बर को तीन साल पूरे होने पर वैसे इन्होंने तीन साल में भट्ठा बैठा दिया प्रदेश का और तीन साल पूरे होने के बाद एक बहुत बड़ा प्रदेश के अन्दर जश्न मनाया गया। जगह-जगह कला जत्थे, इनके मंत्रियों की एक कमेटी उसमें राठौड़ साहब आप भी थे। चार-पांच मंत्रियों की कमेटी बनाई गई। कटारिया जी थे, युनुस खान जी भी थे, वो कहां गये? एक-दो मंत्री और होंगे। उसमें हाई पॉवर कमेटी बनाई गई और कमेटी ने तीन साल का जश्न किस तरीके से मनाना है, मतलब गांव-गांव इन्होंने भेज दिये और उसमें करोड़ों रुपये खर्च किये गये अपनी उपलब्धियां गिनाने में। तीन साल के जश्न के अन्दर मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे कि आप उसका हिसाब दो कि कितना पैसा खर्च किया। इसमें आपको देना चाहिए। ये तो जनता की कमाई है, जनता का पैसा है, आप पानी की तरह लुटा नहीं सकते। आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा कि उस तीन साल के जश्न में आपने कितने पैसे खर्च किये। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हिसाब हमें तो देंगे नहीं। आप ले सकते हो उनसे। मतलब सरकार से हिसाब दिलाओ कि कितना पैसा पूरे प्रदेश में बैनर, होर्डिंग्स, कला जत्थे, प्रदर्शनियां, हर जिले के अन्दर, हर गांव के अन्दर इन्होंने करोड़ों रुपये खर्च कर दिये। यह स्थिति आपकी है फिजूलखर्ची के अन्दर।

अब मैं निवेदन कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, ...।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एक घंटा हो गया साहब, पूरा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): एक घंटा तो बीच में आप भी बोले थे।

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

मैं बजट घोषणाओं की बात कर रहा था। पिछले इन्होंने तीन बजट पेश कर दिये, यह चौथा बजट है। उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी निवेदन किया पहले कि पचास प्रतिशत भी आपकी धरातल पर आयी नहीं। सिराही जिले के बाँध की माननीय सदस्य वहां से आने वाले बार-बार कह रहे थे कि हमारे बाँध बन गया, काम चालू हो गया और वो हो गया ये जो आप भी बोले थे इस बजट चर्चा पर भी, तो सिरोही जिले में 213 करोड़ की लागत से बत्तीसा नाला बाँध बनाया जाएगा, यह बजट में घोषणा की गयी। जुलाई महीने में मुख्यमंत्री जी उसका शिलान्यास करने आप वहां गयी थी उसके बाद में कुछ हुआ ही नहीं। आपने शिलान्यास कर दिया, आज भी वो रुका पड़ा है।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): काम चालू है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): क्यों फालतू में, कितने साल में करोगे, कितने साल में, यह कब की घोषणा है?

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): मैं खुद जाकर आया हूं काम चालू है।

श्री अध्यक्ष: शंकर सिंह जी, विराजिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): सात मेडिकल कॉलेज, आपके चूरू का भी है। तीन साल हो गये। तीन साल के अन्दर उन मेडिकल कॉलेजेज की कोई सुध लेने वाला नहीं है। चूरू में मेडिकल कॉलेज बना, आपने पैसा लगाया, लेकिन दीवार गिर गई। उसकी दीवार भी गिर गयी। आपने चारदीवारी बनाई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं आपको लेकर चलूंगा, देखना, क्या बना है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं चलूंगा साथ में। चारदीवारी उसकी गिर गयी। चारदीवारी बनाई, शुरूआत की और बनाते ही चारदीवारी गिर गयी। ये तो आपके मेडिकल कॉलेजेज का है तीन साल हो गये। कब तक बनाओगे? उसमें कब तक बनाओगे? तीन साल हो गये।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): पाली में तीसरी मंजिल चल रही है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन साल के अन्दर इनके सात मेडिकल कॉलेज चालू नहीं हुए। आईजीएनपी के सड़क मंत्री जी नहीं हैं। आईजीएनपी की पिछले बजटों में घोषणा की गई कि आईजीएनपी एरिया में क्योंकि पहले सीएडी ने रोड्स बनाई थी इर्रिगेशन डिपार्टमेंट ने। वो रोड्स का हमेशा जो चल रहा था कि पहले बनाई सीएडी ने वो सीएडी डिपार्टमेंट ने उन रोड्स को छोड़ ही दिया, उन रोड्स का धणी धोरी कोई नहीं है। हम बार-बार निवेदन करते आये हैं। उसमें आपने कहा कि हम सड़कें पीडब्ल्यूडी के अन्दर ले लेंगे और इन सड़कों को हम फिर रिनोवेट करेंगे। अभी तक ली या नहीं ली, इसका कोई पता नहीं। आईजीएनपी में कुल 476 किलोमीटर सड़कें थीं, 98 सड़कें। आज तक उनका कोई काम नहीं हुआ।

आपने घोषणा कर दी बजट में। पिछले बजट में भरतपुर जिले में वृज भूमि, गोरधन जी और वृज चौरासी कोस की परिक्रमा 103 करोड़ 84 लाख रुपये की घोषणा की। उसका निविदा के अलावा आगे कोई कदम नहीं उठाया। उसको टाइम हो गया।

तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय गड़करी जी केन्द्रीय सड़क मंत्री सालासर के अन्दर, आप गये थे। दो इस सरकार के नम्बर-1 मिनिस्टर भी साथ में थे। अब नम्बर-1 तो कौन हैं वो मेरे को पता नहीं, वो तो आप तय करो, लेकिन मंत्री साथ में थे, उसका शिलान्यास करके आये। ऐसे शिलान्यास करने से, आप शिलान्यास करके आ गये। पता नहीं, रोड बनेगी या नहीं बनेगी इसका कोई भरोसा नहीं। जनता इस पर विश्वास ही नहीं करती। आज तक गड़करी जी ने भी बहुत लंबी-चौड़ी बात की ...कि प्रदेश में अब हम ऐसी सड़कें बनाएंगे कि रोडों पर सीधा प्लेन उतरेगा। यह बातें गडकरी जी ने कहीं। ...(व्यवधान)...

(17.00 बजे)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): जोधपुर से नागौर आप जाते हो तो वहां हवाई जहाज क्या जेट उतार दो, गडकरी जी ने बनाई है सीसी रोड।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): वकील साहब सुनो, मैं इन्हीं खोड़ो खींपों का आदमी हूं, हर जगह घूमता हूं। प्रदेश के हालात न आपसे छुपे हुए हैं, न हमारे से छुपे हुए हैं, चाहे सड़कों की लो या किसी सैक्टर की

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)
आप ले लो। कोटा से दर्रा हाई वे, अभी कोटा के माननीय सदस्य बोल रहे थे कि हमारा काम बहुत प्रगति पर चल रहा है। लेकिन कोटा से दर्रा हाई-वे का काम सिर्फ 13 प्रतिशत हुआ है और उसको कितना टाइम हो गया, यह आप देख लेना। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से वाल बिलाड़ा एनएच का सिर्फ वर्क ऑर्डर निकला है। उसकी भी घोषणा आपने 2015 में की थी, उसका अभी तक तो आदेश निकला है, उसका वर्क ऑर्डर निकला है। ...(व्यवधान)... फाइनल हो गया तो वह पूरा कब होगा, अभी तो वर्क ऑर्डर निकला है। दो साल में तो आपका वर्क ऑर्डर निकला है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रदेश की जो ज्वलंत समस्या और जो दिक्कत है, वह रोजगार की है। रोजगार पर अपन कोई काम नहीं कर रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, उच्च शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं। ये हमेशा किसी भी प्रश्न पर यह कहते हैं कि हमारा तो एक भी पद खाली नहीं है। पूरे स्कूलों का तो आपने सत्यानाश कर दिया। साढ़े 17 हजार स्कूल बंद कर दिये और उन साढ़े 17 हजार स्कूलों में जो बच्चे थे उनको भेड़-बकरियों की तरह एक जगह भर दिये। उनके बैठने की भी जगह नहीं है। आप कभी गये स्कूल? सिर्फ कोलायत में आपने कम से कम सवा सौ स्कूल बंद कर दिये। जिन सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में मर्ज किया, उनमें बैठने की जगह नहीं है। भेड़-बकरियों की तरह भरे हुए हैं। किस तरह से मिड डे मील की व्यवस्था वहां हो रही है, यह भी किसी से छिपी हुई नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा विभाग की बात करूं। शिक्षा विभाग में ...

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): सरकारी स्कूलों का नामांकन देखो, कितना बढ़ा है। देश की जनता का सरकारी स्कूलों पर विश्वास कितना बढ़ा है। शिक्षा में एग्जाम्पल बना है। पूरे देश में नहीं हुआ कहीं। ...(व्यवधान)...

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): 2003 में क्या हुआ लालसोट में?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज स्कूली शिक्षा में चाहे वह आपकी एलीमेंट्री एजुकेशन हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक हो, उनमें डेढ़ लाख पद रिक्त हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): यह सूचना आप कहां से लाये हो?

श्री अध्यक्ष: शिक्षा मंत्रीजी, बैठिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आपका यह वार्षिक प्रतिवेदन है, इसमें लिखा हुआ है। यह आपने ही दिया है, कौन बनाता है। डेढ़ लाख पद रिक्त हैं। अभी कल ही आपने 6120 पद समाप्त कर दिये और डेढ़ लाख पद आलरेडी इनके खाली पड़े हैं, उसमें और पद आप समाप्त कर रहे हो। शिक्षा विभाग में माध्यमिक शिक्षा में 2,77,000 पदों में से 81,954 पद रिक्त हैं। प्रदेश के स्कूली व्याख्याता के 17351 पद रिक्त हैं। वरिष्ठ अध्यापकों के 15775 पद रिक्त हैं। स्कूलों में 10 हजार से ज्यादा सैकण्ड लेवल तृतीय श्रेणी अध्यापक नहीं हैं। 1200 से ज्यादा प्रिंसिपल नहीं हैं। इसी तरह प्रारंभिक शिक्षा में 67509 पद रिक्त हैं। कुल मिलाकर 1,49,463 पद रिक्त हैं। नौकरियां आप निकाल नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप कितना समय और लेंगे?

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह आपके टाइम का पढ़ दिया आपने गलती से।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): यह वार्षिक प्रतिवेदन आपने दिया है या हमने दिया है?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आप जरा ढंग से इसको पढ़िये, अध्ययन कीजिए, फिर बहस कीजिए, तैयार हैं हम।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): यह प्रशासनिक प्रतिवेदन किसने दिया? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाह रहा हूं कि प्रशासनिक प्रतिवेदन किसने दिया? आपके डिपार्टमेंट का दिया हुआ है।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): आपको निपटाने के लिये किसी ने आपके हाथ में दे दिया।

श्री अध्यक्ष: मिस्टर गोठवाल, नो डिस्टर्बेंस। अब खतम करने वाले हैं ये, इनका एक घंटा पूरा हो गया। कितना समय और लेंगे आप?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से सदस्य टीका-टिप्पणी कर रहे हैं...

श्री अध्यक्ष: उसमें ज्यादा समय नहीं गया है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आप कभी पंजाब की बात कर रहे हो, कभी कुछ कह रहे हो। एक गंभीर चर्चा चल रही है, उस गंभीर चर्चा में भाग नहीं लेना चाह रहे। प्रतिपक्ष का काम क्या है। जो आपकी कमियां हैं, उन कमियों को आप तो दिखा नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते, आप में इतनी हिम्मत नहीं। आपको सोचना चाहिये कि यदि बजट में कोई कमियां हैं तो सरकार के हर नुमाइंदे का दायित्व है कि उन कमियों को सरकार की मुखिया को बताये। आप बता नहीं सकते। आपको बतायें तो आप उसकी मजाक कर रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिये। शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं कि यह प्रतिवेदन पता नहीं कहां का आ गया। आपने 6170 पद किस वजह से हटा दिये। क्या आज स्कूलों में मास्टर हैं? बच्चे भेड़-बकरियों की तरह भर दिये।

श्री अध्यक्ष: अब आप कितना समय और लेंगे?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं 10 मिनट और लूंगा।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, 10 मिनट आप और ले लीजिए। वैसे 1 घंटा 2 मिनट हो चुके हैं आपके।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): यह भी आप अभी बता रहे थे कि छात्रों का नामांकन बढ़ा है, माननीय सदस्य ने बताया। माननीय अध्यक्ष महोदय, नामांकन की यह स्थिति हो गई कि प्रदेश की स्कूली शिक्षा में छात्राओं की ड्रोप आउट दर बहुत ज्यादा है। वर्ष 2016 में माध्यमिक शिक्षा में 6,22,154 छात्राओं का नामांकन हुआ जबकि उच्च माध्यमिक में छात्राओं की संख्या घटकर 3,91,000 हो गई। आपकी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में भी आधी हो गई। फिर आप क्या शिक्षा का ध्यान रखते हैं, यह आपकी रेस्पोंसिबिलिटी नहीं है? ...(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था की बात करें। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी चौपट हो गई कि कानून व्यवस्था में जो आपका पुलिस प्रशासनिक ढांचा है, उसमें भी बहुत बड़ी कमी है। पद रिक्त पड़े हैं। पुलिस प्रशासनिक ढ़ांचा सुदृढ़ नहीं कर सकते हैं। कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में चौपट है। आज स्थिति यह है कि आमजन अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा और इस बजट में कहीं कोई आपने प्रावधान नहीं किया।

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं दिसम्बर, 2013 में जब इनकी सरकार आई, उससे पहले हम सत्ता में थे, 12 हजार कांस्टेबलों की भर्ती की। बजट में 5500 कांस्टेबल की भर्ती की घोषणा की गई। यह प्राथमिकता से पूरी होनी चाहिये थी, वह कागजों में ही रह गई। हमने घोषणा कर रखी थी, इन्होंने खतम ही कर दी। आज प्रदेश में हैड कांस्टेबल और कांस्टेबल श्रेणी के 11800 पद रिक्त हैं। उप निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक स्तर के 3410 पद रिक्त हैं। पुलिस निरीक्षक स्तर के 302 पद रिक्त हैं। जब पुलिस थानों में पुलिस नफरी पूरी नहीं करोगे तो कैसे कानून व्यवस्था रहेगी। पुलिस को कोई सुविधा नहीं दे रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस की स्थिति यह हो गई थानों में धक्का देने वाली गाड़ियां हैं, पुलिस के पास हथियार नहीं।

जो गैंगवार है उसके पास तो ए.के.-47 है। आपके पुलिस वाले के पास में लमछड़ है। वह लमछड़ होते थे, जिसमें भरकर खटखट करते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, चलती ही नहीं है। गृह मंत्रीजी को हंसी आ रही है। लमछड़ समझते हो आप? वो वाली पुलिस के पास में है। यह स्थिति कानून व्यवस्था की है जो आप सुधारना चाहते हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह बात रिकार्ड पर जा रही है कि पुलिस के पास लमछड़ है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): वह लमछड़ जैसी है। चलती ही नहीं। दो पुलिस वाले मर गए थे ना उनकी चली नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उनका हथियार चला नहीं। आनंदपाल के पास ए.के.-47 थी, उसने दो मार दिए। क्या वे मरे नहीं थे? वे नागौर के अंदर मरे थे। पुलिस का हथियार चला नहीं और आनंदपाल ने पुलिस के दो जवानों को मार दिया। पुलिस प्रशासनिक ढांचा जब तक सुदृढ़ और मजबूत नहीं होगा। आज थाने के अंदर नफ़री की पोस्ट 40 की है और है 15 और क्राइम रेट दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। मेरा यह निवेदन है कि पुलिस प्रशासनिक ढांचा आपको मजबूत करना चाहिए। बजट में कहीं कोई प्रावधान नहीं है। कहीं आपका ऐसा रोड़ मैप नहीं है, जिससे पुलिस प्रशासनिक ढांचा सुदृढ़ हो सके। मैस अच्छी नहीं है। पुलिस की हालत यह हो गई है।

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

मैं माननीय गृह मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि पुलिस की गाड़ी जो थाने के अंदर दी हुई है, उसके लिए आप एक महीने का कितना डीजल देते हो? जो मुस्तगीस आएगा। जो परिवादी आएगा, वह गाड़ी लेकर आएगा। फिर पुलिस वाले जाएंगे या फिर उससे तेल भरवाएगा। आप उसको तेल दे नहीं रहे। मोटर साइकिल पुलिस के एक कांस्टेबल को दे रखी है। उस कांस्टेबल को आप मोटर साइकिल का कितना पैट्रोल देते हो? यह भी आप बता दो। कहीं एक महीने का पांच लीटर पैट्रोल देते होंगे। एक महीने का पांच लीटर पैट्रोल..। पहले वह पैट्रोल की टंकी की तरफ देखेगा। कहां तो वह परिवादी की सुनेगा और कहां कानून व्यवस्था चाक चौबंद करेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति कानून व्यवस्था की है। चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर भी व्यवस्था की बात करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है।

श्री अध्यक्ष: जल्दी खतम कीजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं जल्दी-जल्दी कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। चिकित्सा विभाग के अंदर भी 34 हजार 741 पद रिक्त पड़े हैं। जिसमें प्रदेश में नर्स श्रेणी प्रथम एवं द्वितीय के 6 हजार 595 पद, लैब टैक्निशियन के 2518 पद रिक्त पड़े हैं। चिकित्सा अधिकारी के 1 हजार 90, कनिष्ठ विशेषज्ञ के 1184 पद रिक्त हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे में प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था कैसे सुचारू रह सकती है? इसमें भी आपको सोचना चाहिए। नौकरियां आपने 15 लाख कह दी और आप नौकरियां लगा नहीं रहे हैं। विद्यार्थी मित्र रो रहा है, संविदाकर्मी रो रहा है, आपके ए.एन.एम., जी.एन.एम. रो रहे हैं। यह हालात हैं, जब आपके पास में हैं। इन सारे विभागों को सुदृढ़ करने का..।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): बिना कर्मचारी विभाग खाली पड़े हैं। आप भर्ती क्यों नहीं करते?

श्री अध्यक्ष: अब समाप्त कीजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, कौशल विकास की बात आई।

श्री अध्यक्ष: अब आप समाप्त कीजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं करता हूं ना दस मिनट में सर।

श्री अध्यक्ष: हो गए, मैं भी घड़ी देख रहा हूं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आपका कौशल विकास बिलकुल चरमरा गया है। इसमें फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांत रहें कृपया। बैठिए आप। जसवंत सिंहजी, विराजिए। (व्यवधान) बैठिए आप। प्रतिपक्ष के नेता आप।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आपका विभाग आया तब, इसमें भी आप दिखाओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी अव्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट में समराइज कर दीजिए आप। हो गया।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: मैं भी देख रहा हूं। हो गया, एक मिनट में समराइज कीजिए। आप तो समराइज भी नहीं करते हैं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं उदयपुर विकास प्राधिकरण की। माननीय गृह मंत्रीजी बैठे हैं। इन्होंने भी मांग की है कि उदयपुर का विकास प्राधिकरण बनना चाहिए। आपने प्रस्ताव बना लिया, अब आप बनाना नहीं चाहते। इनके द्वारा ही प्रस्ताव आया। इसको इग्नोर कर दिया गया। कहीं कोई बना नहीं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): कोटा रन-वे। कोटा दक्षिण से आने वाले माननीय सदस्य ने तो कह दिया कि यदि रन-वे नहीं बना और एयरपोर्ट नहीं बना तो हम प्रधानमंत्रीजी का हवाई जहाज भी उतरने नहीं देंगे। उन्होंने यह भी कहा है। तो इस बजट में इसका कोई रोड मैप नहीं है।

श्री अध्यक्ष: कृपया अब स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट के अंदर सत्ता पक्ष के विधायकों की उपेक्षा की गई है। मैं भी यह निवेदन करना चाहूंगा कि कम-से-कम सत्ता पक्ष के सदस्यों की तो आप सुन

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)
लो। उन्होंने इस बजट की चर्चा में जो मांगें की हैं, उन चर्चाओं को तो आप इस बजट में ले लो। उनकी तो आप पूरी कर लो।

एक माननीय सदस्य: कर तो दिया है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): फिर आप क्यों बोल रहे थे?

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण कर लीजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट। मेरा इतना ही है।

श्री अध्यक्ष: चलिए, एक मिनट।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): चंद्रकांताजी बाहर है।

श्री अध्यक्ष: बैठिए। बेनीवालजी, अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): जयपुर के दो मेगा प्रोजेक्ट हैं, उसमें एक रिंग रोड का है और एक द्रव्यवती नदी का है। वह आपका ही बनाया हुआ है। आप मंत्री थे, अब तो चेंज कर दिया। माननीय सदन की नेता ने पिछले बजट में कहा था कि हम इन्दिरा गांधी नहर के अंदर जहाज चलायेंगे। यह कहा था। यह जहाज वाली बात है।

श्री अध्यक्ष: अब विराजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट सर।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट अच्छा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): तो द्रव्यवती नदी और रिंग रोड का काम किस तरह से कछुआ चाल से चल रहा है। द्रव्यवती नदी का सपना, जयपुर की जनता को एक ड्रीम प्रोजेक्ट दिखा दिया। मुझे नहीं लगता पर हम यह चाहते हैं कि एक सकारात्मक सोच से आप इसको पूरा करो। ये जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, उससे भी आम जनता को फायदा होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में मुख्य मंत्रीजी..।

श्री अध्यक्ष: हो गया आपका। कृपया समाप्त करें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं यह अंत वाला ही बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: अच्छा आखिरी बोल दीजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं अंत में, मुख्य मंत्रीजी के बजट में प्रस्तुत यह कथन दोहराना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने पहले पन्ने पर

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

कहा है कि 'विरासत में मिली चरमराई अर्थव्यवस्था, अकुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण प्रगति का यह सफर अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहा है और आगे भी रहेगा'। मैं सदन की नेता को याद दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान की पहली विधान सभा 1952 में बनी, तब प्रदेश के अंदर क्या था? यह भी आपको पता है। 8 दिसम्बर, 2003 में जब आप पहली बार मुख्य मंत्री बनीं। 1952 से 2003 तक क्या विकास हुआ? यह भी आपको अच्छी तरह पता है। 13 मेगावाट बिजली बन रही थी।

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। प्रतिपक्ष के नेता, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। आपका सब हो गया। विराजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): यह लास्ट पन्ना है। सर, मैं इसको कनक्लूड तो करूं।

श्री अध्यक्ष: लास्ट-लास्ट करते हुए आप कहां पहुंच गए। कृपया बैठिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्षजी, कनक्लूड कर रहा हूं। बीच में छोड़ दिया ना।

श्री अध्यक्ष: आपके पास में बहुत मैटर है। विराजिए। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्षजी, मैं कनक्लूड तो करूं।

श्री अध्यक्ष: आपने तीन बार कनक्लूड कर दिया।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): यह बोलकर पढ़कर बताना है बस।

श्री अध्यक्ष: चलिए, बोल दीजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं अंत में..। प्रदेश के विकास की यात्रा को हमने ऐसे मजबूत संकल्पों के साथ में आगे बढ़ाया। वर्तमान सरकार ने तो इस विकास की यात्रा पर सेंसरशिप लगाने का काम किया है। प्रदेश के एक महान पत्रकार हुए, श्री कर्पूर चंद जी कुलिश। उनकी आज से चालीस साल पहले लिखी हुई यह पुस्तक है- 'मैं देखता चला गया'। मैं सत्ता पक्ष से अनुरोध करूंगा कि यह किताब वे जरूर पढ़ें। उन्हें मालूम चलेगा कि राजस्थान के विकास की यात्रा किन चुनौतियों के साथ में आगे बढ़ी है? चाहे माही बजाज हो, चाहे इंदिरा गांधी नहर हो, चाहे कोटा बैराज हो, चाहे

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)
रावतभाटा परमाणु घर हो, ऐसे कई सैकड़ों उदाहरण हैं। प्रदेश के विकास का विजन क्या होता है, उसको जानने के लिए सदन की नेता को यह पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। तीस साल की अधूरी बजट घोषणाओं के साये में एक दिशाहीन और बेकारी बढ़ाने वाला बजट सरकार ने प्रस्तुत किया है। यदि यही बजट सरकार का विजन है तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह सत्ता पक्ष को सद्बुद्धि प्रदान करें। अध्यक्ष महोदय, मैं दुबारा आप सबको, आपको, जो आपने समय दिया, बोलने का मौका दिया। इनको सद्बुद्धि दो। समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: मैं सबको सद्बुद्धि की प्रार्थना करता हूं। अब माननीय सदन की नेता, मुख्य मंत्री महोदया अपना वक्तव्य देंगी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि बजट भाषण की इस चर्चा में पक्ष और विपक्ष के करीबन 68 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है और करीबन 20 घंटे की डिबेट चली है। बहुत सारे बहुमूल्य सुझाव आए हैं। मैं आपके द्वारा इन सबका आभार प्रकट करना चाहती हूं। इस प्रदेश का, जैसा आप कह रहे थे, हम सब लोगों को मिलकर सर्वांगीण विकास करने की कोशिश करनी है। यह तभी संभव हो सकेगा जब हम लोग इस हाउस को मंदिर मान कर तय करें कि जो कार्य अपने को अच्छी तरह से करने हैं, वह चाहे पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, सब लोग मिलकर, एक लक्ष्य निर्धारित करके उस लक्ष्य की तरफ काम करने की कोशिश करें।

हमारी तरफ से तो हम यह कहना चाहते हैं कि इस प्रदेश के सुनियोजित विकास के लिए एक सक्रिय भूमिका निभाते हुए हमने अपने लक्ष्यों को निर्धारित किया है और हम उन लक्ष्यों की तरफ चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तीन बजट हो गए हैं, यह चौथा बजट हुआ है। इन बजट के द्वारा हम लोगों ने विजन 2020 के द्वारा यह कोशिश की है कि उन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, उन लक्ष्यों की ओर हम चलें ताकि एक-एक करके हर विभाग के अंदर और जनता पर ध्यान देते हुए, उनकी जो आशा-आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें। सोच तो यही रहा है और सुराज संकल्प यात्रा के अंदर मैंने यह भी बात कही थी कि एक नये राजस्थान को हम सबको मिलकर बनाना है। नये राजस्थान को ही नहीं,

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)
परन्तु एक नये भारत के निर्माण की ओर, नया राजस्थान बनता है और हम लोग काम करते हैं तो उसकी ओर भी एक बहुत बड़ा कदम हमारा उठेगा।

अध्यक्ष महोदय, हमारा जो ईयरली बजट होता है, उसको सिर्फ हम आंकड़े नहीं मानते हैं। इसके पीछे हमारी सात करोड़ जनता की आकांक्षाएं, उनकी आशाएं, उनका सोच, उसके अंदर छुपा हुआ है। मैं इस दस्तावेज को इस प्रदेश की दशा और दिशा नापने वाली, बताने वाली। ऐसा दस्तावेज तैयार करने की कोशिश हम लोगों ने की है। आखिर में यह जो चीज है वह हमारी नीयत और हमारी नीतियों को तय करती है। यह हमने कोशिश की है।

सुराज संकल्प के अंदर जो दस्तावेज था, वह हमारी नीयत को पूरी तरह से स्पष्ट करता है। उसका उल्लेख बार-बार हमने बजट भाषण में करने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि दूसरी सरकारें हैं, उन्होंने अपनी ओर से कुछ योगदान नहीं किया। हम मानते हैं कि जरूर कुछ न कुछ योगदान किया होगा। लेकिन यह देखना है कि जो पीछे की सरकारें हैं, क्या-क्या कर सकती थी और उन्होंने क्या किया। क्या कमी थी और उस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने किस तरीके की मेहनत करके उसको सही करने की कोशिश की।

अध्यक्ष महोदय, दृढ इच्छा शक्ति हम सब में होनी चाहिए। उसके साथ-साथ विकास का जुनून हम सबके ऊपर सवार होने की जरूरत है। मैं समझती हूं कि अगर यह है तो संसाधन तो मिल ही जाते हैं, साथ में ऐसे असंख्य लोग हमारे साथ मिल जाते हैं जो हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने के इस बहुत बड़े यज्ञ के अंदर अपनी-अपनी आहूति देने के लिए तैयार है।

हम लोग चाह रहे हैं कि प्रदेश की जनता को खुशहाल बनाएँ। उनको अपने पैर पर खड़े करने की कोशिश करें। उनकी रोजमर्रा की चिंता है उनको हम किस तरीके से दूर करें और हम फाइनेंशियली उनको किस तरीके से मजबूत बनाने की कोशिश करें ताकि उनके ऊपर भी हमारा यह प्रदेश भी आगे बढ़ सके। यह भावना हमने अपने विजन 2020 के अंदर लाने की कोशिश की है। इसको सामने रखते हुए एक टीम राजस्थान को खड़ा करने की हमने कोशिश की। राजस्थान की विकास यात्रा को 13 दिसम्बर से हमने फिर से चालू करने की कोशिश की है। अब मैं यह मानती हूं कि कोई भी अकेला व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकता है। यह मैंने बार-बार कहा है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)
हम तभी सफल होंगे जब सही मायने में एक टीम, एक ट्रू टीम हमको मिल जाए और हम लोग सब मिलकर एक साथ काम करें, तभी पारदर्शिता, प्रामाणिकता और समाज के सभी वर्गों को शामिल करते हुए एक परिवार के रूप में हम अपने प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, आंकड़े हमारी यह पुष्टि करते हैं कि हमारा इकोनोमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है,जिसको हम अपना विकास का आधार स्तम्भ मानते हैं, उस पर किस प्रकार हम लोगों ने विशेष ध्यान देने की कोशिश की है। हो सकता है कि हमने जो कोशिश की है वह सब लोगों के ध्यान में उस तरीके से नहीं आए परन्तु कोशिश में हम लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैं समझती हूं कि जनता इस चीज को समझकर हमारा साथ भी देती है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले पांच वर्षों का रेवेन्यू फ्लो का एनेलिसिस करने की कोशिश की है। आपने भी की, तो मैंने कहा कि थोड़ा हम भी करें। आर्थिक रूप से मार्केट में जो बोयन्सी थी, यह सही बात है कि आज कल में वह बोयन्सी नहीं है। इससे संबंधित जो कुछ आंकड़े हैं, मैं आप सबके सामने रखना चाहती हूं।

पेट्रोलियम की बात आपने की थी। पेट्रोलियम के अंदर एवरेज ग्रोथ रेट 2007-8 से लेकर 2012-13 तक 546.63 परसेंट था, यह एवरेज ग्रोथ रेट पांच गुना बढ़ा। एवरेज ग्रोथ रेट जो 2013-14 और 2015-16 की है, वह माइनस 17.61 यानी नेगेटिव ग्रोथ रेट के हिसाब से चला। इसमें मैं आप सब लोगों को यह कहना चाहती हूं कि यह अकेले ही नहीं था। स्टेम्प एंड रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप ध्यान रखे तो 18.62 तो आपके टाइम में ग्रोथ हुआ है, जो माइनस 0.94 के अंदर हमारे यहां सीमित हो गया। यह इसलिए हुआ कि इस रीयल स्टेट के अंदर बहुत जोरदार मंदी है वह आप सब लोग जानते हैं। हमने बहुत कोशिश की है। एमनेस्टी स्कीम लाई गई, अलग-अलग स्कीम लाने की कोशिश की है। उसके बावजूद भी जब तक यह मंदी नहीं हटेगी, तब तक मैं नहीं समझती हूं कि उस रीयल स्टेट के अदंर या इस एरिया के अंदर वह जान आएगी।

अभी आपने माइनिंग के अंदर बात की। 18.53 परसेंट जो 2007-8 और 2012-13 तक ग्रोथ रेट था, वह 10.18 परसेंट इन तीन-चार वर्षों के अंदर

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

हुआ है। तीन वर्षों के अंदर हुआ है। यह इसलिए बिकोज प्रक्रिया अभी बदली है, अब ई-आक्शन की तरफ हम लोग आ गए हैं और साथ में न्यू रूल्स, न्यू व्यवस्था बनाने का काम चल रहा है। नई व्यवस्था बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह से कुछ न कुछ लोसेज हम लोगों के सामने आए।

व्हीकल टैक्स जो 14.56 परसेंट था, वह 11.92 परसेंट हमारे सामने हुआ है। सैल्स टैक्स 19.19 परसेंट, वह आज के दिन 12.38 परसेंट हुआ है। आपको यह बता दूं कि व्हीकल टैक्स वो ही लोग खरीदते हैं जो मनी सरकुलेशन में होता है। ऐसा सरकुलेशन में अगर नहीं होता है तो फिर, जब बोएन्सी ही नहीं है तो फिर कहां से यह सेल्स होंगे और कहां से आपको यह रेवेन्यू मिलेगा। मैं इसमें सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि आपने बार-बार रायल्टी के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में कहा। मैं मानती हूं कि आपके कार्यकाल के अंदर यह रायल्टी बढ़ी, बिलकुल सही है। परन्तु क्रूड आयल की जो रायल्टी है वह इन्टरनेशनल मार्केट से गवर्न होती है। प्रतिपक्ष के नेता जी, मैं समझती हूं कि सब लोगों को यह चीज मालूम है। राज्य सरकार के द्वारा नहीं। इसलिए अगर वह प्राइस नीचे आती है तो हम लोगों को उसी हिसाब से अपने यहां डील करने की जरूरत होती है। मैं तो सिर्फ इतना ही आप लोगों से पूछना चाहती हूं कि इतना राजस्व आप लोगों को मिला, अभी बताया। इतना राजस्व आप लोगों को मिला तो यह पैसा गया कहां, कहां इस्तेमाल किया? आपके तो महल बन गए होने चाहिए थे, आपके कालेज बन गए होने चाहिए थे, आपके रोड्स बन गए होने चाहिए थे, पीने के पानी के काम हो जाने चाहिए थे। मैं तो यह देख रही हूं कि पीने के पानी का काम हमारे समय में था, आज हम लोग उसको खतम कर रहे हैं। जो पूरे का काम है वह आज हम लोग कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि इतना रेवेन्यू आने के बाद, इतना पैसा आप लोगों के पास आने के बावजूद भी यह पैसा कहां गया और वह क्यूं सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ?

अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ आंकड़े सामने रखना चाहती हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि बजट एलोकेशन कम रहा। मैं इसमें बताना चाहती हूं कि विषम परिस्थितियों के अंदर भी हम लोगों ने एलोकेशन बढ़ाने की कोशिश की है और एलोकेशन बढ़ाया है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

बागीदौरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पी.डबल्यू.डी. के अन्दर, आर.डी. एण्ड पी.आर. के अन्दर जो एलोकेशंस हैं, वे कम हुए हैं। और लोगों ने भी इन चीजों के बारे में बताया तो मैं खाली थोड़े से आपके सामने ये फिगर्स रखना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा के अन्दर 2009-10 से लेकर 2013-14 तक का जो एलोकेशन था, वह 38 हजार 22 करोड़ था। परसेंटेज इनक्रीज इन एलोकेशन, हम लोगों की वजह से 258 प्रतिशत हुआ है, क्योंकि हमारे पीरियड 2014-15 से 2017-18 के अन्दर जो एलोकेशन है वह एक लाख 36 हजार 155 करोड़ हुआ है इन द फील्ड आफ ऊर्जा। पी.एच.ई.डी. के अन्दर जो आपके सामने में 22793 करोड़ का एलोकेशन था, वह 32 परसेंट इन्क्रीज होकर 30115.76 का एलोकेशन हमारे पीरियड के अन्दर हुआ है। पी.डबल्यू.डी. के अन्दर, माननीय सदस्य, बागीदौरा वालों ने कहा कि एलोकेशन कम हुआ है। मैं यह कहना चाहती हूं कि 14725, जो आपके समय के अन्दर था, वह परसेंटेज इन्क्रीज एलोकेशन के अन्दर 41.82 परसेंट, 20883 करोड़ एलोकेशन हुआ। ट्यूरिज्म के अन्दर जो 316.26 एलोकेशन था वह 68.82 परसेंटेज इन्क्रीज इन एलोकेशन होते हुए 533.92 करोड़ हमारे समय में हुआ, जो मैं मानती हूं कि इस सैक्टर को जितना भी हम पुश देंगे, वह हमारे लिये यूजफुल रहता है क्योंकि इसमें एम्प्लायमेंट है। यह एम्प्लायमेंट से जुड़ा हुआ सेक्टर है। इसलिये एलोकेशन बढ़ा और यह हमारे स्टेट के लिये अच्छा ही हुआ है।

इर्रिगेशन के अन्दर आपके समय में 11790 करोड़, जो 25.66 परसेंटेज इन्क्रीज इन एलोकेशन होते हुए 14815.87 करोड़ का एलोकेशन 2014-15 से 2017-18 के अन्दर हुआ। आर.डी. एण्ड पी.आर. के अन्दर जो बता रहे हैं कि कम हुआ है, 39044 एलोकेशन जो आपके पीरियड में हुआ है, 43.24 परसेंट एलोकेशन इन्क्रीज होते हुए 55927.82 करोड़ का आर.डी. एण्ड पी.आर. के अन्दर एलोकेशन हुआ है।

स्पोर्ट्स एण्ड यूथ के अन्दर आपने 359.86 करोड़ पांच साल के अन्दर एलोकेशन किया, 42.62 परसेंट इन्क्रीज हुआ है एलोकेशन के अन्दर। आज स्पोर्ट्स के अन्दर 513.24 करोड़ का एलोकेशन हम लोगों ने करके एक नया रिकार्ड बनाया है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

इतनी सारी चुनौतियों के बाद भी, अध्यक्ष महोदय, हमने इतना सारा काम किया है, तो मैं यह समझ नहीं पाती हूं कि इतने बायएंट रेवेन्यू के बाद आप यह क्यों नहीं कर सके। क्या रीजन था कि इतना सारा पैसा जो आया, वह कहां गया? यह हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। जब इतना बायएंट रेवेन्यू था तो क्यों नहीं आप लोगों ने इतने सारे काम करके उनको कम्पलीट कर दिया, जिसके ऊपर अब आज हम पर अंगुली उठा रहे हैं।

टी.एस.पी. एरिया के लिये भी आपने 13 परसेंट खर्च करने की बात कही। मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि हमारे इन तीन सालों के अन्दर 13.82 परसेंट खर्चा हुआ है, जो मैं समझती हूं कि आपसे ज्यादा है। ये सब ऐसी चीजें हैं, जिनके ऊपर हमको ध्यान देने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं वापस सड़कों के ऊपर आना चाहती हूं। सड़कों के अन्दर, कांग्रेस के पांच वर्षों के अन्दर और हमारे तीन वर्षों के अन्दर जमीन-आसमान का फर्क है। जो हमने तीन वर्षों के अन्दर किया, वह पांच सालों के अन्दर ये नहीं कर पाये। आज चार गांवों को रोज सड़कों से जोड़ा जा रहा है। करीबन 17 किलोमीटर सड़क विकास का काम रोज हो रहा है। अब मैं फिर से दोहराऊंगी वह बात, क्योंकि मैं समझती हूं कि बारबार दोहराने के बाद भी यह चीज सबके जेहन में नहीं उतर रही है तो यह इम्पोर्टेण्ट है कि इसको एक दफा और दोहराया जाये। नई सड़कें हैं, उनके निर्माण के ऊपर जो व्यय हुआ है, वह हमारे तीन वर्षों के अन्दर 4565 करोड़ रुपये खर्च किये गये। आपके पांच सालों के अन्दर 2993 करोड़ रुपये, यानी पांच सालों में भी आप उतना पैसा नहीं खर्च कर सके, जितना हमने अपने तीन सालों के अन्दर खर्च किया है। नवीन सड़कों के अन्दर 14788 किलोमीटर, आपने 12594 किलोमीटर अपने पूरे पांच सालों में किया, हमने तो खाली तीन सालों में किया है। नवीन राजमार्ग 5262 किलोमीटर, आपके टाइम में 174 किलोमीटर, ठीक है एक-दूसरे के ऊपर सदन के अन्दर अपोजिशन और पक्ष के बीच में यह तो नोंक-झोंक होती रहती है। परन्तु हम लोगों को उस रास्ते पर भी चलने की जरूरत है। कभी-कभी पीठ को थपथपा कर बता देना चाहिये कि हां, यह काम हुआ है, यह अच्छा हुआ है और इससे बैटर आप और कर सकते हो और हम आपको मदद करने के लिये तैयार हैं।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सड़कों से जोड़ने वाले आगे जो गांव, ढाणियां और मजरे हैं, उनकी संख्या, आज 4225 हम लोगों ने अभी तक तीन वर्षों के अन्दर किये हैं, आपने अपने पूरे पांच सालों के अन्दर 1638 किये हैं। फिर भी अपन खड़े होकर बात करते हैं और ऐसे प्यार से बात करते हैं, जैसे हम लोग कोई भी कोई कागज पढ़ नहीं रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आजादी से लेकर, केवल तीन सालों के अन्दर नेशनल हाई-वे नेटवर्क इन द स्टेट डबल हो गया है। इसके बाद राज्य देश के अन्दर नेशनल हाई-वे के मामले में प्रथम पोजीशन में आज खड़ा है।

अभी कोटा-दर्रा की चिंता हो रही थी। वह तो हमें भी चिंता है। आखिर में कोटा-दर्रा, झालावाड़, भोपाल का ही वह रास्ता है। हमारे बहुत सारे लोग उस पर गुजरते हैं। फोरेस्ट क्लीयरेंस तो किसी ने लेने की कोई कोशिश ही नहीं की थी। हम लोगों ने मशक्कत करके फोरेस्ट क्लीयरेंसेज भी ले ली है। आज कोटा-दर्रा के ऊपर कार्य तेजी से चल रहा है। दर्रा से तीन धार की डी.पी.आर. भी स्वीकृत हो चुकी है। कोटा-दर्रा का कार्य एक बहुत अच्छी कम्पनी मोंटे कार्लो जिसका नाम है, वह कर रही है। यह चार लेन की सी.सी. रोड बनने जा रही है। भू-अवाप्ति, एन्वायर्नमेंटल क्लीयरेंसेज सब हो चुके हैं। अब किसी प्रकार की अड़चन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा उनको बताना चाहती हूं कि बहुत अच्छी तरह से इस रोड पर काम चल रहा है। ऐसे और भी रोड हैं, जिनके ऊपर बहुत अच्छा काम चल रहा है और हमारे समय के अन्दर उनको पूरा करने का हम पूरा-पूरा प्रयास कर रहे हैं। यह मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय, ये सब रोड्स बनने के बाद यू.पी., एम.पी., हरियाणा, पंजाब और गुजरात इन सबके शहरों से राजस्थान के शहर भी अब जुड़ जायेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें व्यापार हो, कॉमर्स हो, उद्योग हो, पर्यटन हो, इन सब चीजों को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि डाइरेक्ट कम्युनिकेशन अब खुल चुका है। यह सुराज संकल्प के अन्दर भी हम लोगों ने घोषणा की थी कि जिले की जो मुख्य सड़कें हैं, उनको नेशनल हाई-वे से हम लोग जोड़ेंगे। मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी है कि वह संकल्प पूरा हुआ है। क्योंकि आज 5262 किलोमीटर नेशनल हाई-वे घोषित हो चुके हैं

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)
और उनके ऊपर काम चालू है। इससे यह भी हुआ है, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सब माननीय सदस्यों को बताना चाहती हूं कि ये रोड्स सिंगल लेन थे, अब डबल लेन होंगे। इससे क्या होगा कि आवागमन जो भी है, वह सरल भी हो जायेगा, सुगम भी हो जायेगा और लोग उन रोड्स के ऊपर चलना पसंद भी करेंगे।

अब ये आज हैं नहीं, पर मैं फिर भी इसको उठाना चाहूंगी कि बजट के दौरान ड्रिंकिंग वाटर स्कीम फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ की बात उठी और जोर-शोर से उठी। यह कहा गया कि हमारे समय में घोषित हुई थी और अब तक पूरी नहीं हुई है। सच्चाई है कि यह स्कीम 2012-13 के बजट भाषण के अन्दर शामिल हुई थी। छोटी-छोटी स्कीम्स, अध्यक्ष महोदय, 21 करोड़ की, 26 करोड़ की, 28 करोड़ की तो बजट के अन्दर शामिल कर दी गयीं, और इतनी बड़ी स्कीम जो 832 करोड़ की स्कीम थी, उसको वहां तो नहीं किया, परन्तु बाद में चल कर 30 मार्च को, चर्चा में, चूंकि बजट में घोषणा नहीं हुई, इसकी चर्चा के अन्दर घोषणा की गई कि हम आगे चल कर इस रोड को बनाएंगे। इसमें न तो कोई विजन था, न कोई इम्पलीमेंटेशन का थॉट था, न कहां से पैसा आयेगा, उसकी सोच थी। इसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति है, वह 24.08.2012 को हुई। इनके कार्यकाल में करीबन 180 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं परन्तु हमारे तीन सालों में हमने 390 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। यानी दुगुना खर्च किया है और इस साल में 124 करोड़ और खर्च करके इसको पूरा करेंगे। इस स्कीम के ऊपर टोटल 513 करोड़ हम खर्च करने जा रहे हैं।

मैं यह कहना चाहती हूं कि 'भेदभाव'-'भेदभाव', यह शब्द मैंने बहुत सुना है। मैं यह कहना चाहती हूं कि हमने बिना भेदभाव के सबके लिये काम करने की कोशिश की है। यह एक उदाहरण है, क्योंकि हम मानते हैं कि चुनाव तक तो ठीक है, परन्तु चुनाव के बाद पूरा राजस्थान हमारा परिवार है और यह हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व हो जाता है कि हम पूरे क्षेत्रों को, जहां-जहां जरूरत पड़ेगी और जहां-जहां लोग हमारे सामने आयेंगे, या जहां स्कीम्स अधूरी पड़ी हैं, उनको पूरा करना, यह हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। तो घोषणा करने में तो ये माहिर हैं और बोलना भी बहुत आसान

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

है परंतु कम्प्लीशन करने वाली जब बात होती है, वहां फिर आकर अपन अटक जाते हैं। पानी की स्कीम घोषित तो कर दी परंतु ऐसी बहुत सारी स्कीम्स की घोषणा करके, अभी भी यह पड़ी हुई हैं। आपने तो बड़ी ही लंबी लिस्ट अभी खतम कर दी। अभी तो हमारे दो साल और है, यह सब पूरा करके हम आपके सामने इनको दिखाने की कोशिश करेंगे। परंतु जो आपका रह गया है, जिसको हम अब पूरा कर रहे हैं, बोल-बोल कर आपने स्कीम्स तो हमारे सामने खड़ी कर दी है परंतु पूरा हम ही करेंगे।

और, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि हमारी सरकार है वह कागज के अंदर नहीं, वह जमीन के ऊपर काम करना जानती है और करके आपको दिखाएगी।

यही काम सड़कों के ऊपर भी, माननीय सदस्य, सब सड़कों के ऊपर भी यही बात हुई। मैं तीन रोड्स की बात यहां पर करना चाहती हूं। आप इसको चैक कर लें। आज मंत्री महोदय नहीं है, पर जस्टाना-बोंली-निवाई 52 किलोमीटर, बाली-पिण्डवाड़ा 63 किलोमीटर, उदयपुर-संलूम्बर 70 किलोमीटर, यह लास्ट बजट बने इनके 2013-14 वाला, लास्ट बजट के पैरा नम्बर 19 के अंदर इन्होंने इसकी घोषणा की थी और एक-एक रोड के ऊपर उन्होंने 100-100 करोड़ रुपये देने की बात की थी। उस समय न तो इनकी स्वीकृति जारी हुई, न कोई राशि जारी हुई और मैं यह कहना चाहती हूं कि हमने 2017-18 इसी बजट के अंदर पैरा 19-20 के अंदर इनको शामिल कर दिया है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि इनको पूरा भी हम करके छोड़ेंगे।

अब, माननीय अध्यक्ष महोदय, अपन ग्रामीण गौरव पथ के ऊपर आ जाएं। इसके बारे में बहुत सारी बातें उठी हैं। मैं यहां पर यह कहना चाहती हूं कि 2003 से 2008 तक शहरी गौरव-पथ को खड़ा करने की हम लोगों ने कोशिश की थी और इस बार हमने यह कहा है कि इनको ग्रामीण गौरव पथ के रूप में हम सबके सामने लाएंगे। सीमेंट कंक्रीट के वह बनेंगे, साथ में उनकी नालियां बनेंगी और हमने यह चॉइस दे दी थी हमारे एम.एल.ए. साहिबान को कि आप या तो यह ले सकते हो या मिसिंग लिंक आप बनवा सकते हो। कोशिश यह है हमारी कि ज्यादा से ज्यादा ग्राम पंचायत, कवर हो

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो जाए। अच्छा, ग्रामीण गौरव-पथ बनाने के बाद ....(व्यवधान).... आपकी भावना को मैं नहीं पूछ रही है, मुझे इंटरेस्ट है जनता की भावना पर और मैं एक ही उदाहरण आपके सामने रखना चाहती हूं जो यह जनता की उदाहरण आपके सामने पेश होती है।

नागौर जिले की बात है, मेड़ता पंचायत समिति की, मोकाला ग्राम पंचायत की जहां पर श्रीमती सीता देवी की यह जो भावना है, वह आपके सामने पेश कर रही हूं। उन्होंने सड़क के किनारे एक घर खरीदा था। बरसात के दिनों में घुटने-घुटने तक उनके यहां कीचड़ भर जाता था। मक्खी, मच्छर, पानी जमा, यह सब उनके एरिए के अंदर उनको मिलता था। वहां आगे चलकर एक गौरव पथ बना। आज वह कहती हैं कि उस गौरव पथ की वजह से ये सब बीमारियां जो थीं, ये सब जो मुसीबतें और प्रोब्लम्स थीं, वह अब हट गयी हैं और सुगम व्यवस्था हो गयी है। यह तो मैं सिर्फ एक ही उदाहरण आपके सामने रखना चाहती हूं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में हैं। हमने इन सबको इकट्ठा करने की कोशिश की है और आप गांवों में जाओगे तो आपको खुद को मालूम पड़ जाएगा जहां यह सब काम हुआ है। वहां पर आप चले जाओगे तो लोग आपके पास आ-आकर आपको भी बता देंगे जैसे हमको बताते हैं कि इसका काम उनके लिए अच्छा हुआ।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): हम तो गांव में ही रहते हैं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): हां-हां, आप तो रहते हो, बहुत अच्छी बात है। शायद, जितना घूमना चाहिए उतना आप नहीं घूम रहे हो। थोड़ा घूम लें तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि जहां यह सड़कें निकली हैं वहां कोई चिंता नहीं है किसी को, लोग खुश हैं और मैं अब शहरी गौरव-पथ की बात करना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: घनश्याम जी, स्थान ग्रहण करें। घनश्यामजी, स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): मैं शहरी गौरव पथ की बात करना चाहती हूं कि शहर की प्रमुख सड़कों का भी अब हमको विकास करने की जरूरत है, यह हम मानते हैं। 179 जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको हमने 447 करोड़ रुपये का एलोकेशन करके अलग किया है

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

और शहरी गौरव पथ का वहां निर्माण करने का काम हम लोग अब शुरू करने वाले हैं।

माननीय विधायक टोडाभीम के, उन्होंने यह कहा कि सड़कों की खराब स्थिति है और उन्होंने उसका उल्लेख किया तो मैं इनसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि हमारी सरकार आने के बाद उनके क्षेत्र में आर.आई.डी.एफ.-20 और 21 के अंतर्गत 708 यानी, 7 करोड़ रुपये एंड 41.18 किलोमीटर्स में स्वीकृत दस सड़कों के नवीनीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्य करवाये गये हैं। उसके बाद आर.आई.डी.एफ.-22 के अंतर्गत 6 करोड़ 52 लाख के 17 किलोमीटर की लंबाई की 6 सड़कों पर नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण के कार्य स्वीकृत किये गये हैं। ग्रामीण गौरव पथ प्रथम चरण में 5 करोड़ 18 लाख रुपये से 12.725 किलोमीटर लंबाई 15 ग्राम पंचायत में गौरव पथ का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और वह सड़क की जो निविदाएं हैं, दूसरी सड़क जो बाकी बच रही है, उनकी निविदा प्रक्रियाधीन है। ग्रामीण गौरव पथ द्वितीय चरण में 7 करोड़ 80 लाख रुपये के 13 किलोमीटर लंबाई के 13 ग्राम पंचायत पर नाली सहित सी.सी. सड़क निर्माण का कार्य स्वीकृत करके निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इसी प्रकार शहरी गौरव पथ के निर्माण के लिए 3 किलोमीटर सड़क, राशि 2.5 करोड़ की स्वीकृति के बाद कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं। इसके बाद मिसिंग लिंक योजनान्तर्गत 2015-16 में 5 करोड़ 51 लाख रुपये की 20.75 किलोमीटर की लंबाई नाइन मिसिंग लिंक सड़कों को निर्माण कार्य में से 6 काम पूरे हो चुके हैं, शेष प्रगति पर हैं। वर्ष 2016-17 में 3.63 करोड्स की 10 किलोमीटर लंबाई की स्वीकृत चार मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण के लिए कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं और इसके अलावा केन्द्रीय सड़क निधि, देट ईज, सी.आर.एफ. की योजनान्तर्गत 25 करोड्स के 15 किलोमीटर की लंबाई की सड़क का कार्य प्रगति पर है और आप कहते हो कि भाई, आपके लिए काम नहीं करते और भेदभाव करते हैं। मैं तो समझती हूं कि जितना यहां आपको मैंने अभी बताया है, वह शायद ही हमारे किन्हीं लोगों को मिला होगा या उससे ज्यादा किसी को मिला होगा। ...(व्यवधान)... टोडाभीम, टोडाभीम, टोडाभीम।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

अब आपको चिंता हो रही थी, देखिए, अब शहरी क्षेत्र की जब बात करते हैं तो मैं समझती हूं कि एक उदाहरण आपके सामने रखना जरूरी है। आपको बहुत चिंता हो रही थी कि द्रव्यवती नदी का क्या हो रहा है? मैं समझती हूं कि थोड़ा सा अपने को, भले ही अपन अपने एरिये में घूमते हैं परंतु जब आप कभी किसी चीज की बात करते हैं तो उस एरिये को भी देख लें ताकि जब विधान सभा के अंदर आते हैं, पवित्र सदन के अंदर आते हैं तो अपने को कुछ तो नॉलेज हो कि एक्चुअल में जमीन के ऊपर क्या हो रहा है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि यह एक नाला के रूप में परिवर्तित हो गया। नदी थी, द्रव्यवती नदी। समय-समय के अंदर यह एक नाले के रूप में परिवर्तित हो गया। गंदे नाले के रूप में परिवर्तित हो गया और एक किस्म से लोगों की आंखों की किरकिरी बन गयी। हम लोगों ने टाटा संस के साथ बात करके और एक बहुत बड़ा बने, 1677 करोड़ रुपये की स्कीम बनाकर हमने यह तय किया कि जयपुर के सिटीजन्स के लिए पार्क्स के साथ-साथ ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है जहां पर क्लीननिनेंस यानी, सफाई भी हो और जहां पर ग्रीनरी भी हो और जहां लोग अपनी सिटी की क्वालिटी आफ लाइफ को एन्जॉय कर सकें। आज उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए द्रव्यवती नदी के ऊपर काम स्पीडली चल रहा है और मैं समझती हूं कि यह काम जब पूरा हो जाएगा तो अपने आप में ही एक मिसाल आपके सामने साबित होगा और मैं मानती हूं कि अगले साल के अगस्त के महीने तक या सितम्बर के महीने तक यह काम पूरा हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें। शांत रहें, शांत रहें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अब अपन थोड़ा सा ऊर्जा पर आ जाएं। बारबार-बारबार अपन ऊर्जा पर वापस आते हैं तो मैंने कहा कि मैं भी थोड़ा इसको फिर से वापस ध्यान में लाने की सबकी कोशिश करूं। अप टू फर्स्ट अप्रैल, 2009 तब से लेकर, फर्स्ट अप्रैल, 2009 डिस्कॉम्स के अंदर लोन्स जो थे, 21,405 आर.वी.पी.एन. के 4,570 आर.वी.यू.एन. के 7,949 टोटल 33,924 करोड्स बनता है, जोड़ने के बाद। अब आप फर्स्ट अप्रैल, 2009 से लेकर फर्स्ट अप्रैल, 2014 तक आओगे तो डिस्कॉम में 72,723 जो डिस्काम में 21,000 था, ऑल दोज ईयर्स, आर.वी.पी.एन. के अंदर जो 4,570

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

था वहां 8,226 जो आर.वी.यू.एन. के अंदर जो लोन हो गया था 7,949 ओर 16,309 और टोटल जो लोन अब हो जाता है 97,052 करोड्स यानी, पांच साल के अंदर अप्रोक्सिमेटली 63,64,000 करोड्स बढ़ा है और फिर भी सही बात तो है, आप लोग सब हो, आप सब जीत-जीतकर जब अपने-अपने क्षेत्र में गये हैं जब हमने यात्रा के दौरान पूरे राजस्थान का दौरा किया।

हमको जो तंत्र मिला है, वह चरमराया हुआ था, उसमें कोई काम हुआ ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पोल बिलकुल टिल्टेड थे, तार झूल रहे थे, सर्किट ब्रेकर्स थे ही नहीं, रोस्टर्स स्विचेज भी नहीं थे, सब-स्टेशन की हालत बिगड़ी हुई थी, कुछ भी नहीं था। मैं समझती हूं, उस समय इतनी हालत खराब थी, आज उसके साथ हम लोग जूझ रहे हैं। पर अध्यक्ष महोदय, यह पूछने लायक है कि यह इतना सारा पैसा कहां गया? यह सैकण्ड टाइम पूछ रही हूं मैं। यह तो हमसे पूछ रहे हैं कुछ भी। 45,000/- crores, 22,000/- crores, 12,000/- crores and 10,000/- crores पर यह तो फीगर्स हैं, और मैं यह पूछना चाहती हूं कि पहले के फीगर्स के साथ-साथ इन फीगर्स को जोड़ते हुए गया कहां, इतना सारा पैसा लेकर किया क्या? क्या किया? आज दिन तक हमको कोई भी सेटिसफेक्टरी जवाब नहीं मिल रहा है और हम बार-बार पूछ-पूछकर थक गये हैं, पर पूछते रहेंगे।

मैं यहां आपको फिर से कहना चाहती हूं पांच साल में आपने क्या किया और हमने क्या किया हमारे तीन साल के अंदर, इस चीज को ध्यान में रखने की कोशिश करिये। सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता के अंदर मेगावाट में जो वृद्धि हुई है 740 मेगावाट in 3 years और इनके पांच साल के अंदर 661.75 मेगावाट। तापीय बिजलीघर की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है 1750 MW in these 3 years but और इनके टाइम में 1180 MW in 5 years. और डिग्गी सिंचाई, यह काफी चर्चा हो रही थी, डिग्गी सिंचाई योजना के अन्दर तो मैंने सोचा कि बहुत बढ़िया काम किया होगा तो मैंने इसमें देखा। तीन साल के अंदर हमने देखा कि 2450 मेगावाट तो हमने काम किये, इन्होंने पूरे पांच साल में 819 मेगावाट काम ही किये और अगर आप देखो कि तीन साल में आपने क्या किये तो 220 मेगावाट बनाये और मैं यह पूछना चाहती हूं कि तीन साल का तो दस गुना हमने काम किया है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)
इन सब चीजों को अपने को ध्यान में रखने की जरूरत है Criticism for the sake of criticism, is not a good idea.

अध्यक्ष महोदय, किसानों को बिजली दरों में अनुदान, जिसकी अपन बात कर रहे हैं, करोड़ों में है। मैं आपको कहना चाहती हूं कि आपने अपने पांच साल के अंदर जो अनुदान दिया, वह 8 हजार 320 करोड़ थे, हमने अपने समय के अंदर 19 हजार 398 करोड़ यानी इनको अनुदान के रूप में दिया और बिजली कम्पनियों को, जो प्रदत्त आर्थिक सहायता है, वह आपके समय में पांच साल के अंदर 27 हजार 750 करोड़ हमने दिये हैं और तीन साल के अंदर 97 हजार 105 करोड़ का हम लोगों ने बिजली कम्पनियों को आर्थिक सहायता देने का काम किया है।

मैं आपको यह भी कहना चाहती हूं कि जो सहायता हुई है वह कहीं तो ढाई गुना है, कहीं तीन गुना है। पर जब अपन बात करते हैं तो यह सही है कि अपने को फिगर्स भी देख लेने चाहिये। ...(व्यवधान)... फिगर्स देख लो There is no point.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अभी बतायेंगे आपको, बैठो।

श्री अध्यक्ष: प्लीज स्थान ग्रहण करें। रमेशजी, स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सरकार ने तीन साल के अंदर पेयजल को प्राथमिकता दी। 14 हजार 361 करोड़ हमने व्यय किये और 32 मेजर पेयजल परियोजना हमने पूर्ण की हैं। जैसा आपको मालूम है कि हमको करीब पेयजल की 67 स्कीम्स विरासत में मिलीं, जिनमें से हमने 37 स्कीम्स लीं और उसमें से 32 हमने पूरी कर ली हैं और फाइव हम अगले साल तक पूरा कर लेंगे। यह सब इनकी स्कीम्स हैं, जो हम अभी पूरा कर रहे हैं और 4 हजार 29 गांवों और ढाणियों को हमने शुद्ध पेयजल दिया है और बस्तियों को शुद्ध पेयजल 1410 आर.ओ. प्लांट लगाकर हम लोगों ने दिया। मैं यह कहना चाहती हूं कि इन तीन सालों के अंदर 1410 हमने आर.ओ. प्लांट लगाये। मैं इनका जब देखती हूं तो तीन साल के अंदर तो जीरो और पांच साल के अंदर 33, हमारी आदत नहीं है कि गलत फिगर्स हम आप लोगों के सामने और हाउस के अंदर इस तरीके से दें। अभी तक

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

हम लोगों ने यह काम नहीं किया है। परन्तु मैं आपको कहना चाहती हूं कि पूरे टाइम में आपने सिर्फ 33 और पहले तीन वर्ष में जीरो, ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? इसको आगे बढ़ाने की क्यों जरूरत नहीं? आप हमसे प्रश्न पूछते हो तो इनके जवाब भी देना जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, हम सब लोग जानते हैं कि राजस्थान के अंदर मीठा पानी बहुत ही कीमती है। आजादी के इतने साल बाद गांवों के अंदर पहली बार मीठा पानी अब मिल रहा है और हम दे रहे हैं और जिसको मीठा पानी मिला है, वो क्या कहता है। मैं जो चूरू की पेयजल परियोजना है उसको लेना चाहती हूं। जो लाभान्वित गांव हैं वह करीबन 188 हैं चूरू और झुन्झुनूं के। दो लोगों से बात हुई। ऐसे तो बहुत हैं परन्तु दो लोगों का मैं आपके सामने उदाहरण पेश कर रही हूं। संतोष बाई और ज्ञान कंवर, ये दोनों ग्राम मीठड़ी तहसील राजगढ़ की हैं। संतोष बाई कहती है - 'पहले पानी खारा था, जानवर भी तकलीफ में थे, टैंकर के पैसे लगते थे, अब मीठे पानी का आराम है।' दूसरी ज्ञान कंवर कहती है -'पानी लाने के कारण पहले बच्चों का स्कूल छूट जाता था, अब दोनों टाइम अच्छा पानी आता है। अब बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, सब खुश हैं।' अब यह ठीक है कि आप सोचो न सोचो, आप इसको दूसरी तरह से लेने की कोशिश करो, हम तो जनता से बात करके, उनसे पूछकर इन चीजों को आपके ध्यान में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझती हूं कि इसका फायदा है।

हमारे सांचौर के माननीय विधायक ने पेयजल योजना को शुरू नहीं करने और बजट में कोई प्रावधान नहीं किये जाने का उल्लेख किया। हम यह बताना चाहते हैं कि जालौर की नर्मदा ड्रिंकिंग वाटर की स्कीम थी, उसकी आधारभूत योजना के कार्य की जो लागत थी, वह 310.12 करोड़ का कार्यादेश और आई.वी.आर.सी.एल. को जारी कर दिया गया था We know the I.V.R.C.L. योजना कार्य में नर्मदा नहर की सीमा ग्राम रणोदर और तेतरोल पर मुख्य हैड वर्क्स की भूमि आबंटन विधिवत कर लिया गया था परन्तु कालान्तर में भूमि के कब्जे प्राप्ति में गत सरकार के 2008 और 2013, यह चार साल का विलम्ब हुआ है और जून, 2011 तक हम लोगों को कब्जा नहीं मिला था। चार वर्ष की अवधि का कार्य बाधित रहा। वर्तमान

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

में योजना पर संवेदक के अलावा अन्य एजेन्सीज को मिलाकर हम लोगों ने कुल 338.40 करोड़ खर्च किये हैं और योजना के अन्तर्गत अभी फिल्टर प्लांट, पम्प गृह, पाइप लाइन के माध्यम से नर्मदा आधारित पेयजल को जालौर के साथ ही 49 विलेजेज को, जालौर और 49 विलेजेज को वर्तमान सरकार के कार्यकाल में माह जनवरी, 2016 से आपूर्ति की जा रही है। अभी हम पानी पिला रहे हैं और शेष कार्य जो बचता है, वह अध्यक्ष महोदय, अप्रेल, 2017 के अन्त तक हम पूरा करने का लक्ष्य रखते हैं।

अभी इन्होंने यहां कहा कि जोधपुर के अंदर भी हम लोगों ने कुछ काम नहीं किया। मैं बताना चाहती हूं कि 16 वृहत परियोजनाएं यानी मेजर स्कीम्स थीं वहां, जिनमें से 11 मेजर स्कीम्स हमारी पूरी हो गयी हैं, 4 पेयजल परियोजनाएं अभी प्रगतिरत हैं। जोधपुर जिले की जो मेजर स्कीम्स हैं, पीलवा और जम्बेश्वर नगर, जिसकी लागत 63.78 करोड़ है, वह हमने इस बार 2017-18 के बजट के अंदर उसको ले ली है और पैरा 35 के अंदर इसको लिया है। इनको सबको हम पूरा करेंगे। हमने तो आपके द्वारा जो छोड़े हुए काम हैं, उनको सबको पूरा करने के लिये अपने हाथ में ले लिये हैं। मैं विश्वास करती हूं कि जो-जो काम हमने अपने हाथ में लिये हैं, उनको हम पूरा करने में पीछे नहीं रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, जल संसाधन के अंदर मैं यह कहना चाहती हूं कि जो भी पानी व्यर्थ बह रहा है, उसको हम किस तरह से संचित कर सकते हैं, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। इसी की वजह से एम.जी.एस.वाई. को महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए एक अच्छी बड़ी स्कीम बनाकर सबके बीच में उसको ले जाने की कोशिश की है। इसके साथ-साथ हमने मेजर स्कीम्स भी अपने हाथ में ली हैं। हमने जो स्कीम्स लीं, उनको हमने वित्त पोषित कीं और जिनको आगे चलाया है, उसका मुझे विश्वास है कि हम उनको पूरा करेंगे। ऐसी सोच मुझे लगता है कि आपकी नहीं है, क्योंकि मैं ध्यान दिलाना चाहती हूं एक महत्वपूर्ण बजट घोषणा की, अब यह कोट है, इनके बजट घोषणा के अंदर इन्होंने बारां जिला, परवन वृहत सिंचाई और पेयजल योजना, यह इनके पैरा में है। इन्होंने सर्वे और डी.पी.आर. तैयार करने की घोषणा की और यह बताया कि लागत 2 हजार 334 करोड़ रुपये है और इसका कार्य

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

अगले वर्ष प्रारम्भ करना प्रस्तावित बताया और यह कहा कि आर.आर.वी.यू.एन.एल. द्वारा 120 करोड़ अंशदान, यानी शेयर हमको दिया जाएगा, यह हमको बताया नहीं।

(18.00 बजे)

बारां-झालावाड़-कोटा के 313 गांवों को एक लाख 31 हजार 400 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी, यह भी हम को बताया। और 820, रुको। रुक जाओ अभी। समझ के, समझ के, समझ के। आप जैसे, ऐसा है दोनों तरफ है। ...(व्यवधान)... हां।

इसमें यह भी आया कि 820 गांवों में पेयजल सुविधा और बिजली घर को पानी देने का काम, यह भी होगा। यह भी उन्होंने अपने पैराग्राफ में बताने का काम किया। यह बजट घोषणा 2012-13 की और उनके पैरा 32 की घोषणा थी।

अब हमें यह पूछना है, आप लोग सब यहां हाउस के अन्दर बैठे हो, कि इतनी बड़ी परियोजना को क्या संभावित स्वीकृति के आधार के ऊपर आप बजट में ला सकते हो? संभावित स्वीकृति, और इतनी बड़ी परियोजना को क्या आर.आर.वी.यू.एन.एल. के शेयर पर आधारित, माने आप वित्त पोषित कर सकते हो? तो क्या है सच्चाई? सच्चाई यह है कि सरकार के स्टेट बजट को जब देखा जाता है तो उसमें न तो कोई प्रावधान है और न कोई अंशदान। इस परियोजना के लिए पांच वर्ष के अन्दर, यह 2009-10, 2012-13, 2013-14, तीन बार बजट की घोषणाएं कीं और अगेंस्ट 2360.43 करोड़्स 2009-10 के अन्दर, 2009-10 से लेकर 2013-14 तक सिर्फ 7 करोड़ 66 लाख रुपये का वित्तीय प्रावधान किया। चल दिये, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यह आपके बजट हैं। यह बजट है।

क्या है? जल्दबाजी में परियोजना की स्वीकृति हुई है, न वन विभाग की कोई भी आप लोगों ने सेंक्शंस ली हैं, न भूमि अवाप्ति की कोई कार्यवाही हुई है, सब की पूर्ति के लिए जल्दबाजी में जल्दी से शिलान्यास हम लोगों ने कर दिया। नहीं लगता आपको कि इसमें कोई नीयत की खोट है?

इनके मन में, अध्यक्ष महोदय, राजनीतिक लाभ लेने की सोच थी और राजस्थान के विकास का नहीं था कि किस तरीके से हम वहां लाभ ले सकें।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)
हम लोगों ने वहां क्या किया है, सबसे पहले तो हम लोगों ने स्वीकृतियां प्राप्त कीं। हमने यह जल्दबाजी में नहीं किया, हमने अनाउंसमेंट नहीं किया, हमने पत्थर नहीं लगाया, हमने स्वीकृतियां प्राप्त कीं, और आज मैं बताना चाह रही हूं, अभी इनफैक्ट, निविदाएं प्राप्त होने का यह आखिरी दिन है, तो हमारी निविदाएं आज प्राप्त हो जाएंगी। 2014-15 से 2016-17 तक 703.30 करोड़ रुपया हमने वित्तीय प्रावधान किया और स्टेट बजट में किया, इससे भूमि अवाप्ति का काम चालू हो गया और हो भी रहा है। 2017-18 के अन्दर, अभी, हमने हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और हम मानते हैं कि बारां-झालावाड़ और कोटा के अन्दर 2 लाख हैक्टेयर की सिंचाई होगी। ऐसी गम्भीर हालत में, अध्यक्ष महोदय, जब हम यह काम कर सकते हैं तो इनको कौन रोक रहा है? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं क्योंकि राहुल गांधी को बुला कर और नाटक कर के और जनता के सामने पत्थर लगा कर यह दिखाने की कोशिश की कि हम बारां के लोगों के खैर-ख्वाह हैं, वो सब लोग जानते हैं कि कौन कितना नाटक कर रहा है और वो समझ के, क्योंकि वो देख रहे हैं। यह छोटा-मोटा कार्यक्रम नहीं है जो ओवर नाइट आप पत्थर लगा कर वित्त पोषित कर के उसको खड़ा कर दोगे। इसको समय लगने वाला है, सब लोग जानते हैं। परन्तु अगर हर स्टैप को आप अच्छी तरह से, सुदृढ़ तरीके से लेओ तो मैं समझती हूं कि आने वाले समय के अन्दर वो काम होकर रहेगा, पर ऐसे नहीं।

फिर ऐसा ही कुछ हुआ, यह हमारे हरिके बैराज की कहानी, ऐसा ही कुछ है। 40 साल से हरिके बैराज की मरम्मत नहीं हुई, अध्यक्ष महोदय, 40 साल में। राजस्थान को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। क्यों नहीं कर सके? इतने साल गुजर गये, अभी तक तो नहीं कर पाये। मैं यह कहना चाहती हूं सिल्ट हटाने का और बैराज के अन्दर गेटों की मरम्मत करने का क्या बड़ा काम था? आज 66 करोड़ रुपये हमने पंजाब को दे दिये हैं और आगामी नहर बंदी के अन्दर हम लोग अपना यह काम करवाने का शुरू करेंगे, काम करवाएंगे। बट व्हाई नोट, 40 साल के अन्दर आप लोगों ने क्यों नहीं किया? मुझे यह समझ में नहीं आता है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

आज के दिन यह सिंचाई के एरिया में जायका परियोजना के द्वारा 2600 करोड़, जिससे 25 जिले लाभान्वित होंगे। न्यू डवलपमेंट बैंक के द्वारा 3 हजार करोड़, जिसमें इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की नहरों को ठीक कराने का काम हम करेंगे और इसमें वो सेम समस्या भी आ जाती है, तो सेम की रख-रखाव भी वहां हो जायेगी। जिन लोगों को सेम की मुसीबत हो रही है उनको इससे फायदा होगा।

इसके साथ-साथ कमाण्ड एरिया डवलपमेंट प्रोजेक्ट के अन्दर 900 करोड़ प्लस न्यू प्रपोजल्स 1553 करोड़, टोटल यह हुआ जस्ट इस कमाण्ड एरिया डवलपमेंट का 2453 एण्ड टोटल यह तीनों को अगर आप ले लेते हो तो 8053 करोड़ रुपये इसकी तरफ, इर्रिगेशन और सिंचाई विभाग की ओर हम लोगों ने बजट में एलोकेशंस किये हैं। और total provision for irrigation पिछली सरकार से डबल है। यह मैं आपको यहां कहना चाह रही थी।

अब चिकित्सा के ऊपर, कितनी चरमराई हालत है, कितनी हालत खराब है, कितना यह है। है, 60-65 साल से एक ही सरकार चली आ रही है। हमारे हाथ में जादू का डंडा नहीं है कि हम एक मिनट में सब ठीक कर देंगे, और बीच में मौका भी मिला है। जब 60-70 साल के अन्दर ये काम नहीं कर सके तो क्या हम पांच साल में इसको पूरा कर सकेंगे परन्तु हमने जो कदम उठाये हैं वो कदम ऐसे कदम हैं जिनको देश सराह रहा है और जिसकी वजह से चिकित्सा विभाग के अन्दर बहुत बड़े चेंजेज आये हैं।

मैं तो खाली छोटी चीज के ऊपर जाना चाहती हूं। 8 तो आपके बड़े-बड़े मेडिकल कॉलेजेज बन रहे हैं, खाली बाउण्ड्री वॉल नहीं बनी है। अध्यक्ष महोदय, कहीं तो दो मन्जिल बन गये, कहीं तीन मन्जिल बन गये, एम.सी.आई. के इंस्पैक्शंस हो गये तो एम.सी.आई. के इंस्पैक्शंस तो ऐसे नहीं होते। तो मैं तो छोटे काम पर आती हूं।

चलो इस छोटे काम पर, बड़े काम पर तो ठीक है हम और आप एक-दूसरे से कम्पलीट नहीं कर सकते परन्तु छोटे काम पर तो कर सकते थे। मैं कह रही हूं उप-स्वास्थ्य केन्द्र के भवन के निर्माण की संख्या तीन साल के अन्दर 665 और इनके पांच साल में 132, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की संख्या, यह छोटी-छोटी चीजें हैं, हम तो बड़ी चीज की बात ही

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)
नहीं कर रहे हैं, 72 तो हमने तीन वर्ष में किये और इन्होंने अपने पांच वर्ष के अन्दर 10 किये। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की संख्या, हमने अपने तीन साल के अन्दर 22 किये, इन्होंने 7 पूरे पांच साल में। उप-स्वास्थ्य केन्द्र पर आवासीय भवन का निर्माण, जो हमने किया, हमने तीन साल के अन्दर 253 किये इन्होंने 159 दिये। वहां भी नहीं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जो आवासीय भवन निर्माण की संख्या है 268 तो हमने किये और 119 इन्होंने किये। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आवासीय भवन निर्माण की संख्या 24 हमने किये तो 7 इन्होंने किये पूरे पांच साल में। जिला चिकित्सालय पर आवासीय भवन निर्माण, हम लोगों ने तो 22 किये इन्होंने पांच साल के अन्दर 9 ही किये। तो चरमराई तो होगी ही। जिसको पांच साल मिले, अगर हमने इतना काम कर लिया है खाली तीन-तीन साल के अन्दर तो 60 साल के अन्दर कितना काम हो सकता था और राजस्थान कहां से कहां पहुंच सकता था, यह तो हम और आप इमेजिन कर सकते हैं। अब आप भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को ले लीजिए, पूरा देश मानता है कि यह एक ट्रांसफोर्मेशनल योजना है, चाहे हम पक्ष के हैं चाहे हम प्रतिपक्ष के हैं, इसको हमको सब को मानना चाहिए। आज तक ८ लाख ७२ हजार मरीज को ट्रीटमेंट मिला है, ४ करोड़ ३६ लाख लोगों को कैशलैस सुविधा मिली है, ४९७ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, 650 प्राइवेट हॉस्पिटल्स के माध्यम से यह सेवा प्रदान की गयी है। लोगों का इसका भरपूर लाभ मिला है और मैंने आपको दो उदाहरण दिये थे।

एक दिन मैं खुद जब एस.एम.एस. हॉस्पिटल में किसी से मिलने गयी थी और काफी भीड़ थी तो मेरे कंधे के ऊपर किसी ने हाथ लगाया। मैंने मुड़ कर देखा तो एक महिला मेरे पीछे खड़ी थी और रो रही थी, तो मुझे लगा कोई प्रॉब्लम है। मैंने सब को बुला कर मैंने कहा कि, भई, प्रॉब्लम क्या है, इनकी प्रॉब्लम अपन बैठ कर सुन लें। तो उन्होंने कहा, नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको धन्यवाद देने आयी हूं। उन्होंने कहा कि रात को, बहुत देर रात को मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक हुआ और मुझे मालूम नहीं था कि क्या करूं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे पर किसी ने मेरे को याद दिलाया, कहा था कि भई कैशलैस भी हो सकता है, तो चांस लेकर मैं हॉस्पिटल आयी, और

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)
हॉस्पिटल आते ही मेरे हस्बैंड की इतनी अच्छी तरह से देखरेख हुई, आठ घंटे का आपरेशन हुआ और मेरे हस्बैंड आज जिंदा हैं, यह आपकी इस सरकार की नीतियों की वजह से जिंदा हैं और मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं। वो मेरे को हृदय से बात कर के गयी हैं। मेरे तो मैं समझती हूं आंखों में, मजाक लग सकता है परन्तु बात सही है। मैं यह भी कहना चाहती हूं, प्रॉब्लम तो यह है कि हमने अपने 60 साल मजाक-मजाक में गंवा दिये। आज इसी वजह से पूरे देश में हमारी यह स्थिति है।

कुमारवाड़ा, माउंट आबू के अन्दर समीर रज्जाक, 23 वर्ष का है। यह एक और उदाहरण देना चाहती हूं।

वह जब 6 महीने का था तब उसने हाथ बुरी तरह से जला लिया था। गरम दूध के पतीले के अंदर हाथ रख दिया था। हाथ बुरी तरह से जल चुका था। उसका सही इलाज नहीं हुआ। उसकी उंगलियां सब टेढ़ी हो गई और घाव भरता नहीं था। बार-बार घाव भरता था, फिर खुलता था। उसके पिताजी ने यह कहा कि इतनी महंगाई की वजह से मैं इलाज नहीं करा सका था। जब उनको भामाशाह स्वास्थ्य योजना का पता चला तो माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल के अंदर वह गये। वहां सक्सैसफुली प्लास्टिक सर्जरी निःशुल्क हुई। उसके पिता अब्दुल हैं, वह कहते हैं कि 'मेरे पास शुक्रिया कहने के लिए शब्द नहीं हैं'। अब यह उदाहरण हैं जो मैं आप सबके सामने रख रही हूं।

एक और उदाहरण है नागौर की मेड़ता तहसील के श्यामपुरा गांव की श्रीमती बिदामी देवी का। उसके सीने में दर्द हुआ। उसने प्राथमिक उपचार के लिए कहा तो उसको प्राथमिक उपचार के लिए ले गए। वहां से उपचार करने के बाद अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल में उसको भर्ती करा दिया। वहां भामाशाह कार्ड और एनएफएसए की पुष्टि करने के बाद बिदामी देवी की एंजियोप्लास्टी की गई। उसके 2 स्टेंट लगे, जिसमें 78 हजार रुपये लगे। वह क्या कहती है, 'मैं गरीब परिवार से हूं, इस योजना के तहत निःशुल्क इलाज होने पर मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं'। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं।

आप मजाक कर लो, गरीब लोग हैं। यह मालूम होना चाहिए लोगों को कि किस तरीके से गरीब लोगों की व्यथा जब हम हाउस में सुनाते हैं तो आप किस तरह से मजाक मानकर उसको उड़ाने की कोशिश करते हो। मैं

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

आपको यही कहना चाहती हूं कि इसके साथ-साथ हमने नि:शुल्क दवा योजना भी चालू रखी है और नि:शुल्क जांच योजना को भी हमने जारी रखा है। इनको हमने चलाया ही नहीं है बल्कि इनका बजट भी आगे बढ़ाने की कोशिश की है।

अध्यक्ष महोदय, अब शिक्षा के अंदर, मैं आपको यही कह रही थी कि हम लोगों को इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमको तो बहुत लोगों ने पुष्टि करके राजस्थान का लोहा माना है। क्वालिटी एजुकेशन, इसके लिए हमने हर स्तर पर प्रयास करने की कोशिश की है, 37 हजार शिक्षकों की भर्ती हुई है, 41,747 शिक्षकों की भर्ती अभी हो रही है, 86 हजार शिक्षकों की पदोन्नतियां हुई हैं। शिक्षकों के पदों का मानदंडानुसार समानीकरण हुआ है। एकीकृत विद्यालयों की स्थापना हुई है। आदर्श और उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना हुई है। इन नवाचारों को राष्ट्रीय स्तर पर माना गया है और उसकी सराहना हुई है।

अध्यक्ष महोदय, 3 वर्षों में गवर्नमेंट स्कूलों के क्लास 11 और 12 के एनरोलमेंट में वृद्धि हुई है, 32 परसेंट से अधिक वृद्धि अंग्रेजी, गणित और हिन्दी के अंदर हुई है। गवर्नमेंट स्कूल जो प्राइमरी लेवल के थे, उनकी लर्निंग लेवल के अंदर वृद्धि हुई है। एक रिवर्स फ्लो चालू हो गया है, जिसमें बच्चे जो प्राइवेट इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में जा रहे थे, अब वह उनको छोड़-छोड़कर के वापिस गवर्नमेंट स्कूलों में आने लगे हैं। दाखिल होने लगे हैं। यह मैं समझती हूं कि हम लोगों ने बहुत बड़ा कदम उठाया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहती हूं, आभार प्रकट करना चाहती हूं कि इनके प्रयासों द्वारा क्योंकि अच्छा काम हुआ है, जो सराहना उसको मिली है उसको पहुंचाने का काम, हर जगह पर किया है। मुझे बड़ी खुशी है सबने इसको माना है कि गुणवत्ता, क्वालिटी हमारी अब अच्छी हुई है।

हमारी बानसूर से आने वाली माननीय सदस्या शिक्षा के लिए बहुत चिंतित थीं कि शिक्षकों के रिक्त पदों को अभी तक भरे जाने का अभी तक कोई जिक्र नहीं हुआ है। मैं समझती हूं कि मैंने उसका कुछ जिक्र तो किया है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

मैं आपको बताना चाहूंगी कि गत सरकार के कार्यकाल में स्कूल तो खोल दिए गये थे, परन्तु अध्यापकों की समुचित व्यवस्था की ही नहीं गई थी। जिससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पूरी तरह से सफर करा। हमने सरकार में आते ही क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए समानीकरण किया। प्रत्येक स्कूल में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और व्याख्याता के पद भरने पर विशेष ध्यान दिया। स्कूल की शिक्षा में 85 हजार से अधिक विभिन्न पदों के चाहे कनिष्ठ लिपिक हों, प्रधानाचार्य हों, उनकी विभागीय पदोन्नतियां करवाकर उनसे भरा, 37 हजार से अधिक सीधी भर्तियां जो मैंने अभी आपको बताई, वह की। स्कूल व्याख्याता, शारीरिक शिक्षक इन सबकी नियुक्तियां भी की। इसके साथ ही हमने शिक्षकों के विभिन्न पद, स्कूल का व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, तृतीय श्रेणी अध्यापक के लगभग 42 हजार से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है और बहुत जल्दी यह आ जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह कहना चाहती हूं कि यह फीगर्स जो हैं, यह हमने बैठकर के नहीं बनाए हैं। प्रोब्लम आपको है, आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपका प्रदेश कितना आगे बढ़ा है, 70 साल में जो आप नहीं कर पाये, वह हम लोगों ने पिछले 5 साल और इन 3 सालों के अंदर करके दिखाया है।

अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा के अंदर 3 वर्षों में 28 नए कॉलेज, 8 नए इसी बजट सत्र में हमने खोले हैं। जो स्थानीय मांग थी, उनके अनुसार नए संकायों की स्वीकृति थी, 7 कॉलेजों को पी.जी. करने की बात थी, वह किया है, 7 डिवीजनल हैडक्वार्टर्स पर हमने एक नया काम चालू किया है गवर्नमेंट कॉलेजेज में जहां 7 स्मार्ट साइंस लैबों की हमने स्थापना की है। इसमें एक अलग ही प्रयास चल रहा है कि थ्री डी एनिमेटेड मॉडयूल्स हैं, वर्चुअल रियलिटी इनके द्वारा हम बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। यह राजस्थान के अंदर पहली बार हो रहा है। ऐसे आइडियाज को लेकर हम कॉलेजों में शिक्षा को बढ़ाने की, उसको उत्कृष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।

दूसरी तरफ युवाओं के क्या हाल हैं? उसकी हमें कोई चिंता नहीं थी। हमने 45 कॉलेजेज की घोषणा की। आखिरी 6 महीनों में 45 में से 42 की घोषणा की। इनकी जिम्मेदारी तो नैचुरली हम पर ही है क्योंकि उन्होंने तो

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

अपने टाइम में 3-4 ही कालेज कम्पलीट किए, 42 में से 32 कालेजेज को हमने अब टेकअप किया है, 8 इंजीनियरिंग कालेजेज को सुदृढ़ करने के लिए 7 करोड़ 10 लाख रुपए हम लोगों ने दिए हैं। यह तो हमारी सोच है। हमने शिक्षण स्तर सुधरे और सैल्फ स्टेमिंग बने, इसके लिए मेहनत की है।

लेकिन आपने क्या सोचा? यह भी एक महत्वपूर्ण घोषणा है। मैं इसकी तरफ भी आपका ध्यानआकर्षित करना चाहती हूं और यह कोट है इनके बजट डॉक्यूमेंट से, 'बाड़मेर, बारां, चूरू, करौली, धौलपुर, जैसलमेर जिले में वर्तमान में इंजीनियरिंग कालेज नहीं हैं। अत: निजी क्षेत्र में इन जिलों में इंजीनियरिंग कालेज प्रारंभ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नि:शुल्क भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी'। यह बजट 2011-12 का पैरा 147 है। अब सुन लो आप। हमें बताएं नि:शुल्क भूमि उपलब्ध करवाने का तो नाम और निशान ही नहीं है। आपको हम बताएं कि क्या किया? इन 6 स्थानों में से कहीं भी गत सरकार द्वारा इंजीनियरिंग कालेज नहीं खोले। इन 6 जगहों पर प्रारंभ ही नहीं किये।

अध्यक्ष महोदय, यहां के जो छात्र और छात्राएं थीं, उन लोगों को दूसरे शहरों में जाकर के इंजीनियरिंग के सब्जैक्ट को पढ़ना पड़ा। अब बाड़मेर, बारां, करौली और धौलपुर के अंदर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कालेज खोलने का निर्णय हुआ है। जो काम आपने नहीं किया, 3 साल के अंदर हमने इनकी भूमि तक आबंटित करके दे दी है। यह हमने काम किया है। ऐसी बात करने का कोई मतलब नहीं है। अब यह काम हमने किया है। आपका जैसा काम है, वह सबके सामने है, इसलिए जनता ने जिस तरीके से आपको नकारा है, वह आगे भी आपको नकारती रहेगी, अगर आप लोग सुधरोगे नहीं और समझोगे नहीं कि किस रास्ते पर हम लोगों को सरकारों को ले जाना है। यह मजाक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, अब आप आइए रोजगार के ऊपर। रोजगार के बारे में पता नहीं क्या-क्या पढ़ा। कहां से कागज लेकर के और पता नहीं क्या पढ़ा। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने एक वादा किया था और उस वादे को पूरा करने के लिए हमने कदम भी उठा लिए हैं। विभिन्न राजकीय विभागों के द्वारा हमने अभी तक जो भर्तियां की हैं, वह करीबन 1 लाख 10 हजार

भर्तियां की हैं। जो है वो है, वाह-वाह करने से कोई मतलब नहीं है। है वाह-वाह, सही बात है।

अध्यक्ष महोदय, रोजगार संवर्धन के लिए 6 लाख 50 हजार लोगों को हम लोगों ने कौशल विकास कार्यक्रम के द्वारा रोजगार का अवसर दिया है। स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंदर हमने 31,962 करोड़, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर तो 15 लाख लोगों का बताया है, परंतु हमने 1 लाख 14 हजार ही उसमें से जोड़ा है। कुल 632 एकीकृत रोजगार सहायता शिविरों में 1,81,216 युवाओं का प्राथमिक चयन हमने किया है। ई मित्रों के अंदर 36 हजार लोग, रिप्स की अर्थात् योजना जो है, जिसमें एम्पलायमेंट जनरेशन के ऊपर हम सब्सिडी से लाभान्वित करते हैं उस इंडस्ट्रियलिस्ट को, उसमें 47,614 लोगों को किया। आर्मी रैलीज के अंतर्गत हमने 9,513 और अगर उसका पूरा योग कर लेते हो तो 11,73,211 लोगों को हम लोगों ने आज तक रोजगार देने का काम किया है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सरकारी नौकरी कितनों को दी? ...(व्यवधान)...

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): जिस रुचि के हिसाब से ...(व्यवधान)... हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो अपने मन से ...(व्यवधान)... जिस विषय में रुचि रखते हैं, उस चीज में प्रशिक्षित हों और अपने पैर पर खड़े हो जाएं। आर्थिक रूप से वह स्वावलम्बी बनें इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। विश्वास है कि इस वर्ष के अंत तक हमने जो वादा किया था पन्द्रह लाख का उसको हम पूरा करने का काम करेंगे।

हमारे माननीय प्रधानमंत्रीजी ने यह कहा है कि आज गरीब अवसर की मांग करते हैं, अवसर मिलने पर वह खुद अपनी मेहनत से अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं और इसी रास्ते पर हम चलने की कोशिश करते हैं, हमें डॉल नहीं देना है किसी को, बार-बार डॉल देते रहो, हम चाहते हैं कि वह अपने पैर पर खड़े हो जाएं, स्वावलम्बी हो जाएं, उनको अवसर देने का काम हम कर रहे हैं, हमने किया है और मैं विश्वास रखती हूं कि पन्द्रह लाख अपन पूरा कर सकेंगे बाई दिसम्बर ऑफ दिस ईयर।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सांचौर से आने वाले माननीय विधायकजी ने कहा कि बेरोजगारों के लिए बजट में हमने कुछ भी नहीं किया है तो मैं माननीय सदस्य का ध्यान ...(व्यवधान)... नहीं हैं यहां अभी। पर फिर सबका ध्यान इस पर आकर्षित हो जाए कि अगर आप ध्यान से पढ़ो या ध्यान से बजट को सुनो तो आप इसको मिस नहीं करते। परन्तु इस बजट के पैरा 256 पर बेरोजगार युवकों के लिए अक्षत योजना को और सुदृढ़ करने का काम किया है। इसमें सहायता राशि की हमने बढ़ोत्तरी की है और इसमें योजना में हमने कहा है कि 500 रुपए की राशि को बढ़ाकर 600 युवकों के लिए, युवतियों को 500 से बढ़ाकर 750 और विशेष योग्यजन को 600 से 750 का हम बढ़ावा करेंगे और 3 साल के लिए इसका प्रावधान रखेंगे, उन बच्चों को ताकि वह अपने मां-बाप पर बोझ न बने और 3 साल के बाद का समय काफी है कि नौकरी उनको मिल जाएगी और वह आगे बढ़ सकेंगे अपनी जिंदगी के अंदर। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट खाली घोषणाओं का 109 पेज का पुलिंदा नहीं था, हमारे लिए यह एक पवित्र ग्रंथ है, यह दिखाता है हमारी दृढ़ इच्छाशक्ति और प्रदेश के समग्र विकास का हमारे सामने जो प्लान है वह दर्शाया जाता है आपको इसके द्वारा। यह ऐसा ग्रंथ है जिसमें सब वर्ग, सब संप्रदाय, छत्तीस की छत्तीस कौम को हमने उनका उत्थान करने का एक अध्याय जोड़ने की कोशिश की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे नवाचार भी हमने इस बजट के अंदर लाने की कोशिश की है। राज्य में पहली बार है यह पहला बजट है जिसमें प्लान और नोन प्लान का क्लासीफिकेशन हमने समाप्त कर दिया है। यह पहला बजट है जिसमें लैस पेपर यूज करते हुए लैस पेपर वाला बजट आपके सामने लाए हैं। एमएलए, एमपीज को हमने सीडीज और पेन ड्राइव्ज्स के जरिये हमने अपना बजट उपलब्ध कराया है। बजट की खाली कुछ ही प्रतियां हमने छपवाई हैं और बजट की जो अनेक कई घोषणाएं हैं जो पहली बार हमारे राजस्थान के अंदर हुई हैं। उनके बारे में थोड़ा सा कुछ आपके सामने इंगित करना चाहूंगी।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पहली बार है कि राजस्थान राज्य का जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग है उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए मेधावी जो छात्र-छात्राएं हैं उनके समस्त स्रोत से आय अगर 2.5 लाख रुपए से कम है तो उनके लिए अलग से आर्थिक पैकेज देने का हमने काम किया है।

पहली बार और यह देश में पहली बार है कि जो हमारे बुजुर्ग माता-पिता हैं, 500 ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को हवाई यात्रा के द्वारा हम तीर्थ यात्रा करवाएंगे और इस बार तिरुपति के लिए कुछ लोग हवाई यात्रा के लिए गये हैं। ऐसा देश में पहली दफा हुआ है।

पहली बार विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, हमने आयु का जो आधार माना जाता था, उस आयु के आधार को बिलकुल ही खतम कर दिया है और समान रूप से 750 रुपए पर मंथ देने की हमने घोषणा की है, यह देश में पहली दफा है, कहीं नहीं है।

पहली बार नगर निकायों के अंदर नागरिकों को कम दर पर नाश्ता और भोजन अन्नपूर्णा रसोई के द्वारा।

पहली बार बैकवर्ड एरिया और मोस्ट बैकवर्ड एरिया में निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमने रिप्स के द्वारा अतिरिक्त लाभ देने की घोषणा की है। एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी है, हमने यह कहा है कि जो मूल निवासी हैं राजस्थान के, उनको आप ले लेते हैं तो उसके लिए थोड़ी सी सब्सिडी हम आपको देते हैं। अगर सामान्य श्रेणी के हैं तो 25 हजार से उसको बढ़ाकर 35 हजार देंगे और भू रूपांतरण शुल्क की छूट जो 50 प्रतिशत थी उसको बढाकर 100 प्रतिशत करें, मुफ्त करा दी है, ताकि लोग इन बैकवर्ड एरिया में जाने का कष्ट करेंगे।

पहली बार खनन पट्टों के अंदर हम लोगों ने उनके आबंटन और उनकी रॉयल्टी ठेकों में पारदर्शिता लाने की कोशिश में ई-ऑक्शन के माध्यम से इसको चालू करने का काम किया है।

पहली बार There is no tax except on cigarette. पहली बार आपके एसएमएस के अंदर हार्ट ट्रांसप्लांट का काम चालू हो गया है और बहुत ही जल्दी कोटा मेडिकल कॉलेज के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)
भी मिल जाएगी, तो फर्स्ट टाइम इन राजस्थान किडनी ट्रांसप्लांट भी वहां होंगे। यह अपने आप में बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आपके आई हैं और मैं समझती हूं कि इसको अपन नकार नहीं सकते।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सब नवाचार ऐसे हैं जो राजस्थान को एक नए राजस्थान और एक आधुनिक राजस्थान के रास्ते पर ले जाने का काम करेगा। ऐसा ही एक नवाचार मैं सबके सामने लाना चाहती हूं, पिछले बजट में मैंने इसकी घोषणा की थी। सातों संभाग मुख्यालयों के ऊपर स्टेट ऑफ द आर्ट, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स की स्थापना हम करेंगे। कल ही मैंने जयपुर के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण किया था। इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट, सेफ्टी, सिक्योरिटी, रियल टाइम, ट्रेकिंग, क्राइम कंट्रोल, वह कह रहे थे न कि लॉ एंड ऑर्डर में क्या हो रहा है, इसको अगर कोई जाकर देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि ऐसे फीचर्स हैं, and probably, it is the best in the country. जून के महीने तक जो छह बाकी बचते हैं, जो डिवीजन हैडक्वाटर हैं उनके ऊपर भी यह आ जाएगा और मैं आप सबसे आग्रह करती हूं कि आप लोग प्लीज जाकर उसको जरूर देखें तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि यह कितना उत्कृष्ट काम पुलिस और आईटी डिपार्टमेंट से मिलकर और दूसरी कम्पनीज से मिलकर किया है। मैं समझती हूं कि ऐसा कभी-कभी देखने को मिलता है और आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आगे यह कमांड एंड कंट्रोल के द्वारा हम बढ़ सकते हैं।

American Architect Mr. Buckminster Fuller था उसने कुछ बात कही जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं कि “You never change the things by fighting the existing reality. To change something, you have to build a new model that makes the existing model obsolete.” इसका मतलब यह है कि अगर आप जर्जर व्यवस्था को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आप नए विचार और नई व्यवस्था का निर्माण करें ताकि जंग खा चुकी पुरानी व्यवस्था स्वत: ही इर्रेलेवेंट हो जाए। अगर ईमानदारी के साथ विश्लेषण किया जाए तो यह बजट बहुत अच्छा एक इन्क्ल्यूसिव बजट है, अब लोग चाहते हैं कि उनको ऐसी सरकार मिले जो अपना नहीं सोचती है परन्तु प्रदेश और देश का सोचने लगती है और सोचती है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा इरादा बहुत ही स्पष्ट है और हमारा जो सोच है वह भी स्पष्ट और दृढ़ है। हमने जैसलमेर से लेकर धौलपुर तक, गंगानगर से लेकर बांसवाड़ा तक, राजस्थान के हर गांव, हर ढाणी के संपूर्ण विकास के लिए मैंने कहा है कि कुछ भी करेंगे हम परंतु संपूर्ण विकास का काम हम लोग करके छोड़ेंगे, इसके सिवाय कुछ भी हमको मंजूर नहीं है। यह काम हमको करना ही है और पांच साल हम उसके लिए डेडिकेटेड है, जब तक हम यह नहीं करते हैं तब तक न हम थकेंगे और न हम रुकेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ा ग्रीक फिलोसॉफर था, उसका नाम था, Socretes उसने कहा था कि "Success is dependent on efforts." मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि we will make the efforts. We can, we must and we will. हमें अपने नहीं सबके विकास के लिए काम करना है, यह आपने भी कहा था, हम सबको मिलकर उस विकास को करने की कोशिश करनी है, मैं मानती हूं कि हमें इसीलिए लोगों ने सदन में भेजा है, जो भी यहां बैठे हुए हैं माननीय सदस्य, उन सबको जनता ने चुनकर भेजा है, यह सोचकर भेजा है कि यह हमारे विकास के लिए काम करेंगे। जब हम इसी दिशा में काम करेंगे तभी मैं समझती हूं कि इस प्रदेश का विकास होगा इसलिए 'आओ सब साथ चलें और एक राजस्थान, नए राजस्थान का निर्माण करें। थैंक यू।

श्री अध्यक्ष: सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 20 मार्च 2017 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18:30 बजे सोमवार, दिनांक 20 मार्च 2017 के 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

नगर निगम जयपुर द्वारा संचालित हिंगौनिया गौशाला में गौवंश की मृत्यु की रोकथाम के उपाय

328. डा. मंजू बाघमार (जायल): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगर निगम जयपुर द्वारा संचालित हिंगौनिया गौशाला में गत पांच वर्षों में गौवंश की मृत्यु के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नगर निगम जयपुर द्वारा उक्त मृत्यु की रोकथाम हेतु गत पांच वर्ष में क्या-क्या प्रयास किए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) दिनांक 1.8.2016 से दिनांक 31.10.2016 तक सरकार द्वारा हिंगौनिया गौशाला के उपयोगार्थ कितनी जेसीबी, डम्पर, लेवलर क्रेन, टैंकर व एम्बूलेन्स लगाए गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त गौशाला में दिनांक 01.1.2014 से दिनांक 31.10.2016 तक प्रतिमाह कितने श्रमिकों की स्वीकृति जारी की गई? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर निगम जयपुर द्वारा संचालित गौ-पुनर्वास केन्द्र हिंगोनिया में गत पांच वर्षों में गौ-वंश की मृत्यु का मुख्य कारण बीमार, कुपोषित, दुर्घटनाग्रस्त वृद्ध अथवा मरणासन्न अवस्था में गौ-वंश का आना रहा है। इसके अतिरिक्त कुछेक गौ-वंश की मृत्यु का कारण एक्सफिक्सिया शॉक कार्डियक शॉक एवं सेफ्टीसेमीक शॉक भी रहा है।

(2) नगर निगम जयपुर द्वारा उक्त मृत्यु की रोकथाम हेतु गत पांच वर्षों में गौ-पुनर्वास केन्द्र में निम्नानुसार प्रयास किये गये हैं-

1. इन्फ्रास्ट्रक्चर पशुओं के लिये चारा दाना-पानी हरा चारा मिनरल्स सॉल्ट आदि की उपलब्धता।
2. धूप-छाया सर्दी वर्षा आदि से बचाव की समुचित व्यवस्था।
3. एक बहुउद्देशीय चिकित्सालय संचालन जिसमें 17 पशु चिकित्सा अधिकारियों सहित कुल 73 अधिकारी/कर्मचारियों का स्टॉफ।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

4. रोग निदान केन्द्र में प्रयोगशाला की स्थापना, जिसमें अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा 23 प्रकार की जांचों की व्यवस्था।

5. संक्रमित बीमारियों से बचाव हेतु समय अनुसार टीकाकरण कार्य।

6. गौ-हितार्थ "हरे कृष्णा मूवमेन्ट" के साथ एमओयू सम्पादन।

(3) दिनांक 1.8.16 से दिनांक 31.10.16 के बीच हिंगौनिया गौशाला में लगाये गये संसाधनों का विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(4) हिंगौनिया गौशाला में दिनांक 1.01.2014 से दिनांक 31.10.2016 के बीच प्रतिमाह स्वीकृत की गई बीट्स का विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

किशनगढ़ (अजमेर) उपखण्ड मुख्यालय में गोदाम का निर्माण

334. श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले की समस्त पंचायत समितियों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन पूर्ण हो चुका है? यदि हां, तो पंचायत समितिवार गठित समितियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सहकारी समितियों में से कई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदामों का निर्माण नहीं हुआ है? यदि हां, तो कौन-कौनसी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त गोदामों के शीघ्र निर्माण हेतु ठोस विभागीय योजना की क्रियान्विति आगामी वित्तीय वर्ष 2017-18 की विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार जनसंख्या की दृष्टि से राज्य के सबसे बड़े उपखण्ड मुख्यालय किशनगढ़ (अजमेर) में ग्रामीणों एवं किसानों को पर्याप्त उपलब्ध कृषि सामग्री के भण्डारण हेतु 2000 टन क्षमता का नवीन भण्डारण गोदाम निर्माण की महती आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष 2017-18 की विभागीय कार्य योजनाओं के अन्तर्गत लगभग 50 लाख रुपये का बजट आवंटन करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर जिले में 9 पंचायत समितियां एवं 282 ग्राम पंचायत हैं। 282 ग्राम पंचायतों में से 175 ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन हो चुका है। पंचायत समितिवार सूची परिशिष्ट एक पर है।

(2) जी हां। यह सही है कि निम्न 9 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण नहीं हुआ है:-

(सहकारिता मंत्री)

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति	समिति का नाम
1	केकडी	ख्वास
2	भिनाय	लामगरा
3	भिनाय	कुम्हारिया
4	पीसांगन	कालेसरा
5	मसूदा	दौलतपुरा-II
6	किशनगढ़/सिलोरा	सुरसुरा
7	किशनगढ़/सिलोरा	सलेमाबाद
8	किशनगढ़/सिलोरा	सरगांव
9	श्रीनगर	कायड

(3) समितियों के पास भूमि की उपलब्धता एवं प्रस्ताव प्राप्त होने पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार गोदाम निर्माण करवाये जाते हैं ।

(4) समितियों के पास भूमि की उपलब्धता एवं प्रस्ताव प्राप्त होने पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार गोदाम निर्माण करवाये जाते हैं ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या 335

(स्थगित)

महाराव भीमसिंह चिकित्सालय कोटा में नया ओ.पी.डी. ब्लॉक बनाने की योजना

336. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) महाराव भीमसिंह चिकित्सालय, कोटा में कितने बैड स्वीकृत हैं तथा नियमित रूप से कितने मरीज भर्ती किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में मरीजों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर अस्पताल की बैड संख्या बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में नया ओ.पी.डी. ब्लॉक बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) महाराव भीमसिंह चिकित्सालय, कोटा में 474 बैड स्वीकृत हैं। नियमित रूप से लगभग 95 मरीज प्रतिदिन भर्ती किये जा रहे हैं।

(2) महाराव भीमसिंह चिकित्सालय, कोटा में 474 बैड स्वीकृत हैं तथा वहां पर 693 बैड्स विभिन्न विभागों में लगे हुए हैं। अत: जो 219 अतिरिक्त बैड्स लगे हुए हैं उनकी प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार किया जा रहा है।

(3) महाराव भीमसिंह चिकित्सालय में नये ओ.पी.डी. ब्लॉक के प्रस्ताव पर विश्लेषण उपरांत वित्त विभाग से सहमति प्राप्त कर तदनुरूप कार्यवाही की जा सकेगी।

वल्लभनगर के यू.आई.टी पैरिफरी के गांवों में कराये गये विकास कार्य

337. म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वल्लभनगर विधान सभा क्षेत्र के कितने गांव यू.आई.टी. पैरिफरी में आते हैं?

(2) उक्त गांवों में अब तक कितने विकास कार्य यू.आई.टी. द्वारा करवाये है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वल्लभनगर विधान सभा क्षेत्र के कुल सात गांव (दरोली, मंदेसर, टूस डांगियान, रावतपुरा टूस, गाडरियावास, काटका का कुंआ एवं महाराज की खेडी) यू.आई.टी. पैराफेरी क्षेत्र में आते हैं।

(2) उक्त सातों गांवों में नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा कोई विकास कार्य नहीं करवाया गया है।

बीकानेर (पश्चिम) में तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना

338. डॉ. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पश्चिम) में तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा होने के उपरान्त भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हां, तो क्या? सरकार उक्त तकनीकी विश्वविद्यालय को वर्ष 2017 में प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। बजट घोषणा 2016-2017 के बिन्दु संख्या 166.01 के तहत बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित है।

वर्तमान में उक्त बजट घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 का प्रारूप विधिक्षाधीन है तत्पश्चात बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय के स्थापना हेतु विधेयक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

अलवर जिले के उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार

339. श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार अलवर जिले में संचालित उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। रोजगार विभाग में अलवर जिले में संचालित उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की नीति बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

चित्तौड़गढ़ के ऋषिमंगरी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना

340. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ में ऋषिमंगरी नाम से प्रसिद्ध पर्यटकों को लुभाने वाला सैकड़ों वर्ष पुराना प्राचीन धार्मिक स्थल विद्यमान है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पर्यटक स्वागत केंद्र, चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त धार्मिक स्थल को पर्यटक की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण विकसित करने हेतु प्रस्ताव सरकार को भिजवाये गये है? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विश्व धरोहर में शामिल चित्तौड़गढ़ दुर्ग से सटे हुए उक्त प्राचीन दर्शनीय स्थल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित पर्यटकीय विकास योजना में शामिल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। चित्तौड़गढ़ में ऋषिमंगरी नाम से प्रसिद्ध प्राचीन धार्मिक स्थल विद्यमान है जो सैकड़ों वर्ष पुराना है।

(2) जी हां। पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटक स्वागत केंद्र, चित्तौड़गढ़ से ऋषिमंगरी को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने संबंधी प्रस्ताव मंगवाये गये थे, जिसके क्रम में प्राप्त हुए विकास प्रस्ताव विभाग में परीक्षणाधीन हैं।

(3) ऋषिमंगरी में पर्यटकीय विकास कार्य कराये जाने के प्रस्ताव विभाग में परीक्षणाधीन है।

जालौर जिले में राजकीय बालिका छात्रावास की स्थापना

341. श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जालौर जिले में वर्तमान में कितने राजकीय बालिका छात्रावास संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जालौर जिला मुख्यालय पर सभी विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए एक राजकीय बालिका छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या गत पांच वर्षों में जालौर में ऐसे किसी छात्रावास की मंजूरी दी गई है, जिसमें किसी जाति या वर्ग विशेष के छात्र-छात्राओं को ही प्रवेश दिया जावेगा? यदि हां, तो कहां? नाम व स्थान सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जालौर जिले में वर्तमान में दो विद्यालय स्तरीय एवं एक महाविद्यालय राजकीय बालिका छात्रावास संचालित है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	छात्रावास का नाम	श्रेणी	स्वीकृत क्षमता	लाभान्वित संख्या
1	राजकीय सावित्री बाई फुले छात्रावास जालौर	एससी	50	50
2	राजकीय देवनारायण कन्या छात्रावास जालौर	एसबीसी	50	50
3	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास जालौर	एससी	75	75
		योग	175	175

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(2) जालौर जिला मुख्यालय पर विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं हेतु विभाग द्वारा पूर्व से ही दो विद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास सचालित हैं, जिनमें जालौर में संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है।

(3) जी नहीं। जालौर में ऐसा कोई भी छात्रावास गत पांच वर्षों में स्वीकृत नहीं किया गया है, जिनमें किसी जाति या वर्ग विशेष के छात्र छात्राओं को ही प्रवेश दिये जाने का प्रावधान नियत किया गया है।

अलवर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार में अनियमितताओं पर कार्यवाही

342. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार अलवर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अलवर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार में फार्मासिस्टों को नियुक्त करने, दवाओं की खरीद एवं पेंशनर्स को दवा देने में करोड़ों रुपये के घोटाले किये गये हैं? यदि हां, तो कितनी राशि का घोटाला किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) यह सही है कि अलवर शहर में दिसम्बर, 2016 में जिला कोषाधिकारी अलवर के द्वारा की गयी जांच में सिटी डिस्पेन्सरी की शॉप नं. 4 पर कार्यरत अलवर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार के फार्मासिस्ट द्वारा मृत व्यक्ति की पेंशन डायरी में चार बार राजकीय चिकित्सक से दवा लिखवाकर गबन किया गया था? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त फार्मासिस्ट एवं अलवर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार अलवर के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। अलवर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. में अनियमितताओं की जांच हेतु अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां भरतपुर खण्ड भरतपुर द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 55 के अन्तर्गत दिनांक 25-01-2017 को उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, अलवर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(सहकारिता मंत्री)

(2) अलवर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. में फार्मासिस्टों की नियुक्ति एवं दवाओं की खरीद में अनियमितता की शिकायत प्राप्त नही हुई है। भण्डार द्वारा पेन्शनर्स को दवा वितरण में अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 55 के अन्तर्गत जांच प्रक्रियाधीन है। जांच उपरान्त ही राशि की जानकारी हो पायेगी।

(3) अलवर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. द्वारा सिटी डिस्पेन्सरी अलवर में संचालित मेडिकल शॉप नम्बर 4 में संविदा पर कार्यरत फार्मासिस्ट द्वारा मृत पेन्शनर को दवा देने का प्रकरण प्रकाश में आने पर दोषी फार्मासिस्ट को भण्डार की सेवाओं से कार्यमुक्त कर सेवाएं संबंधित एन.जी.ओ. को वापिस लौटा दी गयी है एवं भण्डार के महाप्रबन्धक को भी दिनांक 15-02-2017 को पद से हटा दिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जमवारामगढ़ में जनजाति वर्ग को स्वरोजगार के लिए सहायता

343. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार, व्यापार एवं उद्योग स्थापित करने में सहायता देने की क्या-क्या योजनाएं वर्तमान में संचालित हैं? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जनजाति वर्ग में उद्यमिका एवं स्वरोजगार बढ़ाने हेतु कोई नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा माडा एवं बिखरी क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार, व्यापार एवं उद्योग स्थापित करने हेतु एस.टी.पोप योजना संचालित की जा रही हैं। जिसमें योजना की पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को स्वरोजगार, व्यापार एवं उद्योग इकाईयों को स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है तथा विभाग द्वारा इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा राशि 10,000/- रु. जो भी

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

कम हो अनुदान दिया जाता है। योजना का संक्षिप्त विवरण एवं पात्रता परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति युवाओं को कौशल विकास हेतु आरएसएलडीसी के माध्यम से जनजाति युवाओं को रोजगार हेतु विभिन्न प्रकार के अल्पकालीन अवधि के प्रशिक्षण प्रदान किये जा रहे हैं। साथ ही राजस्थान अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा भी अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार, व्यापार एवं उद्योग स्थापित करने हेतु कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। जिसका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) अनुसूचित जनजाति युवाओं को कौशल विकास हेतु आरएसएलडीसी के माध्यम से जनजाति युवाओं को रोजगार हेतु विभिन्न प्रकार के अल्पकालीन अवधि के प्रशिक्षण प्रदान किये जा रहे हैं। साथ ही राजस्थान अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा भी अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार, व्यापार एवं उद्योग स्थापित करने हेतु कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई नीति बनाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में फूड सेफ्टी ट्रिब्यूनल की स्थापना

344. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में फूड सेफ्टी ट्रिब्यूनल कब स्थापित किया गया तथा अब तक किस-किस मद पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ट्रिब्यूनल द्वारा अब तक कितने प्रकरणों की सुनवाई की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.34(9)एमएण्डएच/ ग्रुप-3/2012 दिनांक 24.07.2015 के द्वारा खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण का सृजन किया गया। आदेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

मदवार व्यय राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

बजट हैड		व्यय राशि (रुपयें में)
1	संवेतन	19,03,750.00
3	यात्रा व्यय	0
4	चिकित्सा व्यय	89,370.00
5	कार्यालय व्यय	96,940.00
6	वाहनों का क्रम	7,90,020.00
7	कार्यालय वाहनों का संचालन एवं संधारण	50,000.00
8	वृत्तिक एवं विशिष्ट सेवायें	0
10	विज्ञापन विक्रय, प्रचार और प्रसार व्यय	0
36	वाहनों का किराया	0
37	वर्दियों तथा अन्य सुविधायें	0
41	संविदा व्यय	0
62	कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्संबंधी संचार व्यय	0
	कुल योग	29,30,080.00 (उनतीस लाख तीस हजार अस्सी रुपये मात्र)

(2) खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण द्वारा अब तक दो मामलों की सुनवाई की गई है जिसका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलगन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

झुंझुनूं शहर के लिये स्वीकृत सीवरेज योजना

345. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) झुन्झुनूं शहर में सीवरेज के कार्य हेतु कितनी राशि की योजना कब स्वीकृत की गई?

(2) उक्त योजना का कार्य कब प्रारम्भ हुआ एवं यह कार्य कब तक पूर्ण होना चाहिए था एवं वर्तमान में कार्य की क्या प्रगति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

(3) सरकार उक्त शेष बचे कार्य को कब तक पूर्ण कर जनता को इसकी सुविधा देने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त कार्य में देरी के लिए कौन-कौन दोषी है? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) झुन्झूनूं शहर हेतु आरयूआईडीपी के अधीन यूआईडीएसएसएमटी योजनान्तर्गत सीवरेज कार्यों हेतु राशि रुपये 37.81 करोड़ की स्वीकृति वर्ष 2009 में जारी की गयी थी।

(2) उक्त योजना का कार्य दिनांक 30.7.2009 को प्रारम्भ हुआ तथा दिनांक 29.01.12 तक पूर्ण किया जाना था, जिसे संवेदक की धीमी कार्य गति के कारण दिनांक 27.4.2015 को अनुबन्ध निरस्त कर दिया गया। आरयूआईडीपी फेज-तृतीय के अन्तर्गत झुन्झुनूं शहर में सीवरेज एवं पेयजल कार्य हेतु राशि रुपये 237.50 करोड़ का अनुबन्ध किया जाकर दिनांक 26.12.2016 को कार्यादेश जारी कर दिया गया है। वर्तमान में फर्म द्वारा सर्वे, पाइपों की खरीद सम्बंधी कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं।

(3) आरयूआईडीपी के अधीन यूआईडीएसएसएमटी के शेष बचे कार्यों को आरयूआईडीपी के फेज-तृतीय में करवाये जाने वाले कार्यों के साथ सम्मिलित किया गया है, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाना लक्षित है। आरयूआईडीपी के फेज-तृतीय के कार्य दिनांक 29.03.2019 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। इसके उपरान्त जनता को इसकी सुविधा प्राप्त हो जायेगी।

(4) उक्त कार्य में असाधारण देरी के लिये संवेदक मैसर्स राम स्वरूप इन्डस्ट्रीज, कोलकाता के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए फर्म की बैंक गारन्टी जब्त कर ली गयी एवं अनुबंध निरस्त कर दिया गया है।

बड़ी सादड़ी के विद्यालयों में कार्यरत कुक-कम-हेल्परों को देय वेतन

346. श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के विद्यालयों में भोजन बनाने के लिए कुक-कम-हैल्परों को लगाया गया है? यदि हां, तो बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र

(श्री गोतम कुमार)

में वर्तमान में कितने कुक-कम-हैल्पर कार्यरत हैं? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कुक कम हेल्पर को न्यूनतम वेतन से भी कम मासिक वेतन दिया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार इनको न्यूनतम मजदूरी के समान वेतन देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश के राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भोजन बनाने के लिए कुक-कम-हैल्पर के रूप में स्थानीय व्यक्तियों का सहयोग लिया जा रहा है, जिन्हें प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 1000/- रुपये मानदेय दिया जाता है। विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी (चित्तौड़गढ़-प्रतापगढ़) में कुल 441 राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल 749 कुक-कम-हैल्पर कार्यरत है। विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) विद्यालयों में मध्याह्न भोजन तैयार किये जाने का कार्य एक पार्ट टाईम कार्य है, जिसमें एक विद्यालय के शैक्षणिक कार्य दिवस पर एक समय (मध्यान्ह समय में) का पौषाहार तैयार कर विद्यार्थियों को वितरित किया जाता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की अधिसूचना में "कुक-कम-हैल्पर संवर्ग" का पदनाम नहीं है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी उन नियोजनों पर लागू होती है, जो नियोजन द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा-27 में "अनुसूचित नियोजन" के रूप में सम्मिलित किये गये हों। कुक-कम-हैल्पर इस अनुसूचित में नहीं हैं। योजनान्तर्गत प्रत्येक कुक-कम-हैल्पर को प्रतिमाह 1000/- मानदेय के रूप में दिया जा रहा है। कुक कम हैल्पर के मानदेय में वृद्धि भारत सरकार के स्तर से ही संभव है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सलूम्बर के हाड़ी रानी महाविद्यालय में कक्षा कक्षों का निर्माण

347. श्री अमृतलाल (सलूम्बर): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार हाड़ी रानी महाविद्यालय की चारदीवारी एवं कक्षा कक्षों का निर्माण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। हाड़ीरानी राजकीय महाविद्यालय, सलूम्बर में चारदीवारी, पांच कक्षा कक्षों एवं पांच प्रयोगशालाओं के निर्माण हेतु राशि रुपये 372.975 लाख का तकमीना प्राचार्य, हाड़ीरानी राजकीय महाविद्यालय, सलूम्बर जिला उदयपुर द्वारा भिजवाया गया है। बजट प्रावधान होने पर अपेक्षित कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रदेश में आई.टी.आई. केन्द्र खोलने की योजना

348. श्री कैलाश चौधरी (बायतू): क्या तकनीकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2010-11 की अवधि में कितने आई.टी.आई. केंद्र खोले गये? वर्षवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक की अवधि में कितने आई.टी.आई. केंद्र खोले गये? वर्षवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) आगामी दो वर्षों में सरकार उक्त कितने केन्द्र खोलने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2007-08 में देवनारायण योजनान्तर्गत 06 राजकीय आईटीआई स्वीकृत किये गये, तत्पश्चात् वित्तीय वर्ष 2010-11 में 05 आईटीआई अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में स्वीकृत की गई। परिशिष्ट-1

(2) वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य सरकार के पत्रांक 1(3)(2)त.शि./2013-1 दिनांक 17.12.2014 द्वारा मुख्य मंत्री बजट घोषणा के तहत 20 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र व 25 सामान्य क्षेत्र पूर्व में घोषित आईटीआई की नये सिरे से प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई, वित्तीय वर्ष 2015-16 में 04 आईटीआई स्वीकृत की गई। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 18 आईटीआई की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई। परिशिष्ट -2

(3) माननीय मुख्य मंत्री बजट घोषणा वर्ष 2014-15 (संशोधित) के बिन्दु संख्या 136 के अनुसार अगले दो वर्ष में ऐसी कोई पंचायत समिति नहीं बचेगी जिसमें आईटीआई उपलब्ध नहीं हो उसकी पालना में राज्य की सभी पंचायत समितियों में राजकीय/निजी आईटीआई स्वीकृत हो चुकी है।

फिर भी यदि गुणवगुणों के आधार पर व जनप्रतिनिधियों की मांग अनुरूप राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिये जाते हैं तो नवीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाना संभव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बारां जिले के किशनगंज कस्बे में आयोजित फूल डोल लोकोत्सव

349. श्री ललित कुमार (किशनगंज): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार बारां जिले के सीताबाड़ी में प्रत्येक वर्ष आदिवासियों (सहरिया) जनजाति के कुम्भ मेले के आयोजन को दृष्टिगत रखते हुए उसके सौन्दर्यीकरण, सड़क निर्माण, मंदिरों का जीर्णोद्धार व बाउण्ड्रीवाल आदि कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बून्दी की तीज व कोटा के दशहरा को पर्यटन विभाग के कलेण्डर में शामिल किया गया है। यदि हां, तो क्या सरकार बारां जिले के किशनगंज कस्बे में 130 वर्षों से लगातार आयोजित फूल डोल लोकोत्सव को पर्यटन से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बारां जिले के किशनगंज कस्बे में आयोजित फूल डोल लोकोत्सव का आयोजन स्थानीय लोगों के आर्थिक सहयोग से किया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त लोकोत्सव को और अधिक भव्य बनाने के लिए आर्थिक सहयोग देने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले के सीताबाड़ी के सौन्दर्यीकरण, सड़क निर्माण, मंदिरों का जीर्णोद्धार, बाउन्ड्रीवाल आदि कार्य करवाने की कोई कार्ययोजना/प्रस्ताव पर्यटन विभाग में वर्तमान में विचाराधीन नहीं हैं।

(2) जी हां। बून्दी की तीज व कोटा के दशहरा को पर्यटन विभाग के कलेण्डर में शामिल किया गया है। फूल डोल लोकोत्सव को पर्यटन विभाग के कलेण्डर में जोड़ने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(3) बारां जिले के किशनगंज कस्बे में आयोजित फूल डोल लोकोत्सव को आर्थिक सहयोग प्रदान करने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

रायसिख समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की योजना

350. श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

क्या यह सही है कि रायसिख समाज हर दृष्टि से पिछड़ा हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार रायसिख समाज को अन्य राज्यों के अनुसार अनुसूचित जाति में शामिल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। इस संबध में तथ्य यह है कि राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 75681 दिनांक 12.11.1999 द्वारा रायसिख जाति को राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में क्रम संख्या 55 पर सम्मिलित किया गया है। किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का मुख्य आधार अस्पृश्यता एवं छुआछूत होता है एवं उक्त कार्य भारत सरकार द्वारा एक निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जाता है।

बामनवास के चरागांव पट्टीकलां में गौशाला का निर्माण

351. श्री कुंजीलाल (बामनवास): क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बामनवास के चरागांव पट्टीकलां में गौशाला का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा गौशालाओं की स्थापना/ संचालन नहीं किया जाता है।

राजस्थान गौशाला अधिनियम,1960 के अंतर्गत स्वयंसेवी संस्थाओं/ट्रस्टों द्वारा संचालित गौशालाओं का निदेशालय गोपालन द्वारा पंजीयन किया जाता है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

केन्द्रीय सहायता के तहत जनजाति के काश्तकारों को स्वीकृत पम्प सैट

350. श्री नवनीत लाल (घाटोल): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सहायता योजना के संयुक्त शासन सचिव जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर के पत्रांक एफ 5/अभि./सीटीएडी/275(1)एससीए/प्रस्ताव/14-15 /स्वीकृति संख्या 71/2014-15 दिनांक 24.02.2015 के तहत जनजाति के बीपीएल चयनित काश्तकारों को आईएसआई डीजल पम्प सेट मय पाईप व ऐसेसरीज देने के आदेश हुए थे? यदि हां, तो जिला डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के अनुसूचित जनजाति के बी.पी.एल. परिवारों को पंचायत समितिवार स्वीकृत डीजल पम्प सेट व एसेसरीज का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रतापगढ जिले में पंचायत समिति पीपलखूंट में अनुसूचित जनजाति के कितने बी.पी.एल. काश्तकारों को उक्त योजना के तहत वर्ष 2014-15 व 2015-16 में आई.एस.आई. डीजल पम्प सैट मय पाईप व एसेसरीज स्वीकृत किये गये? काश्तकारवार स्वीकृत डीजल पम्प सैट मय राशि व पते के सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर के पत्रांक एफ 5/अभि/ सीटीएडी/275(1) एससीए/प्रस्ताव/14-15/स्वीकृति संख्या 71/2014-15/ दिनांक 24.02.2015 द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत जनजाति बी.पी.एल. कृषकों को विद्युत पम्प सैट, कुओं का विद्युतीकरण, पी.वी.सी. पाइप लाइन एवं ड्रिप/स्प्रिंकलर सेट हेतु सहायता की स्वीकृति जारी की गई थी।

जिला डूंगरपुर, बांसवाडा व प्रतापगढ के पंचायत समितिवार स्वीकृत विद्युत पम्पसैट व एसेसरीज के अनुसूचित जनजाति बी.पी.एल. परिवारों की सूची परिशिष्ट-अ, ब एवं स पर संलग्न है।

(2) जिला प्रतापगढ के पंचायत समिति पीपलखूंट में अनुसूचित जनजाति बी.पी.एल. काश्तकार को उक्त योजना के तहत वर्ष 2014-15 में

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

38 एवं 2015-16 में 62 को लाभान्वित किया गया। सूची परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा जिले की पंचायतों को माडा योजनान्तर्गत आवंटित राशि

351. श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) माडा योजना में 1 अप्रैल, 2014 से 31 जनवरी, 2017 तक कोटा जिले को कितनी राशि आवंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में माडा योजनान्तर्गत कितनी पंचायत समितियां आती हैं व सबसे अधिक ग्राम पंचायतें व गांव कौनसी पंचायत समिति में हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में आवंटित राशि में से कोटा जिले की पंचायत समितियों को कितनी-कितनी राशि, कौन-कौनसे कार्य के लिये आवंटित की गई? वर्षवार व पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माडा क्षेत्र योजना में वर्ष 2014-15 से अब तक कोटा जिले को आवंटित की गई राशि का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) कोटा जिले में माडा क्षेत्र योजनान्तर्गत पांच पंचायत समितियां आंशिक रूप से आती हैं। इनमें सबसे अधिक ग्राम पंचायतें व गांव इटावा पंचायत समिति में है। चयनित माडा ग्रामों की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) राशि का आवंटन पंचायत समितिवार नहीं किया जाता है। कोटा जिले में कराये गये कार्यों का वर्षवार एवं पंचायत समितिवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मारवाड़ जंक्शन में संचालित उप स्वास्थ्य केन्द्र

352. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री केसाराम चौधरी)

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र कहां-कहां पर किस-किस गांव में संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त केन्द्रों में से अनेक केन्द्रों में विभिन्न श्रेणी के अनेक पद रिक्त चल रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में संचालित उप स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मारवाड जंक्शन में संचालित उप स्वास्थ्य केन्द्रों में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के स्वीकृत पदों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र मारवाड जंक्शन में संचालित उप स्वास्थ्य केन्द्रों में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची मय रिक्ति अवधि के परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद सीधी भर्ती के हैं, जिन्हें विभागीय स्तर पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर भरे जाने का प्रयास किया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में संचालित रैफरल चिकित्सालय

353. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्तमान में कितने एवं कौन-कौनसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व रैफरल चिकित्सालय संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में वर्तमान में कितने एवं कौन-कौनसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

(3) प्रदेश में महिला एवं शिशुओं हेतु पृथक् से कितने एवं कौन-कौनसे चिकित्सालय कहां-कहां पर संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में 579 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 62 रैफरल चिकित्सालय संचालित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में 2079 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-ब एवं 14407 उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) प्रदेश में महिला एवं शिशुओं हेतु 100 बैडेड एम.सी.एच. विंग-22, 50 बैडेड एम.सी.एच. विंग-15, 50 बैडेड जे.एस.वाई. वार्ड-17 एवं 20 बैडेड जे.एस.वाई. वार्ड-98 पूर्व में संचालित अस्पतालों में ही विस्तार स्वरूप बनाये गये हैं। जिसकी सूची परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंधित चिकित्सालयों में कार्यरत मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्रों, शिशु चिकित्सालयों एवं महिला चिकित्सालयों का विवरण परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आयुर्वेद नर्सेज को एलोपैथिक नर्सेज के समान वेतन देने की योजना

354. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) आयुर्वेद नर्सेज को एलोपैथिक नर्सेज के समान वेतनमान/ग्रेड-पे दिये जाने के सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि आयुर्वेद नर्सेज के कैडर रिव्यू के लिए कोई समिति गठित की गई है? यदि हां, तो कब व उक्त समिति मे कौन-कौन सदस्य बनाये गये हैं?

(3) क्या उक्त समिति में किसी नर्सेज को शामिल किया गया है? यदि हां, तो किन-किनको व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश में ऐसे कितने आयुर्वेद, होम्योपैथी व यूनानी चिकित्सालय/औषधालय हैं, जहां पर नर्सेज के पद स्वीकृत नहीं हैं? विधानसभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रताप सिंह)

(5) क्या सरकार उक्त चिकित्सालय/ औषधालयों में नर्सेज के पद स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) प्रदेश के 'ब' श्रेणी औषधालयों में चिकित्सक तथा नर्सेज के पदों का क्या अनुपात है तथा इसके क्या मानदण्ड निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में सरकार की कोई योजना नहीं है।

(2) जी नहीं। परन्तु आयुष नर्सेज के विभिन्न संघों द्वारा प्रस्तुत मांग पत्रों (जिसमें कैडर रिव्यू भी एक मांग है) के परीक्षण हेतु निदेशालय, आयुर्वेद विभाग अजमेर के आदेश दिनांक 20.02.2017 के द्वारा निम्न कमेटी का गठन किया गया हैं-

1. श्री प्रकाश शर्मा, अतिरिक्त निदेशक (आयुर्वेद)
2. श्री रामस्वरूप शर्मा, उप निदेशक (आयुर्वेद)
3. श्री चन्द्र शेखर शर्मा, लेखाधिकारी
4. श्री दिनेश चन्द्र शर्मा, क्लर्क ग्रेड।

(3) जी नहीं। उक्त कमेटी नर्सेज से सम्बन्धित विभिन्न मांगों के परीक्षण हेतु ही गठित की गई है।

(4) विभागान्तर्गत आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सालय औषधालय, जहां नर्सेज के पद स्वीकृत नहीं हैं का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न हैं। प्रदेश में सभी होम्योपैथी चिकित्सालय/ औषधालय में नर्सेज के पद सृजित हैं।

(5) उपलब्ध बजट प्रावधान तथा गुणावगुण के आधार पर नर्सेज के पद स्वीकृत किये जाते है।

(6) विभागान्तर्गत संचालित चिकितसालयों/ औषधालयों में वर्तमान में कोई 'ब' श्रेणी निर्धारित नहीं हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिला मुख्यालय पर शिशु चिकित्सालय की स्थापना

355. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्तमान में कितने शिशु चिकित्सालय संचालित हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अलवर जिला मुख्यालय पर शिशु चिकित्सालय नहीं है व राजकीय चिकित्सालय में ही शिशु वार्ड है? यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान में संचालित उक्त शिशु वार्ड को शिशु चिकित्सालय घोषित किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्तमान में एक चिकित्सालय सरपदमपत मातृ शिशु स्वास्थ्य संस्थान जयपुर में संचालित है।

(2) अलवर जिला मुख्यालय पर राजकीय जिला चिकित्सालय स्वीकृत है। उक्त जिला चिकित्सालय के अधीन वर्तमान में शिशु वार्ड एवं शिशु चिकित्सा से संबंधित अन्य सेवाएं पृथक् से निर्मित कराये गये भवन में संचालित की जा रही है। वर्तमान में संचालित उक्त शिशु वार्ड को शिशु चिकित्सालय घोषित किया जाना विचाराधीन नहीं है।

कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक का निर्माण

356. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक का निर्माण करवाया जा रहा है? यदि हां, तो किस योजना के तहत? इसमें भवन और उपकरणों पर कितनी लागत आएगी और कौन वहन करेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त ब्लॉक सभी चिकित्सकीय सुविधाओं से परिपूर्ण होगा? यदि हां, तो इसमें कौन-कौनसे विभाग की कौन-कौनसी विशेषज्ञ सुविधाएं व मशीनें उपलब्ध होंगी? क्या इसमें कार्य करने हेतु विशेष

(श्री भवानी सिंह राजावत)

प्रशिक्षित चिकित्सक एवं नर्सिंग कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी अथवा वर्तमान चिकित्सक एवं नर्सिंगकर्मियों को ही लगाया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक का निर्माण कब प्रारंभ हुआ व वर्तमान कार्य प्रगति क्या है और इसका निर्माण कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक का निर्माण करवाया जा रहा है। यह प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी.एम.एस.एस.वाई.) के अन्तर्गत हो रहा है। इसमें कुल 150 करोड़ रुपये की लागत आएगी। जिसमें से 60 प्रतिशत केन्द्र सरकार एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी। उक्त में से 90 करोड़ रुपये बिल्डिंग हेतु तथा 60 करोड़ रुपये उपकरणों पर व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

(2) जी हां। कोटा मेडिकल कॉलेज के सभी सुपर स्पेशियलिटी विभागों को शिफ्ट किया जाएगा और सुपर स्पेशियलिटी की सभी सुविधाएं इसके द्वारा प्रदान की जाएंगी। वर्तमान में कार्यरत योग्य(Qualified) चिकित्सक ही लगाये जायेंगे एवं वर्तमान में कार्यरत नर्सिंग कर्मियों से उक्त विभागों को संचालित कर लिया जायेगा। उक्त सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक में निम्न विभाग होंगे:- नेफ्रोलॉजी, यूरोलोजी, न्यूरोलोजी, न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलोजी, कार्डियोथोरोसिक सर्जरी, पिडियाट्रिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी एवं गेस्ट्रोएन्ट्रोलोजी। सभी हेतु मय उपकरण एवं मशीनों के साथ सुविधा उपलब्ध रहेगी।

(3) सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक का निर्माण मई 2016 से प्रारंभ हुआ। वर्तमान में स्ट्रक्चर कार्य पूरा हो चुका है एवं Brick Work चालू है और Civil Work सितम्बर 2017 तक पूर्ण होना संभावित है।

प्रदेश में एन.आर.एच.एम. कर्मचारियों का नियमितीकरण

357. डॉ. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(डॉ. राजकुमार शर्मा)

(1) प्रदेश में 31 दिसम्बर, 2013 को एन.आर.एच.एम. में कितने कर्मचारी किन-किन पदों पर कार्यरत थे? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) 01 जनवरी, 2014 के पश्चात् प्रदेश में कितने एन.आर.एच.एम. कर्मचारियों को नियमित किया गया और कितने कर्मचारी नियमितीकरण से वंचित हैं? पदवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अनेक एन.आर.एच.एम. कर्मचारी नियमितीकरण से वंचित हैं? यदि हां, तो क्या सरकार सभी एन.आर.एच.एम. कर्मचारियों को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में 31 दिसम्बर, 2013 को एन.आर.एच.एम. में 14622 कर्मचारी विभिन्न पदों पर कार्यरत थे, जिनका पदवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) एन.आर.एच.एम. के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी संविदा कार्मिक को नियमित नहीं किया गया है।

(3) एन.आर.एच.एम. के अन्तर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों के नियमितीकरण की कोई कार्यवाही प्रक्रियाधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा संचालित पाठ्यक्रम

358. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा वर्तमान में कौन-कौनसे कोर्स संचालित किये जा रहे हैं?

(2) उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना से 31 जनवरी, 2017 तक कितने छात्रों का प्लेसमेंट हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा छात्रों को प्लेसमेंट दिलवाने के लिए क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा वर्तमान में कुल 101 कोर्स संचालित किये जा रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किये जा रहे पाठ्यक्रमों की सूची परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(2) वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा दूरस्थ शिक्षा पद्धति पर आधारित शिक्षा प्रदान करता है। अध्ययनरत छात्र नियमित रूप से विश्वविद्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं। अध्ययनरत छात्रों को प्लेसमेंट के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

(3) राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों में छात्रों को प्लेसमेंट में सहयोग की दृष्टि से प्लेसमेंट सेल की स्थापना की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय महाविद्यालय सोजत शहर में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना

359. श्रीमती संजना आगरी (सोजत): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय महाविद्यालय सोजत शहर वर्ष 2003-04 में स्वीकृत हुआ और इसके भवन का निर्माण भामाशाहों द्वारा कराया गया था?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्वीकृत राजकीय महाविद्यालय एन एच 162 पर स्थित है और वर्तमान में उक्त महाविद्यालय में चारदीवारी के साथ फर्श कक्षा-कक्ष व लैबोरेट्री जैसी मूलभूत सुविधाएं व पेयजल का कनेक्शन भी नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करवाने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान संकाय के लिए प्रयोगशाला सामग्री व टेक्नीशियन (प्रयोगशाला सहायक) नहीं होने से छात्र छात्राओं को प्रेक्टिकल जैसी समस्याएं हो रही हैं? क्या सरकार उक्त समस्याओं का समाधान करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। महाविद्यालय में मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति हेतु अनुमानित

(उच्च शिक्षा मंत्री)

लागत राशि रुपये 94.73 लाख रुपये का तकमीना प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, सोजत शहर द्वारा भिजवाया गया है। बजट प्रावधान होने पर अपेक्षित कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) राजकीय महाविद्यालय, सोजत सिटी में प्रयोगशाला सहायक के 04 पद स्वीकृत हैं जिनके विरुद्ध 02 प्रयोगशाला सहायक पदस्थापित हैं। नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

नागौर के माडीबाई राजकीय महिला महाविद्यालय में एन.सी.सी. विंग की स्थापना

360. श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार नागौर में माडीबाई राजकीय महिला महाविद्यालय में एन.सी.सी. विंग खोलने का विचार रखती है यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। महाविद्यालय द्वारा एनसीसी विंग खोलने हेतु अभी तक आवेदन नहीं किया गया है।

आवेदन प्राप्त होते ही महाविद्यालय का नाम प्रतिक्षा सूची में सम्मिलित कर लिया जाएगा एवं वरीयता के आधार पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।

शेरगढ़ में गोदाम विहीन सहकारी समितियां

361. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम बने हुए हैं व कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियां गोदाम विहीन हैं? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति शेरगढ़, बालेसर एवं सेखाला में ग्राम सेवा सहकारी समिति के सुचारू संचालन हेतु

(श्री बाबू सिंह)

गोदाम निर्माण कराने की स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में 26 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम बने हुए हैं व 8 ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ गोदाम विहीन हैं। जिसका विवरण परिशिष्ट एक पर संलग्न है।

(2) बालेसर ग्राम सेवा सहकारी समिति में भूमि उपलब्ध नहीं है। समितियों के पास भूमि की उपलब्धता एवं प्रस्ताव प्राप्त होने पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार गोदाम निर्माण करवाये जाते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चौमूं के मण्डा-भिण्डा, गुढ़लिया व फतेहपुरा में गोदाम का निर्माण

362. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चौमूं में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समिति बनी हुई है? यदि हां, तो कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों में बनी हुई हैं व किन-किन में नहीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदाम बने हुए नहीं हैं? यदि हां, तो क्या सरकार गोदाम विहीन सहकारी समितियों के गोदाम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तों क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मण्डा-भिण्डा, गुढ़लिया व फतेहपुरा में गोदाम निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। 23 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में से एक समिति घिनौई में भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण गोदाम नहीं है। समितियों के पास भूमि

(सहकारिता मंत्री)

की उपलब्धता एवं प्रस्ताव प्राप्त होने पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार गोदाम निर्माण करवाये जाते हैं।

(3) मण्डा भिण्डा एवं गुढ़लिया समिति में गोदाम बने हुए हैं व फतेहपुरा बांसा ग्राम सेवा सहकारी समिति में गोदाम व कार्यालय भवन निर्माण की वित्तीय स्वीकृति वर्ष 2016-17 में जारी की जा चुकी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर जिले में सरस सुरक्षा कवच योजना के लाभार्थी

363. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में सरस सुरक्षा कवच योजना कब से प्रारंभ की गई तथा उक्त योजना दुग्ध उत्पादकों के लिए किस प्रकार से क्रियान्वित की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बाड़मेर जिले में उक्त योजना के तहत कितने किसानों को कब-कब व कितना-कितना लाभ दिया गया? विधान सभा वार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना आरसीडीएफ द्वारा वर्ष 2004-05 में जिला दुग्ध संघों के दुग्ध उत्पादकों हेतु प्रारम्भ की गई ।

योजनान्तर्गत दुग्ध उत्पादकों को जीवन बीमा एवं दुर्घटना बीमा सुरक्षा प्रदान करने हेतु पृथक्-पृथक् योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। सरस सुरक्षा कवच योजनान्तर्गत सामान्य सदस्य हेतु प्रीमियम राशि का 12.50, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं महिला सदस्य हेतु 20 प्रतिशत आरसीडीएफ द्वारा, 12.50 प्रतिशत संबंधित जिला दुग्ध संघ द्वारा तथा 30 प्रतिशत सक्षम दुग्ध समितियों द्वारा वहन किया जाता है। शेष प्रीमियम राशि दुग्ध उत्पादक द्वारा देय होती है।

वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से जीवन बीमा हेतु आम आदमी बीमा योजना एवं यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी के माध्यम से राज सरस सुरक्षा कवच दुर्घटना बीमा योजना जारी है।

(डेयरी मंत्री)

(2) सरस सुरक्षा कवच में जनश्री/आम आदमी बीमा योजनान्तर्गत बाड़मेर दुग्ध संघ द्वारा लाभान्वित किये गये दुग्ध उत्पादक किसानों की संख्या एवं बीमा लाभ का वर्षवार एवं विधान सभावार विवरण परिशिष्ट क पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बूंदी जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का प्रति माह भुगतान

364. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बून्दी जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत किन-किनकों पेंशन का भुगतान किया जा रहा है? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखे।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले में पेंशन का भुगतान 4-5 माह में एक बार किया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार पेंशनधारियों को प्रतिमाह पेंशन का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत बून्दी जिले में पेंशन की निम्न योजनाओं में लाभान्वित किये जा रहे पेंशनरों का श्रेणी/संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन योजना	7292
2	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	2175
3	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तजन पेंशन योजना	3 2 0
4	मुख्य मंत्री वृद्वजन सम्मान पेंशन योजना	71955
5	मुख्य मंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना	13216
6	मुख्य मंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना	6893

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(2) जी नहीं। सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत बून्दी जिले में पेंशनर्स को नियमानुसार प्रत्येक माह पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। सभी पात्र पेंशनधारियों को नियमित रूप से समय पर पेंशन का भुगतान प्राप्त हो इसके लिये सीधे लाभ अन्तरण (DBT) योजना एवं भामाशाह योजनान्तर्गत लाभार्थियों के खुलवाये जा रहे बैंक खातों के माध्यम से पेंशन भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

आमेर की आबादी

365. श्री नवीन पिलानिया (आमेर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

आमेर विधान सभा क्षेत्र की वर्ष 1981-1991 व 2011 की कुल आबादी कितनी है तथा इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या कितनी है? गांववार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

आमेर तहसील की कुल आबादी तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की सूचना परिशिष्ट अ पर सलंग्न है।

जनगणना कार्य निदेशालय द्वारा विधानसभावार एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या संकलित नहीं की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन बंद करने की जांच

366. श्री रमेश (टोडाभीम): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश के लाखों लोगों की सामाजिक सुरक्षा (बुजुर्ग, विधवा एवं विकलांग) पेंशन बंद होने की शिकायत की जांच कराई गई है? यदि हां, तो कब एवं किसके द्वारा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जांच में किस-किस जिले में कितने-कितने प्रकरणों में पेंशन गलत तरीके से बंद होना पाया गया एवं सरकार द्वारा किस-किस जिम्मेदार अधिकारी/ कर्मचारी के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखे।

(श्री रमेश)

(3) प्रदेश के किस-किस जिले में कितने-कितने व्यक्तियों को पेंशन की बन्द अवधि का भुगतान किया गया तथा कितने व्यक्तियों को ब्याज का भुगतान किया गया व नहीं, तों क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत राज्य में पेंशन की विभिन्न श्रेणियों में पेंशन बन्द होने कि शिकायत पर दिनांक 14.07.2016 को समस्त जिला कलक्टर्स को निर्देश दिये गये कि जिन पेंशनरों की पेंशन विशेष रूप से मृत्यु, डुप्लीकेट या अन्य कारण अभिलिखित कर निरस्त की गई है, के समस्त प्रकरणों की पुन: जांच/सत्यापन ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत समिति के अधीन पदस्थापित ग्राम सेवक, पटवारी और वार्ड पंच की संयुक्त टीम तथा शहरी क्षेत्र में संबंधित नगर निकाय के अधिकारी एवं वार्ड पार्षद की संयुक्त टीम द्वारा सत्यापन किया जावे तथा सत्यापन में अगर पेंशनर पात्र पाया जावे तो उसकी पेंशन एरियर के साथ प्रारम्भ करें तथा गलत सूचना देने वाले कार्मिकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाने के आदेश दिये गये हैं। सत्यापन की कार्यवाही जिला स्तर पर चल रही है, जो शीघ्र ही सम्पन्न कर ली जाएगी।

(2) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन विशेष रूप से मृत्यु, डुप्लीकेट एवं अन्य कारण अभिलिखित कर स्टाप की गई पेंशन के समस्त प्रकरणों की पुन: जांच/सत्यापन की रिपोर्ट जिला कलक्टर कार्यालयों से चाहे जाने पर आज दिनांक तक 14 जिलों से प्राप्त हुई है जिसके अनुसार 35,285 प्रकरणों में त्रुटिपूर्ण तरीके से पेंशन को बन्द किया गया है। जिनको पुन: शुरू कर दिया गया है। दोषी अधिकारियों/कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने हेतु जिला कलक्टर्स को निर्देशित किया गया है।

(3) जिन प्रकरणों में पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी के स्तर से पेंशन आदेश को गलत/त्रुटिपूर्ण तरीके से निरस्तीकरण किये जाने के आदेश जारी किये जाने के कारण पेंशनर की पेंशन को बन्द किया गया है तो उन प्रकरणों में पेंशनर की पेंशन को नियमानुसार तुरन्त प्रारम्भ करने एवं निरस्त किये जाने की दिनांक से एरियर राशि देने के आदेश जारी किये गये हैं। नियमों में पेंशन की एरियर राशि पर ब्याज के भुगतान का प्रावधान नहीं है।

जगदम्बा नगर (जयपुर) में जारी आवासीय पट्टे की जांच

367. श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अपोलो हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी लि. द्वारा अजमेर रोड स्थित पावर हाउस के पीछे, जगदम्बा नगर नामक आवासीय योजना बनाई गई थी? यदि हां, तो सोसायटी द्वारा प्रस्तुत ले-आउट प्लान एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत ले-आडट प्लान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कॉलोनी के भू-खण्डधारियों को पट्टे वितरित कर दिये गये हैं? यदि हां, तो किन-किन को? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड संख्या डी 580 ई का भी पट्टा जारी किया गया है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? भूखण्ड संख्या डी-580-ई की मोका रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा/पट्टा रसीद की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त स्थान (भूखण्ड संख्या डी-580-ई) से दिनांक 02-04-2014 व 04-03-2017 को अतिक्रमण हटाया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार सोसायटी द्वारा उक्त भूखण्ड के नाम से जारी पट्टे की जांच करवाकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही कर उक्त पट्टे को निरस्त करने तथा अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अपोलो हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी लि. द्वारा अजमेर रोड स्थित पावर हाउस के पीछे जगदम्बा नगर नामक योजना बनाई गई थी, जिसका बाद में सोसायटी द्वारा जगदम्बा नगर 'ए' के नाम से संशोधित ले-आउट प्लान प्रस्तुत किया गया था। इस आधार पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जगदम्बा नगर 'ए' का अनुमोदन किया गया। सोसायटी द्वारा प्रस्तुत मूल मानचित्र संशोधित मानचित्र जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित मानचित्र की प्रति क्रमशः परिशिष्ट "अ", "ब" तथा "स" पर संलग्न है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(2) जगदम्बा नगर 'ए' कॉलोनी में जारी किये गये पट्टों की सूची परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। उक्त भू-खण्ड का पट्टा जारी नहीं किया गया है तथा न ही उक्त भू-खण्ड की पत्रावली प्रस्तुत की गई है। भू-खण्ड संख्या डी-580-ई जगदम्बा नगर 'ए' का हिस्सा न होकर जगदम्बा नगर 'डी' का हिस्सा है।

(4) जी नहीं। क्योंकि उक्त स्थान (भू-खण्ड संख्या डी-580-ई) के पट्टे हेतु न तो कोई पत्रावली पेश हुई है और न ही कोई पत्र जारी किया गया है, जिसके अभाव में यह तय नहीं किया जा सकता कि अतिक्रमण है या नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नगर परिषद् श्रीगंगानगर में सफाई कर्मचारियों की भर्ती

368. श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद श्रीगंगानगर में पर्याप्त सफाई कर्मचारी हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त नगर परिषद् में नए सफाई कर्मचारी भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नगर परिषद में गत तीन वर्षों में कब-कब कितने- कितने सफाई कर्मचारी ठेका प्रथा द्वारा लगाये गये व उनमें से कितने कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य की नगरीय निकायों के द्वारा की जाने वाली सफाई कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के द्वारा एसबी सिविल रिट पिटीशन 6461/2015 दिनांक 16.1.16 के द्वारा भर्ती के संबंध में नवीन निर्देश प्रदान किये गये हैं। उक्त निर्देशों का परीक्षण कर शीघ्र भर्ती के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

(2) गत तीन वर्षों में नगर परिषद श्रीगंगानगर द्वारा सफाई कर्मचारी ठेका प्रथा पर नही रखे गये हैं। नगर परिषद श्रीगंगानगर में 16 वार्डों में सफाई कार्य ठेके पर दिया हुआ है। ठेकेदार फर्म द्वारा अपने स्तर पर सफाई श्रमिक रखकर, सफाई कार्य करवाते हैं।

परवाना विहार, गजसिंहपुरा में सड़क का निर्माण

369. श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पृथ्वीराज नगर की जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमित कॉलोनियों में सड़क निर्माण के क्या प्रावधान हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण जोन- 18 में गजसिंहपुरा स्थित परवाना विहार व महालक्ष्मी नगर का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित मानचित्र एवं पी.टी. सर्वे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि परवाना विहार कॉलोनी, गजसिंहपुरा जोन-18 में सड़क निर्माण करवाया जा रहा है? यदि हां, तो क्या उक्त कॉलोनी में सड़क निर्माण कार्य नियमानुसार चौड़ाई एवं अन्य मानदण्डों के अनुसार ही किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार सड़कों पर आ रहे अवैध निर्माणों को हटवाकर कॉलोनी में नियमानुसार चौड़ी सड़कों का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि ग्रीन ऐवन्यू नगर तथा परवाना विहार कॉलोनी के मध्य (प्लाट नं. 11, परवाना विहार) के सामने से गुजर रही सड़क पर अस्थायी दीवार बनाकर अतिक्रमण कर आगे से रास्ते को बिलकुल बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क से अतिक्रमण हटाकर दोनों सम्पर्क सड़क बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या उक्त कॉलोनी के बीच से गुजर रही एच.टी लाइन के नीचे सर्विस लेन पर सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो क्या सरकार कॉलोनी वासियों की सुविधा हेतु उक्त एच.टी. लाइन के नीचे भी अविलम्ब सर्विस सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पृथ्वीराज नगर की अनुमोदित योजनाओं में जविप्रा द्वारा भूखण्डों के नियमन होने के पश्चात् सड़क निर्माण कार्य करवाया जाता है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(2) पृथ्वीराज नगर में गजसिंहपुरा स्थित परवाना विहार व ग्रीन एवेन्यू नगर अनुमोदित योजनाएं हैं, जिनका पी.टी. सर्वे मानचित्र तथा अनुमोदित मानचित्र एक ही है, जो क्रमश: परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। जय माता वैष्णो नगर एवं महालक्ष्मी नगर कॉलोनियां गैर-अनुमोदित योजनाएं हैं। प्रश्न में अंकित किशोर विहार के नाम से किसी भी योजना का रिकॉर्ड संबंधित जोन में प्राप्त नहीं हुआ है, जो रिकॉर्ड जोन में उपलब्ध है उस योजना का नाम किशोर विहार 'बी' है जो वर्तमान में गैर-अनुमोदित योजना है। गैर-अनुमोदित योजनाओं का पी.टी. सर्वे नहीं करवाया गया है।

(3) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित परवाना विहार, गजसिंहपुरा में जविप्रा द्वारा अनुमोदित योजना मानचित्र एवं तय मापदण्डों के अनुसार सड़क निर्माण कार्य करवाया जा रहा है।

(4) जी हां। अवैध निर्माण हटवाये जाने की सतत् प्रक्रिया है।

(5) जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत योजना परवाना विहार के रिकॉर्ड अनुसार विकास समिति द्वारा प्रस्तुत योजना मानचित्र में भूखण्ड संख्या 11 ए के सामने 30 फीट सड़क दर्शाई गई है जो कि भूखण्ड संख्या 10 पर योजना सीमा तक ही है। उसके बाद अन्य योजना सृजित है जिसका पार्ट प्लान परिशिष्ट "स" पर संलग्न है तथा परवाना विहार योजना का समिति द्वारा प्रस्तुत मानचित्र परिशिष्ट "द" पर संलग्न है। योजना परवाना विहार के भूखण्ड संख्या 10 के सामने योजना सीमा के पश्चिम की ओर योजना ग्रीन एवेन्यू सृजित है। ग्रीन एवेन्यू योजना अनुमोदित मानचित्र संलग्न "ब" एवं मौका स्थिति के अनुसार भूखण्ड संख्या 96 सृजित है ना कि सड़क जिसका पार्ट प्लान परिशिष्ट "ई" पर संलग्न है। प्रस्तुत रिकॉर्ड, मौका स्थिति एवं अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुसार ग्रीन एवेन्यू योजना में भूखण्ड संख्या 96 सृजित होने के कारण भूखण्ड के ऊपर से दोनों योजनाओं में उक्त 30 फीट सड़क को सम्पर्क सड़क किया जाना सुसंगत नहीं है।

(6) जी हां। एच.टी. लाइन के समानान्तर सड़क निर्माण कार्य हेतु प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियाधीन है। मौके पर उपलब्ध सर्विस लेन निर्माण हेतु प्रशासनिक निर्णय उपरान्त ही सर्विस लेन का निर्माण करवाया जाना है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा नगर धौलाई में सड़क निर्माण से प्रभावित भू-खण्ड

370. श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की विधानसभा नगर ग्राम धौलाई मानसरोवर (सांगानेर) आवासीय योजना को नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कौन से नक्शे से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समिति की विधानसभा नगर ग्राम धौलाई, सांगानेर में प्रस्तावित 200 फीट सड़क का निर्माण कार्य किन कारणों से रूका हुआ है? क्या उक्त प्रस्तावित सड़क को सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया है?

(3) उक्त समिति की उक्त योजना में प्रस्तावित 200 फिट सड़क से प्रभावित भू-खण्ड धारियों को क्या जयपुर विकास प्राधिकरण मुआवजा देने का विचार रखता है? यदि हां, तो किस तरह व किस दर से? नियम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त आवासीय योजना में भू-खण्ड धारियों द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है? यदि हां, तो किन-किन भू-खण्ड धारियों द्वारा व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या उक्त आवासीय योजना में बिल्डरों/भूमाफियाओं को सोसायटी/सरकार की मिली भगत से निर्माण कार्य की छूट प्रदान की गई है? यदि हां, तो किस नियम के तहत? नियम की प्रति व जिन भू-खण्डों पर निर्माण कार्य चल रहा है, उनके भू-खण्ड धारियों के नाम व भू-खण्डों के नम्बर सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना विधान सभा नगर ग्राम धौलाई आवासीय योजना के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में वाद लम्बित होने व कुछ प्रकरणों में यथास्थिति के आदेश पारित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। न्यायिक विवादों के कारण योजना का नियमन नहीं किया जा सकता है। न्यायिक विवादों के कारण नियमन हेतु आधार बनाये जाने वाले नक्शे के संबंध में टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(2) उक्त समिति की विधान सभा नगर ग्राम धौलाई में प्रस्तावित 200 फीट सड़क का निर्माण कार्य न्यायिक विवादों के कारण रुका हुआ है जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर है। प्रस्तावित सड़क को सरकार द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। उक्त सड़क प्रस्तावित सैक्टर प्लान अनुसार यथावत है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(4) जी हां। उक्त आवासीय योजना में जिन भू-खण्ड धारियों द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है, उनकी सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(5) जी नहीं। जिन भू-खण्ड धारियों द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है, उनको जेडीए एक्ट की धारा 32-33 के तहत नोटिस जारी किये गये हैं जिनका विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विश्वेसरिया नगर (जयपुर) का सुविधा क्षेत्र

371. श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या गोपालपुरा बाई-पास जयपुर स्थित विश्वेसरिया नगर का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमन किया जा चुका है? यदि हां, तो भू-खण्ड धारियों की सूची मय प्लाट नम्बर व साईज के सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित मानचित्र एवं पी.टी. सर्वे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त योजना में सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो किस स्थान पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गोपालपुरा बाईपास जयपुर स्थित विश्वेसरिया नगर योजना का अनुमोदन जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 22.04.2002 को किया जा चुका है। उक्त योजना की भू-खण्ड धारियों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त योजना का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

मानचित्र की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है एवं उक्त योजना का पी.टी. सर्वे नहीं करवाया गया था।

(3) उक्त योजना में सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया हुआ है। संलग्न मानचित्र में सुविधा क्षेत्र को गुलाबी रंग से दर्शित किया हुआ है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

372. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने एवं खोलने के क्या मानदण्ड एवं नियम निर्धारित हैं? मानदण्डों एवं नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में वर्तमान में कितने कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं और उनमें क्या-क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रशिक्षण केन्द्रों को केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधाएं एवं अनुदान दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त में से कई प्रशिक्षण केन्द्रों की सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो जनवरी 2015 से दिसम्बर 2016 तक किन-किन केन्द्रों की शिकायतें प्राप्त हुई? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा सभी योजनाओं में प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं के चयन हेतु EOI प्रकाशित की जाती है। इन EOI में पात्रता मानदंडों की योजनानुसार विस्तृत जानकारी दी जाती है। योजनावार मापदण्ड व नियमों की प्रति परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) प्रदेश में वर्तमान में 275 कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं। कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों व उनमें संचालित कोर्स की जिलेवार सूची परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

(3) निगम द्वारा प्रशिक्षण केन्द्रों को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जाता है। संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अनुमानित दरें निम्नानुसार हैं-

1. रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ELSTP): निगम मार्गदर्शिका के अनुसार राज्य के बेरोजगार पात्र युवाओं हेतु उत्पादन क्षेत्र से संबंधित आर्थिक क्षेत्रों के पाठ्यक्रमों के लिए प्रति प्रशिक्षणार्थी दर 23 रुपये प्रति घण्टा निर्धारित है। सेवा क्षेत्रों से संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए प्रति प्रशिक्षणार्थी दर 20 रुपये प्रति घण्टा निर्धारित है। आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रति प्रशिक्षणार्थी दर 120/- रुपये प्रतिदिन निर्धारित है।
2. पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY): भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के बीपीएल/गरीब ग्रामीण बेरोजगार युवाओं हेतु इस योजनान्तर्गत तीन महीने के कोर्स हेतु रुपया 13696/- प्रति प्रशिक्षणार्थी, इसके अतिरिक्त रुपया 17000/- प्रति प्रशिक्षणार्थी आने जाने का किराया, मुफ्त आवास, यूनिफार्म, पदस्थापन इत्यादि के मद में निर्धारित है।
3. नियमित कौशल प्रशिक्षण योजना (RSTP): इस योजना के अन्तर्गत सभी वर्ग के बेरोजगार युवाओं/युवतियों हेतु 14/- रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति घन्टा एवं 30/- रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति घन्टा विशेष योग्यजन हेतु निर्धारित है। आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रति प्रशिक्षणार्थी दर 120/- रुपये प्रतिदिन निर्धारित है।

(4) जी हां। निगम को कुछ प्रशिक्षण केन्द्रों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जनवरी 2015 से दिसम्बर 2016 के मध्य जिन प्रशिक्षण केन्द्रों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनकी सूची परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के संविदा कर्मियों का केन्द्र सरकार के अनुरूप मानदेय बढ़ाने की योजना

373. श्री रतन लाल जलधारी (सीकर): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रतन लाल जलधारी)

(1) क्या सरकार प्रदेश के संविदा कार्मिकों को केन्द्र सरकार के अनुरूप न्यूनतम 10,000 रुपये मानदेय देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार राज्य में न्यूनतम मजदूरी की दरें केन्द्र सरकार के अनुरूप करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सभी वर्गों की न्यूनतम मजदूरी दरें बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा-3 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी की दरों का निर्धारण एवं पुनरीक्षण करने के लिए राज्य सरकार सक्षम है। प्रदेश में राज्य सरकार 62 अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की दरों का निर्धारण/पुनरीक्षण करती है। इसके लिए अधिनियम की धारा-5(1) (बी) के अनुसार अधिसूचना जारी कर प्रभावित व्यक्तियों से सुझाव एवं आपत्ति मांगने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। न्यूनतम मजदूरी की दरों का निर्धारण/पुनरीक्षण लेबर ब्यूरो शिमला से जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के आधार पर किया जाता है।

राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी की दरेां का प्रतिवर्ष पुनरीक्षण करती है इसी क्रम में दिनांक 1.1.2017 से प्रभावी करने हेतु दिनांक 7.2.2017 को जारी अधिसूचना से निम्नांकित न्यूनतम मजदूरी की दरों को प्रस्तावित कर 2 माह में सुझाव एवं आपत्तियां मांगी गई हैं।

अकुशल		**अदर्धकुशल**		**कुशल**		**उच्च कुशल**	
दैनिक	मासिक	दैनिक	मासिक	दैनिक	मासिक	दैनिक	मासिक
207	5382	217	5642	227	5902	277	7202

उपरोक्त दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित श्रमिकों पर भी लागू होती हैं।

(2) राज्य सरकार लेबर ब्यूरो शिमला से जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के आधार पर न्यूनतम मजदूरी की दरें उपरोक्तानुसार निर्धारित करती है।

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

(3) राज्य सरकार 62 अनुसूचित नियोजन जिनमें धारा-2(1)(बी) के अंतर्गत समुचित सरकार राज्य सरकार है, में न्यूनतम मजदूरी की दरें उपरोक्तानुसार निर्धारित करती है। राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दरों का प्रतिवर्ष पुनरीक्षण किया जाता है। इसी क्रम में दिनांक 1.1.2017 से प्रभावी करने हेतु दिनांक 7.2.2017 को जारी अधिसूचना से निम्नांकित न्यूनतम मजदूरी की दरों को प्रस्तावित कर 2 माह में सुझाव एवं आपत्तियां मांगी गई हैं।

अकुशल		**अद्र्धकुशल**		**कुशल**		**उच्च कुशल**	
दैनिक	मासिक	दैनिक	मासिक	दैनिक	मासिक	दैनिक	मासिक
207	5382	217	5642	227	5902	277	7202

जवाहर कला केन्द्र की आर्ट एण्ड कल्चर गवर्निंग काउंसिल का गठन

374. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जवाहर कला केन्द्र की आर्ट एंड कल्चर गवर्निंग काउंसिल का गठन किया गया है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त काउंसिल के गठन में किस-किस को शामिल किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त काउंसिल में प्रदेश के निवासियों के अलावा बाहर के सदस्यों को भी लेने का प्रावधान है?

(4) उक्त काउंसिल में प्रदेश से एवं प्रदेश के बाहर से कौन-कौन सदस्य हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जवाहर कला केन्द्र के गवर्निंग बोर्ड का गठन दिनांक 30.09.2016 को किया गया है।

(2) जवाहर कला केन्द्र के संविधान के अनुच्छेद संख्या 4 के अनुसार केन्द्र में एक गवर्निंग बोर्ड का प्रावधान है, जिसके वर्तमान में निम्न सदस्य हैं:-

(कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री)

ए. मुख्य मंत्री, राजस्थान - अध्यक्ष (पदेन)

बी. मंत्री, कला एवं संस्कृति - उपाध्यक्ष (पदेन)

सी. महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र - सदस्य सचिव (पदेन)

डी. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग - सदस्य (पदेन)

ई. अध्यक्ष, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर - सदस्य (पदेन)

एफ. अध्यक्ष, राजस्थान ललित कला अकादमी, जयपुर - सदस्य (पदेन)

जी. वित्त विभाग का प्रतिनिधि जो विशिष्ट शासन सचिव/शासन सचिव से नीचे स्तर का न हो - सदस्य (पदेन)

एच. ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ - न्यूनतम 12 एवं अधिकतम 30 (अधिकतम 03 गैर सरकारी सदस्य राजस्थान से) राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों से मनोनीत करने का प्रावधान है, जिसके तहत निम्नानुसार ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया गया है

1. डा.- सरयू दोषी
2. सुश्री अमल अलाना
3. श्री सुनील मुँजल
4. श्री सुबोध गुप्ता
5. श्री अमरीश अरोड़ा
6. सुश्री फरोजा गोदरेज
7. श्री सलील सिंघल
8. श्री अशोक कजारिया
9. श्री अनिल राय गुप्ता
10. श्री विक्रम गोलछा
11. श्री विश्वमोहन भट्ट
12. श्री मुकन्द लाठ

(कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री)

(3) जी हां। केन्द्र के संविधान के अनुच्छेद संख्या 4 के उप बिन्दु एच के अनुसार ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ न्यूनतम 12 एवं अधिकतम 30 (अधिकतम 03 गैर सरकारी सदस्य राजस्थान से) राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों से मनोनीत किए जाने का प्रावधान है।

(4) केन्द्र के गवर्निंग बोर्ड में राजस्थान से निम्न ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ सदस्य मनोनीत हैं

1. श्री विक्रम गोलछा
2. श्री विश्व मोहन भट्ट
3. श्री मुकन्द लाठ

राजस्थान से बाहर के निम्नांकित ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ सदस्य मनोनीत हैं

1. डा. सरयू दोषी
2. सुश्री अमल अलाना
3. श्री सुनील मुँजल
4. श्री सुबोध गुप्ता
5. श्री अमरीष अरोड़ा
6. सुश्री फरोजा गोदरेज
7. श्री सलील सिंघल
8. श्री अशोक कजारिया
9. श्री अनिल राय गुप्ता

झुन्झुनूं जिले की प्राचीन हवेलियों का संरक्षण

375. श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार द्वारा प्राचीन हवेलियों व बावड़ियों के संरक्षण हेतु कोई कार्य योजना बनाई गई है? यदि हां, तो गत 10 वर्षों में झुंझुनूं जिले की प्राचीन हवेलियों व बावड़ियों के संरक्षण हेतु क्या-क्या कार्य कब-कब किये गये हैं व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। झुंझुनूं जिले में पुरातत्व विभाग द्वारा कोई हवेली या बावड़ी संरक्षित घोषित नहीं है और न ही वर्तमान में किसी हवेली या बावड़ी को संरक्षित घोषित करने का प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन है।

नगरपरिषद झुंझुनूं द्वारा 9 दिसम्बर, 2016 से मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) के अन्तर्गत प्राचीन मेडतानी बावड़ी की पानी भराव क्षमता बढ़ाने/पानी की आवक सुनिश्चित किये जाने हेतु मिट्टी निकालने (डिसिल्टिंग) का कार्य करवाया जा रहा है।

कोटा संभाग में विषयवार व्याख्याताओं के स्वीकृत पद

376. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी व तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? श्रेणीवार स्वीकृत पदों का जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने-कितने पदों पर अध्यापक कार्यरत हैं? श्रेणीवार कार्यरत पदों का जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) कोटा संभाग में प्रथम श्रेणी के विषयवार व्याख्याताओं के कितने पद स्वीकृत हैं तथा इसके विरुद्ध कितने व्याख्याता कार्यरत हैं? जिलेवार व विषयवार व्याख्याताओं के स्वीकृत पद व कार्यरत पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी व तृतीय श्रेणी के स्वीकृत पदों का श्रेणीवार व जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-"क-1" एवं परिशिष्ट-"क-2" पर संलग्न है।

(2) उक्त स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत अध्यापकों का श्रेणीवार व जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-"क-1" एवं परिशिष्ट-"क-2" में सम्मिलित है।

(3) कोटा संभाग में प्रथम श्रेणी के विषयवार व्याख्याताओं के स्वीकृत एवं कार्यरत पदों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-"ख" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के विद्यालयों में उर्दू विषय के अध्यापकों के रिक्त पद

377. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

वर्तमान में प्रदेश में ऐसे कितने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें उर्दू विषय पढ़ाया जाता है तथा ऐसे कितने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें उर्दू विषय के वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

प्रदेश के 131 राजकीय माध्यमिक तथा 816 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों (कुल 947) में उर्दू विषय पढाया जाता है। उक्त विद्यालयों में उर्दू व्याख्याता तथा वरिष्ठ अध्यापकों के स्वीकृत एवं रिक्त पद इस प्रकार हैं:-

पदनाम	स्वीकृत	रिक्त
व्याख्याता	421	58
वरिष्ठ अध्यापक	795	300

उक्त स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विद्यालय वार विवरण परिशिष्ट-क 01 से 09 पर संलग्न है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति से पात्र आशार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

धोद में रमसा के अन्तर्गत कार्य

378. श्री गोरधन (धोद) क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सैकण्डरी व हायर सैकण्डरी विद्यालयों में रमसा के अन्तर्गत भवन निर्माण व स्कूल चार दीवारी का कार्य किया जाता है? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र धोद में किस-2 विद्यालय में क्या-2 काम करवाया गया व उक्त योजना में विद्यालयों को चयन करने की क्या प्रक्रिया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। सैकण्डरी व हायर सैकण्डरी विद्यालयों में रमसा के अन्तर्गत भवन निर्माण का कार्य किया जाता है, परन्तु चारदीवारी निर्माण के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना अन्तर्गत कोई प्रावधान नहीं है। दिशा-निर्देशों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र धोद के विद्यालयों के करवाए कार्यों की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

विद्यालयों में भवन निर्माण हेतु यू-डाइस गैप के आधार पर प्रस्ताव तैयार कर एमएचआरडी को भिजवाया जाता है। प्रेषित प्रस्तावों में से एमएचआरडी द्वारा चयन किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

दूदू के विद्यालयों में नवीन संकाय खोलने की योजना

379. श्री प्रेम चन्द बैरवा (दूदू): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र दूदू में संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गत कई वर्षों से विभिन्न विषयों के व्याख्याताओं व वरिष्ठ अध्यापकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? हां, तो कब तक? पदवार रिक्त पदों की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उगरियावास में कला संकाय के अतिरिक्त नवीन संकाय (वाणिज्य), राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महलां में नवीन संकाय (वाणिज्य वर्ग) तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केसरीसिंहपुरा में नवीन संकाय (कला वर्ग) खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत व्याख्याताओं के 13098 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को प्रेषित किये जाने पर आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित कर परिणाम घोषित

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

किया जा चुका है, परन्तु वर्तमान में विशेष पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्तियों पर रोक के कारण नियुक्ति दिया जाना संभव नहीं है।

वरिष्ठ अध्यापक के 6468 एवं वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) के 211 पदों पर भर्ती हेतु अभ्यर्थनाएं आयोग को भेजी जा चुकी है, जिनकी परीक्षा माह अप्रैल, 2017 में आयोजित किये जाने की संभावना है।

अत: राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जाना संभव हो सकेगा।

विधान सभा क्षेत्र दूदू में संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न विषयों के व्याख्याता व वरिष्ठ अध्यापकों के विषयवार रिक्त पदों का पदवार विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। बजट घोषणा वर्ष 2016-17 में ऐसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जिनमें कक्षा 10 में 100 से अधिक नामांकन था, ऐसे 152 चिन्हित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय खोले जाने की घोषणा की गई थी। उक्त बजट घोषणा की पालना में 152 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त विषय संकाय स्वीकृत किये जा चुके हैं। उक्त विधान सभा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उगरियावास, महलां एवं केसरीसिंहपुरा में अतिरिक्त संकाय खोला जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सरदारशहर के विद्यालयों में रिक्त पद

380. श्री भंवरलाल (सरदारशहर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किस-किस संवर्ग के कौन-कौनसे पद स्वीकृत हैं? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री भंवरलाल)

(2) उक्त विद्यालयों में कहां-कहां, किस-किस संवर्ग के, कितने-कितने पद कब-कब से रिक्त हैं? विद्यालयवार, संवर्गवार व विषयवार रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त सभी संवर्ग के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र के सरदारशहर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत पदों का संवर्ग वार, विद्यालयवार संख्या विवरण परिशिष्ट "क" तथा "ख" पर संलग्न है।

(2) उक्त राजकीय प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पद एवं पद कब से रिक्त हैं, का संवर्गवार, विषयवार, विद्यालय वार संख्या विवरण परिशिष्ट "क" तथा "ख" में सम्मिलित है।

(3) जी हां। प्रारंभिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती, 2012 व 2013 के माननीय न्यायालय निर्णय की अनुपालना में शेष बचे (2,000+8,000) कुल 10,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2016 के 15,000 पदों पर भर्ती की कार्यवाही रीट परीक्षा के माध्यम से भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष संवर्ग के रिक्त राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, राजस्थान मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड अजमेर व विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित पात्र, आशार्थी उपलब्ध होने पर भरे जा सकेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-1

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

नागौर में विद्युत विभाग द्वारा निकाली गई बकाया राशि की समाप्ति

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र नागौर में विभाग द्वारा बढ़ाई गई दरों व ऑडिट द्वारा निकाली गई बकाया व विजिलेंस चैकिंग के नाम से उपभोक्ताओं से लाखों रुपये की बकाया राशि निकाल कर विद्युत बिल भुगतान हेतु जारी कर दिये गये। उपभोक्ता द्वारा नियमित बिल भुगतान किया जा रहा है, फिर भी बकाया के नाम से घरेलू उपभोक्ताओं के 50 से 60 हजार रुपये तक के दुकानों के विद्युत कनेक्शनों के 2 से 5 लाख तक की राशि का भुगतान के बिल प्राप्त होने पर विद्युत विभाग के कार्यालय पर सम्पर्क करने पर बताया कि ऑडिट द्वारा पिछला बकाया निकाला गया है। इस संदर्भ में संसदीय सचिव, श्री लादूरामजी को इस समस्या से अवगत करवाया तो माननीय श्री लादूरामजी द्वारा नागौर में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्या समाधान हेतु दो दिन का कैम्प भी लगाया गया। भारी संख्या में उपभोक्ता अपनी समस्याएं लेकर उपस्थित हुए, परन्तु इसका कोई समाधान विद्युत विभाग द्वारा नहीं किया गया। संसदीय सचिव, श्री लादूरामजी द्वारा पूरी रिपोर्ट तैयार कर मुख्य मंत्री कार्यालय को प्रस्तुत की गई, फिर भी उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान नहीं निकाला एवं उनके बकाया के नाम पर विद्युत कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र की जनता में भारी रोष व्याप्त हो रहा है।

अत: मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ऑडिट व विजिलैंस चैकिंग के नाम से निकाली गई, बकाया व बढ़ी हुई दरों से बकाया राशि को समाप्त करने के आदेश जारी करें, ताकि उपभोक्ताओं को हो रही आर्थिक व मानसिक परेशानी से निजात मिल सके।

हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा
(नागौर)

सैटेलाइट अस्पताल प्रताप नगर में नार्म्स के अनुरूप समस्त संसाधनों का विकास

महोदय,

मैं आपका ध्यान विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के सैटेलाइट अस्पताल, प्रताप नगर, जोधपुर में सैटेलाइट स्तर अनुरूप संसाधनों के विकास की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं।

उक्त अस्पताल को 20.06.2013 को सैटेलाइट स्तर पर क्रमोन्नयन किया गया था। परन्तु आज तक यहां के प्रभारी को आहरण वितरण अधिकार नहीं दिये गये हैं। मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी में लाखों रु. जमा है, परन्तु आवश्यक राशि व्यय नहीं की जा सकी है। स्वीकृत पदों में से अधिकांश पद रिक्त हैं तो कुछ पदस्थापित चिकित्सक और कार्मिक लगातार प्रतिनियुक्ति पर हैं। सैटेलाइट स्तर का अस्पताल होने के बावजूद लिपिक संवर्ग का एक पद स्वीकृत नहीं है। अस्पताल भवन को अविलम्ब मरम्मत की आवश्यकता है, परन्तु इस बाबत् कोई बजट राशि किसी भी मद से स्वीकृत नहीं की गई है। एक्स-रे मशीन है, परन्तु रेडियोग्राफर नहीं होने से उपयोग नहीं हो पा रहा है। सैटेलाइट स्तर का अस्पताल होने के बावजूद यहां अब तक केवल औषधालय स्तर की ही निःशुल्क जांच सुविधाएं उपलब्ध हो पा रही हैं। इस हेतु स्थानीय विधायक होने के नाते मेरे विधायक कोष से उपकरण उपलब्धता हेतु राशि स्वीकृत की गई है जो कि एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी तक कागजी कार्यवाही में लंबित चल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त अस्पताल को विभागीय अधिकारियों द्वारा जान बूझकर उपेक्षित रखा जा रहा है ताकि नजदीकी निजी अस्पतालों को लाभ पहुंचाया जा सके। यह बहुत ही खेदजनक स्थिति है कि स्थानीय विधायक द्वारा नियमित निरीक्षण कर सभी तथ्यों का उल्लेख करते हुए सभी स्तर पर रिपोर्ट भेजे जाने के बावजूद व्यवस्थाओं में सुधार के कोई प्रयास किसी भी स्तर से नहीं किये जा रहे हैं।

मेरा निवेदन है कि सैटेलाइट अस्पताल प्रतान नगर, जोधपुर में प्रभारी चिकित्सक को आहरण वितरण अधिकार दिये जाएं, चिकित्सक/कार्मिक स्टाफ के समस्त रिक्त पदों को भरा जाए, प्रतिनियुक्त स्टाफ को अविलम्ब प्रतिनियुक्ति से कार्यमुक्त किया जाए, मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी की

अविलम्ब बैठक आयोजित कर लंबित सभी प्रस्तावों को क्रियान्वित किया जाए। स्थानीय विधायक के निरीक्षण प्रतिवेदन को सुझावों को अविलम्ब क्रियान्वित किया जाए, नि:शुल्क जांच सुविधाओं का दायरा सैटेलाइट स्तर तक बढ़ाने के लिए विधायक कोष से स्वीकृत राशि से उपकरणों की खरीद प्राथमिकता से की जाए और आवश्यक तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति की जाए, भवन मरम्मत मद में राशि स्वीकृत की जाए।

सादर। **सूर्यकान्ता व्यास**
(सूरसागर)

नगर में आवासीय महाविद्यालय खोलने के संदर्भ में

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि नगर विधान सभा क्षेत्र में सरकारी कॉलेज न होने की वजह से वहां के विद्यार्थियों अलवर पढ़ने जाना पड़ता है, वहां कमरा किराये पर लेना पड़ता है जिससे खर्चा बहुत बढ़ जाता है और नगर में SBC व OBC के लोग ज्यादा रहते हैं जो आर्थिक रूप से विकलांग हैं। गरीब किसान रहते हैं और जिसकी वजह से अच्छे, होनहार व काबिल विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और जो कॉलेज या निजी स्तर पर चल रहे हैं उनमें शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। रजिस्टर में नाम जिन प्रोफेसर का लिखा है वो वहां पढ़ाता नहीं और कम स्तर के व्याख्याता पढ़ाते हैं। परीक्षा काल में सब कॉलेज वाले मिलीभगत करते हैं और फीस भी ज्यादा वसूलते हैं जिसकी वजह से किसान गरीब के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। अत: निवेदन है कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ रहा है उसे आगे बढ़ाने के लिए सरकार महाविद्यालय खोले। देवनारायण योजना के अंतर्गत या MSDP के अंतर्गत भी आवासीय महाविद्यालय खोला जा सकता है। मवात व SBC, OBC के गरीब किसान रहते हैं। कृपया वहां महाविद्यालय खोलने की कृपा करें। वहां शिक्षा के क्षेत्र में निजी महाविद्यालय की जांच भी कराए ताकि वहा के शिक्षा के स्तर में गुणवत्ता आए इसके लिए ठोस उपाय किये जाएँ।

विषय की बात करे तो विज्ञान व कामर्स के छात्र तो दर ब दर

भटक रहे हैं। सरकार सबका साथ सबका विकास नारे को सार्थक करने के लिए किसान के बच्चों को अच्छी व कम खर्च पर शिक्षा मिले, इसके लिए नगर विधान सभा क्षेत्र जो 100 किलोमीटर में फैला है और आस पास सरकारी कॉलेज नहीं है। उसमें सरकारी कॉलेज खोला जाए।

धन्यवाद।

अनीता
(नगर)

गोगुन्दा में आदिवासियों को वन अधिकार पत्र दिया जाना

महोदय,

मेरा विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा पहाड़ी एवं वन क्षेत्र है। भारत सरकार के विधेयक के अनुसार 2005 से पूर्व वन क्षेत्र में परम्परागत निवास किरने वाले जन जाति आदिवासी परिवारों को वन अधिकार पत्र दिये जाने थे। मेरे विधान सभा क्षेत्र पं. स. गोगुन्दा की ग्राम पंचायतों क्रमश: समीजा, वीरपुरा, मादड़ा, पड़ावली कलां, पड़ावली खुर्द, वास, अम्बाना, नाल, पाटिया, मोरवल, दादिया, झाड़ौली पं. स. सायरा की ग्राम पंचायतों कडेच, चित्रावास, रावछ, विसमा, सेमड, बोखाड़ा, सिंघाड़ा, पलासमा तथा पं.स. कोटड़ा की 44 ग्राम पंचायतें वन क्षेत्र में आती हैं। सरकार की विभिन्न योजनाएं जैसे- भूमि समतलीकरण, मुख्य मंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित होती हैं। साथ ही सरकारी भवन यथा ग्राम पंचायत भवन, विद्यालय भवन, आंगनबाड़ी भवन, भी बनाने होते हैं। किन्तु वन क्षेत्र में अधिकार पत्र जारी नहीं किये जाने से उक्त सभी कार्यों में भारी परेशानी आ रही है। जिससे क्षेत्र का विकास यथोचित रूप से नहीं हो पा रहा है।

मेरा निवेदन हैं कि सरकार शिविर लगवाकर वन अधिकार पत्र वितरण का अभियान चलाए जिससे क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासियों का भला हो सकेगा।

प्रताप लाल भील
(गोगुन्दा)

परबतसर में गौरव पथ निर्माण में यूटीलिटी शिफ्टिंग का कार्य नहीं करने से उत्पन्न समस्या

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण राजस्थान प्रदेश के 179 निकायों में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से गौरव पथ विकसित किये जाते हैं।

यह राजस्थान के मुख्य मंत्री माननीया वसुन्धरा राजे की एक महत्वाकांक्षी योजना पूरे राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ व शहरी गौरव पथ के माध्यम से प्रदेश को स्वच्छ बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है।

उक्त गौरव पथ मॉडल के रूप में विकसित किये जाने हैं जिसमें 179 निकायों में गौरव पथ निर्माण बाधित कर रही यूटिलिटी जैसे पानी, बिजली, टेलीफोन के खंभे व लाइनों का शिफ्टिंग का कार्य भी किया जाना है। इसके लिए समस्त जिला कलेक्टर्स को पवन अरोड़ा निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान ने पत्र दिनांक 16.02.2017 लिख कर माननीया मुख्य मंत्री महोदया द्वारा दिये गये निर्देश दिनांक 30.05.2016 व दिनांक 27.09.2016 को विभाग द्वारा दिये गये निर्देश में गौरथ पथ निर्माण 179 नगरीय निकायों में गौरव पथ निर्माण कार्य R.T.I.D.F. में स्वीकृत राशि से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जा रहा है।

साथ ही यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य संबंधित विभागों, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, विद्युत वितरण निगम, दूरसंचार विभाग, नगर विकास न्यास नगरीय निकाय आदि द्वारा स्वयं के स्तर पर ही किया जाएगा। जिसका व्यय संबंधित विभाग द्वारा ही वहन किया जाएगा। गौरव पथ निकाय कार्य हेतु स्वीकृत राशि का उपयोग केवल गौरव पथ निर्माण में ही किया जाएगा परन्तु उपरोक्त यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य संबंधित विभागों द्वारा नहीं किया जा रहा है जिससे परबतसर व कई नगरीय निकायों को गौरव का कार्य बाधित हो रहा है।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस कार्य के लिए अविलम्ब कार्यवाही सरकार के द्वारा करवाएं।

मानसिंह किनसरिया

(परबतसर)

कनवास तहसील (सांगोद) में डाइवर्जन चैनल का निर्माण

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र के कनवास तहसील में पठारी क्षेत्र एवं मुकुन्दरा हिल्स क्षेत्र से बारिश के दिनों में अधिक वर्षा के कारण भारी मात्रा में बारिश का पानी मैदानी भू- भाग में आ जाता है, जहां पानी भरने के कारण किसानों की फसल को नष्ट कर देता है। जिससे किसानों का बड़ा नुकसान होता है एवं रबी की फसल पूर्ण रूप से चौपट हो जाती है। इस हेतु मेरे द्वारा जल संसाधन विभाग के माध्यम से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव सरकार को भिजवाये गये। जिसमें विभाग द्वारा डीपीआर तैयार की जा चुकी है। वर्तमान में कनवास तहसील के पठारी क्षेत्र में अधिक पानी आने से पोकल्या खाल, सतमुड़िया खाल, काल्याखेडी का खाल, दाता, मन्दारिया का खाल के क्षेत्र से पानी के बहाव के कारण ग्राम पंचायत मामोर, हिंगोनिया, झालरी, बालुहेडा, देवली सहित अनेक गांव में जल पलायन हो जाता है, जिसे रोकने की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री महोदय का ध्यान पुन: आकर्षित करते हुये निवेदन करना चाहता हूं कि सांगोद विधान सभा कनवास तहसील के गांव को वर्षा जल से होने वाली तबाही को रोकने हेतु प्रथम चरण में प्रधानमंत्री सिंचाई योजनान्तर्गत भिजवाये गये प्रस्ताव के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए स्वीकृत कर डायवर्जन चैनल का निर्माण करने का श्रम करें।

हीरालाल नागर
(सांगोद)

फलौदी को नवीन जिला घोषित किया जाना

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा फलौदी का उपखण्ड़ मुख्यालय फलौदी जिला मुख्यालम जोधपुर से 140 कि.मी. तथा बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर जिला मुख्यालयों से औसतन 150 से 160 कि.मी. दूरी पर है। जिला मुख्यालय से दूरी होने के कारण इस क्षेत्र में निरन्तर देश विरोधी गतिविधियों एवं सामरिक महत्त्व की सूचनाओं के लिए विदेशी ताकतों के द्वारा निरन्तर गतिविधियों को अन्जाम दिया जा रहा है। जिला मुख्यालय से दूरी होने के कारण उन पर वर्तमान में प्रभावी नियन्त्रण नहीं रखा जा रहा है।

फलौदी जिले का गठन दो उपखण्ड - फलौदी एवं बाप, तीन तहसील - फलौदी, बाप एवं लोहावट एवं पांच पंचायत समितियां हैं। नवीन फलौदी जिला बनने पर इस क्षेत्र में स्थापित सोलर हब, पवन ऊर्जा, नहर से सिंचित क्षेत्र, नलकूपों से सिंचित क्षेत्र, नमक उत्पादन क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र के विकास में तीव्र विकास गति होने की अपार सम्भावनाएं हैं। फलौदी मुख्यालय पर पर्याप्त राजकीय भूमि तथा भवन इत्यादि उपलब्ध है।

वर्तमान में फलौदी में अतिरिक्त जिला एवं सत्र् न्यायालय, अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्टेड, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय, जिला उद्योग केन्द्र, उपज मण्डी समिति फल सब्जी मण्डी कृषि विज्ञान केन्द्र दुग्ध अभिशीतन केन्द्र राजस्थान पथ परिवहन निगम का आगार, विभिन्न बैंकों की शाखाएं डाकघर, भूमि विकास बैंक इत्यादि वित्तीय संस्थान स्थापित हैं तथा शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण संस्थाएं स्थापित हैं।

नवीन जिला फलौदी के गठन हेतु जोधपुर जिले की दो विधान सभा क्षेत्र फलौदी एवं लोहावट क्षेत्र में जैसलमेर जिले की पोकरण विधान सभा क्षेत्र की सात ग्राम पंचायतें जो कि उपखण्ड क्षेत्र बाप की सीमा से लगती हुई है क्रमश: नोख, टावरीवाला, बोडाना, शक्तिनगर, मदासर, चिन्नू, जालूवाला, को शामिल करते हुए जिले का गठन किया जा सकता है।

मैं सदन के माध्यम से विशेष उल्लेख के द्वारा सरकार से आग्रह करता फलौदी को नवीन जिला गठन किया जाए।

पब्बाराम

(फलौदी)

सीकर से लुहारू बार्डर तक फोर-लेन सड़क

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर से सीकर तक फोर-लेन का उपयोग हम कर रहे हैं। अब टुल रोड बनाकर जनता को राहत दी है, परन्तु सीकर से लुहारू बार्डर तक पूर्व में बी.ओ.टी. सडक थी, परन्तु उसका टाइम खतम हो गया है, पुन: 2 वर्ष तक श्याम मंदिर है, हनुमानजी का सालासर का मंदिर है, हरियाणा, दिल्ली, यूपी व मध्यप्रदेश से लोग आते हैं।

अत: इतनी महत्वपूर्ण सड़क को फोर-लेन घोषित करें और राजस्थान का नाम पूरे भारत में ऊँचा करें।

यह सरकार जवाबदेही है, पारदर्शी है और किसानों की होने की वजह से सरकार उसे स्वीकृति प्रदान करेगी।

श्रवण कुमार
(सूरजगढ़)

नगरपालिका खैरथल व किशनगढ़ बास में सीवरेज व्यवस्था

महोदय,

निवेदन है कि नगरपालिका क्षेत्र खैरथल व नगरपालिका किशनगढ़ बास में सीवरेज व्यवस्था व गन्दे पानी की निकासी नहीं है। नगरपालिका खैरथल की आबादी लगभग 50 हजार व नगरपालिका किशनगढ़ बास की आबादी लगभग 35 हजार है। उक्त दोनों नगरपालिकाएं एन.सी.आर. क्षेत्र में आती हैं। नगरपालिका खैरथल में औद्योगिक क्षेत्र व राजस्थान की प्रमुख कृषि उपज मण्डी भी है। नगरपालिका किशनगढ़ बास में बरसात के दिनों में पानी की निकासी सही नहीं होने के कारण आमजन को आवागमन में कठिनाई होती है। उक्त दोनों नगरपालिकाओं की लगभग दूरी 7 किमी. है, दूरी कम होने पर उक्त दोनों नगरपालिकाओं में व्यापारियों व आमजन का आवागमन काफी बड़ी संख्या में रहता है। उक्त दोनों नगरपालिकाओं में सीवरेज व्यवस्था व गन्दे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से उक्त क्षेत्र के लागों में काफी भारी रोष है।

अत: मैं सदन के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि नगरपालिका खैरथल व किशनगढ़ बास में सीवरेज व्यवस्था व गन्दे पानी की समुचित व्यवस्था करवाई जाए, जिससे आमजन को आवागमन में आसानी हो सके।

रामहेत सिंह यादव
(किशनगढ़ बास)

किसानों को प्याज का उचित मूल्य दिलवाने के संबंध में

महोदय,

माण्डलगढ़ विधान सीा क्षेत्र के बिजौलिया तहसील में वर्तमान में 21 आदर्श रा.उ.मा. विद्यालय स्थित हैं जिनमें विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के बालक/बालिकाएं अध्ययनरत हैं। इस क्षेत्र के सभी विद्यालयों में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या होने के साथ ही उचित एवं आवश्यक संसाधन सभी आदर्श स्कूलों में हमारी सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं। इस क्षेत्र में शैक्षिक वातावरण उत्कृष्ट दर्जे का बना हुआ है। इस क्षेत्र में मुख्यतया, खेराड, ऊपरमाल व कुछ हाड़ौती क्षेत्र के भी बच्चे अध्ययनरत हैं। इसका प्रमुख कारण यह रहा है कि यहाँ पर हमारी सरकार द्वारा दी गई समुचित सुविधा व संसाधन हैं। यहां पर विभिन्न सरकारी व निजी विद्यालयो में लगभग 5326 छात्र एवं 4082 छात्राएं अध्ययनरत हैं।

परन्तु विगत कई वर्षो से और पिछली कांग्रेस सरकार की उपेक्षा की शिकार रही बिजौलिया तहसील में अब तक महाविद्यालय नहीं खुल पाया है। जिससे यहाँ पर गरीब मध्यम वर्ग व मुख्य रूप से बालिकाओं को उच्च शिक्षा में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तथा कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि ग्रामीण व पिछड़ी बालिकाओं को बीच में शिक्षा (पढ़ाई) छोड़नी पड़ती है। जिससे सरकार की मुहिम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ भी कमजोर होती है।

हम शिक्षा के क्षेत्र में जो दृश्य राजस्थान का और पूरे भारत का देखना चाहते हैं। उसके लिए हमें ग्रामीण और जरूरतमंद क्षेत्रों में संसाधन उपलब्ध कराने होंगे और यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता भी है कि हम उन वंचित लोगों तक सुविधा उपलब्ध करवाएंगे जो आज तक इन मौलिक अधिकारों से वंचित हैं।

बिजौलिया क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यह अपने आसपास के सभी क्षेत्रों से ऊपर है इसलिए इसे ऊपरमाल भी कहा जाता है।

बिजौलिया तहसील से नजदीकी महाविद्यालय की दूरी 38 किलोमीटर है जो माण्डलगढ़ में स्थित है। उसके बाद बूंदी में है जो 50 किलोमीटर है। उसके बाद भीलवाड़ा है जिसकी दूरी 80 किलोमीटर है, कोटा की दूरी 70 किलोमीटर है। इतनी दूरी पर ये महाविद्यालय हैं जहां पर गरीब व ग्रामीण बच्चे और विशेष रूप से बालिकाओं का जाकर या रहकर उच्च शिक्षा ग्रहण करना मुश्किल हो जाता है।

आपके द्वारा मेरा निवेदन है कि महाविद्यालय खोला जाए इस क्षेत्र की जनता आपकी आभारी रहेगी।

कीर्तिकुमारी
(माण्डलगढ़)

राज्य में मंदिर, मस्जिद एवं पर्यटन स्थलों हेतु सड़क निर्माण

महोदय,

राज्य में मुख्य मंदिरों, मस्जिदों एवं पर्यटक स्थलों तक आवागमन हेतु सड़कों का भारी अभाव है। मुख्य मंदिर, मस्जिद एवं पर्यटक स्थलों के सड़कों से नहीं जुड़ने के कारण आने वालों को भारी असुविधाएं हो रही हैं एवं राज्य सरकार के विरुद्ध रोष व्याप्त है।

पूर्ववर्ती राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में मंदिरों एवं पर्यटक स्थलों हेतु 5 सड़कें प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में बनवायी गयी थीं। ऐसी ही योजना वर्तमान राज्य सरकार को संचाचित किये जाने की महती आवश्यकता है।

राज्य सरकार को प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 5 प्रमुख मंदिरों, 2 मस्जिदों एवं अन्य पर्यटक स्थलों के लिये सड़क निर्माण हेतु पूर्ववर्ती राज्य सरकार की तरह ही बजट प्रावधान किया जाना आवश्यक हो गया है। इससे न केवल राज्य में विकास को गति मिलेगी बल्कि राज्य सरकार द्वारा आस्था एवं आवागमन को बढ़ावा व सुविधायुक्त किये जाने से आमजन की निष्ठा राज्य सरकार के प्रति अगाध हो सकेगी।

ज्ञानदेव आहूजा
(रामगढ़)

सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में लीजधारकों द्वारा अवैध खनन

महोदय,

उपरोक्त संदर्भ में ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि जिला सवाई माधोपुर की तहसील चौथ का बरवाड़ा में बनास नदी के सात गांव धोती, देवली, डिडायच, समुद्रपुरा, बन्देडिया, बगीना एवं एंचेर के 100.55 हैक्टैयर क्षेत्र में श्री मंगलसिंह सोलंकी द्वारा वर्ष 2013 से 2016 की अवधि में 9 भारी एलएनटी मशीनों, एक बुलडोजर व एक रोड रोलर का उपयोग कर लाखों डम्पर, ट्रोला, ट्रक एवं ट्रैक्टर ट्रोली 45 लाख टन बजरी (करीबन 100 करोड़) का सरेआम, रात-दिन कार्य चलाकर बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया गया। क्षेत्र के गांवों के हर नागरिक ने इस अवैध खनन को देखा व संबंधित अधिकारियों को भी अनेक बार शिकायत भी की। बिना परमिट बजरी निकालकर लीजधारक मंगल सिंह सोलंकी ने खान व खनिज (विकास एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1957 की धारा 4 (i), का अल्लघन किया है। खान

एवं खनिज (विकास एवं नियत्रंण) अधिनियम 1957 की धारा 4 (i) का उल्लघन करने पर भी मंगल सिंह सोलंकी ने 45 लाख टन बजरी की राशि अधिनियम 1957 की धारा 21(5) के तहत बाजार कीमत पर वसूल की जाये। अवैध खनन करने के लिए श्री मंगल सिंह सोलंकी ने जिन नौ एलएनटी मशीनों एवं अन्य साधनों का उपयोग किया, उन्हें अधिनियम की धारा 21(4) के तहत जब्त किया जाए। धारा 4(1), 4(1ए) तोड़ने पर श्री मंगल सिंह सोलंकी पर अधिनियम की 1957 की धारा 21(1) के तहत दण्ड व पैनल्टी लगाई जाए। धारा 4(1) तोडने पर अधिनियम 1957 की धारा 21(3) के तहत कार्यवाही करके बनास नदी को खाली कराया जाए। अधिनियम 1957 की धारा 4(1) या 4(1ए) को तोड़ना एक संगीन अपराध है। उक्त लीज शर्तो के उल्लंघन को लेकर लीजधारक की लीज निरस्त की जाए। तहसील मलारना डूंगर व तहसील सवाई माधोपुर में श्री मनजीत चावला को लीज क्षेत्र सुपुर्द नहीं किया गया, फिर भी वह 2013 से रॉयल्टी के साथ जाली रसीद काट कर जनता से मनमानी राशि वसूल रहा है।

जाली रसीदों पर कोई CST/ST/VAT/ED/TIN/PAN/SERVICE TAX इत्यादि का ब्यौरा नहीं है। इन जाली रसीदों को बार-बार शिकायत करने के बाद भी बन्द नहीं किया जा रहा है, लीजधारक की अवैध वसूली के कारण मार्केट में बजरी के भाव आसमान छू रहे हैं। उक्त संबंध में थाना चौथ का बरवाड़ा में एफआईआर भी दर्ज करायी है, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

डॉ. किरोड़ीलाल मीणा
(लालसोट)